चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

1986 से प्रकाशित

दिल्ली, 20 फरवरी–26 फरवरी 2012

मूल्य 5 रुपये

बिहार में नई सियासी नौटंकी

पेज-3

क्या रशीद मसूद मुख्यमंत्री बन सकते हैं

पेज-4

एक तीर से कई निशाने

पेज-5

भारत में कोयले की काली लकीर

पेज-7

लोक स्वराज

टीम अन्ना का नया आंदोलन

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

समय सीमा 2014. इससे पहले टीम अन्ना एक नया आंदोलन शुरू करेगी, नाम होगा लोक स्वराज. काग़ज़ी तैयारी हो चुकी है, ज़मीनी तैयारी भी लगभग शुरू हो गई है. इंतज़ार है तो सिर्फ़ विधानसभा चुनाव ख़त्म होने का. इसके बाद फिर एक बिल आएगा. फिर से आंदोलन होगा. फिर से एक मांग होगी. आख़िर क्या है नया मुद्दा, कैसे शुरू होगा नया आंदोलन और क्या है एजेंडा? पेश है चौथी दुनिया की यह ख़ास रिपोर्ट...

शशि शेखर

चौथी दुनिया के पास उपलब्ध जानकारी के मुताबिक़, लोक स्वराज आंदोलन की तैयारी दरअसल लोकपाल आंदोलन से काफी पहले हो चुकी थी. यह पूरी कहानी 2009 से ही शुरू होती है, जब क़रीब–क़रीब लोक स्वराज आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी. दिल्ली के कुछ इलाक़ों में पीसीआरएफ और परिवर्तन जैसी संस्थाओं ने लोक स्वराज के प्रयोग भी शुरू किए थे, लेकिन सरकारी लोकपाल बिल बनने की ख़बर जैसे ही आई, वैसे ही अरविंद केजरीवाल ने लोक स्वराज के मुद्दे को स्थगित कर दिया और फिर जन लोकपाल आंदोलन की नींव डाली. बहरहाल, टीम अन्ना अब यह मानकर चल रही है कि लोकपाल का उस स्वरूप में संसद से पारित हो पाना मुश्किल है, जैसा वह चाहती थी. इसे टीम अन्ना की हार न कहें तो भी एक झटका तो है ही, जो उसे केंद्र की सरकार ने दिया है. लेकिन अब टीम अन्ना अपनी रणनीति में थोड़ा फेरबदल करके फिर से अपने पुराने मुद्दे यानी लोक स्वराज आंदोलन की तैयारी में जुट गई है. यानी एक और नया आंदोलन शुरू होने वाला है.

ज़ाहिर है, लोकपाल आंदोलन से मिले जन समर्थन से उत्साहित टीम अन्ना लोक स्वराज आंदोलन शुरू होने के संकेत काफी पहले से ही दे रही थी. अन्ना हजारे जब रामलीला मैदान में अपना अनशन तोड़ रहे थे, उसी वक़्त उन्होंने कहा था कि लोकपाल के बाद की लड़ाई गांव, किसान, मज़दूर और ज़मीन की होगी, लेकिन कोई ठोस तस्वीर इस संबंध में बनती नहीं दिख रही थी. बीती 26 जनवरी को दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में अन्ना का जो संदेश प्रसारित किया गया, उसमें ग्रामसभा और प्रजा सत्ता की बात थी. अन्ना ने कहा कि प्रजा सत्ता स्थापित करने के लिए आंदोलन करना होगा. सबसे अहम जानकारी यह है कि टीम अन्ना के एक अहम सदस्य अरविंद केजरीवाल 2 साल पहले ही केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नगर राज बिल के मुक़ाबले कई सारे सुझाव तैयार कर चुके थे. इतना ही नहीं, बाकायदा सरकार के नगर राज बिल के मुक़ाबले एक आदर्श नगर राज बिल भी इन लोगों ने तैयार कर लिया है. जैसा कि सरकारी लोकपाल के मसले पर हुआ, इस बार भी टीम अन्ना अपनी तरफ़ से एक आदर्श लोक स्वराज बिल पेश कर सकती है, जो लोक स्वराज आंदोलन का एक बड़ा आधार बन सकता है.

टीम अन्ना लोक स्वराज आंदोलन की ज़मीन तैयार करने के लिए सबसे पहले देश में वैचारिक मंथन के ज़रिए वैचारिक क्रांति पर जोर दे रही है. इसके लिए देश भर में चर्चा समूहों का गठन किया जा रहा है, जिन्हें स्वराज चर्चा समूह या अन्ना चर्चा समूह का नाम दिया गया है. इन समूहों के ज़रिए जनता अपने सवालों को उठाएगी और ख़ुद ही उनका समाधान भी ढूंढेगी. कोई भी व्यक्ति अपने कुछ मित्रों, सहकर्मियों एवं पड़ोसियों आदि के साथ मिलकर यह चर्चा समूह शुरू कर सकता है.

लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल पर राजनीतिक दलों का जो रुख़ रहा, उसे लेकर टीम अन्ना का मानना है कि देश की अधिकांश जनता ने जिस मज़बूत लोकपाल की मांग की, उसे इस देश की संसद देने में अक्षम रही और देश की संसद ही जनता की उस मांग के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई. टीम अन्ना और ख़ुद अन्ना हजारे की नज़र में यह जनतांत्रिक क़दम नहीं था. टीम अन्ना सीधे इस देश की संसद पर सवाल उठाते हुए कहती है कि क्या यह संसद इस देश को ग़रीबी, भुखमरी और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सकती है? टीम अन्ना लोकपाल क़ानून पारित न होने की इस घटना के आधार पर इस पूरी व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव की बात कर रही है. इसके लिए उसे लोक स्वराज का रास्ता बेहतर लग रहा है, लेकिन 2009 और 2012 के बीच काफी अंतर आ चुका है. 2009 में जिस स्वरूप में लोक स्वराज आंदोलन की शुरुआत की गई थी, वह अब 2012 में बिल्कुल ही अलग है. उसकी तैयारी अलग तरीक़े से की जा रही है. टीम अन्ना लोक स्वराज आंदोलन की ज़मीन तैयार करने के लिए सबसे पहले देश में वैचारिक मंथन के ज़रिए वैचारिक क्रांति पर जोर दे रही है. इसके लिए देश भर में चर्चा समूहों का गठन किया जा रहा है, जिन्हें स्वराज चर्चा समूह या अन्ना चर्चा समूह का नाम दिया गया है. इन समूहों के ज़रिए जनता अपने सवालों को उठाएगी और ख़ुद ही उनका समाधान भी ढूंढेगी. कोई भी व्यक्ति अपने कुछ मित्रों, सहकर्मियों एवं पड़ोसियों आदि के साथ मिलकर यह चर्चा समूह शुरू कर सकता है. वह व्यक्ति आयोजक कहा जाएगा और उसे स्वराज चर्चा समूह या अन्ना चर्चा समूह का नाम दिया जाएगा. चर्चा समूह की बैठक हर सप्ताह निश्चित समय और स्थान पर किए जाने की योजना बनाई जा रही है.

ऐसे चर्चा समूह शुरू भी हो चुके हैं और इसकी शुरुआत सबसे पहले टीम अन्ना के सदस्यों ने की है. वे लोक स्वराज से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करके उसके वीडियो बनाकर ब्लॉग पर डाल रहे हैं. इसी तरह के एक चर्चा समूह के वीडियो में टीम अन्ना इस बात को स्वीकारती नज़र आ रही है कि अभी तक वह अपने आंदोलन (जन लोकपाल) में अपनी बात केवल मीडिया के ज़रिए जनता तक पहुंचाती थी. इसका नतीजा यह हुआ कि जनता सीधे उससे

(शेष पृष्ठ 2 पर)

इन मसलों पर होगी लड़ाई

चौथी दुनिया के पास टीम अन्ना के अहम सदस्य अरविंद केजरीवाल एवं अन्य सदस्यों द्वारा तैयार उस मॉडल नगर राज बिल की प्रति है, जो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नगर राज बिल की खामियों को सामने लाते हुए शहरों में ग्रामसभा की तर्ज पर मोहल्ला सभा बनाने और नगर पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़ाने की बात करता है. इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था में पहले से मौजूद ग्रामसभा को मज़बूत बनाने के लिए भी कई सुझाव तैयार किए गए हैं, जिनके आधार पर टीम अन्ना लोक स्वराज आंदोलन की नींव रखेगी. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक़, टीम अन्ना निम्न बिंदुओं के आधार पर ही लोक स्वराज की लड़ाई लड़ेगी. टीम अन्ना अगर स्थानीय शासन प्रणाली यानी नगर और पंचायती राज जैसी संस्थाओं को मज़बूत बनाने के लिए कोई बिल बनाकर सरकार के सामने रखती है, (जैसे कि लोक स्वराज बिल) तो उसमें

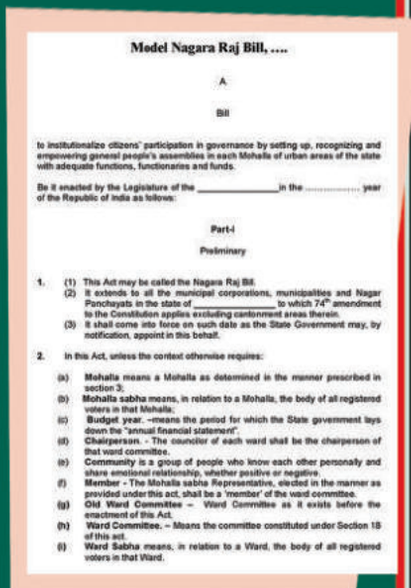

Model Nagara Raj Bill, ...

A

Bill

to institutionalize citizens' participation in governance by setting up, recognizing and empowering general people's assemblies in each Mohalla of urban areas of the state with adequate functions, functionaries and funds.

Be it enacted by the Legislature of the _____ in the _____ year of the Republic of India as follows:

Part-I

Preliminary

1. (1) This Act may be called the Nagara Raj Bill.
(2) It extends to all the municipal corporations, municipalities and Nagar Panchayats in the state of _____ to which 74th amendment to the Constitution applies excluding cantonment areas therein.
(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

2. In this Act, unless the context otherwise requires:
(a) Mohalla means a Mohalla as determined in the manner prescribed in section 3;
(b) Mohalla sabha means, in relation to a Mohalla, the body of all registered voters in that Mohalla;
(c) Budget year. –means the period for which the State government lays down the "annual financial statement".
(d) Chairperson. - The councilor of each ward shall be the chairperson of that ward committee.
(e) Community is a group of people who know each other personally and share emotional relationship, whether positive or negative.
(f) Member - The Mohalla sabha Representative, elected in the manner as provided under this act, shall be a 'member' of the ward committee.
(g) Old Ward Committee – Ward Committee as it exists before the enactment of this Act.
(h) Ward Committee. – Means the committee constituted under Section 18 of this act.
(i) Ward Sabha means, in relation to a Ward, the body of all registered voters in that Ward.

निश्चित तौर पर यही बिंदु शामिल होंगे. ज़ाहिर है, टीम अन्ना के लोक स्वराज आंदोलन का ख़ाका इन्हीं बिंदुओं के इर्द-गिर्द बुना जाएगा:-

1. वे सभी काम, जो गांव में किए जाने हैं और जिनका वास्ता कहीं और से नहीं है, ग्राम स्तर पर ही किए जाएं. ऐसे काम, जो इस स्तर पर नहीं हो सकते और जिनका संबंध अन्य गांवों से भी है, उन्हें ब्लॉक स्तर पर किया जाए. जो काम इस स्तर पर भी नहीं हो सकते, उन्हें ज़िला स्तर पर और जो ज़िला स्तर पर नहीं हो सकते, उन्हें राज्य स्तर पर किया जाए. शासन के प्रत्येक स्तर के लिए ऐसे कार्यों की एक सूची बना ली जाए और उनसे संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और फंड संबंधित स्तर को सौंप दिए जाएं.

2. इसी तरह सड़क, जन शौचालय, स्कूल, अस्पताल एवं दवाखाने इत्यादि जो एक गांव की सीमा के भीतर हों, उनकी देखरेख की ज़िम्मेदारी ग्राम स्तर पर दे दी जाए. ऐसी संपत्ति, जिसका संबंध एक से ज़्यादा गांवों से हो, उसकी ज़िम्मेदारी ब्लॉक को दे दी जाए और अगर ऐसी संपत्ति एक से ज़्यादा ज़िलों से संबंधित हो तो उसकी देखरेख

(शेष पृष्ठ 2 पर)

मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को एक पत्र लिखा है, जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि जो बाबू नौकरी छोड़कर राजनीति में आना चाहते हैं.

दिल्ली का बाबू

कोल इंडिया का चेयरमैन कौन बनेगा

कोल इंडिया के नए चेयरमैन की नियुक्ति का मामला गरमा गया है. पांच आईएएस अधिकारी यानी पर्यावरण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नंदिता चटर्जी, पर्यावरण सचिव आर के काहलोन, लालू यादव के पूर्व ओएसडी, राजस्थान के मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीमत पांडेय और सिंगरेनी कोलियरी के प्रबंध निदेशक इस पद के लिए दौड़ में शामिल हैं. पिछले साल जनवरी से ही कोल इंडिया के निदेशक (टेक्निकल) एन सी झा निदेशक का पद संभाल रहे हैं, लेकिन पिछले महीने से कोयला मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव जोहरा चटर्जी अस्थायी तौर पर निदेशक पद को देख रही हैं. कोल इंडिया के नियमों के मुताबिक़ इस पद के लिए जिस आईएएस अधिकारी का चयन होता है, उसे पदभार ग्रहण करने से पहले अपना वर्तमान पद छोड़ना पड़ता है.

उत्तर प्रदेश के बाबुओं की बेचैनी

क्या उत्तर प्रदेश के बाबू यह समझ चुके हैं कि सूबे में सत्ता परिवर्तन होने वाला है? लखनऊ में बैठे बाबुओं के बीच वोट शेयर, सीटों और दलों के प्रदर्शन पर चर्चा नहीं हो रही है. उनके बीच चर्चा किसी और बात को लेकर है. सूत्रों का कहना है कि सूबे के बड़े-बड़े अधिकारियों मसलन, मुख्य सचिव अनूप मिश्रा, अतिरिक्त कैबिनेट सचिव रवींद्र सिंह एवं मुख्यमंत्री मायावती के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आर पी सिंह ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं और उसके लिए अपना अनुरोध भी भेज दिया है. इसके अलावा इस कतार में तेजी से कई अन्य अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं. हाल फ़िलहाल तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे कुंवर फतेह बहादुर सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव नवनीत सहगल एवं अनिल संत भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के इच्छुक हैं.

बाबू और राजनीति

दिलीप चेरियन

चुनाव आयोग ऐसे बाबुओं की तेजी से बढ़ती संख्या देखकर चिंतित नज़र आ रहा है, जो नौकरी छोड़कर राजनीति में जा रहे हैं. इस कॉलम में पहले ही बताया जा चुका है कि पंजाब में इस बार कई आईएएस एवं आईपीएस अधिकारी नौकरी से इस्तीफ़ा देकर चुनाव लड़ रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक़ , मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को एक पत्र लिखा है, जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि जो बाबू नौकरी छोड़कर राजनीति में आना चाहते हैं, उनके लिए एक कूलिंग ऑफ पीरियड तय किया जाए. कूलिंग ऑफ पीरियड का अर्थ है कि नौकरी छोड़ने के बाद एक खास वक्त यानी कुछ साल (जो सरकार तय करे) तक वे राजनीति में न आ सकें. ऐसी ही व्यवस्था उन अधिकारियों के लिए पहले से है, जो अवकाश के बाद कॉरपोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, लेकिन उस नियम पर कड़ाई से अमल नहीं हो पाता.

dilipcherian@gmail..com

टीम अन्ना का नया आंदोलन

पृष्ठ एक का शेष

सवाल नहीं कर पाती थी. टीम अन्ना यह मानती है कि चूंकि जनता और उसके बीच सीधा संवाद नहीं था, सो जनता उस तक अपने सुझाव भी सीधे नहीं पहुंचा पाती थी. इसीलिए टीम अन्ना अपने नए आंदोलन में ऐसी व्यवस्था चाहती है, जिससे जनता से सीधे दोतरफा संवाद क़ायम हो सके. टीम अन्ना का कहना है कि लंबी लड़ाई के लिए ऐसी व्यवस्था ज़रूरी है और यही वजह है कि देश भर में गांवों एवं शहरों में चर्चा समूहों का गठन करने का निर्णय लिया गया है. इन चर्चा समूहों में देश की ज्वलंत समस्याओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार होगा. मसलन, क्या आज का जनतंत्र भारत को ग़रीबी और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सकता है? विधानसभा चुनाव ख़त्म होने के बाद लोक स्वराज आंदोलन का आगाज़ तो ज़रूर होगा, लेकिन देश की जनता यह ज़रूर चाहेगी कि इसका अंजाम लोकपाल आंदोलन जैसा न हो. टीम अन्ना के लिए भी यह ज़रूरी है कि वह ख़ुद का, टीम के सदस्यों का निरीक्षण करें, ताकि इस बार जनता को न सिर्फ़ एक बड़ा आंदोलन, बल्कि एक बड़ा परिणाम भी देखने को मिल सके.

टीम अन्ना के एक अहम सदस्य अरविंद केजरीवाल 2 साल पहले ही केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नगर राज बिल के मुक़ाबले कई सारे सुझाव तैयार कर चुके थे. इतना ही नहीं, बाकायदा सरकार के नगर राज बिल के मुक़ाबले एक आदर्श नगर राज बिल भी इन लोगों ने तैयार कर लिया है. जैसा कि सरकारी लोकपाल के मसले पर हुआ, इस बार भी टीम अन्ना अपनी तरफ़ से एक आदर्श लोक स्वराज बिल पेश कर सकती है, जो लोक स्वराज आंदोलन का एक बड़ा आधार बन सकता है.

लोक स्वराज आंदोलन का आधार

आम आदमी को अपने विधायकों एवं सांसदों से काफी आशाएं होती हैं. अगर उनके इलाक़े में कुछ ग़लत होता है तो वे अपने विधायक या सांसद के पास जाते हैं, जिनके पास रोजमर्रा की समस्याओं, जैसे बिजली, सड़क एवं पानी इत्यादि का हल निकालने लायक़ प्रशासनिक अधिकार नहीं होते, यदि वे मंत्री नहीं हैं. हां, वे विधानसभा या संसद में उस मुद्दे को उठा सकते हैं, लेकिन वहां भी ऐसी समस्याओं से संबंधित मामले कम ही उठ पाते हैं. विधानसभा या संसद में वे मामले आते हैं, जिनसे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हों. फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सरकार ऐसे मामलों में दखल देगी या समस्याओं का ऐसा हल निकालेगी, जिससे जनता संतुष्ट हो सके. चूंकि ऐसे मामलों की संख्या भी ज़्यादा होती है, बहुत से सांसद या विधायक सवाल भी करना चाहते हैं, लेकिन संसद या विधानसभा के पास इतना वक़्त नहीं होता कि इन सभी मामलों को वहां रखा जा सके. इसलिए ज़रूरी है कि स्थानीय अधिकारियों को ग्रामसभा (ग्रामीण इलाक़ों में) और मोहल्ला सभा (शहरी इलाक़ों में) के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए, लेकिन राजनीतिक दल जनता को अधिकार देने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से विधायकों और सांसदों का महत्व ख़त्म हो जाएगा. पर यह ग़लत है. यदि जनता रोजमर्रा की समस्याओं, मसलन स्ट्रीट लाइट, पानी एवं सीवर इत्यादि का समाधान ख़ुद निकाल ले तो विधायक और सांसद आराम से बड़े मुद्दों पर ध्यान दे सकते हैं. बहुत से लोग यह सोचते हैं कि राजनीति में अच्छे लोगों के आने से अच्छे विधायक एवं सांसद निकल कर सामने आएंगे और सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि इससे उस विधायिका की कार्यप्रणाली नहीं सुधरने वाली, जहां जनप्रतिनिधि अपने पार्टी हाईकमान के आदेशानुसार मतदान करता है और न कार्यपालिका की कार्यप्रणाली सुधरने वाली है. असल बदलाव तभी आएगा, जब बुनियादी स्तर पर ग्रामसभाओं को अधिकार दिए जाएंगे, ताकि लोग अपनी स्थानीय समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकें.

shashishekhar@chauthiduniya.com

इन मसलों पर होगी लड़ाई

पृष्ठ एक का शेष

की ज़िम्मेदारी राज्य के पास रहे.

3. राज्य को जो भी राजस्व प्राप्त होता है, उसका 50 प्रतिशत सीधे पंचायत को दिया जाना चाहिए. इस फंड से सिर्फ़ पंचायत के विकास से जुड़े काम किए जाएं. गांव, ब्लॉक और ज़िला स्तर से संबंधित राज्य की योजनाएं ख़त्म कर देनी चाहिए.

4. ग्राम स्तर पर सभी निर्णय ग्रामसभा ही लेगी, जिसकी बैठक महीने में एक बार होगी. ग्रामसभा के सचिव की नियुक्ति ग्रामसभा ही करेगी. सभी निर्णय लागू करने की ज़िम्मेदारी सचिव की होगी. ग्रामसभा के निर्णय अंतिम माने जाएंगे, यदि उस निर्णय में कोई त्रुटि न हो या उससे किसी क़ानून का उल्लंघन न होता हो. यदि ग्रामसभा के किसी निर्णय को लेकर विवाद होता है तो उसका निपटारा लोकपाल (ओंबड्समैन) द्वारा किया जाएगा.

5. सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण: दो तरह के कर्मचारी होंगे,
-शासन के अलग-अलग स्तरों द्वारा सीधे नियुक्त कर्मचारी
-राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी
लेकिन गांव, ब्लॉक या ज़िले में तैनात कर्मचारी जब सेवानिवृत्त हो जाएं तो उनकी जगह नई नियुक्ति शासन के संबंधित स्तर द्वारा की जानी चाहिए.
ग्रामसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण किया जाएगा:-
ग्रामसभा गांव, ब्लॉक या ज़िला स्तर के किसी भी कर्मचारी को सम्मन जारी कर सकती है. यदि ऐसे कर्मचारियों के काम से ग्रामसभा असंतुष्ट है तो वह सम्मन जारी करके बैठक बुलाकर उससे सफाई मांग सकती है. यदि कर्मचारी का व्यवहार लगातार खराब रहता है तो ग्रामसभा उस पर आर्थिक दंड लगाने का निर्णय ले सकती है.

6. यदि ग्रामसभा के पास किसी अनियमितता की जानकारी पहुंचती है या किसी अन्य कारण से ग्रामसभा चाहे तो एक जांच शुरू कर सकती है. ग्राम सभा चाहे तो स्वयं या अन्य सक्षम अधिकारी को जांच के लिए कह सकती है, जो एक निश्चित समय सीमा के भीतर जांच रिपोर्ट ग्रामसभा को सौंपेगा. ग्रामसभा उस रिपोर्ट को स्वीकार या ख़ारिज कर सकती है या सुझावों को पूर्णत: या आंशिक मान सकती है, उस पर उचित क़दम उठा सकती है.

7. राज्य सरकार ग्रामसभा को अपना कार्यालय चलाने के लिए अलग से पैसा उपलब्ध कराएगी.

8. ग्रामसभा वार्षिक योजना बनाएगी. ग्रामसभा के संतुष्ट हुए बिना किसी परियोजना के लिए भुगतान नहीं हो सकता. पंचायत के कार्यों के लिए भुगतान की जाने वाली मजदूरी भी ग्रामसभा ही तय करेगी, जो राज्य सरकार द्वारा तय की गई मज़दूरी से कम नहीं होनी चाहिए. पंचायत लोगों को कोई छोटा धंधा शुरू करने के लिए क़र्ज़ भी दे सकती है. राशन की दुकान एवं केरोसिन डिपो का लाइसेंस निरस्त करने और नया लाइसेंस जारी करने का अधिकार भी उसी के पास रहेगा. ज़रूरत के हिसाब से ग्रामसभा, ब्लॉक या ज़िले द्वारा अपने-अपने स्तर पर ज़्यादा कर्मचारियों, जैसे शिक्षक इत्यादि की नियुक्ति की जा सकती है. प्रत्येक औद्योगिक या खनन इकाई को ऐसी कोई इकाई स्थापित करने से पहले संबंधित ग्रामसभा की अनुमति लेनी होगी.

9. ग्रामसभा की सहमति के बिना राज्य सरकार किसी भी ज़मीन का अधिग्रहण नहीं कर सकती. भू-अधिग्रहण क़ानून के मामले में ग्रामसभा ही राज्य की भूमिका में होगी. ग्रामसभा ही भू-अधिग्रहण के लिए नियम एवं शर्तों का निर्धारण करेगी. भू-उपयोग में बदलाव भी ग्रामसभा ही तय करेगी.

10. यदि कुल ग्रामसभाओं का 5 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा किसी क़ानून का प्रस्ताव देता है तो राज्य सरकार उसकी एक प्रति सभी ग्रामसभाओं के पास उनकी सहमति के लिए भेजेगी. यदि 50 प्रतिशत से ज़्यादा ग्रामसभाएं उस प्रस्ताव को पारित कर देती हैं तो राज्य सरकार को वह क़ानून पास करना पड़ेगा. इसी तरह ग्रामसभा के पास किसी क़ानून को पूर्णत: या आंशिक तौर पर निष्प्रभावी करने का अधिकार होगा.

11. ज़िला स्तर पर ओंबड्समैन संस्था: प्रत्येक ज़िले में एक ओंबड्समैन होगा, जो पंचायती राज क़ानून से संबंधित विवादों एवं समस्याओं का निपटारा करेगा, साथ ही पंचायती राज क़ानून के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराएगा. उसके पास पर्याप्त अधिकार होंगे, ताकि वह अपने आदेशों को लागू करा सके, साथ ही कर्मचारियों के ख़िलाफ़ सम्मन जारी कर सके.

साउथ ब्लॉक

शर्मा का प्रमोशन

जोगिंदर पाल शर्मा उत्तर प्रदेश कैडर और 1981 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. फ़िलहाल वह नॉर्थ-ईस्ट रीजन विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात थे. उन्हें पदोन्नति देकर इसी मंत्रालय का अतिरिक्त सचिव बनाया गया है.

संजय बनेंगे जेएस

महाराष्ट्र कैडर एवं 1984 बैच के आईएएस अधिकारी संजय कुमार जल्द ही भारत सरकार में संयुक्त सचिव बनाए जाएंगे.

रवि निदेशक बने

1984 बैच के आईडीएसई अधिकारी रवि सिन्हा को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है. वह ए के मिश्रा का स्थान लेंगे.

नीलेश होंगे राजस्व निदेशक

1997 बैच के आईआरएस (सी एंड सीई) अधिकारी नीलेश कुमार गुप्ता को राजस्व विभाग का निदेशक बनाया गया है. वह ए के पाठक का स्थान लेंगे.

श्रीनिवासन नए एएस

सुदर्शनम श्रीनिवासन 1980 बैच और उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 50
दिल्ली, 20 फरवरी–26 फरवरी 2012
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना–800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226001
फोन : 0522–2204678, 9415005111

प्रबंध संपादक
श्रीनिवास गुप्ता (ठाकुर) (उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)
सी–20, ट्रांस यमुना, एनएच–2, आगरा
फोन : 0526–4064901, 9837082462

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन
मुरलीधर कॉम्प्लेक्स, बुटीवाडा के सामने होटल गणराज के बाजू में टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर–440012
फोन नं : 0712–2544988, 2549846

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/011–23418962
0120–6450888, 0120–6452888
0120–6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120–4783999
+91 9266627366
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

लालू यादव के पास 22 विधायक हैं और लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान के पास एक विधायक है. इस तरह इनके पास कुल संख्या 125 हो रही है, जो सरकार बनाने के लिए पर्याप्त है.

बिहार में नई सियासी नौटंकी

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

रूबी अरुण

सियासत में शह–मात का खेल कैसे होता है, पल भर में सियासी समीकरण कैसे बदल जाते हैं. अगर आप यह जानना चाहते हैं तो बिहार की सियासी फ़िज़ा में फैले शगूफ़ों पर ग़ौर फ़रमाने की ज़रूरत है, जहां यारों के बीच ही यानी जद–यू और भाजपा के दरम्यान चेक–मेट का खेल अपने शबाब पर है. कुछ इस तरह से गोटियां बिछाई जा रही हैं कि लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद सियासी जंग की सरज़मीन अब बिहार ही बनने वाला है. यूं तो सरकार में जद–यू और भाजपा साथ–साथ हैं, पर यह बात भी किसी से छुपी नहीं है कि उनके दिल में दरारें हैं, एक–दूसरे की ज़हनी मुख़ालफ़त है. लिहाज़ा जद–यू का एक अदना सा नेता लालकृष्ण आडवाणी और शाहनवाज़ हुसैन जैसे क़द्दावर नेताओं को बिहार में सबक़ सिखाने की बात कर रहा है. सवाल इसलिए प्रासंगिक है, क्योंकि जिस बिहार में, जहां की सरकार में, नीतीश कुमार की मर्ज़ी के बिना आप जम्हाई तक नहीं ले सकते, वहां मुंह खोलना और बयानबाज़ियां कर देना तो गुनाह है. फिर पिछली कतार में खड़े पिछलग्गू नेताओं में शुमार जद–यू एमएलसी नीरज कुमार की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वह आडवाणी और शाहनवाज़ जैसे नेताओं को ज़ुबानी ललकार दें. इसलिए सवाल बनता है. शक शुबहा की गुंजाइश बनती है. इस संशय के पीछे पुख्ता वजह भी है. वह है बिहार के अख़बारों में हाशिए पर सिमटे हुए इस नेता के बयान का प्रमुखता से छपना. सभी जानते हैं कि बिहार से छपने वाले अख़बारों के संपादक हों या संवाददाता, उन्हें इतनी भी आज़ादी मयस्सर नहीं कि वे सरकार के ख़िलाफ़ सांस भी ले सकें, किसी के दु:ख–तकलीफ़ या ख़ुशी से सरोकार रखती ख़बरें बिना नीतीश कुमार की इच्छा के छाप सकें.

ज़र–ख़रीद ग़ुलामों की तरह बिहार के पत्रकारों की क़लम पर, उनकी अभिव्यक्ति पर, नीतीश कुमार की तालिबानी नज़र रहती है. आपने एक हर्फ़ भी उनके ख़िलाफ़ लिखा नहीं कि आपकी रोज़ी–रोटी गई. तो फिर अख़बार वालों ने यह ख़बर छापने की हिम्मत कैसे कर दिखाई. कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही तो नहीं चाहते कि इस तरह की बातें हवा में उड़ती रहें और जिस भाजपा ने उत्तर प्रदेश चुनाव में उनसे अलग होकर चुनाव लड़ा और नरेंद्र मोदी को उनके मना करने के बावजूद एक हीरो की तरह पेश करके मुख़ालफ़त के तेवर दिखाने में कोताही नहीं की, वह कम से कम बिहार में उनके दबाव में आकर साथ बनी रहे, ताकि उनकी राजनीति की दुकान यूं ही चलती रहे. लेकिन नीतीश कुमार इस बात से भी ख़ूब वाक़िफ़ होंगे कि इस तरह फ़ाख्ता उड़ाने का अंजाम क्या होता है. ज़ाहिर है, नीतीश की चाल ने उनके ही ख़िलाफ़ माहौल तैयार करना शुरू कर दिया है. चौथी दुनिया बिहार की जो राजनीतिक तस्वीर आपके सामने रखने जा रहा है, वह शक्ल अख्तियार कर ही ले, यह ज़रूरी नहीं, पर इससे बिहार के राजनीतिक और सामाजिक हालात पर फ़र्क़ ज़रूर पड़ेगा. हमारे पास बिहार की सियासत में ख़ासा दख़ल रखने वाले जद–यू और भाजपा नेताओं की ही मार्फ़त जो ख़बरें आ रहीं हैं, उनसे यह बात साफ़ तौर पर उभर कर सामने आ रही है कि भाजपा के शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, शाहनवाज़ हुसैन और सुशील मोदी लगातार राजद प्रमुख लालू यादव के संपर्क में हैं. उनसे विचार–विमर्श और मान–मनुहार का दौर भी चल रहा है, जिसे नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ मानकर देखा जा रहा है. लालू यादव की बेटी रागिनी की शादी में महरौली फार्म हाउस में भाजपा के ऊपर से लेकर नीचे तक के नेताओं का सपरिवार जमावड़ा भी कुछ अलग इशारे कर रहा है.

दरअसल राजनीतिक विश्लेषक भी तभी से इस बात का क़यास लगाने में लगे हैं कि बिहार की राजनीति में कोई नया गुल खिल सकता है. क्या बिहार में जदयू–भाजपा की सरकार का तालमेल बिगड़ सकता है? क्या नीतीश कुमार की कुर्सी ख़तरे में है? क्या अगले विधानसभा चुनाव से पहले ही राजद प्रमुख लालू यादव की बिहार की सत्ता में भागीदारी हो सकती है? तमाम सवाल मंडरा रहे हैं और उन सवालों की बिना पर एक नया–अलहदा क़िस्म का समीकरण भी पेश किया जा रहा है. दलीलों और तर्कों से परे इस समीकरण में कुर्सी पर क़ाबिज़ होने की लालसा ही सबसे प्रबल है. इन अंदाज़ों का दौर शुरू हुआ, राजद प्रमुख लालू यादव की बेटी की दिल्ली में शादी होने के बाद ही. यह बात मामूली नहीं है कि लालू यादव की बेटी रागिनी की शादी में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने शिरकत करना मुनासिब नहीं समझा, जबकि ये सभी उस दिन दिल्ली में मौजूद थे. कहते हैं कि लालू यादव उनके इस आचरण से बेहद आहत हैं. कांग्रेस ने राष्ट्रीय राजनीति में पहले से ही लालू से किनारा कर रखा है. पिछले दिनों लालू की हरचंद कोशिश रही कि वह कांग्रेस हाईकमान का भरोसा एक बार फिर से हासिल कर केंद्र में एक मज़बूत जगह बना सकें. संभावनाएं दिखने भी लगी थीं. ख़ासकर लोकसभा में जन लोकपाल बिल पेश करने के मसले पर बहस होते समय लालू यादव की कांग्रेस के पक्ष में वाचालता के बाद, लेकिन फिर उत्तर प्रदेश चुनाव ने सारे समीकरण बिगाड़ दिए. मुलायम सिंह का कांग्रेस से समझौता और ख़ुद को देश के उप प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करना लालू यादव को अखर गया. उधर अपनी हर लड़ाई हार चुके लालकृष्ण आडवाणी को भी यह डर शिद्दत से सताने लगा कि उनकी प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश महज़ एक ख्वाब न बनकर रह जाए. नीतीश–आडवाणी और लालू के इर्द–गिर्द रहने वाले लोग जो इस नई दंत कथा के सूत्रधार हैं, उनके अंदाज़ों की ज़रा उड़ान देखिए और आप भी जोड़–तोड़ के इस सियासी गणित को समझने की कोशिश कीजिए.

इन सूत्रधारों के मुताबिक़, भाजपा की कार्यकारिणी बैठक एवं स्वाभिमान रैली के दौरान एक विज्ञापन को लेकर नीतीश–नरेंद्र मोदी विवाद वाला जो दृश्य बना, अब वह अपने क्लाईमेक्स की ओर बढ़ रहा है, जिसके नतीजे में नीतीश को अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ सकती है. इस सियासी नौटंकी के अखाड़े में कब कौन सा अप्रत्याशित दृश्य जनता के सामने उपस्थित हो जाए, कब कौन सा सियासी किरदार कौन सा रूप धारण कर ले और क्या संवाद दोहराने लगे, कहना मुश्किल है. एक नज़र डालिए इनकी परिकल्पनाओं पर, जिनके बारे में इन सूत्रधारों का यह दावा है कि आडवाणी जी की लालू यादव जी से डील पक्की हो चुकी है, बस मौक़े का इंतज़ार है और नीतीश की बादशाहत ख़त्म. हम फिर कह रहे हैं कि यह पूरी कहानी नीतीश कुमार, आडवाणी और लालू यादव के बेहद क़रीबियों की ज़ुबानी है, बस आपको सुनाने–बताने का ज़रिया हम बन गए हैं. तो मुलाहिज़ा फ़रमाएं आप भी. इन नेताओं के मुताबिक़, आडवाणी जी ने लालू यादव से यह कहा है कि आप बिहार में हमारा साथ दीजिए, ताकि वहां जद–यू और राजद मिलकर सरकार बना सकें और केंद्र पर भी हम दोनों धावा बोल सकें. लालू जी आप उप प्रधानमंत्री बन जाएं और प्रधानमंत्री की कुर्सी भाजपा के ज़िम्मे सौंप दें, ताकि हम अपनी चिर अभिलाषा पूरी कर सकें और प्रधानमंत्री बन सकें. बिहार में सुशील कुमार मोदी मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल लें और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी राजद के खाते में चली जाए. राजद के 11 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए और बाक़ी कुर्सियों पर भाजपा का क़ब्ज़ा रहे.

अगर वाक़ई ऐसी बात है, जो कही जा रही है, तो जो आंकड़े हैं, उनके पास विधायकों के और बहुमत के लिए जितने नंबर चाहिए, वे भाजपा और राजद के पास मौजूद हैं. बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं. सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों की ज़रूरत है. भाजपा और उसके साथ मर्ज़ कर गए विधायकों की कुल संख्या 102 है. लालू यादव के पास 22 विधायक हैं और लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान के पास एक विधायक है. इस तरह इनके पास कुल संख्या 125 हो रही है, जो सरकार बनाने के लिए पर्याप्त है. जबकि जद–यू के पास महज़ 114 विधायक ही बचेंगे, जो बहुमत से बहुत कम हैं. लिहाज़ा उसके लिए मुश्किलें हो सकती हैं. मतलब यह कि फ़िलहाल हवाई ही सही, भाजपा और राजद गठबंधन की सरकार बनती नज़र आ रही है. दूसरा शगूफ़ा यह भी है कि कांग्रेस से मुलायम की डील के बाद उनका नाम उप प्रधानमंत्री के तौर पर उछलने से लालू यादव विचलित से हो गए हैं. उन्हें लगता है कि जब वह देश के सबसे बड़े और स्थापित यादव नेता हैं तो मुलायम इसका फ़ायदा उठाकर उनकी हक़मारी कैसे कर सकते हैं. प्रधानमंत्री न सही, पर उप प्रधानमंत्री के पद पर तो उन्हीं का दावा बनता है. मिली सूचना के मुताबिक़, आडवाणी ने उनसे यह चर्चा भी की है कि कांग्रेस से नाराज़ ममता दीदी को भी अपने साथ मिला लेंगे, जिससे हमारी राह आसान हो जाएगी. लेकिन इन आसमानी कल्पनाओं को अमलीजामा पहनाने में जुटे सूत्रधारों के सामने कई ज़मीनी अड़चनें आ सकती हैं. मसलन, क्या लगातार नीचे जा रहे ग्राफ के बाद भी भाजपा इतना बड़ा जोखिम लेने की हालत में है. उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या लालू यादव भाजपा से हाथ मिलाकर अपने माई समीकरण को मटियामेट कर सकते हैं, वह अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि से समझौता कर सकते हैं? नहीं कर सकते. फिर ऐसे में क्या यह डील ज़मीनी शक्ल अख्तियार कर सकती है?

हालांकि यह बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार की तानाशाही से न सिर्फ़ भाजपा, बल्कि जद–यू के मंत्री एवं नेता भी बेहद आहत और नाराज़ हैं. ज़्यादातर नेता मजबूरी में उनके साथ है, न कि उनकी फ़रमाबरदारी में. अब तो बिहार की जनता भी उनके दोहरे चरित्र से वाक़िफ़ हो चुकी है. एक तरफ़ लुधियाना की सभा में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के हाथ में हाथ डालकर लंबी–चौड़ी मुस्कुराहट के साथ फोटो खिंचवाते हैं तो दूसरी तरफ़ बिहार में नरेंद्र मोदी का नाम लेने से भी ऐसे बिदकते हैं, जैसे किसी भूत का नाम ले लिया हो. जिस पार्टी के गठबंधन से उनकी सरकार लगातार दूसरी बार चल रही है, क्या नीतीश कुमार नहीं जानते कि नरेंद्र मोदी उसी पार्टी के बेहद मज़बूत और राष्ट्रीय नेता हैं. लेकिन जब उत्तर प्रदेश में चुनाव की बारी आती है तो नीतीश नरेंद्र मोदी के नाम पर वहां भाजपा से कन्नी काट जाते हैं. मुसलमान मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए नीतीश रोज़ नए ड्रामे रच रहे हैं. क्या नीतीश को पहले यह नहीं पता था कि नरेंद्र मोदी की छवि सांप्रदायिक नेता की है? नीतीश की ये हरकतें जितनी हास्यास्पद हैं, उतनी ही उनकी समझ पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करने वाली भी. दरअसल, अभी नीतीश के सामने बिहार विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का मसला है. ज़ाहिर है, नीतीश के सामने उलझने हैं, पर क्या अपने ही ख़िलाफ़ छुटभैये नेताओं से अफ़वाहों को हवा दिलाकर नीतीश आने वाली मुश्किलें हल कर लेंगे या उनका यह दांव उनके लिए मुसीबतों का सबब बन जाएगा? आइए, इंतज़ार करते हैं.

ज़र-ख़रीद ग़ुलामों की तरह बिहार के पत्रकारों की क़लम पर, उनकी अभिव्यक्ति पर, नीतीश कुमार की तालिबानी नज़र रहती है. आपने एक हर्फ़ भी उनके ख़िलाफ़ लिखा नहीं कि आपकी रोज़ी-रोटी गई. तो फिर अख़बार वालों ने यह ख़बर छापने की हिम्मत कैसे कर दिखाई. कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही तो नहीं चाहते कि इस तरह की बातें हवा में उड़ती रहें और जिस भाजपा ने उत्तर प्रदेश चुनाव में उनसे अलग होकर चुनाव लड़ा और नरेंद्र मोदी को उनके मना करने के बावजूद एक हीरो की तरह पेश करके मुख़ालफ़त के तेवर दिखाने में कोताही नहीं की, वह कम से कम बिहार में उनके दबाव में आकर साथ बनी रहे, ताकि उनकी राजनीति की दुकान यूं ही चलती रहे.

ruby@chauthiduniya.com

आम मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बदनाम कांग्रेस पार्टी किसी मुसलमान को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दे, यह बात एक अनहोनी सी लगती है.

उत्तर प्रदेश

क्या रशीद मसूद मुख्यमंत्री बन सकते हैं

उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं रशीद मसूद, जो पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वह समाजवादी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए. उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का वोट हासिल करने के अब तक तमाम प्रयासों में नाकाम रहने के बाद, अब कांग्रेस पार्टी की ओर से यह बात निकलकर सामने आने लगी है कि सरकार बनने पर रशीद मसूद को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है. क्या ऐसा संभव है?

डॉ. क़मर तबरेज़

रशीद मसूद का नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी परिचय का मोहताज नहीं है. सहारनपुर से पांच बार लोकसभा और दो बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके रशीद मसूद समाजवादी पार्टी के अंदर रहकर इतने परेशान हो गए थे कि आख़िरकार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया. आज़म ख़ान से नाराज़गी और मुलायम सिंह की वादाख़िलाफ़ी से मजबूर होकर उन्होंने यह निर्णय लिया था. आज़म ख़ान पर उनका आरोप था कि वह मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की शह पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का अपमान करने पर आमादा हैं. उनका आज़म ख़ान पर यह भी आरोप था कि जब वह पार्टी के बाहर रहकर समाजवादी पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो अब पार्टी के अंदर आकर समाजवादी पार्टी की बुनियाद को खोखला करने में लगे हुए हैं. हालांकि अखिलेश की ज़िद के सामने अब ख़ुद आज़म ख़ान भी समाजवादी पार्टी के अंदर ख़ुद को बेबस महसूस कर रहे हैं. पिछले दिनों समाजवादी पार्टी की बड़ी चुनावी रैलियों से उनका ग़ायब रहना, पार्टी का घोषणा पत्र जारी होते समय मंच पर न होना और रामपुर के अंदर आज़म ख़ान को सीमित कर दिया जाना, इस बात का सबूत है कि ख़ुद आज़म ख़ान की भी समाजवादी पार्टी में अब कोई ज़्यादा हैसियत नहीं है.

दूसरी ओर ख़ुद सपा प्रमुख मुलायम सिंह से रशीद मसूद की यह शिकायत थी कि वह उनकी बात नहीं मानते. 1997 में रशीद मसूद ने मुलायम सिंह से मुसलमानों और अति पिछड़े हिंदुओं को आरक्षण कोटे में आबादी के हिसाब से जब आरक्षण देने की बात कही थी तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था. हालांकि आज यही मुलायम सिंह मुसलमानों को अलग से 18 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, लेकिन 2003 से 2006 के बीच जब वह राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने रशीद मसूद के सुझाव को मानने से इंकार कर दिया था. इस बार के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी रशीद मसूद ने मुलायम सिंह से टिकटों के वितरण में मुसलमानों के साथ होने वाली ज़्यादती को दूर करने की बात कही तो पार्टी के मुखिया पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि ज़्यादातर मामलों में उन्होंने आज़म ख़ान के सुझाव को ही प्राथमिकता दी. आख़िरकार पार्टी के अंदर लगातार उपेक्षित किए जाने के कारण रशीद मसूद ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस में शरण ले ली. यही नहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी की ओर से अपनी राज्यसभा की सीट से भी इस्तीफ़ा दे दिया. अब कांग्रेस पार्टी के अंदर से यह ख़बर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो रशीद मसूद को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है. लेकिन क्या ऐसा होना संभव है? शायद नहीं, क्योंकि पहले तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब तक के रुझान से कांग्रेस की सरकार बनने के आसार दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं, दूसरा यह कि ख़ुद कांग्रेस के अंदर बहुत से ऐसे नेता हैं, जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं.

आम मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बदनाम कांग्रेस पार्टी किसी मुसलमान को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दे, यह बात एक अनहोनी सी लगती है. लेकिन अगर इस घोषणा के कारण उसकी सरकार बनती दिखाई दे रही हो तो वह ऐसा कर भी सकती है, क्योंकि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनाए जाने से पहले कोई यह अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि कांग्रेस पार्टी किसी सिख को इस देश का प्रधानमंत्री बना सकती है. यद्यपि, रशीद मसूद का मामला थोड़ा पेचीदा है. उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के अभिलाषी कांग्रेस के अंदर बहुत से नेता हैं. उदाहरण के तौर पर अगर पीएल पुनिया के साथ कांग्रेस का मिशन 85 वाला फार्मूला कामयाब होता है और कांग्रेस को दलितों का ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिलता है, तो ज़ाहिर है पीएल पुनिया मुख्यमंत्री के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं. इसी तरह बेनी प्रसाद वर्मा के क़रीबी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेकर आते हैं तो उनकी दावेदारी मज़बूत हो सकती है. अगर इसी तरह मुस्लिम उम्मीदवारों को जीत दिलाने में कांग्रेस को कोई कामयाबी मिलती है तो रशीद मसूद का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आ सकता है. इसलिए यह कहना अभी जल्दबाज़ी होगी कि रशीद मसूद को उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है. लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजकल कांग्रेस के उम्मीदवार मुसलमानों के बीच जाकर यही बोल रहे हैं कि रशीद मसूद उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे.

कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों का वोट हासिल करने का प्रयास तो कर ही रही है, लेकिन उसने मुसलमानों की समस्याओं का समाधान करने में कभी गंभीरता नहीं दिखाई. ख़ुद कांग्रेस पार्टी के अंदर जो मुस्लिम नेता हैं, वे चाहते हैं कि सरकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मुसलमानों को पहुंचे, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करने में हमेशा आड़े आ जाती है. उदाहरण के तौर पर बटला हाउस एनकाउंटर के मामले को ही लें. कांग्रेस के अंदर बैठे ग़ुलाम नबी आज़ाद, सलमान ख़ुर्शीद, अहमद पटेल, सैफ़ुद्दीन सोज़, राशिद अल्वी जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी मुस्लिम नेताओं ने इस घटना पर बेचैनी व्यक्त की और आलाकमान को मनाने की कोशिश की कि बटला हाउस एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, ताकि कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में फैली ग़लतफ़हमियों और संदेह को दूर किया जा सके. कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह भी मुस्लिम नेताओं का समर्थन अलग-अलग मंचों से करते रहे हैं, लेकिन गृहमंत्री पी चिदंबरम समेत पार्टी आलाकमान ने इस विवादित एनकाउंटर की जांच कराने से पूरी तरह से इंकार कर दिया. इसी तरह इस देश के मुसलमानों ने जहां कहीं भी अपना अलग नेतृत्व बनाने का प्रयास किया, कांग्रेस ने कुछ मुसलमानों को तोड़कर अपने गुट में शामिल कर लिया और मुस्लिम नेताओं को मज़बूत होने का कभी मौक़ा नहीं दिया. उदाहरण के तौर पर 1970 के दशक में असम में जब ग़ुलाम उस्मानी ने यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट का गठन किया तो कांग्रेस ने उन्हें बहला-फुसला कर असम का मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखाया और उनकी पार्टी का कांग्रेस में ही विलय कर लिया. बाद में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाने का अपना वादा कभी पूरा नहीं किया, बल्कि ग़ुलाम उस्मानी साहब को असम के मंत्रिमंडल में एक मामूली मंत्री का पद दिया. अब असम में ही मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) अपने क़दम पूरी तरह जमा चुकी है, जिसके कारण वह कांग्रेस की आंखों में खटकने भी लगी है. पिछले साल असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में 18 सीटें जीतकर आई एआईयूडीएफ ने विधानसभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी है. अब कांग्रेस बदरुद्दीन अजमल को तोड़कर अपने गुट में मिलाने के जी तोड़ प्रयास में लगी हुई है. यह प्रयास थोड़ा बहुत कामयाब होता नज़र आ रहा है, क्योंकि बदरुद्दीन अजमल उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह के राष्ट्रीय लोकदल के लिए प्रचार कर रहे हैं. जगज़ाहिर है कि रालोद इस समय केंद्र की यूपीए सरकार में शामिल हो चुकी है और उसके प्रमुख अजीत सिंह नागरिक उड्डयन मंत्री का पद संभाले हुए हैं. लिहाज़ा, इस तरह देखा जाए तो बदरुद्दीन अजमल के ज़रिये रालोद का समर्थन करना, एक तरह से कांग्रेस का ही समर्थन करना है.

जमीयत उलेमा, ऑल इंडिया मजलिस मशावरत, ऑल इंडिया मजलिसे-इत्तेहाद उल मुसलेमीन, पसमांदा मुहाज़ और इस जैसे तमाम मुस्लिम संगठनों से कांग्रेस की नज़दीकियां इसी बात का इशारा देती हैं कि कांग्रेस को अलग से मुसलमानों की कोई राजनीतिक पार्टी स्वीकार नहीं, बल्कि उसकी हमेशा यही कोशिश रही है कि मुसलमान मजबूर होकर सिर्फ़ और सिर्फ़ कांग्रेस को वोट दें. भाजपा और आरएसएस से मुसलमानों को डराना और कांग्रेस की इसी मानसिकता का परिचायक है. कांग्रेस अगर मुसलमानों के प्रति गंभीर होती तो सत्ता में होने के बावजूद इस देश के मुसलमानों पर होने वाली ज़्यादतियों की ख़बर ज़रूर लेती. राहुल गांधी का हाल में उर्दू संपादकों की एक बैठक में केवल यह मान लेना ही काफ़ी नहीं है कि सरकारी मशीनरी में मौजूद अधिकारी और पुलिस दस्ते मुसलमानों के प्रति सांप्रदायिक दृष्टिकोण अपनाते हैं. अगर सरकार कांग्रेस की है तो भला ऐसे लोगों को सामने लाकर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई में क्या परेशानी है. निर्दोषों और मासूमों को क्यों परेशान किया जा रहा है? ज़ाहिर है, वादे करने भर से ही जनता का विश्वास प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसके लिए काम करके दिखाना पड़ता है, तब कहीं जाकर लोगों का विश्वास प्राप्त होता है. इस देश का मुसलमान सबसे ज़्यादा कांग्रेस की सत्ता के दौरान ही परेशान किया गया. सरकार के पास तमाम रिपोर्टें मौजूद हैं, लेकिन सब आलमारियों की शोभा बनी हुई हैं.

एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के सामने आने से कुछ चीज़ें सामने आईं तो इस पर भी कांग्रेस को इसकी तमाम सिफ़ारिशें लागू करने में परेशानी हो रही है. जब समय होता है तो कांग्रेस काम नहीं करती और जब चुनाव का समय आता है तो नए-नए वादे करने लगती है. वादे पूरे नहीं होंगे तो भला इस देश का मुसलमान कांग्रेस पर विश्वास कैसे करेगा. मुसलमान तो इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कांग्रेस उनकी समस्याओं का समाधान करके उनके वोट हासिल करे, लेकिन कांग्रेस काम करना ही नहीं चाहती, फिर भला किस मुंह से उनके वोट मांगती है.

Tabrez@chauthiduniya.com

रशीद मसूद का मामला थोड़ा पेचीदा है. उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के अभिलाषी कांग्रेस के अंदर बहुत से नेता हैं. उदाहरण के तौर पर अगर पीएल पुनिया के साथ कांग्रेस का मिशन 85 वाला फ़ार्मूला कामयाब होता है और कांग्रेस को दलितों का ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिलता है, तो ज़ाहिर है पीएल पुनिया मुख्यमंत्री के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं. इसी तरह बेनी प्रसाद वर्मा के क़रीबी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेकर आते हैं तो उनकी दावेदारी मज़बूत हो सकती है.

ग्राम्य विकास मंत्री दद्दू प्रसाद एवं सपा सांसद आर के पटेल ने दस्यु राधे के पुत्र सोनू द्वारा कराए गए भंडारे में शिकरत की थी. यही नेता चुनाव के समय ददुआ गिरोह से वारदातें कराते थे.

पोंटी चड्ढा के ख़िलाफ़ छापेमारी का नाटक

एक तीर से कई निशाने

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड ही नहीं, देश भर में लोग उत्सुकता से इस बात का इंतज़ार करने लगे कि क्या पोंटी का तिलिस्म टूटेगा? यह वे लोग थे, जिनके लिए वाइन किंग का साम्राज्य एक अबूझ पहेली जैसा था. भले ही इसकी चर्चा वाइन किंग के रूप में होती थी, लेकिन रंगीन पानी का यह सौदागर यहीं तक सीमित नहीं था, इसने कई धंधों में अपने पांव पसार रखे थे. रीयल स्टेट, चीनी मिल, ब्रासवेयर एवं फिल्म निर्माण आदि कई व्यवसायों में इसके हज़ारों करोड़ रुपये लगे हैं. मायावती के मुख्यमंत्री बनते ही लोगों को लगा कि मुलायम सिंह के क़रीबी पोंटी के दिन ख़त्म हो जाएंगे. बसपा शासनकाल में अलग-अलग बैकग्राउंड से आए उक्त लोगों ने ख़ूब दौलत-शोहरत कमाई. अगर मायावती ने मुलायम सिंह के किसी एक वफ़ादार को नहीं छेड़ा तो वह वाइन किंग पोंटी चड्ढा ही था, जिसका सिक्का दोनों ही राज में ख़ूब चला.

जहां तक बात पोंटी के लिए मायावती सरकार द्वारा नीतिगत फ़ैसले बदलने की है तो उसकी बानगी बसपा शासनकाल की शुरुआत में ही दिख गई थी. बसपा सरकार का गठन होते ही उत्तर प्रदेश चीनी निगम के माध्यम से पोंटी चड्ढा की ब्लू वाटर लिमिटेड को शराब व्यवसाय का लाइसेंस प्रदान किया गया. इस पर जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो सरकार ने जवाब दाख़िल कर दिया कि आबकारी विभाग ने अपनी नीति बदल दी है. इसके बाद एक और बदलाव करते हुए सरकार ने मेरठ जोन के 23 ज़िलों में शराब कारोबार का लाइसेंस उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ को दे दिया, जिसने पोंटी चड्ढा की ही दूसरी कंपनी लोर एंड फेना लिमिटेड के हाथों में शराब कारोबार की डोर थमा दी. ऐसे कई फ़ैसले लिए गए, जिनसे पोंटी और उसकी कंपनियां सीधे तौर पर फ़ायदे में रहीं. आबकारी मंत्री नसीमुद्दीन अपनी सरकार की सुप्रीम पॉवर और पोंटी के बीच डील मैनेज करने का काम करते थे. बसपा के लिए पोंटी चड्ढा एटीएम जैसा हो गया था. पोंटी ने धंधे की ख़ातिर दिल्ली और लखनऊ में बैठे कुछ कांग्रेसी नेताओं से अपनी निकटता बना रखी थी. इसके अलावा एक ही ज़िले मुरादाबाद के निवासी होने के कारण पोंटी की गांधी परिवार के एक पारिवारिक सदस्य से भी काफ़ी नजदीकियां हो गई थीं. पोंटी को पता था कि ज़रूरत पड़ने पर कांग्रेस का यह सबसे ताक़तवर मोहरा उसके काम आ सकता है.

कांग्रेस को पता था कि पोंटी और बसपा सरकार के रिश्तों को लेकर प्रदेश की जनता के बीच मायावती की छवि बेहद ख़राब है. इसी बात को भुनाने के लिए कांग्रेस ने एक तुरुप का पता चला. आयकर विभाग ने पोंटी के ख़िलाफ़ सबूत पहले से ही जुटा रखे थे. ऊपर से इशारा पाते ही पोंटी के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी शुरू हो गई. लखनऊ, दिल्ली, नोएडा, मुरादाबाद एवं बरेली आदि ज़िलों में एक साथ पोंटी के 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई. उस समय पोंटी दुबई में था. छापे में अरबों रुपये का काला धन सामने आने की बात कही जाने लगी. पोंटी के यहां आयकर विभाग के छापे की ख़बर जैसे ही उसके हमदर्दों को लगी, उन्होंने गुपचुप तरीक़े से छापे की हवा निकालने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया. उन्हें पता था कि छापेमारी के पीछे कांग्रेस का ही हाथ है. डैमेज कंट्रोल के लिए निकले पोंटी के लोगों ने गांधी परिवार के उस सदस्य से सबसे पहले संपर्क साधा, जो मुरादाबाद में रहता तो था ही, पोंटी से उसके पुराने संबंध भी थे. बात शुरू हुई तो बनने में देर नहीं लगी. धनकुबेर पोंटी चड्ढा के लोगों ने कुछ ही घंटों में सब कुछ मैनेज कर लिया. आयकर विभाग के जो अधिकारी छापेमारी के समय आत्मविश्वास से लबरेज़ थे, उनके चेहरों पर ऊपर से आए एक आदेश ने कुठाराघात कर दिया. विभागीय अधिकारी हाथ मलते रह गए. जिस तिजोरी में अरबों रुपये होने की बात कही जा रही थी, उसमें एक पैसा भी नहीं मिला. सब कुछ मैनेज कर लेने के बाद पोंटी के आदमी सीना चौड़ा करके बात करने लगे. उनकी तरफ़ से आयकर विभाग को कठघरे में खड़ा करने वाला बयान आया, हमारी कंपनी कोई ग़लत या नंबर दो का काम नहीं कर रही है. जितना भी कारोबार किया जा रहा है, उसका लेखा-जोखा कंपनी के पास है और आयकर का भुगतान भी समय से किया जा रहा है.

आयकर विभाग को मुंह की खानी पड़ी और पोंटी का बाल बांका नहीं हुआ. बहरहाल, छापे के बाद पोंटी को फ़ायदा यह हुआ कि अब उसके पास न कोई चंदा लेने आ रहा है और न कोई यह पूछ रहा है कि क्या उसकी आस्था बदल गई है. कांग्रेस ने एक ही झटके में पहले पोंटी को झटका और फिर उसे सहारा देकर उबार लिया. लोग इसे कांग्रेसी राजनीति और रणनीति बता रहे हैं.

आयकर विभाग को मुंह की खानी पड़ी और पोंटी का बाल बांका नहीं हुआ. बहरहाल, छापे के बाद पोंटी को फ़ायदा यह हुआ कि अब उसके पास न कोई चंदा लेने आ रहा है और न कोई यह पूछ रहा है कि क्या उसकी आस्था बदल गई है. कांग्रेस ने एक ही झटके में पहले पोंटी को झटका और फिर उसे सहारा देकर उबार लिया. लोग इसे कांग्रेसी राजनीति और रणनीति बता रहे हैं. कहने वाले यह भी कह रहे हैं कि वाइन किंग ने स्वयं अपने ख़िलाफ़ छापेमारी का जाल बिछवाया था. इसके बदले उसने मोटी रक़म भी ख़र्च की थी, लेकिन यह उस रक़म से काफ़ी कम थी, जिसकी बसपा आलाकमान ने पोंटी से उम्मीद लगा रखी थी. आयकर विभाग की छापेमारी कराकर पोंटी ने एक साथ कई निशाने साधे. एक तो अब कोई यह नहीं कह पाएगा कि पोंटी के पास काले धन की खान है, दूसरा पोंटी के क़रीबी यह कहते हुए बसपा को उसका हक़ देने से बच जाएंगे कि उन्होंने कुछ कमाया ही नहीं तो देंगे कैसे. पोंटी जिस तरह बसपा से दूरी बना रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि अगला शासन मायावती का नहीं होगा. वह मायावती से दूरी बनाकर और कांग्रेस एवं समाजवादी पार्टी के क़रीब आकर अपने भविष्य पर लगे ग्रहण को भी

feedback@chauthiduniya.com

बुन्देलखण्ड

फ़रमानों से निजात

दस्युओं के परिवारीजन विधानसभा चुनाव में हिस्सा तो ले रहे हैं, लेकिन उनकी गतिविधियां सिर्फ़ अपने तक सीमित रह गई हैं. जिन बाहुबलियों को अपने आक़ा पर नाज़ हुआ करता था, वे भी जनता के बीच से नदारद दिख रहे हैं, क्योंकि दस्यु सम्राटों का ख़ात्मा हो चुका है. चंबल में चुनावी बयार आते ही दस्युओं के दरबार में अपने-अपने पक्ष में फ़रमान जारी कराने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का जमावड़ा लग जाता था. वर्ष 2007 के चुनाव में डाकू ठोकिया की मां चितारा देवी राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़ी थी, लेकिन वह कुछ वोटों के अंतर से हार गई थी. वहीं ददुआ के फ़रमान के चलते बुंदेलखंड और चंबल के सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में लंबे समय तक सपा एवं बसपा ने अपना हित साधा. इस समीकरण के बिगड़ जाने के बाद कभी ददुआ के दम पर जीतने वाले दद्दू प्रसाद उसके दुश्मन बन गए थे. सपा ने ददुआ के बेटे बीर सिंह को पहले चित्रकूट से टिकट दिया, फिर प्रतापगढ़ पट्टी भेज दिया और फिर एक बार फ़ैसला बदलते हुए उसका टिकट चित्रकूट कर दिया.

समाजवादी पार्टी ने दस्यु सुंदरी फूलन देवी को मिर्ज़ापुर से चुनाव लड़ाया था और वह पार्टी की सांसद भी रहीं. मिर्ज़ापुर से सपा सांसद एवं दस्यु सम्राट ददुआ के भाई बाल कुमार पटेल ने पिछले दिनों चित्रकूट में बयान दिया कि ददुआ की कृपा से दद्दू एवं आर के पटेल विधायक बने थे. ग्राम्य विकास मंत्री दद्दू प्रसाद एवं सपा सांसद आर के पटेल ने दस्यु राधे के पुत्र सोनू द्वारा कराए गए भंडारे में शिकरत की थी. यही नेता चुनाव के समय ददुआ गिरोह से वारदातें कराते थे. इंडियन जस्टिस पार्टी ने 2007 के चुनाव में दस्यु सुंदरी सीमा परिहार को चुनावी जंग में उतारा था. डाकू गब्बर सिंह, शंकर सिंह एवं पूजा बब्बा गिरोह के सहारे चुनाव जीतने का आरोप कांग्रेस में रहे बुंदेलखंड के सुजान सिंह बुंदेला के परिवार पर आठवें एवं नवें दशक में लगते रहे हैं. पूर्व सांसद सुजान सिंह बुंदेला अब सपा में हैं और उनका पुत्र गुड्डू राजा बुंदेला सपा से ललितपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं. वहीं भाजपा ने मुलायम सिंह यादव से मुक़ाबले के लिए पूर्व दस्यु सरगना तहसीलदार सिंह को चुनावी जंग में उतारा. इटावा, औरैया, मैनपुरी, एटा, आगरा, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, फ़तेहपुर, मिर्ज़ापुर एवं ललितपुर आदि जनपदों में दस्यु सरदारों का फ़रमान पिछले चुनावों तक हावी रहा.

सब दिन होत न एक समान

विधानसभा चुनाव में चित्रकूट ज़िले से दो दिग्गज नेता चुनावी अखाड़े से बाहर दिख रहे हैं. डेढ़ दशक में यह पहला चुनाव होगा, जिसमें ज़िले की दोनों सीटों से सांसद आर के पटेल एवं मंत्री दद्दू प्रसाद परिदृश्य से बाहर हैं. आज़ादी के बाद यदि 1992 एवं 1957 के विधानसभा चुनावों को छोड़ दिया जाए तो 1962 से चित्रकूट की दोनों सीटों पर चुनाव अनुसूचित जाति, पटेल एवं ब्राह्मणों के इर्द-गिर्द लड़ा जाता रहा है. मानिकपुर सीट से डेढ़ दशक से लगातार जीतते आ रहे मंत्री दद्दू प्रसाद इस बार प्रत्याशी नहीं हैं. दद्दू एवं आर के पटेल का साथ 2007 के विधानसभा चुनाव में तब छूटा, जब पटेल ने दस्यु ददुआ का विरोध न करके ख़ुद को दांव पर लगा दिया था. आज दोनों अलग-अलग दलों में हैं. इन दोनों नेताओं के दख़ल के बिना चुनाव परिणाम निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हो सकते हैं. पटेल एवं ब्राह्मण पहले की तरह आज भी चुनावी समर में हैं. चुनाव की तस्वीर दलित मतदाताओं के रुझान पर बननी-बिगड़नी है, जिन्होंने फ़िलहाल चुप्पी साध रखी है.

बुंदेलखंड में तीन दशकों तक बादशाहत रखने वाले ददुआ का पूरा परिवार राजनीति के रंग में रंग गया है. भाई बाल कुमार पटेल मिर्ज़ापुर से सांसद है और बेटा बीर सिंह चित्रकूट ज़िला पंचायत अध्यक्ष रह चुका है और वर्तमान में सपा से चित्रकूट से विधानसभा उम्मीदवार है. दस्यु सरगना राम आसरे उर्फ़ फक्कड़ बाबा जेल में रहकर चुनावी गतिविधियों में सक्रिय है. राम आसरे ने टिकट के लिए जेल से संदेश भेजा है. दस्यु निषाद की पत्नी के चित्रकूट जनपद या तिंदवारी से चुनाव लड़ने की ख़बरें सुर्ख़ियों में हैं.

ग्राम पंचायत के प्रधान और बीडीसी पद का चुनाव जिताने के लिए फ़रमान जारी करने वाले दस्युओं में निर्भय गुर्जर, रागिया, ददुआ, कुसमा नाइन, सीमा परिहार, अरविंद गुर्जर, लुक्का एवं पंचम सिंह का नाम पहली पंक्ति में था. फूलन देवी के सांसद बनने के साथ ही विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में दस्युओं के फ़रमान मतदाताओं को हलकान किए रहते थे. मुलायम सिंह सरकार में निर्भय गूर्जर एवं बसपा सरकार में ददुआ, ठोकिया एवं रागिया जैसे डाकुओं का सफ़ाया हो जाने से इस विधानसभा चुनाव में दस्युओं के फ़रमानों और बंदूक़ों की आवाज़ों से आम जन को मुक्ति मिल गई है. दिनदहाड़े अपहरण, हत्या, लूट एवं चुनावी फ़रमान के साथ बैलेट पर बुलेट की मार करने वाले दस्युओं से निजात पाने में बसपा और सपा सरकार ने काफ़ी हद तक सफलता पाई. इसलिए क़रीब पचास सालों के बाद यह पहला अवसर है, जब निचले तबक़े के लोग अपने घरों से वोट डालने के लिए निकलेंगे, जो हमेशा दस्युओं से डरे रहते थे. चित्रकूट का मतदाता बहुत ख़ुश है, वह मतदान के लिए लालायित है. राजनीतिक पंडितों का मानना है कि लंबे अर्से के बाद बिना किसी दबाव, दख़ल एवं भय के बुंदेलखंड की जनता अपना वोट डाल सकेगी.

दर्शन शर्मा
feedback@chauthiduniya.com

नक्सल प्रभावित घोषित अनूपपुर में वेलस्पन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ ही मोजर बियर एवं न्यूज़ोन नामक कंपनियों के पावर प्रोजेक्टों के लिए भी बड़े पैमाने पर ज़मीन अधिग्रहण का काम आश्चर्यजनक तेजी से निपटाया गया है.

मध्य प्रदेश

नक्सल प्रभावित क्षेत्र घोषित होने का फ़ायदा किसे

राज्य में पूर्व के तीन ज़िलों मंडला, डिंडोरी एवं बालाघाट के मुक़ाबले 5 अन्य नए ज़िलों सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल एवं अनूपपुर में नक्सलियों का प्रभाव बढ़ गया है. राज्य सरकार की लगातार कोशिशों के बाद प्रदेश के इन सभी आठ ज़िलों को नक्सल प्रभावित घोषित कराने में कामयाबी मिल गई और ऐसे प्रत्येक ज़िले के लिए 25 करोड़ रुपये की सालाना केंद्रीय सहायता हाल में शुरू भी हो गई है. उक्त राशि व्यय किए जाने में कहीं कोई अनियमितता अथवा भ्रष्टाचार नहीं है. अब यह केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह इन इलाक़ों के लिए विशेष संसाधन एवं सहायता राशि उपलब्ध कराने में किसी तरह की कोई कोताही न बरते. इस संदर्भ में इससे ज़्यादा चर्चा करना मुझे ज़रूरी नहीं लगता. राज्य के गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता पिछले दिनों कटनी ज़िला मुख्यालय में आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में इन नए ज़िलों में नक्सलियों के बढ़ते प्रभाव की परस्पर विरोधाभाषी स्थितियों के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कुछ इसी अंदाज़ में पेश आए.

प्रदेश सरकार की ओर से नक्सलवाद का हौव्वा खड़ा करके यहां के ग्रामीण इलाक़ों में प्रचुर मात्रा में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, ज़मीन एवं बहुमूल्य खनिज संपदा आदि के दोहन पर आधारित विभिन्न संचालित और प्रस्तावित छोटे–बड़े उद्योगों के साथ ही बड़ी संख्या में सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को शासन–प्रशासन विशेषकर पुलिस द्वारा अनुचित लाभ अर्जित कराने के लिए खुलकर मदद की जा रही है. कटनी ज़िले के एक आदिवासी बाहुल्य एवं आरक्षित विधानसभा क्षेत्र बड़वारा के भाजपा विधायक मोती कश्यप के कई परिवारीजन इस क्षेत्र में अवैध उत्खनन जैसे कामों में संलिप्त हैं. उमाशंकर गुप्ता ही नहीं, मुख्यमंत्री

शिवराज सिंह एवं उनकी सरकार की ग़लत बयानियों को उजागर करता एक और मामला पिछले दिनों उस समय सामने आया, जब अनूपपुर ज़िले में निजी पावर कंपनियों की स्थापना के लिए 27 हज़ार एकड़ कृषि भूमि के अधिग्रहण के मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार सहित सात लोगों से जवाब–तलब किया. न्यायमूर्ति के के त्रिवेदी की एकल पीठ ने पीड़ित किसानों की याचिकाओं पर विपक्षियों को 6 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. उक्त याचिकाएं अनूपपुर ज़िले की कोतमा तहसील के ग्राम उमरदा और मझटलिया के पीड़ित किसान रामनिवास कंवर, बुधरिया अगरिया, संतोष कुमार, शंकर यादव, सुंदर केवट, मोहन साहू, रामपति साहू, संतोष साहू, जयकिरन साहू, मीराबाई, नंददास केवट, श्यामलाल पनिका, रामसूरत उर्फ पुसुवा एवं बुधवा यादव की ओर से दायर की गई हैं. इन किसानों का कहना है कि मुंबई की वेलस्पन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य कंपनियों की स्थापना के लिए अनूपपुर ज़िले में तक़रीबन 27 हज़ार एकड़ कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है. इनका आरोप है कि अनूपपुर के ज़िलाधिकारी द्वारा लोकहित एवं लोक प्रयोजन के नाम पर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई तथ्यों को छिपाकर की जा रही है, जो अवैधानिक है. आरोप है कि शासन के अमले ने धारा 4 एवं 6 के तहत अधिसूचनाएं तो जारी कीं, लेकिन धारा 5–ए के तहत पीड़ित पक्षों से आपत्तियां मांगने के प्रावधानों की पूरी तरह उपेक्षा की जा रही है. सुनवाई के बाद अदालत ने केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव–राजस्व, प्रमुख सचिव–पंचायत विभाग, शहडोल के संभागायुक्त, ज़िलाधिकारी अनूपपुर, भू–अर्जन अधिकारी और वेलस्पन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं.

कटनी में नौ और अनूपपुर, शहडोल एवं ब्यौहारी में 19 ताप विद्युत केंद्र बनाने के लिए 28 बड़ी कंपनियां आ रही हैं. प्रति कंपनी लगभग तीन हज़ार एकड़ के हिसाब से 84 हज़ार एकड़ ज़मीन के अलावा बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता है. इन क्षेत्रों में अभी घोषित तौर पर केवल पांच कंपनियां काम कर रही हैं, शेष आने की तैयारी में हैं, जिसकी प्रक्रिया चल रही है. राज्य मंत्रि परिषद द्वारा मेसर्स वेलस्पन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की अनूपपुर ताप विद्युत परियोजना के लिए किए गए अधिग्रहण के संबंध में विस्थापितों-प्रभावितों को प्रतिकर के अलावा पुनर्वास नीति के अंतर्गत विशेष सुविधाएं एवं सहायता भी देने का निर्णय लिया गया है.

नक्सल प्रभावित घोषित अनूपपुर में वेलस्पन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ ही मोजर बियर एवं न्यूज़ोन नामक कंपनियों के पावर प्रोजेक्टों के लिए भी बड़े पैमाने पर ज़मीन अधिग्रहण का काम आश्चर्यजनक तेजी से निपटाया गया है. जबकि प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की ओर से इन उद्योगों की स्थापना के संदर्भ में प्रारंभिक जन सुनवाइयों के दौर से ही गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई जाती रही हैं. कटनी ज़िले के बड़वारा अंचल के अंतर्गत ग्राम गुढ़ाकला में सांघी कंपनी द्वारा स्थापित उद्योग, जिसे धान की भूसी के माध्यम से संचालित किया जाना था, वहां पिछले दिनों इलाकाई जंगलों से बड़ी मात्रा में अवैध रूप से काटी गई लकड़ी से भरे कई ट्रैक्टर पकड़े गए. नक्सल प्रभावित सिंगरौली, सीधी, उमरिया एवं शहडोल के साथ–साथ सीमावर्ती कटनी जैसे ज़िलों में भी यही स्थिति है. मेसर्स वेलस्पन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने अनूपपुर में आदिवासियों की 2700 एकड़ ज़मीन अधिग्रहीत कर ली थी. इन आदिवासियों को रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास जैसी सुविधाएं भी नहीं मिलीं. हाल में राज्य सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है कि पुनर्वास अनुदान, प्रति एकड़ ढाई लाख रुपये मुआवज़ा एवं पांच हज़ार रुपये परिवहन व्यय दिए जाने के साथ–साथ सामान की ढुलाई मुफ्त में की जाएगी. इसके अलावा नियमित रोज़गार, स्व–रोज़गार, रजिस्ट्री में छूट और बच्चों के लिए छात्रवृत्तियों की भी व्यवस्था की जाएगी.

कटनी में नौ और अनूपपुर, शहडोल एवं ब्यौहारी में 19 ताप विद्युत केंद्र बनाने के लिए 28 बड़ी कंपनियां आ रही हैं. प्रति कंपनी लगभग तीन हज़ार एकड़ के हिसाब से 84 हज़ार एकड़ ज़मीन के अलावा बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता है. इन क्षेत्रों में अभी घोषित तौर पर केवल पांच कंपनियां काम कर रही हैं, शेष आने की तैयारी में हैं, जिसकी प्रक्रिया चल रही है. राज्य मंत्रि परिषद द्वारा मेसर्स वेलस्पन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की अनूपपुर ताप विद्युत परियोजना के लिए किए गए अधिग्रहण के संबंध में विस्थापितों–प्रभावितों को प्रतिकर के अलावा पुनर्वास नीति के अंतर्गत विशेष सुविधाएं एवं सहायता भी देने का निर्णय लिया गया है. अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के भूमि स्वामी को 22 हज़ार रुपये का एकमुश्त पुनर्वास अनुदान दिया जाएगा. छोटे एवं सीमांत किसानों को एकमुश्त 16 हज़ार रुपये एवं अन्य वर्ग के किसानों को 11 हज़ार रुपये दिए जाएंगे. प्रत्येक किसान को उसकी अधिग्रहीत भूमि के लिए प्रति एकड़ के मान से उतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे देय प्रतिकर मिलाकर उक्त भूमि के बदले 2 लाख 50 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्राप्त हो जाएं.

भूमिहीन विस्थापित परिवार को एकमुश्त 22 हज़ार रुपये की राशि विशेष आर्थिक अनुदान के रूप में दी जाएगी. अन्य श्रेणी के ऐसे विस्थापित परिवारों, जो शासकीय भूमि पर विगत तीन वर्षों या उससे अधिक समय से अतिक्रमक के रूप में कृषि कार्य करते रहे हैं, को एक लाख 10 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के मान से पुनर्वास अनुदान देय होगा. एक एकड़ से कम के ऐसे किसानों को न्यूनतम एक लाख रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा विस्थापन के परिणामस्वरूप घरेलू सामान अन्यत्र ले जाने के लिए कंपनी द्वारा 25 किलोमीटर की दूरी तक नि:शुल्क परिवहन सुविधा दी जाएगी. विस्थापितों को 5 हज़ार रुपये प्रति परिवार के हिसाब से परिवहन व्यय भी दिया जाएगा. परियोजना के लिए अधिग्रहीत किए जाने वाले आवासीय भवनों के विस्थापितों को भूखंड एवं आवास निर्माण के लिए एक लाख रुपये का एकमुश्त अनुदान देय होगा. विस्थापितों के लिए नियमित रोज़गार, स्व–रोज़गार प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं और मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क में छूट संबंधी प्रावधान भी किए गए हैं. कंपनी की ओर से विस्थापित परिवारों के बालक–बालिकाओं को छात्रवृत्तियां भी दी जाएंगी.

यहां यह बताना आवश्यक है कि ये सारे लाभ उन लोगों को दिए जाएंगे, जो अपनी ज़मीनों का जबरिया अधिग्रहण स्वीकार कर लेंगे. उन लोगों का क्या होगा, जो ऐसे तमाम प्रलोभनों के झांसे में न आकर किसी भी क़ीमत पर, यहां तक कि जान देकर भी अपनी ज़मीनें इन कंपनियों को देने के लिए तैयार नहीं होंगे, उनके साथ राज्य सरकार क्या बर्ताव करने जा रही है, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है. ऐसे मामलों से संबंधित ज़्यादातर ज़िले वही हैं, जिन्हें राज्य सरकार ने केंद्र पर लगातार दबाव बनाकर नक्सल प्रभावित घोषित कराया है. इस स्थिति में संबंधित क्षेत्रों के किसानों, आम नागरिकों एवं उनके समर्थन में खड़े हो रहे जन संगठनों के किसी भी आंदोलन को सरकार नक्सलवाद का प्रभाव बताकर कुचलने के लिए तत्पर नहीं होगी, यह भला कैसे माना जा सकता है. ज़ाहिर है, मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों के दौरान नक्सलवाद का सरकार द्वारा बढ़ता हुआ बताया जा रहा कथित प्रभाव भी तथाकथित विकास के नाम पर सरकारी लूट के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा.

अरविंद वर्मा
feedback@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... रिटायरमेंट की वजह

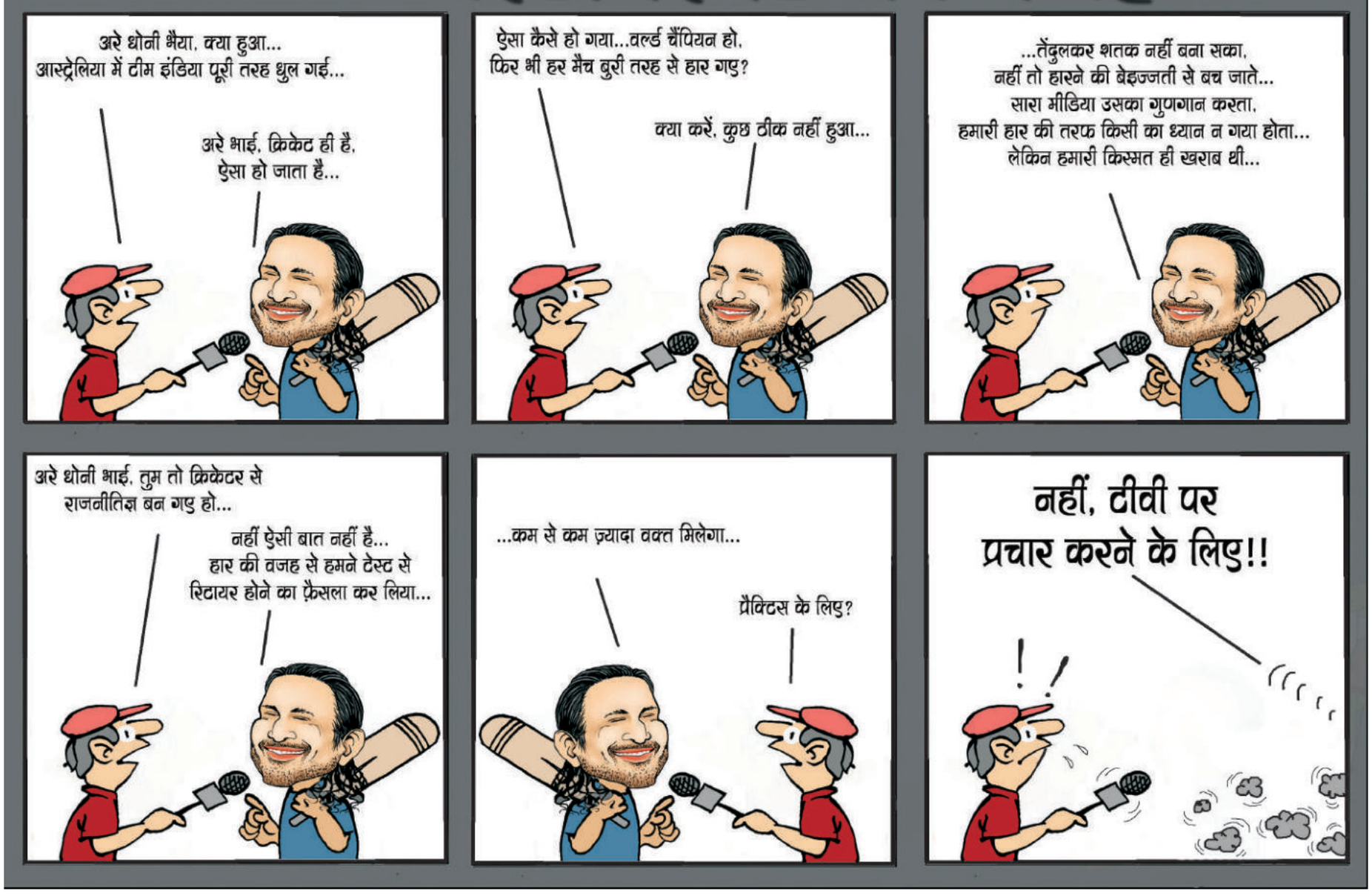

भारत में कोयले की काली लकीर

यह समय सबसे अच्छा था, यह समय सबसे ख़राब था, यह युग समझदारी का था, यह युग ही बेवकूफ़ियों का था. कोयले की इस वर्तमान गतिशीलता की तुलना किसी षड्यंत्र और दो शहरों की कथा (ए टेल ऑफ़ टू सिटीज़) के झंझावात से नहीं की जा सकती. यह कथा निश्चय ही आरंभिक भावनाओं को प्रतिबिंबित करती है और इससे इस क्षेत्र में चलने वाले घटनाचक्र का अंदाज़ा हो जाता है. हाल में बाज़ारी पूंजीवाद के संदर्भ में सबसे प्रतिष्ठित कंपनी के रूप में कोल इंडिया के उदय होने की चर्चा समाचार पत्रों में गूंजती रही है. वित्तीय जश्न मनाने की बजाय पिछले कुछ वर्षों से भारत में कोयले की भारी कमी रही है, जिसके कारण राज्य सरकारें, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की पावर और इस्पात कंपनियां समय पर कोयले की डिलीवरी न होने की लगातार शिकायतें करती रही हैं.

घरेलू कोयले के सुरक्षित भंडार से काफ़ी मात्रा में कोयला निकालने की भारत की क्षमता में गिरावट आने के कारण उसकी नीति पर भी मूल रूप में इसका असर पड़ा है. कोयला मंत्रालय द्वारा निष्पादित नवीनतम कोयला ईंधन आपूर्ति क़रार (एफएसए) बिजली संयंत्रों की ईंधन संबंधी 75 प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा करने की गारंटी देते हैं, शेष की पूर्ति निजी तौर पर की जानी चाहिए. यदि कोयला ईंधन आपूर्ति क़रार (एफएसए) निष्पादित हो भी जाए, जो अपने आपमें संपर्क अनुमोदन प्रक्रिया की जटिलताओं को देखते हुए बेहद अनिश्चित है तो भी रेल और सड़क मार्ग के मिले-जुले रूप के कारण स्त्रोत स्थल से ले जाकर गंतव्य स्थल पर उन्हें ख़ाली करने-कराने के तौर-तरीक़ों और उसके लिए ज़िम्मेदार एजेंसियों द्वारा लॉजिस्टिकल प्रबंधन के कमज़ोर समन्वयन के कारण और भी नुक़सान और देरी होती रहती है. इस बात को लेकर हैरानी भी नहीं होनी चाहिए कि बड़े-बड़े कोयला उपभोक्ता बेहतर क़िस्म के कोयले को चुनने के लिए उसे उन देशों से आयातित करने पर आमादा होने लगे हैं, जहां पर क़रार और लॉजिस्टिक्स से संबंधित दायित्वों का पूर्वानुमान किया जा सकता है. इसकी प्रतिक्रिया में कोयला निर्यातक देशों और अभी हाल में इंडोनेशिया ने भी कोयले की बढ़ती मांग को देखते हुए उसकी क़ीमत में बढ़ोतरी और विनियमों में परिवर्तन करना शुरू कर दिया है.

आशा है कि भारत अगले कुछ वर्षों में एक मिलियन टन से अधिक कोयले का आयात करेगा. क्या कारण है कि कोयले का घरेलू उत्पादन मांग को पूरा करने में विफल रहा है? हालांकि इस बारे में बहुत-से स्पष्टीकरण दिए जा चुके हैं, फिर भी यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कदाचित सबसे कठिन है. कुछ लोग कहते हैं कि पर्यावरण संबंधी स्वीकृति और भूमि अधिग्रहण ही मुख्य बाधाएं रही हैं. कुछ लोग इसका दोष राज्यों द्वारा स्वाधिकृत कोयला कंपनियों पर मढ़ देते हैं जो अपने परिचालन में आधुनिक खनन की परिपाटियों और प्रौद्योगिकी को प्रभावशाली रूप में अपनाने में असमर्थ रहे हैं. सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कोयला कंपनियों के इन पुराणपंथी मालिकों की काफ़ी आलोचना भी हुई है. इनके कई मालिकों ने तो उत्पादन के लिए ब्लॉक ला पाने में विफल होने के बाद अपने आवंटित ब्लॉकों को अनावंटित भी करा दिया. क़िस्सागोई की तरह आपराधिक तत्वों के साथ कोयला उद्योग की मिलीभगत और उसके फलस्वरूप होने वाली चोरी और ग्रेड की गुणवत्ता को कम करने की वारदातों को भी समझा जा सकता है. यही कारण है कि घरेलू उद्योग में वर्तमान कमी के सही कारणों को समझना इतना आसान नहीं है, परंतु एक बात तो साफ़ है कि परंपरागत बाज़ार की अपेक्षित क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं हो पाया है.

भारतीय कोयला बाज़ार एक अजीबो-ग़रीब दानव है. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), सिंगरेनी कोल कोलियरी लिमिटेड (एससीसीएल) और नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (एनएलसी) के बीच राज्यों की स्वाधिकृत कंपनियों के उत्पादन के अल्पाधिकार की भरपाई ऐतिहासिक रूप में क्रय के एकाधिकार द्वारा की जाती रही है. उदारीकरण से पहले तक कोयले के सबसे बड़े औद्योगिक उपभोक्ता अर्थात बिजली, लोहा व इस्पात और सीमेंट के कारख़ाने भी ज़्यादातर राज्यों के स्वाधिकृत कारख़ाने ही रहे हैं, लेकिन वास्तव में रेलवे ही एक ऐसी संस्था है जिसके पास कोयले को बड़े पैमाने पर उठाने और उसे वितरित करने की अच्छी-ख़ासी मूल्य-शक्ति है. उदारीकरण के बाद जब ये ज़िम्मेदारियां सीआईएल को औपचारिक रूप में सौंप दी गईं, तब कोयला मंत्रालय ने 2000 के दशक की शुरुआत तक मूल्यों पर नियंत्रण बनाए रखा. फिर भी आयात-समानता के मूल्यों पर केवल कोयले के उच्चतम ग्रेड ही बेचे गए और भारत का अधिकांश उत्पादन निचले ग्रेड का होने के कारण कम मूल्य पर बेचा गया और हो सकता है कि इन मूल्यों का निर्देश अनिवार्य वस्तुओं, ख़ास तौर पर बिजली की लागत को कम रखने के लिए कदाचित कोयला मंत्रालय द्वारा दिया गया था. सन 2011 के आरंभ में सीआईएल ने विभेदक मूल्य प्रणाली शुरू की, जिसके आधार पर बाज़ार-संचालित क्षेत्रों के लिए उच्चतर मूल्य तय किए गए.

इन बदलती हुई मूल्य-व्यवस्थाओं के बावजूद काले बाज़ार को छोड़कर

कोयले की आपूर्ति की निगरानी के लिए विकसित प्रशासनिक प्रणाली बहुत जल्द ही अपनी विश्वसनीयता खोने जा रही है. बिजली के क्षेत्र की क्षमता, शायद कुछ मूर्खतापूर्ण लगे, लेकिन कोयले की आपूर्ति की क्षमताओं से कहीं आगे निकल गई है. इस समय चलने वाले कई संयंत्र, ख़ास तौर पर वे संयंत्र जो राज्य के क्षेत्र में हैं, अपनी क्षमता से बहुत कम काम कर रहे हैं. पिछले साल वर्तमान संविदागत क़रारों को पूरा करने में सक्षम न होने के कारण ही बहुत कम कोयला ईंधन आपूर्ति क़रारों पर हस्ताक्षर हो पाए हैं.

खुले बाज़ार में थोक में कोयला ख़रीदना सचमुच बहुत कठिन है. भारत के छह सौ मिलियन टन के घरेलू कोयला उत्पादन में से लगभग 80 प्रतिशत का आवंटन कोयला मंत्रालय की प्रशासनिक समितियों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के आवेदकों को किया गया. अतिरिक्त 10 प्रतिशत की बिक्री ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से की गई, जिसके परिणामस्वरूप अच्छा-ख़ासा राजस्व भी मिला है. 2009-10 में ई-नीलामी मूल्य औसतन अधिसूचित मूल्यों से लगभग 60 प्रतिशत ऊपर रहा. अवरुद्ध कोयला ब्लॉक, जिन्हें जल्द ही प्रतियोगी बोलियों के माध्यम से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को आवंटित कर दिया जाएगा, 19 प्रतिशत अतिरिक्त था. अंततः घरेलू कोयला उत्पादन का आख़िरी 1 प्रतिशत राज्य सरकार की एजेंसियों को, जो इसे स्थानीय बाज़ारों को उपलब्ध करा देते हैं, आवंटित कर दिया जाता है.

कोयले के कम मूल्य के पीछे का तर्क था कि बिजली, इस्पात और सीमेंट का परिणामी उत्पादन अनिवार्य था और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उसकी क़ीमत कम करना ज़रूरी था, लेकिन आर्थिक सलाहकार के कार्यालय से हाल के मूल्यों के आंकड़ों को देखते हुए 2004 से 2011 तक कोयले के मूल्य में 89 प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि बिजली, इस्पात और सीमेंट के मूल्यों में क्रमशः 13 प्रतिशत, 26 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई. उसी अवधि में थोक मूल्य सूचकांक में 54 प्रतिशत वृद्धि हुई. जहां एक ओर बिजली के मूल्य विनियमित कर दिए गए, वहीं दोनों के मूल्य का विनियमन नहीं हुआ है, जिसका अर्थ यह हुआ कि इन दोनों उद्योगों ने कोयले के बढ़ते मूल्यों को पर्याप्त रूप में आत्मसात करते हुए उनका प्रबंधन कर दिया. यदि स्थिति यही है तो कृत्रिम रूप से कोयले के कम मूल्य के रूप में सहायता की इनपुट राशि का तर्क काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन मूल्य-निर्धारण मूलभूत समस्या भी नहीं है.

कोयले की आपूर्ति की निगरानी के लिए विकसित प्रशासनिक प्रणाली बहुत जल्द ही अपनी विश्वसनीयता खोने जा रही है. बिजली के क्षेत्र की क्षमता, शायद कुछ मूर्खतापूर्ण लगे, लेकिन कोयले की आपूर्ति की क्षमताओं से कहीं आगे निकल गई है. इस समय चलने वाले कई संयंत्र, ख़ासतौर पर वे संयंत्र जो राज्य के क्षेत्र में हैं, अपनी क्षमता से बहुत कम काम कर रहे हैं. पिछले साल वर्तमान संविदागत क़रारों को पूरा करने में सक्षम न होने के कारण ही बहुत कम कोयला ईंधन आपूर्ति क़रारों पर हस्ताक्षर हो पाए हैं. पिछले कुछ महीनों में श्रमिक संकट, भारी वर्षा और तेलंगाना विरोध के कारण इस प्रणाली की ऐसी कमी भी सामने आई है, जिसके कारण बिजली के संयंत्रों में कोयले के भंडार कम होने लगे और अनेक दक्षिणी राज्यों में लंबे समय तक बिजली की कटौती होने लगी.

ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियों में निजी क्षेत्र में भी जोखिम बढ़ने के कारण उत्साह में कमी दिखाई पड़ने लगी. सीआईएल के मूल्य-निर्धारण के उत्साह से भरे सारे प्रयासों पर बार-बार पावर क्षेत्र द्वारा पानी फेर दिया गया. यदि इन्हें उचित रूप में कार्यान्वित किया जाए तो इससे पावर क्षेत्र में सैद्धांतिक रूप में स्थितियों में सुधार आ जाएगा, लेकिन बढ़िया कोयले की डिलीवरी में सीआईएल के ख़राब रिकॉर्ड के कारण कई ऑपरेटर भारी रद्दोबदल करने की बजाय स्थिति को यथावत बनाए रखना ही पसंद करते हैं. इस प्रकार का संतुलन, जहां कोई भी पक्ष पूरी तरह से निकम्मी पड़ी इस प्रणाली में कोई भारी परिवर्तन नहीं चाहता, बहुत समय तक नहीं चल सकता.

इस प्रकार की समस्याओं का कोई सरल समाधान नहीं है, इसलिए इन पर गंभीर विचार मंथन की आवश्यकता है. रणनीतिक कारणों से विदेशों से कोयले के संसाधन मंगवाने की बात ठीक तो लगती है, लेकिन इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि कोयले की किसी खान को पूरी तरह से विकसित करने में पांच से सात साल तक का समय लगता है, अपने देश में ही कुछ अल्पकालिक उपायों की आवश्यकता तो होगी ही. कोयले के क्षेत्र में सुधारों पर शंकर समिति की रिपोर्ट में चार साल पहले कई ऐसी समस्याओं की भविष्यवाणी की गई थी और उस समिति की सिफ़ारिशों पर कार्रवाई करने में कुछ समय तो लगेगा ही. अनेक महत्वपूर्ण सवालों पर विचार करना होगा. उदाहरण के लिए पिछले बीस वर्षों में भारतीय कोयला खनन कंपनियों की उत्पादकता में बदलाव कैसे आया? कोयले की आपूर्ति की लाइनें कैसे चलती हैं और इस प्रक्रिया में बाधाएं और विचलन कहां हैं? क्या भारत अपनी घरेलू खानों से इष्टतम मात्रा में कोयला निकाल सकता है? क्या यह संभव है कि वर्तमान क़ानूनी ढांचे के भीतर अधिक खुले कोयला बाज़ार में संक्रमण किया जा सके? इन सवालों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद ही पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में चली आ रही समस्याओं के लगातार समाधान की कोशिशें रंग ला पाएंगी.

रोहित चंद्रा
feedback@chauthiduniya.com

(लेखक भारतीय उच्च अध्ययन केंद्र (सीएएसआई) में अनुसंधान समन्वयक हैं)

मालिक लोग यही चाहते हैं कि उनके माल–असबाब को बनाने या पैदा करने में जितने श्रम की आवश्यकता होती हो.

महावीर प्रसाद आर मोरारका

वर्ग युद्ध

मध्यम वर्ग का या उत्पादन करने वाला कोई भी व्यवसायी जिस तरह से अपने जीवन निर्वाह के लिए अपना माल बेचना आवश्यक समझता है, उसी तरह एक मज़दूर भी अपना माल–असबाब बेचे बिना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता. उसका माल–असबाब उसका श्रम ही है. उसकी जितनी ज़्यादा क़ीमत मिल सके, उतना ही उसके लिए अच्छा है, जितनी कम मिले, उतना ही बुरा है. अगर कुछ न मिले तो वह एकदम दरिद्र हो जाएगा और भूखों मरेगा. इसलिए मज़दूर हमेशा यही प्रयत्न करता है कि उसके श्रम का अधिक से अधिक मूल्य मिले या उसे कम से कम श्रम करना पड़े. उसकी कोशिश यही रहती है कि उसे कम से कम घंटे काम करना पड़े और ज़्यादा तनख्वाह मिले. दूसरी ओर जो मालिक है, उसका यह प्रयत्न रहता है कि उसे श्रम सस्ता मिले. कम से कम वेतन पर ज़्यादा से ज़्यादा काम लेने की प्रवृत्ति इन मालिकों की रहती है.

तात्पर्य यह कि मज़दूर और मालिक के हित विपरीत दिशा में चलते हैं. परिणामत: अशांतिमूलक और दु:खदायक भयानक संघर्ष पैदा होते हैं, जिन्हें वर्ग युद्ध कहा जाता है. इससे सभ्यता को लज्जित होना पड़ता है, क्योंकि परिस्थिति भद्दे वातावरण में बदल जाती है. शासन को बार–बार बीच में पड़ना पड़ता है, ताकि श्रम विक्रेता और श्रम ख़रीददार दोनों को उचित सीमा के अंतर्गत रखा जा सके. मालिक लोग यही चाहते हैं कि उनके माल–असबाब को बनाने या पैदा करने में जितने श्रम की आवश्यकता होती हो, वह उन्हें कम से कम क़ीमत में मिले. भले ही वह श्रम पुरुषों का हो, स्त्रियों का हो या बालकों का हो, उन्हें तो सस्ती से सस्ती मज़दूरी में काम कराने से मतलब है. उनका एकमात्र लक्ष्य मुनाफ़ा है. उदाहरण के लिए किसी भी चलते हुए तांगे, इक्के, घोड़ा गाड़ी को लीजिए. ज़्यादातर ये तांगे–इक्के ठेकेदारों के होते हैं, जो उसी मध्यम श्रेणी के मालिक होते हैं. तांगा या इक्का चलाने के लिए ये लोगों को भाड़ा या वेतन देकर रखते हैं.

विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसा ख़ूब हुआ है, होता आया है. भारत में भी उसी पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत कल तक यह होता था. एक ऐसा भी समय था, जब छोटे-छोटे बालकों से कठिन श्रम कोड़ों से मार-मार कर लिया जाता था. पत्थर तोड़ने-फोड़ने का काम स्त्रियों से लिया जाता था. दार्शनिकों ने यह कहावत बना ली थी कि मालिक की उम्र में मज़दूरों की 5-5 या 7-7 पीढ़ियां बदल जाती हैं.

अब मान लीजिए, अच्छी तरह खिलाया–पिलाया जाए और चार घंटे रोज़ाना ड्यूटी ली जाए तो 1 घोड़ा 12 वर्ष तांगा या इक्का चला सकता है और अगर यों ही आधा पेट सड़ा–गला, घास खिलाकर रोज़ाना 8 या 12 घंटे ड्यूटी लेकर चलाया जाए तो वही घोड़ा 2 वर्ष में मर जाएगा. जब उसे दूसरा घोड़ा बहुत कम क़ीमत में उपलब्ध होता है तो वह अच्छी तरह ख़र्च करने और कुल 4 घंटे ही रोज़ाना जोतने की अपेक्षा, 10–12 घंटे काम लेना ज़्यादा फ़ायदे का क्यों न समझे? इसी तरह मानव के काम के संबंध में भी है. अगर कठिन से कठिन परिश्रम कराने से हड्डी चूर–चूर हो जाए, मज़दूर की जीवनलीला 5 या 7 वर्ष काम करने पर ही समाप्त हो जाए और उसकी जगह पर्याप्त मात्रा में दूसरे मज़दूर मिलते रहें तो वे मालिक, जिनकी नज़र हमेशा अपने मुनाफ़े पर है, कभी भी मानवीय दया का भाव रखकर कठिन श्रम से काम लेने में नहीं हिचकेंगे.

विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसा ख़ूब हुआ है, होता आया है. भारत में भी उसी पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत कल तक यह होता था. एक ऐसा भी समय था, जब छोटे–छोटे बालकों से कठिन श्रम कोड़ों से मार–मार कर लिया जाता था. पत्थर तोड़ने–फोड़ने का काम स्त्रियों से लिया जाता था. दार्शनिकों ने यह कहावत बना ली थी कि मालिक की उम्र में मज़दूरों की 5–5 या 7–7 पीढ़ियां बदल जाती हैं. यानी इतनी ज़्यादा संख्या में श्रमिकों की मृत्यु होती थी और इतनी ही ज़्यादा संख्या में वे पैदा होते थे, इससे आदमियों की कमी तो महसूस होती नहीं थी. पर आज जब विचार करते हैं तो हृदय कांप उठता है कि कितना राक्षसी व्यापार था यह. यही वजह है कि कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक कैपिटल में जोर–शोर से इन मध्यमवर्गीय मालिकों के विरुद्ध विद्रोह किया और कठोर शब्दों में खुलेआम हिंसा तक को प्रोत्साहन दिया. कार्ल मार्क्स की पुस्तक प्रकाशित होने के बहुत पहले ही ब्रिटेन और अन्य कई देशों में मालिक और मज़दूरों के बीच संघर्ष की नींव पड़ चुकी थी और कई नए क़ानून इस तरह की निर्दयता को रोकने के लिए बन चुके थे, जिन्हें फैक्टरी एक्ट के नाम से संबोधित किया जाता है.

feedback@chauthiduniya.com

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

कमल मोरारका का ब्लॉग

www.kamalmorarka.com

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्र की गरिमा को पुनर्स्थापित किया

एक बार फिर उच्चतम न्यायालय ने देश की प्रतिष्ठा बचाई और उसका मान रखा. जहां एक तरफ़ देश की कार्यपालिका भ्रष्ट मंत्रियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में असफल रही, वहीं एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने देश के सम्मान को बचाया और उसकी गरिमा को पुनर्स्थापित किया. पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने 2–जी के सभी लाइसेंस निरस्त कर दिए. सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह बुद्धिमानी का परिचय देते हुए निष्पक्षता दिखाई, वह इस देश के लोकतंत्र के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है. सुप्रीम कोर्ट का दूसरा निर्णय भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें उसने उच्च प्रतिमान स्थापित किए. अब किसी के ख़िलाफ़ अभियोजन की कार्रवाई चलाने के लिए सरकार को चार महीने के भीतर निर्णय लेना होगा. यदि सरकार ऐसा नहीं कर पाती है तो स्वत: यह मान लिया जाएगा कि स्वीकृति मिल गई है और फिर अभियोजन की कार्रवाई चलाई जा सकेगी.

भारतीय राजनीति फ़िलहाल मुश्किलों के दौर से गुजर रही है. आम जनता राजनेताओं को अपराधियों की शक्ल में देख रही है. अगर एक भी व्यक्ति की छवि राजनेता के रूप में ख़राब हो जाती है तो जनता सभी को एक ही नज़रिए से देखती है. वह नेता को जिस रूप में देखती है, दरअसल उसी रूप में लोकतंत्र को भी देखने लगती है. इसके लिए स्वयं राजनीतिज्ञ दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति का ग़लत इस्तेमाल किया है. ख़ासकर वे राजनेता दोषी हैं, जो सत्ता में है और जो ग़लत को ठीक कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते.

इस एक मामले में ख़ास तौर पर यूपीए सरकार को ही दोषी ठहराया जाना चाहिए. बड़े अफसोस की बात है कि सीएजी रिपोर्ट में दोषी पाए गए मंत्री का सरकार के वरिष्ठ मंत्री बचाव कर रहे थे और सीएजी द्वारा बताए गए घाटे को ग़लत ठहराते रहे और कहते रहे कि 2–जी घोटाले में सरकार को नुक़सान नहीं हुआ. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसी मंत्री ने बाक़ायदा प्रेसवार्ता आयोजित करके घोटाले का ठीकरा पूर्व की एनडीए सरकार के सिर पर फोड़ा और उसे ज़िम्मेदार ठहराया. प्रधानमंत्री को चाहिए कि वे भ्रष्ट मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर करें. ज़ाहिर है, सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, सिवाय सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने के.

भारतीय राजनीति फ़िलहाल मुश्किलों के दौर से गुजर रही है. आम जनता राजनेताओं को अपराधियों की शक्ल में देख रही है. अगर एक भी व्यक्ति की छवि राजनेता के रूप में ख़राब हो जाती है तो जनता सभी को एक ही नज़रिए से देखती है. वह नेता को जिस रूप में देखती है, दरअसल उसी रूप में लोकतंत्र को भी देखने लगती है.

कुछ महीने पूर्व मैंने लिखा था कि सरकार को चाहिए कि वह ग़लत और अवैध तरीक़े से कमाए गए धन को ज़ब्त कर ले. महाराष्ट्र सरकार को चाहिए कि वह आदर्श हाउसिंग सोसायटी में हुए फ्लैट आवंटन को तत्काल रद्द करे और उन सभी लोगों के पैसे वापस कर दे, जिन्हें उक्त फ्लैट आवंटित हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वह एक ऐसी व्यवस्था बनाए, जिससे भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्तियां ज़ब्त की जा सकें . वहीं प्रधानमंत्री को भी चाहिए कि वह भ्रष्ट मंत्रियों को बाहर करके एक सही उदाहरण प्रस्तुत करें, सक्षम एवं प्रतिभावान लोगों की एक टीम बनाएं. अगर वह ऐसा करते हैं, तभी उनकी प्रतिष्ठा बची रह पाएगी.

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

सर्वश्रेष्ठ पत्र

भ्रष्टाचारियों को ईमानदार बनाना होगा

भ्रष्टाचार देश के समक्ष आज सबसे बड़ी समस्या है. जब तक हमारे देश के जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी ईमानदार नहीं होंगे, तब तक भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता. सिर्फ़ भ्रष्टाचारियों को सज़ा देने से कुछ होने वाला नहीं है. इसके लिए ज़रूरी है कि भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को ईमानदार बनाने का प्रयास किया जाए. यह किस तरह होगा, इस पर विचार करने की ज़रूरत है. भ्रष्टाचार के कारण ही लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं.

–रंजन कुमार सिंह राजपूत, *पटना, बिहार.*

राजनीति में लाभ ही लाभ

आज़ादी के 64 वर्षों बाद भी ग्रामीण बदहाल हैं और इसके लिए हमारे नीति निर्माता ज़िम्मेदार हैं, चाहे वे राजनीतिज्ञ हों या सरकारी अधिकारी. कौटिल्य ने कहा है कि राजनीति एवं दंडनीति अप्राप्त को प्राप्त करती है, लेकिन अब राजनीति लोक कल्याण के बजाय महा लाभ का उद्योग है. यहां अरबों–खरबों का पूंजी निवेश है. पार्टी चलाना भी उद्योग है. सत्ता, विपक्ष, आयोग या जांच समितियों में होना लाभप्रद है यानी हर तरह से लाभ ही लाभ है.

–अशोक मल्होत्रा, *नई दिल्ली.*

पर्यावरण संकट

दुनिया भर में अमीरों ने अपनी सुख–सुविधा और हैसियत बनाने के लिए जितना प्रदूषण फैलाया है, उतना ग़रीबों ने नहीं फैलाया. भारत में ग़रीबों ने पर्यावरण संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए पौधारोपण को अपनाया है. पौधारोपण में ग़रीब एवं मध्यम वर्ग के लोग ही बढ़–चढ़कर भाग लेते हैं, जबकि गाड़ियों में घूमने वाले अमीर जहां–तहां कूड़ा फैलाते रहते हैं. संयुक्त राष्ट्र संघ भी अमीरों पर लगाम नहीं लगाता. तुलसीदास ने सही लिखा है–समरथ को नहीं दोष गुसाईं.

–प्रताप नारायण सिंह, *बेगूसराय, बिहार*

कलाम के बयान पर हैरानी

चौथी दुनिया में प्रकाशित आलेख–कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का स्याह पक्ष पढ़ा. रेडियोधर्मी विकिरण सबसे ज़्यादा भयंकर होता है और इस प्रदूषित बिजली की ज़रूरत ही क्या है? जर्मनी, जिसके पास भारत जितने सौर ऊर्जा साधन नहीं हैं, शीघ्र ही अपने संयंत्र बंद करने जा रहा है. सबसे कठिन इसके कचरे का निस्तारण है. पता नहीं क्यों, हमारे मिसाइल मैन डॉ. कलाम इसे सुरक्षित बता रहे हैं. बेहतर होगा कि हम जल, सौर एवं गैस आधारित ऊर्जा तक सीमित रहें.

–चंद्रकांत यादव, *चंदौली, उत्तर प्रदेश.*

नेताओं की कथनी–करनी में अंतर

चौथी दुनिया में प्रकाशित आलेख–आसमान में घोटाला पढ़ा. इस लेख को पढ़कर पता लगा कि हमारे देश के नेताओं की कथनी–करनी में कितना फ़र्क है. एक ओर वे चुनावों के समय आम आदमी, किसानों के उत्थान की बात करते हैं, लेकिन सहायता अरबों–खरबों का व्यापार करने वाले उद्योगपतियों की करते हैं. एक आम आदमी को क़र्ज़ देने में बैंक तमाम परेशानियां खड़ी करता है. अगर क़र्ज़ दे भी दे तो समय से अदायगी न होने पर उसकी संपत्ति कुर्क करा देता है, वहीं माल्या जैसे उद्योगपति क़र्ज़ नहीं चुका पाते तो उनकी पैरवी सभी दलों के नेता से लेकर प्रधानमंत्री तक करते हैं. यह प्रचलन ठीक नहीं है.

–अवनीश शुक्ल, *गोंडा, उत्तर प्रदेश.*

मुसलमानों को ख़ुश करने की कोशिश

लगभग सभी पार्टियां मुसलमानों को ख़ुश करने में लगी हैं. कांग्रेस ने भी अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की बात कही है. अल्पसंख्यकों में मुसलमानों की संख्या अधिक है, इसलिए सभी पार्टियां उनकी चिंता ज़्यादा करती हैं. वैसे आज सवर्णों को छोड़कर लगभग सभी जातियों को आरक्षण प्राप्त है. आरक्षण का मतलब पार्टियों ने बदल दिया है.

–अरुण कुमार सरोहा, *नई दिल्ली.*

अंत में

भला विचारा कभी
हम क्या थे और क्या हो गए,
स्वार्थ की प्रतिस्पर्धा ऐसी जगी
परहित भूल, अलमस्त हो खो गए,
न फ़िक्र की समाज की
किसी के दु:ख से न रहा कोई वास्ता,
फंसकर छल–कपट के जंगल में
बहाया अपनों का लहू,
चुना बर्बादी का रास्ता,
तिल भर सौहार्द्र न बचा हृदय में
भला किसने रचा यह परिवेश,
तुम ख़ुद बदल गए हो
और कहते हो बदल गया है देश.

–संतोष कुमार प्यासा

राजकमल प्रकाशन समूह

1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110 002
फोन 011-23274463, 23288769, फैक्स 011-23278144
www.rajkamalprakashan.com Email : info@rajkamalprakashan.com
शाखा : अशोक राजपथ, पटना-800006 फोन 0612-2672280
पहली मंजिल, दरबारी बिल्डिंग, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-211001 फोन 0532-3293838, 2427274

लेखन विद्या सम्मान 2011

'चौथी दुनिया' में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को दी जानेवाली 700 रुपए की किताबें

देश के जाने-माने पत्रकार एवं 'चौथी दुनिया' के सम्पादक संतोष भारतीय के संपादन में प्रकाशित 'दलित अल्पसंख्यक सशक्तीकरण' के वैश्विक प्रयासों का तथ्यात्मक दस्तावेज। यह पुस्तक प्रमाणित करती है कि दुनिया भर के गरीब, दबे-कुचले और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग समूहबद्ध होकर यदि शक्तिसम्पन्न होने का संकल्प लें तो वैश्विक स्तर पर बड़े बदलाव सामने आएँगे।

राजकमल प्रकाशन समूह की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें
हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी
हेल्पलाइन : 09311196029

पाठक पूरे नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएँ इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ- 2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश), पिन - 201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

देश के पांच राज्यों में एक साथ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. इसे कांग्रेस की क़िस्मत कहें या कुछ और कि इनमें से तीन राज्यों में वह सत्ता में नहीं है.

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

निराशा पैदा करने वाला फ़ैसला

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का सभी सम्मान करेंगे. आख़िर यह भारत के सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, लेकिन इस फ़ैसले से उन लोगों को निराशा हुई, जो ईमानदारी में यक़ीन रखते हैं. देश का सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि हमें ईमानदारी और इंटीग्रिटी से कोई मतलब नहीं है तो फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या देश ईमानदारी छोड़ दे, क्या इस देश में उन्हीं लोगों की सुनी जाएगी, जो भ्रष्ट या बेईमान हैं? शायद कहीं चूक हुई है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट से यह आशा करनी चाहिए कि वह एक बड़ी बेंच बनाकर अपने फ़ैसले की समीक्षा करे. हो सकता है कि हमारी अपेक्षा पूरी न हो, क्योंकि हम आम आदमी हैं और आम आदमी की अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होतीं. व्यवस्था आम आदमी के ख़िलाफ़ खड़ी होती है और सुप्रीम कोर्ट भी व्यवस्था का ही एक अंग है.

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया. शायद वे ध्यान देने योग्य बातें न हों, लेकिन फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट और जनता के सामने कुछ तथ्य रखना चाहते हैं. आर्मी हॉस्पिटल में पैदाइश की तारीख़ लिखी है, क्या उस पैदाइश की तारीख़ का कोई मतलब नहीं है. आर्मी हॉस्पिटल में क्या इतनी बड़ी जालसाज़ी चलती है कि रिकॉर्ड में आदमी पैदा हो और उसके एक साल पहले पैदा होने का रिकॉर्ड दर्ज कर दिया जाए. मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला यह कहता है कि जनरल वी के सिंह की जन्म की तारीख़ जो आर्मी हॉस्पिटल में लिखी है, वह उससे एक साल पहले पैदा हो गए. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ध्यान देना उचित नहीं समझा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फ़ैसले को उलट दिया और कहा कि उसे हाईस्कूल के प्रमाणपत्र से कोई मतलब नहीं है और अगर अनजाने में या ग़लती से क़लम से कुछ लिख दिया जाता है तो वही लिखा और वही आख़िरी माना जाएगा. इसका नतीजा शायद यह होगा कि देश में बहुत सारे लोग, जो रिटायर होने वाले हैं, वे एफिडेविट देकर कहेंगे कि हमने ग़लती से वह तारीख़ लिख दी थी...दरअसल हमारी जन्मतिथि यह है, इसे ही जन्मतिथि मान लिया जाए.

सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, न्याय का आख़िरी स्थान. बहुत सारे लोग होते हैं, जिन्हें न्याय नहीं मिलता और बहुत सारे लोग होते हैं, जिनके साथ अन्याय होता है. जनरल वी के सिंह के मामले में भी शायद ऐसा ही है. उन्हें न्याय नहीं मिला और उनके साथ अन्याय हो गया. वह सरकार के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट गए थे और जब सुप्रीम कोर्ट यह कहे कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम चाहते हैं कि आप मामले को आपस में शांतिपूर्वक, परस्पर सौहार्द्र के साथ तय कर लें. अगर यह मामला पहले तय हो जाता सौहार्द्रपूर्ण ढंग से, तो पहले ही वी के सिंह इस मसले को हल कर लेते. लेकिन जब सरकार ने उनकी नहीं सुनी, तभी वह सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बता दिया कि अगर आपका भारत सरकार के साथ कोई विवाद है तो आज के बाद हमारे पास मत आइए, क्योंकि हम सरकार के ख़िलाफ़ कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं. हम आपसे कहेंगे कि आप इत्मीनान से आपस में मसला सुलझाएं. अगर आप नहीं सुलझाएंगे तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी.

सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, न्याय का आख़िरी स्थान. बहुत सारे लोग होते हैं, जिन्हें न्याय नहीं मिलता और बहुत सारे लोग होते हैं, जिनके साथ अन्याय होता है. जनरल वी के सिंह के मामले में भी शायद ऐसा ही है. उन्हें न्याय नहीं मिला और उनके साथ अन्याय हो गया. वह सरकार के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट गए थे और जब सुप्रीम कोर्ट यह कहे कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम चाहते हैं कि आप मामले को आपस में शांतिपूर्वक, परस्पर सौहार्द्र के साथ तय कर लें. अगर यह मामला पहले तय हो जाता सौहार्द्रपूर्ण ढंग से, तो पहले ही वी के सिंह इस मसले को हल कर लेते.

अब इस बात को क्या कहा जाए. हमें दु:ख प्रकट करने का कोई हक़ तो नहीं है, क्योंकि यह न्याय का फ़ैसला है, लेकिन न्याय के इस फ़ैसले ने निराशा बढ़ाई है और हम अपील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट से यह कह सकते हैं कि वह इस मसले को दोबारा सुने, क्योंकि इस फ़ैसले के साथ न केवल सेना, बल्कि आम नागरिकों के बीच जो ईमानदार छवि वाले लोग हैं, उनकी आशाएं जुड़ी थीं, जो टूट गईं. ऐसे में अब लोगों का यह कहना कि हम क्यों ईमानदार रहें, शायद ज़्यादा तर्कपूर्ण लगता है. जनरल वी के सिंह से हमें हमदर्दी है. हमदर्दी इसलिए है कि उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी और न्याय की लड़ाई लड़ने वाले बहुत सारे लोग हारते हैं. गैलीलियो हारा था, क्योंकि उसने कहा था कि दुनिया गोल है, लेकिन उस समय की अदालत, उस समय के न्यायविदों और उस समय के मनीषियों ने कहा कि यह पागल हो गया है. दुनिया तो चपटी है, क्योंकि आंख जहां तक देखती है, दुनिया कहीं गोल नज़र नहीं आती, चपटी नज़र आती है. सुकरात को ज़हर पीना पड़ा, गांधी को गोली खानी पड़ी और जय प्रकाश नारायण के गुर्दे डॉक्टरों ने इमरजेंसी के दौरान ख़राब कर दिए. इसका क्या मतलब है?

इसका मतलब यह है कि सच की राह पर चलना मुश्किल होता है. ईमानदारी की राह पर चलना आज के ज़माने में बहुत सही चीज़ नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि हमें इंटीग्रिटी से, ईमानदारी से कोई लेना-देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है. आप होंगे ईमानदार! इसके बावजूद सच्चाई यह है कि ईमानदार होना चाहिए, हमें सच की राह पर चलना चाहिए, हमें किसी को दु:ख नहीं देना चाहिए और यह भी सच है कि हमें हमेशा न्यायपूर्ण रास्तों पर चलना चाहिए, भले ही कोई कहे कि ईमानदारी से उसे मतलब नहीं है. इसलिए हम जनरल वी के सिंह और उनके जैसे तमाम लोगों से अपेक्षा करेंगे कि वे हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलें और इस देश में ऐसे लोगों को खड़ा करने में अपनी भूमिका अदा करें. उन लोगों की ऐतिहासिक भूमिका, जो देश में ईमानदारी का शासन, ईमानदारी का राज्य चाहते हैं.

हमें मालूम है और हमने पहले भी कहा था कि व्यवस्था के वे लोग जो बेईमानों का साथ देते हैं, जो अन्याय का साथ देते हैं, वे हमारे ख़िलाफ़ भी अब हथियार उठाएंगे. हम उनके हथियार उठाने का इंतज़ार कर रहे हैं और हम गैलीलियो, सुकरात, गांधी और जय प्रकाश नारायण के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं. उनका जो अंजाम हुआ, वह अंजाम भी हम सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ईमानदारी, सत्यता, भरोसा और विश्वास का संबल छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं. आख़िर में फिर सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध है और ख़ासकर मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध है कि कृपा करके आप बड़ी बेंच बनाकर अपनी तरफ़ से इस फ़ैसले की पुनर्समीक्षा करें और देश को एक सही राह दिखाने के लिए अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाएं.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

भारत यानी डॉ. जैकेल और मिस्टर हाइड

पाकिस्तान भारत की तरह किस मायने में समान है? इसमें कोई शक नहीं कि वह क्रिकेट में बेहतर है. इंग्लैंड से हुए मुक़ाबले में उसे जीत मिली, जबकि ऑस्ट्रेलिया में भारत का सूपड़ा साफ़ हो गया. जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है तो निश्चित तौर पर वह भी भारत के सुप्रीम कोर्ट की तरह अच्छा है. पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट वहां के लोकतंत्र का सजग प्रहरी है, वरना पाकिस्तान में लोकतंत्र कभी भी कुचला जा सकता है. भविष्य में भी सुप्रीम कोर्ट ऐसी ही भूमिका निभाएगा, ऐसी आशा है. संवैधानिक रक्षा के लिए वहां का सुप्रीम कोर्ट निर्णायक भूमिका निभा रहा है और क़ानूनी लड़ाई लड़ रहा है. वहीं भारत में सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के ग़लत कृत्यों की आलोचना कर रहा है, साथ ही राज्य सरकारों के कामकाज की भी देखरेख कर रहा है.

यह सही बात है कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिस पर सभी को गर्व है. इस देश में भी कई विसंगतियां देखने को मिल रही हैं. वैसे मुस्लिम नज़रिए से इसे एक उदारवादी देश माना जाता है. यहां एक निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव आयोग है, जिसकी हरसंभव कोशिश यह रहती है कि चुनावी प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो. वहीं हमारे राजनीतिक दल संसद और उसके बाहर अपनी बातें रखते हैं. यहां का मीडिया भी कमोबेश स्वतंत्र और भयमुक्त है. यह डॉ. जैकेल का इंडिया है. यहां हमने देखा कि आधार योजना को लेकर किस क़दर रस्साकशी हुई,

आज़ादी के बाद के वर्षों में भारत भ्रष्ट होता चला गया. पहले भ्रष्टाचार को एक समस्या माना जाता था, लेकिन अब नहीं. विदेशी भी भारत में भ्रष्टाचार को एक बड़ी समस्या मानते हैं, लेकिन वे फिर भी यहां निवेश करते हैं. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वजह से ही 2-जी घोटाला सामने आया.

फिर प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद उसका दोस्ताना हल निकाला गया. इसके बाद हमने देखा कि किस तरह प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा प्रधानमंत्री के लिए मीडिया सलाहकार के तौर पर एक व्यक्ति की नियुक्ति हुई और पुराने आदमी को पीएमओ से बाहर का रास्ता दिखाया गया.

दूसरी ओर हाइड के भारत में हमने यह भी देखा कि 2-जी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को किस तरह हज़म करने की कोशिश की गई. सुंदर चेहरे के पीछे की वास्तविकता कैसी होती है, इसे गहराई से समझने की ज़रूरत है. सत्ता में कुछ भी ग़लत नहीं होता, तभी तो यह खुला रहस्य है कि द्रमुक और अन्नाद्रमुक जब भी केंद्र में किसी गठबंधन सरकार में शामिल होते हैं तो वे हमेशा मलाईदार मंत्रालयों को अपने खाते में लेने के लिए ज़ोर देते हैं. ए राजा क्या कर रहे थे, यह किसी के लिए कोई रहस्य नहीं था. बात यहीं ख़त्म नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह टेलीकॉम लाइसेंस के आवंटन में ढिलाई बरतने के लिए पीएमओ को खरी-खोटी सुनाई, साथ ही इसरो प्रमुख और सेना प्रमुख के जन्मतिथि विवाद का हालिया प्रकरण देखने को मिला, उनसे कई सवाल पैदा होते हैं. भ्रष्टाचार के मामले पर किसी भी एक दल को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. देश के पांच राज्यों में एक साथ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. इसे कांग्रेस की क़िस्मत कहें या कुछ और कि इनमें से तीन राज्यों में वह सत्ता में नहीं है. यही वजह है कि वहां मौजूदा सरकार के ख़िलाफ़ कांग्रेस भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है. भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, सरकारें इसे नकार नहीं सकतीं. कोई भी सत्ताधारी पार्टी हो, उसे अपनी भ्रष्ट सरकार के ख़िलाफ़ मुंह खोलना चाहिए. अफ़सोसजनक बात यह है कि देश में किसी तरह चुनाव जीतना ही बड़ी चीज़ रह गई है. हर चुनाव में हर पार्टियां जाति का कार्ड खेलती हैं. किस उम्मीदवार पर क्या आरोप हैं, इसकी चिंता किसी को नहीं है. पार्टियां विकास को लेकर कितनी गंभीर हैं, यह पूछा जाना ज़रूरी है. चुनाव के समय हर दल में भगदड़ की हालत होती है, भगोड़ों का स्वागत हर पार्टियों में होता है. ख़ासकर टिकट बंटवारे के समय हालत कुछ अलग होती है. इन चुनावों में जमकर काले धन का इस्तेमाल होता है. काले धन का इस्तेमाल करने वाले अक्सर चुनाव आयोग द्वारा पकड़े जाते हैं. किसी भी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है और संभावित मुख्यमंत्री का चुनाव पूरी तरह शीर्ष नेतृत्व के लिए छोड़ दिया जाता है.

आज़ादी के बाद के वर्षों में भारत भ्रष्ट होता चला गया. पहले भ्रष्टाचार को एक समस्या माना जाता था, लेकिन अब नहीं. विदेशी भी भारत में भ्रष्टाचार को एक बड़ी समस्या मानते हैं, लेकिन वे फिर भी यहां निवेश करते हैं. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वजह से ही 2-जी घोटाला सामने आया. पिछले दिनों हुआ सत्यम घोटाला भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में उजागर हुआ, न कि इसे उजागर करने के पीछे आंध्र प्रदेश सरकार और कोई केंद्रीय संस्था थी. कुछ लोगों का मानना है कि एफडीआई समस्या है, न कि स्थानीय भ्रष्टाचार. भारत में हुए उदारीकरण और आर्थिक नीतियों से यह भ्रष्टाचार पनपा है. राष्ट्रमंडल घोटाले का पर्दाफ़ाश अधिकारियों द्वारा ब्रिटेन में किया गया था, जब एक कंपनी वैट की छूट हासिल करने के लिए तिकड़म कर रही थी. इसमें कोई शक नहीं कि 121 टेलीकॉम कंपनियों का लाइसेंस रद्द करने के फ़ैसले ने भारत की छवि अच्छी बनाई है. यहां विदेशी लोग अपना व्यापार कर सकते हैं. साथ ही यह भी साबित हो गया कि पूंजीवादी ताक़तों ने किस तरह इन्हें लाइसेंस दिलाने के लिए पूरी ताक़त झोंक दी थी. ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है.

feedback@chauthiduniya.com

बचपन में जो बच्चा अपनी मां से जितना ही ज़्यादा जुड़ा होता है, वह अपनी युवावस्था में संबंधों में आई खटास आसानी से दूर कर पाता है.

चौथी दुनिया
दिल्ली, 20 फरवरी–26 फरवरी 2012

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

संसदीय विशेषाधिकार और आरटीआई के बीच क्या संबंध है

सूचना क़ानून का इस्तेमाल करने वाले आवेदकों ने तीसरे पक्ष और न्यायालय की अवमानना जैसे शब्दों का कई बार सामना किया होगा, क्योंकि इन्हीं शब्दों की आड़ में कई बार सूचना देने से मना कर दिया जाता है. कभी–कभी सूचना न देने के पीछे जो वजह बताई जाती है, वह सही होती है, लेकिन कई बार इन तकनीकी शब्दों का बेजा इस्तेमाल भी सूचना अधिकारियों द्वारा किया जाता है. ऐसे में आरटीआई क़ानून का इस्तेमाल करने वालों के लिए इन तकनीकी शब्दों और इनके उपयोग की सही जानकारी होना ज़रूरी है. पिछले कुछ अंकों में हमने तीसरे पक्ष और न्यायालय की अवमानना के बारे में बताया है. इस अंक में हम आपको ऐसे ही एक और शब्द से परिचित करा रहे हैं. इस बार हम बात करेंगे संसदीय विशेषाधिकार के बारे में. कैसे और कब फंसता है संसदीय विशेषाधिकार का पेंच? सबसे पहले एक उदाहरण से इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं. अमेरिका से एटमी डील के दौरान यूपीए सरकार को जब सदन में विश्वास मत हासिल करना था, उसके कुछ घंटे पहले सदन में भारत के संसदीय इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना घटित हुई. भाजपा के तीन सांसदों ने सदन में नोटों की गड्डियां लहराते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि ये नोट उन्हें विश्वास मत के दौरान सरकार के पक्ष में वोट देने के लिए रिश्वत के रूप में मिले हैं. इसे एक टीवी चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान अपने कैमरे में कैद कर लिया था और लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी को सौंप दिया था. बाद में कुछ ग़ैर सरकारी संगठनों एवं लोगों ने जब सूचना अधिकार क़ानून के तहत आवेदन करके उक्त वीडियो टेप सार्वजनिक करने की मांग की तो लोकसभा ने ऐसा करने से मना कर दिया. लोकसभा ने कहा कि वीडियो टेप अभी संसदीय समिति के पास है और जांच की प्रक्रिया चल रही है. जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक इस सूचना के दिए जाने से धारा 8 (1)(सी) का उल्लंघन होता है. इस धारा में कहा गया है कि ऐसी सूचना, जिसके सार्वजनिक किए जाने से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकारों का हनन होता है, उसे सूचना अधिकार क़ानून के तहत दिए जाने से रोका जा सकता है. ऐसा ही एक मामला और है, जिसमें वर्तमान केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेष गांधी ने महाराष्ट्र के सामान्य प्रशासनिक विभाग से मुख्यमंत्री राहत कोष में मुंबई ट्रेन धमाकों के बाद प्राप्त अनुदानों के ख़र्चों का ब्योरा मांगा था. सूचना यह कहकर देने से मना कर दी गई कि मुख्यमंत्री राहत कोष एक निजी ट्रस्ट है और वह सूचना क़ानून के दायरे में नहीं आता. जबकि शैलेष का मानना था कि राहत कोष एक पब्लिक बॉडी है और वह आयकर छूट का लाभ उठाता है. मुख्यमंत्री जनता का सेवक होता है, इसलिए यह सूचना दिए जाने से विधानमंडल के विशेषाधिकारों का हनन नहीं होता है.

एक मासिक पत्रिका से जुड़े रमेश तिवारी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष एवं सचिव के पास एक आवेदन किया था. आवेदन के माध्यम से उन्होंने यह जानना चाहा था कि क्या कोई विधायक ख़ुद कोई सरकारी ठेका ले सकता है और यदि ऐसा किया गया है तो क्या ऐसे सदस्य की विधानसभा से सदस्यता रद्द की जा सकती है? जब रमेश तिवारी को विधानसभा से कोई जवाब नहीं मिला तो वह मामले को राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष ले गए. आयोग के तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त एम ए ख़ान ने विधानसभा अध्यक्ष एवं सचिव को सूचना अधिकार क़ानून के तहत नोटिस जारी कर दी. नोटिस पाते ही सबसे पहले तो रमेश का आवेदन ख़ारिज कर दिया गया और उसके बाद विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पारित किया गया, जिसके माध्यम से सूचना आयोग को चेतावनी दी गई कि उसका इस मामले से कोई लेना–देना नहीं है और इस तरह की सूचना मांगने और आयोग द्वारा नोटिस भेजे जाने से विधानमंडल के विशेषाधिकारों का हनन होता है. आयोग को आगे से ऐसे मामलों में सावधान रहने की चेतावनी दी गई. राहुल विभूषण ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और तीन सांसदों के बीच हुए पत्र व्यवहार की प्रतिलिपि मांगी थी. दरअसल एक पेट्रोल पंप को अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण बंद कर दिया गया था. इस पेट्रोल पंप को दोबारा खुलवाने के लिए तीन सांसदों ने पेट्रोलियम मंत्री को पत्र लिखा था. राहुल ने इस पत्र के जवाब की प्रतिलिपि मांगी थी, जिसे यह कहकर देने से मना कर दिया गया कि ऐसा करने से संसद के विशेषाधिकारों का हनन होता है. आयोग में सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त ने माना कि सांसद द्वारा लिखे गए पत्र का संसद या संसदीय कार्रवाई से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और इस सूचना के सार्वजनिक किए जाने से संसद के किसी विशेषाधिकार का कोई हनन नहीं होता. आयुक्त ने मांगी गई सूचना 15 दिनों के भीतर आवेदक को दिए जाने का आदेश दिया. कुल मिलाकर देखें तो ज़्यादातर मामलों में लोक सूचना अधिकारी संसदीय विशेषाधिकारों की आड़ में सूचना देने से मना कर देते हैं, जबकि वास्तव में वह मामला संसदीय विशेषाधिकार से जुड़ा नहीं होता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन –201301
ई–मेल : rti@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

बुढ़ापे का केमिकल लोचा

आम तौर लोगों की राय यह है कि बुद्धिमत्ता ज़्यादातर आनुवांशिक होती है, लेकिन बुढ़ापे में भी किसी शख्स के तेज एवं बुद्धिमान बने रहने में जीन और उसके आसपास के माहौल का असर शामिल होता है. 45 वर्ष की उम्र से हमारा दिमाग़ ख़राब होना शुरू हो जाता है. एक अध्ययन में यह बात सामने आई है. बुढ़ापे में दिमाग़ तेज रखने में जीन और परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. पूर्व में अलग–अलग परिवेश में बड़े हुए जुड़वां बच्चों या एक ही माता–पिता की संतानों पर यह अध्ययन किया गया. पाया गया कि इनमें बुद्धिमत्ता का आनुवांशिक तत्व होता है,

लेकिन यह जीवनपर्यंत कैसे बदलता है, यह पता नहीं था. ब्रिटेन के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में किए गए नवीनतम शोध में पता चला है कि जीन और परिवेश के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि उम्र के साथ कैसे बदलती है. लाइव साइंस पत्रिका के अनुसार, शोधकर्ताओं के दल के प्रमुख इयान डियरी ने कहा कि ये परिणाम बताते हैं कि उम्र के बढ़ते जाने के साथ बुद्धिमत्ता पर परिवेश और जीन का असर पड़ता है. उन्होंने बताया कि शोधकर्ताओं ने स्कॉटलैंड के 1,940 लोगों के बुद्धि स्तर की 11 वर्ष की उम्र में जांच की थी. हाल में उनके बुद्धि स्तर की जांच तब की गई, जब उनकी उम्र 65 से 79 वर्ष हो गई. शोधकर्ताओं ने कहा कि इन व्यक्तियों के जीन का उनकी बुद्धि पर प्रभाव पड़ा था, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ परिवेश के अनुसार भी उनकी बुद्धिमत्ता में बदलाव आया. बुद्धि स्तर का 25 प्रतिशत जीन के अनुसार बदलता है, बाक़ी परिवेश के अनुसार. परिवेश के अनुसार कुछ लोगों का बुद्धि स्तर बेहतर हो जाता है और कुछ का कम.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राजनीति, बीयर और ...

यह शोध संस्कृति से जुड़ा है. प्राचीन मेसोपोटामियाई सभ्यता के लोगों की दैनिक गतिविधियों में सेक्स, राजनीति और बीयर पीना उच्च प्राथमिकता के विषय थे. लगभग 3,500 वर्ष पुराने एक शिलापट्ट के अनुवाद के ज़रिए इस बात का पता लगाया गया है, जिस पर मेसोपोटामियाई सभ्यता के लोगों के दैनिक जीवन से संबंधित पहेलियां लिखी हैं. इस लिखावट को देखकर लगता है कि संभवत: किसी विद्यार्थी ने इसे लिखा है. ग़ौरतलब है कि मेसोपोटामिया को सभ्यताओं की जननी माना जाता है. अनुवाद करने वाले शोधार्थियों ने बताया कि इसे कीलाक्षर लिपि का इस्तेमाल करके अक्कादी भाषा में लिखा गया है, जिसे बेबिलोनियाई सभ्यता के लोग इस्तेमाल करते थे. लाइव साइंस ने हीब्रू विश्वविद्यालय के पुरातत्व विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर एवं शोधकर्ता नाथन वास्सरमैन के हवाले से बताया कि यह एक दुर्लभ रचना है. उनके जीवन के अनेक पहलू ऐसे हैं, जिन्हें हम आज भी अपनाते हैं. उस समय के दैनिक जीवन में जो उच्च प्राथमिकता थी, वह आज समाज की बुराई है, लेकिन समाज उसे बढ़–चढ़ कर अपनाता है.

रोमांस का जीन

अगर आप बहुत रोमांटिक हैं तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आपके माता–पिता भी बहुत रोमांटिक रहे होंगे. मां–बेटे के बचपन का संबंध बच्चे की युवावस्था में उसके रोमांटिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है. एक नए शोध के मुताबिक़, इस संबंध का प्रभाव अक्सर सकारात्मक होता है, लेकिन कई बार यह बच्चे के लिए परेशानी का सबब बन जाता है. यूनिवर्सिटी ऑफ मिनिसोटा में मनोविज्ञान के प्रोफेसर एवं शोधकर्ता जेफ्री सिम्पसन का कहना है कि बचपन में जो बच्चा अपनी मां से जितना ही ज़्यादा जुड़ा होता है, वह अपनी युवावस्था में संबंधों में आई खटास आसानी से दूर कर पाता है. इसलिए वह एक स्थिर रिश्ते को निभाने में सफल हो पाता है. लाइव साइंस में प्रकाशित इस शोध के मुताबिक़, अगर बेटा मां पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहता हो तो इसका असर काफी ख़राब होता है. ऐसे में उसके लिए युवावस्था में रोमांटिक जीवन जीना मुश्किल होता है और उसे अपने संबंधों में आई किसी भी प्रकार की समस्या सुलझाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

राशिफल

मेष 21 मार्च से 20 अप्रैल

आपकी सामाजिक-व्यवसायिक प्राथमिकताएं बदल सकती हैं. राजनीति या समाजसेवा दो ऐसे क्षेत्र हैं, जहां आपकी राशि को दिन दूनी-रात चौगुनी उन्नति मिलती है. यदि आप किसी संगठन से जुड़े हैं तो अच्छी बात है. इन दिनों आपके लिए कई मौक़े ऐसे आ रहे हैं, जहां फिट होकर आप अपना जीवन-ध्येय पूरा कर सकते हैं.

वृष 21 अप्रैल से 20 मई

इस सप्ताह ग्रह योग आपके काम में कुछ अड़ंगा डाल सकते हैं या फिर किसी अटकलबाज़ी-अफवाह के कारण आप अपने लक्ष्य से पीछे हट जाएं. इस प्रकार अगर उत्साह भंग होता गया तो आपकी प्रगति रुक जाएगी और विरोधी प्रसन्न होंगे. विरोधियों का सिर नीचा करने के लिए अपनी क्रियाशीलता क़ायम रखें.

मिथुन 21 मई से 20 जून

यह सप्ताह कर्मठता दिखाने का अवसर देगा. मंजिल पर पहुंच कर भी आप कभी-कभी ख़ुद को बहुत पीछे महसूस करेंगे. फासला तय करने में अभी एक सांस की दौड़ और लगानी है. आप तत्काल कमर कस लें और बचे काम जल्दी संपन्न कर लें. आलस्य-आशंका का त्याग करके कम साधनों में भी जंग जीती जा सकती है.

कर्क 21 जून से 20 जुलाई

आप हमेशा दूसरों के भरोसे बैठकर अपने लिए कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं. किसी दूसरे के प्रयासों पर स्वयं लाभ उठाना बहुत दिनों तक जारी नहीं रहेगा. एक न एक दिन आपको अपने लिए परिश्रम करना पड़ेगा. व्यवसायिक स्थितियां अनुकूल हैं, आप थोड़ा-बहुत भी जोर लगाएंगे तो आपके लिए काम करने वाले बहुत हैं.

सिंह 21 जुलाई से 20 अगस्त

अर्से से आप किसी संत, महात्मा, दार्शनिक और धार्मिक विचारों पर अच्छी तरह गौर कर रहे हैं. आपके विचार गंभीर होते जा रहे हैं. कोई काम बिगड़ने या विलंब होने पर आपको खीझ नहीं होती. ऐसा आपके ग्रहों के संचार बदलाव से हो रहा है या फिर कोई शुभ ग्रह आपको प्रेरित कर रहा है, लेकिन यह अच्छा है.

कन्या 21 अगस्त से 20 सितंबर

आप अपने कार्यक्षेत्र में परिवर्तन आने से कभी घबराते नहीं हैं, लेकिन इस सप्ताह वरिष्ठ अधिकारी या व्यवस्था की तरफ से कुछ ऐसे बदलाव आ रहे हैं, जिनसे आपकी हिम्मत जवाब दे रही है. सगे-संबंधियों से संपर्क करते रहें. हो सकता है, कोई ऐसा ऑफर आ जाए जो एक नया कार्यक्षेत्र हो.

तुला 21 सितंबर से 20 अक्टूबर

इस सप्ताह आपको संभल कर चलना होगा. कार्यक्षेत्र में हमेशा दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए. कभी-कभी अपनी शर्तों पर काम करने की कोशिश करनी चाहिए. हो सकता है, सही समय पर काम की शुरुआत करने से आपकी व्यग्रता-तनाव अपने आप घट जाए.

वृश्चिक 21 अक्टूबर से 20 नवंबर

काफी समय बाद कोई अच्छी ख़बर आपको मिलेगी. कोई ज़रूरी काम बन जाने से लाभदायक अवसरों की प्राप्ति होगी. कहीं पर आपका रुका हुआ धन भी हाथ में आ जाएगा. जिस रखरखाव के काम को आप कई दिनों से नहीं कर पा रहे थे, उसे ठीक करने में किसी का सहयोग चमत्कारी सिद्ध होगा.

धनु 21 नवंबर से 20 दिसंबर

आपके अथक प्रयास इस सप्ताह रंग ला रहे हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और कई दिनों बाद आपके चेहरे पर रौनक नज़र आएगी. अधीनस्थों-सहयोगियों के प्रति आपका व्यवहार उदारतापूर्ण होगा और उनकी गलतियों को आप माफ करने के लिए तैयार हो जाएंगे.

मकर 21 दिसंबर से 20 जनवरी

इस सप्ताह आप कई प्रकार की उलझनों से ग्रस्त रहेंगे. कार्यक्षेत्र में काम का दबाव ज़्यादा रहेगा. आपका वाहन भी समय पर साथ नहीं देगा. ऐसे में आपकी अपनी सूझबूझ और इच्छाशक्ति बहुत काम आएगी. थोड़े से समय में सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी .

कुंभ 21 जनवरी से 20 फरवरी

इन दिनों मित्रों-प्रियजनों के लिए आप कुछ ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं. अपने काम छोड़कर आप दूसरों के साथ अपना क़ीमती वक़्त बर्बाद कर लेते हैं. अब आपको अपने बारे में ज़्यादा सोचना है. नई ज़िम्मेदारी लेने से पीछे न हटें. कामकाज की स्थिति अनुकूल हो रही है.

मीन 21 फरवरी से 20 मार्च

कुछ भावनात्मक और दिल से जुड़े प्रसंग सामने आएंगे. आपकी करुणा और उदारता कहीं-कहीं आपके लिए भारी पड़ जाती है. यदि किसी प्रकार की न्याय नीति का मामला हो या क़ानूनी दायरे में कुछ कर दिखाने की इच्छा हो तो आपके पास एक ठोस योजना रहती है. दूसरों की मदद के लिए आप अपने निजी हित भी त्याग देते हैं.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

यह पहली बार हुआ कि पाकिस्तान से इतना बड़ा प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश आया, जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों में भी काफ़ी उत्साह था.

भारत-पाकिस्तान

अमन क़ायम करने की मुहिम

रोमा

इस समय पाकिस्तान पर फ़ौजी हुकूमत द्वारा सत्ता पलट के साये बुरी तरह मंडरा रहे हैं. पाकिस्तान क्या अपने देश में लोकतंत्र की बलि चढ़ाएगा, यह तो आने वाला वक़्त ही बताएगा. पिछले दिनों पाकिस्तान–इंडिया फोरम फोर पीस एंड डेमोक्रेसी द्वारा दोनों देशों की जनता के प्रतिनिधियों ने अमन और दोस्ती का पैग़ाम देते हुए एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया. इस घोषणा पत्र का आधार दोनों देशों में ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में लोकतंत्र को मज़बूत करना और नवउदारवादी नीतियों के तहत जो तबाही अंतरराष्ट्रीय सम्राज्यवादी पूंजी द्वारा की जा रही है, उसे रोकने का प्रयास करना है.

इलाहाबाद में आयोजित संयुक्त अधिवेशन में पाकिस्तान के कई इलाक़ों सिंध, ब्लूचिस्तान, कश्मीर, पंजाब, पेशावर, इस्लामाबाद से आए क़रीब 200 प्रतिनिधियों ने शिरकत की. पाकिस्तान–इंडिया फोरम फोर पीस एंड डेमोक्रेसी द्वारा आयोजित यह आठवां अधिवेशन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आम नागरिकों के बीच संवाद स्थापित करने व कूटनीतिक दायरों से ऊपर उठकर दोनों देशों में अमन और जनवाद को स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था. यह मंच दोनों देशों के आम नागरिकों द्वारा सन् 1994–95 में शुरू किया गया था. इसके सदस्य दोनों देशों में हैं, जो दोनों देशों में अमन क़ायम करने की मुहिम छेड़े हुए हैं. पिछला अधिवेशन सन् 2005 में आयोजित किया गया था. इस आधिवेशन और पिछले अधिवेशन के बीच पांच साल का अंतराल रहा. इस लंबे अंतराल का मुख्य कारण इन सालों में मुंबई आतंकी हमलों के चलते दोबारा से अविश्वास और दुश्मनी का माहौल पैदा होना रहा था. साथ ही इस दौरान पाकिस्तान के अंदर ओसामा और तालिबान को लेकर राजनीतिक परिस्थितियों का गड़बड़ाना था. जो रिश्ते 12 साल पहले कुछ संभले थे, वे काफ़ी हद तक बिगड़ गए थे. हालांकि इन रिश्तों में अभी भी सुधार नहीं हुआ है, लेकिन इसी तरह के माहौल में ही मंच के काम करने की ज़्यादा ज़रूरत थी. पांच साल बाद ही सही, फिर भी मंच द्वारा उठाया गया यह क़दम सराहनीय है.

मौजूदा दौर में पाकिस्तान के हालात के मद्देनज़र इस अधिवेशन पर अनिश्चितता के काले बादल मंडरा रहे थे, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में सरकार और फ़ौज के बीच ठनी हुई है, उससे वहां फ़ौजी हुकूमत क़ायम होने के पूरे आसार बने हुए थे. इसके कारण पाकिस्तान से 200 प्रतिनिधियों के भारत आने में काफ़ी अनिश्चितता थी. लेकिन समय पर हालात सामान्य हो जाने की वजह से 200 लोगों को पाकिस्तान से भारत आने की अनुमति मिली और आख़िरी समय पर वीज़ा मिल जाने से सब लोग काफ़ी उत्साहित थे. यह पहली बार हुआ कि पाकिस्तान से इतना बड़ा प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश आया, जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों में भी काफ़ी उत्साह था. इस प्रतिनिधि मंडल ने अमृतसर से इलाहाबाद का सफ़र मूरी एक्सप्रेस से लगभग 36 घंटों में तय किया. घने कोहरे के कारण गाड़ी पंहुचने में देरी होने पर भारतीय मेज़बान इलाहाबाद स्टेशन पर उनका बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे. जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो जिस तरह से नाचते हुए पाकिस्तान के साथियों का स्वागत हुआ वह देखते ही बनता था. पूरे स्टेशन का माहौल जश्न के रूप में बदल गया. इलाहाबाद में इस कार्यक्रम का पूरा आयोजन पाकिस्तान इंडिया पीपुल्स फोरम फोर पीस एंड डेमोक्रेसी ने ही किया. इसमें इलाहाबाद के कई सामाजिक संगठन, रंगकर्मी, साहित्यकार, प्रगतिशील लेखक संघ, स्त्री अधिकार संगठन आदि शामिल रहे. पाकिस्तान से इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने की किसी को उम्मीद नहीं थी, यहां तक आयोजकों को भी नहीं. पाकिस्तानी प्रतिनिधियों से मिलकर इस आयोजन में शामिल आम लोग भी बहुत प्रभावित हुए. वहां से आए मुनीब हक़ ने कहा कि जब वह किसी भी देश में जाते हैं, तो उनके बच्चे काफ़ी ख़ुश होते हैं, लेकिन भारत आने की बात से वे काफ़ी चिंतित थे. उन्होंने कहा कि अब वह अपने बच्चों को बताएंगे कि हिंदुस्तान में उनको कितना प्यार मिला और जहां कोई दुश्मनी नज़र नहीं आई. उस समय माहौल भावुक हो उठा, जब दोनों देशों से आए प्रतिनिधियों ने एक साथ मिलकर नाचते–गाते हुए आपस में प्रेम और शांति का संदेश दिया. अधिवेशन में शामिल नौजवान वालेंटियर राघवेंद्र ने कहा कि हमें तो यही बताया जाता रहा है कि पाकिस्तानी काफ़ी ख़ूंख़ार होते हैं और वे भारत से काफ़ी नफ़रत करते हैं, लेकिन यहां तो हमें बहुत मान–सम्मान मिला है.

भारत–पाकिस्तान की दोस्ती का यह प्रयास क़रीब 15 साल पहले शुरू हुआ था, जिसने अब एक लंबा सफ़र तय किया है. मंच की सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि इसमें लोगों को आपस में जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, जिसकी बुनियाद हज़ार वर्षों से सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर गंगा–जमुना की सभ्यता से जुड़ी हुई है. जिस तहज़ीब को जोड़ने के लिए हज़ारों सालों में कई सूफ़ी–संतों, पीर–पैग़ंबरों ने काम किया है, उसकी झलक मंच के इस कार्यक्रम में देखने को मिली. यह परंपरा आज भी इस आधुनिक युग में इन दोनों देशों के लोगों में क़ायम है, जो इस मंच के माध्यम से अपने आपको एक दूसरे से जोड़ने में लगे हुए हैं. इस अधिवेशन को जहां आयोजित किया गया, उसका नाम भी कबीर–ख़ुसरो सभागार रखा गया. सभी पंडालों व मंचों के नाम भी सूफ़ी संतों के नाम से रखे गए, जो ऐतिहासिक काल में हर दौर में अमन और भाईचारे का पैग़ाम पहुंचाते रहे हैं. जैसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होता, पूरा माहौल ख़ुशनुमा और जज़्बाती हो जाता. भाषणों और चर्चाओं से ज़्यादा जीवंत कार्यक्रम यही रहा, जहां न कुछ कहने और न ही बोलने की ज़रूरत थी, बल्कि सूफ़ियाना कलाम, गीत–ग़ज़लों, संगीत, गायन और नृत्य ने ही वे सब बातें कह डालीं, जिन्हें भाषणों में कहना आसान नहीं है. इस कार्यक्रम को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था, जैसे एक दिन अचानक पूर्व और पश्चिम जर्मनी के बीच की बर्लिन की दीवार ढह गई थी, उसी प्रकार एक दिन वाघा में बनी दोनों देशों के बीच की नफ़रत की दीवार भी ढह जाएगी. अधिवेशन में कई तरह की चर्चाएं की गईं, जिनमें दोनों देशों में जनवादी प्रक्रिया, वैश्विक पूंजी से लड़ने के लिए जनआंदोलनों और सामाजिक आंदोलन की शुरुआत तथा दोनों देशों में हो रहे फ़ौज के फैलाव एवं बुनियादी ज़रूरतों से ज़्यादा हथियार पर ख़र्च होने वाले बजट पर चिंता जताना आदि शामिल था. हालांकि मंच के इस अधिवेशन का आयोजन करने में लगभग पांच वर्ष लग गए जो 25–28 फरवरी 2005 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था. इस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि दोनों देशों के नागरिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक न्याय, नागरिकों की सुरक्षा तथा आम नागरिकों की जीने के अधिकार एवं आजीविका की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे. ये दोनों देश नवउदारवादी नीतियों एवं साम्राज्यवादी वैश्वीकरण के चौतरफ़ा हमले झेल रहे हैं. इसके कारण दोनों देशों की सरकारें इन साम्राज्यवादी ताक़तों के सामने कठपुतली बनकर नाच रही हैं और अपने देश की सार्वभौमिकता को दांव पर लगा रही हैं. सिर्फ़ इन दोनों देशों में ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सार्वभौमिकता ख़तरे में है. ऐसे में भारत–पाकिस्तान की दोस्ती ही इस ख़तरे से उबरने का काम कर सकती है. इन नवउदारवादी नीतियों जैसे भारत–अमेरिका परमाणु संधि ने सिर्फ़ भारत की विदेश नीति को ही नज़रअंदाज नहीं किया है, बल्कि भारतीय लोगों पर एक बेहद ही ख़तरनाक परमाणु परियोजना का विस्तार थोपा है, ताकि विदेशी कंपनियों और अमेरिकी निगमों के स्वार्थों की पूर्ति हो सके. इसी तरह पाकिस्तान में भी आतंकी जनता के तमाम मानवाधिकारों को कुचलने में पूरी तरह से कामयाब हो गए हैं.

पाकिस्तान के अभिजात वर्ग, सेना और अमेरिकी शासन का गठजोड़ लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है. इस अधिवेशन में दोनों देशों में हो रहे आर्थिक सुधारों के नाम पर नवउदारवादी नीतियों को विकास का मॉडल बताकर जनता को गुमराह करने, देश में ग़रीबी और ग़ैर बराबरी को पैदा करने वाले हालात को भी विशेष रूप से संज्ञान में लिया गया. जहां एक ओर सरकारों को अपने देश की जनता की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, वहीं इन दोनों देशों की सरकारें इस ज़िम्मेदारी को न निभाते हुए अपने ही देश के नागरिकों को देश द्रोही साबित कर अंतरराष्ट्रीय पूंजी की गुलाम बनती जा रही हैं. वे सार्वजनिक संसाधनों और प्राकृतिक संसाधनों को लूटकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मुनाफ़ा पहुंचाने की नीतियों का समर्थन कर रही हैं. नतीजतन, ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक ग़रीबी रेखा से नीचे जीने को मजबूर हो रहे हैं. इस मंच के लिए आगामी दिनों में काफ़ी चुनौतियां हैं. मंच में दोनों देशों से उन लोगों को जोड़ना है, जो दोनों देशों में जनवादी ताक़तों को मज़बूत कर सकें. भारत और पाकिस्तान की दोस्ती का मुख्य आधार जनतांत्रिक मूल्य हैं, जिसका आधार सामाजिक संगठन एवं जन संगठनों में निहित है. यह प्रस्ताव पाकिस्तान के हालात के मद्देनज़र और भी प्रसांगिक है. अरब में चली जनवाद की लहर और तानाशाहों का तख्ता पलट पाकिस्तान की फ़ौज के लिए नसीहत होगी.

feedback@chauthiduniya.com

अधिवेशन में कई संकल्प पारित किए गए

- हम जनवादी ताक़तें, कभी इन दोनों देशों के बीच जंग नहीं होने देंगी.
- महिलाओं को बराबरी का अधिकार स्थापित करने के लिए मंच द्वारा ठोस कार्य किया जाएगा, ताकि उन सारे क़ानूनों को रद्द किया जा सके जो महिलाओं के प्रति भेदभाव करते हों.
- दोनों देशों के नागरिकों को आसानी से आने जाने के लिए वीजा मुक्त नीतियों को लागू करने के लिए संघर्ष किया जाएगा.
- मंच मानता है कि कश्मीर का मामला वहां पर रहने वाली जनता की मंशा के अनुरूप ही सुलझना चाहिए, जो दोनों देशों में कश्मीर में रहने वाले लोगों द्वारा तय किया जाए. कश्मीर के मसले पर आने जाने में रोक हटाई जाए, व्यापार को खोल दिया जाए, (जब दोनों देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार को खोल सकते हैं तो इन दोनों देशों में व्यापार क्यों नहीं शुरू हो सकता), बच्चों और युवाओं का आपसी मिलन, निशस्त्रीकरण की नीतियों को पूरी तरह से लागू करना, सियाचिन से सेना और फ़ौज को फ़ौरन वापस बुलाने और आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को रद्द करने जैसी सिफ़ारिशें मौजूद थीं.
- अधिवेशन में गठित कार्यकारी समूह ने दोनों देशों में कश्मीर में जनवाद और अमन की बहाली के लिए कश्मीर के लिए अलग से संयुक्त मंच बनाने की सिफ़ारिश भी की.
- दोनों देशों में शांति और जनवाद बहाल करने के लिए मीडिया की भूमिका पर प्रमुखता से बात रखी गई और मंच में एक मीडिया सेल भी बनाने की बात हुई.
- एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह भी पारित किया गया कि फ़ौज पर संविधान के तहत जनता का नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए.

देश का पहला इंटरनेट टीवी

हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

- दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

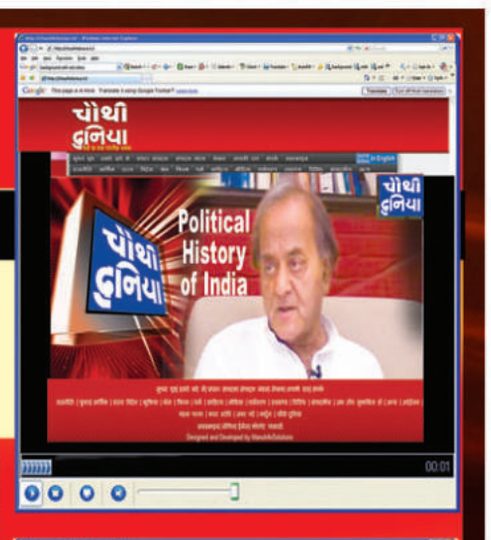

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

भक्ति की रस्मों-रिवाजों की मान्यताओं में परमात्मा के दिव्य अवतरण के संस्मरण विभिन्न रूपों में मिलते हैं.

बाबा की महिमा अपरंपार

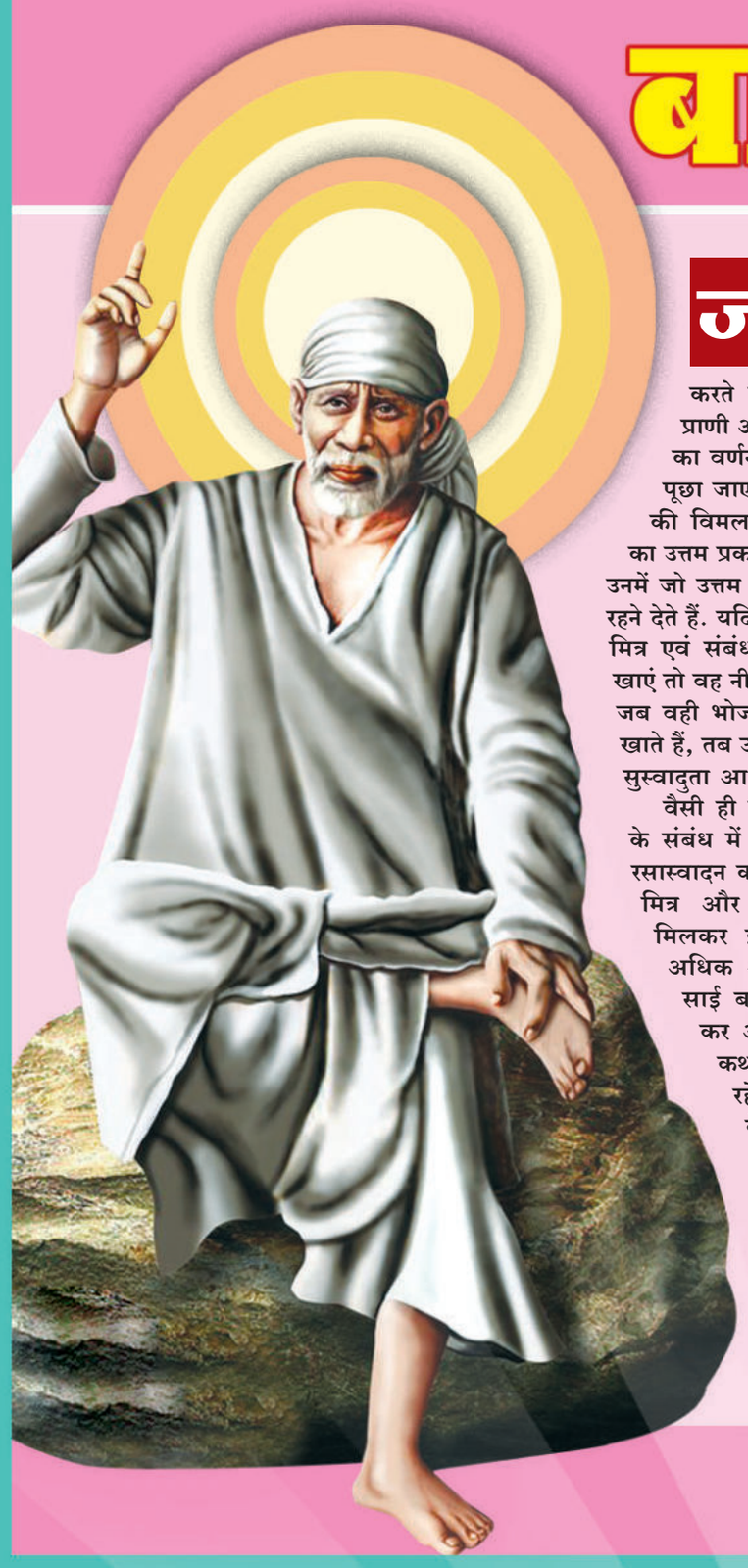

जब वेद और पुराण ही ब्रह्मा या सद्गुरु का वर्णन करने में असमर्थता प्रगट करते हैं, तब हम एक अल्पज्ञ प्राणी अपने सद्गुरु श्री साई बाबा का वर्णन कैसे कर सकते हैं. सच पूछा जाए तो मूक रहना ही सद्गुरु की विमल पताकारूपी विरुदावली का उत्तम प्रकार से वर्णन करना है, परंतु उनमें जो उत्तम गुण हैं, वे हमें मूक कहां रहने देते हैं. यदि स्वादिष्ट भोजन बने और मित्र एवं संबंधी आदि साथ बैठकर न खाएं तो वह नीरस सा प्रतीत होता है और जब वही भोजन सब एक साथ बैठकर खाते हैं, तब उसमें एक विशेष प्रकार की सुस्वादुता आ जाती है.

वैसी ही स्थिति साई लीला अमृत के संबंध में भी है. इसका एकांत में रसास्वादन कभी नहीं हो सकता. यदि मित्र और पारिवारिक जन सभी मिलकर इसका रस लें तो और अधिक आनंद आ जाता है. श्री साई बाबा स्वयं ही अंत:प्रेरणा कर अपनी इच्छानुसार ही इन कथाओं को मुझसे वर्णित कर रहे हैं. इसलिए हमारा तो केवल इतना ही कर्तव्य है कि अनन्य भाव से उनके शरणागत होकर उनका ही ध्यान करें. तप, साधना, तीर्थयात्रा, व्रत, यज्ञ एवं दान से हरिभक्ति श्रेष्ठ है और सद्गुरु का ध्यान इन सबमें परम श्रेष्ठ है. इसलिए सदैव मुख से साई नाम का स्मरण, उनके उपदेशों का निदिध्यासन एवं स्वरूप का चिंतन करके हृदय में सत्य और प्रेम के भाव से समस्त चेष्टाएं उनके ही निमित्त करनी चाहिए. भव बंधन से मुक्त होने का इससे उत्तम साधन और कोई नहीं. यदि हम उपयुक्त विधि से कर्म करते जाएं तो साई को विवश होकर हमारी सहायता कर हमें मुक्ति प्रदान करनी ही पड़ेगी. अब इस अध्याय की कथा श्रवण करें.

हरि कानोबा

बंबई के हरि कानोबा नामक एक महानुभाव ने अपने कई मित्रों और संबंधियों से साई बाबा की अनेक लीलाएं सुनी थीं, परंतु उन्हें विश्वास नहीं होता था, क्योंकि वह संशयालु प्रकृति के व्यक्ति थे. अविश्वास उनके हृदय पटल पर अपना आसन जमाए हुए था. वह स्वयं बाबा की परीक्षा करने का निश्चय करके अपने कुछ मित्रों सहित बंबई से शिरडी आए. उन्होंने सिर पर एक जरी की पगड़ी और पैरों में नए सैंडिल पहन रखे थे. उन्होंने बाबा को दूर से ही देखकर उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम तो करना चाहा, परंतु उनके नए सैंडिल इस कार्य में बाधक बन गए. उनकी समझ में नही आ रहा था कि अब क्या किया जाए. उन्होंने अपने सैंडिल मंडप के एक सुरक्षित कोने में रखे और मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए, लेकिन उनका ध्यान सैंडिलों पर ही लगा रहा. उन्होंने बड़ी नम्रतापूर्वक बाबा को प्रणाम किया और उनसे प्रसाद एवं उदी प्राप्त कर लौट आए, पर जब उन्होंने कोने में नज़र डाली तो देखा कि सैंडिल नदारद थे. पर्याप्त छानबीन भी व्यर्थ हुई और अंत में निराश होकर वह अपने स्थान पर वापस आ गए.

स्नान, पूजन और नैवेद्य आदि अर्पित करके वह भोजन करने के लिए तो बैठे, परंतु पूरे समय तक सैंडिलों के चिंतन में ही मग्न रहे. भोजन करके मुंह-हाथ धोकर जब वह बाहर आए तो उन्होंने एक मराठा बालक को अपनी ओर आते देखा, जिसके हाथ में डंडे के कोने पर नए सैंडिलों का जोड़ा लटका हुआ था. उस बालक ने हाथ धोने के लिए बाहर आने वाले लोगों से कहा, बाबा ने मुझे यह डंडा हाथ में देकर रास्तों में घूम-घूमकर हरि का बेटा-जरी का फेंटा की पुकार लगाने के लिए कहा है और जो कोई कहे कि सैंडिल हमारे हैं, उससे पहले यह पूछना कि क्या उसका नाम हरि और उसके पिता का नाम क (अर्थात कानोबा) है. साथ ही यह भी देखना कि वह जरीदार साफा बांधे हुए है या नहीं, तब इन्हें उसे दे देना.

बालक का कथन सुनकर हरि कानोबा को बेहद आनंद एवं आश्चर्य हुआ. उन्होंने आगे बढ़कर बालक से कहा कि ये हमारे ही सैंडिल हैं, मेरा ही नाम हरि और मैं ही क (कानोबा) का पुत्र हूं. यह मेरा जरी का साफा देखो. बालक संतुष्ट हो गया और सैंडिल उन्हें दे दिए. उन्होंने सोचा कि मेरी जरीदार पगड़ी तो सबको ही दिख रही थी. हो सकता है कि बाबा की भी दृष्टि में आ गई हो, परंतु शिरडी यात्रा का मेरा यह प्रथम अवसर है, फिर बाबा को यह कैसे विदित हो गया कि मेरा नाम हरि है और मेरे पिता का नाम कानोबा. वह तो केवल बाबा के परीक्षार्थ वहां आया था. उन्हें इस घटना से बाबा की महानता विदित हो गई. उनकी इच्छा पूर्ण हो गई और वह सहर्ष घर लौट गए.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

साई बाबा की आरती

आरती उतारे हम तुम्हारी साई बाबा ।
चरणों के तेरे हम पुजारी साई बाबा
विद्या बल बुद्धि, बंधु माता-पिता हो
तन, मन, धन प्राण, तुम ही सखा हो
हे जगदाता अवतारे, साई बाबा ।
आरती उतारे हम तुम्हारी साई बाबा

ब्रह्म के सगुण अवतार तुम स्वामी
ज्ञानी दयावान प्रभु अंतरयामी
सुन लो विनती हमारी साई बाबा ।
आरती उतारे हम तुम्हारी साई बाबा

आदि हो अनंत त्रिगुणात्मक मूर्ति
सिंधु करुणा के हो उद्धारक मूर्ति
शिरडी के संत चमत्कारी साई बाबा ।
आरती उतारे हम तुम्हारी साई बाबा

भक्तों की खातिर, जनम लिए तुम
प्रेम ज्ञान सत्य स्नेह, मरम दिए तुम
दुखिया जनों के हितकारी साई बाबा ।
आरती उतारें हम तुम्हारी साई बाबा ।

शिवरात्रि: एक सार्वभौमिक उत्सव

इसे विडंबना ही कहेंगे कि जिस सर्वशक्तिमान परमात्मा को लोग अपने विचारों एवं भावनाओं में याद करते हैं, उसे यथार्थ रूप से जानते ही नहीं है. सृष्टि के नियंता परमात्मा की अद्भुत रचना को देखकर उसका गुणगान तो बहुत लोग करते आए हैं, किंतु उन्हें उस परम चैतन्य परमात्मा का यथार्थ अलौकिक अनुभव नहीं है. आश्चर्य तो यह है कि परमात्मा को न जानते हुए भी वे उसे याद करते हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि आत्माओं के स्थूल नेत्रों के समक्ष कोई मूर्त रूप न होते हुए भी कहीं न कहीं उनके अंतर्मन में उस विचित्र निराकार परमात्मा की अस्पष्ट छवि अवश्य होती है, जिसे उनकी भ्रमित बुद्धि समझ नहीं पाती. अतीत में अनेक ऋषियों-मनीषियों ने घोर तपस्या करके अंतत: नेति-नेति कह दिया. परमात्मा का अंत पाना कठिन है. विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करने वाले वैज्ञानिकों ने भी यही कह दिया कि जहां विज्ञान समाप्त होता है, वहीं से अध्यात्म शुरू होता है. विज्ञान केवल यही कहता है कि ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के पार ऊर्जा का कोई ऐसा स्रोत है, जो इन सभी ऊर्जाओं को नियंत्रित करता है. वह स्रोत क्या है? इसके उत्तर में विज्ञान भी मौन है. विज्ञान केवल इतना ही कहता है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में जो भी अभी तक ज्ञात है, वह इस विशाल महासागर की तुलना में केवल एक बूंद के बराबर है.

प्रकृति की ऊर्जा से प्रभावित मानव आध्यात्मिक शक्ति के असीम स्रोत परमात्मा को नहीं जान सकता. दरअसल, एक सामान्य मनुष्य को परमात्म दिव्य शक्तियों का एहसास ही नहीं होता और न वह बुद्धि सूक्ष्म शक्तियों की रहस्यमयी गतिविधियों के बारे में सोच सकने में समर्थ है. इसलिए यह स्पष्ट समझ लेने की बात है कि परमात्मा और उसकी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म शक्तियों को साधारण बुद्धि से नहीं समझा जा सकता. परमात्मा के अस्तित्व को समझने और उनके साथ परम मिलन का अनुभव करने के लिए केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं है. परमात्मा का यथार्थ परिचय स्वयं परमात्मा ही देते हैं. परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है. सृष्टि के महापरिवर्तन में परमात्मा की अहम भूमिका है. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने से यह स्पष्ट होता है कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना या सतो प्रधान से तमो प्रधान रूप में परिवर्तन एक समय के चक्रीय क्रम में होता है. तमो प्रधान ऊर्जा को सतो प्रधान में परिवर्तित करने को सृष्टि का नवीनीकरण कहते हैं. सृष्टि का नव निर्माण करने के इस क्रम में ऊर्जाओं के महास्रोत परमात्मा के साधारण मानवीय शरीर में दिव्य अवतरण की दिव्य घटना भी ऐसे ही समय पर घटती है, जब सृष्टि की तात्विक ऊर्जाएं तमो प्रधान हो जाती हैं. तात्विक ऊर्जाओं का तमो प्रधान होना और चैतन्य अभौतिक आत्माओं का पतित होना साथ-साथ होता है. इसलिए कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्या ग्लानिर्भवति...अर्थात जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, तब परमात्मा का अवतरण होता है. यह सृष्टि के समय चक्र का अंतिम सच है. अब सभी प्रकार की तात्विक ऊर्जाएं संपूर्ण तमो प्रधान अवस्था को प्राप्त हो चुकी है. अब पुन: निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा अवतरित होकर अपने दिव्य रूप से कर्तव्य करा रहे हैं. अब यह धरा धाम एवं संपूर्ण ब्रह्मांड अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगा. यह संसार परिवर्तन प्रक्रिया से पुन: सतयुग में परिवर्तित होगा. विज्ञान के मतानुसार, पदार्थ या तत्व का जितना सूक्ष्म रूप होता है, उतना ही वह अधिक शक्तिशाली होता है. अध्यात्म विज्ञान की सूक्ष्मता इससे भी आगे का क्रम है. गुणों एवं शक्तियों के सागर होने के कारण परमात्मा को विशेषणात्मक रूप से सर्वशक्तिमान कहते हैं. वह इसलिए सर्वशक्तिमान हैं, क्योंकि वह अत्यंत सूक्ष्मातिसूक्ष्म हैं. विज्ञान के अनुसार, यह भी तर्कसंगत है कि किसी भी भौतिक पदार्थ या तत्व का वस्तुत: एक रूप (आकार) होता है. ठीक उसी प्रकार अभौतिक असीम चैतन्य शक्ति परमात्मा का भी एक अपना दिव्य आकार (रूप) होता है. जब जड़ का आकार होता है तो उसका नाम भी होता है. बिना नाम के कोई भी वस्तु नहीं होती. ठीक उसी प्रकार सर्वशक्तिमान निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा का आकार और नाम दोनों ही हैं. उनका गुण और कर्तव्यवाचक नाम शिव है. परमात्मा का अभौतिक रूप सूक्ष्मातिसूक्ष्म दिव्य बिंदु और स्वरूप ज्योति है. परमात्मा को परम चैतन्य ऊर्जा और सर्व प्रकार की ऊर्जाओं का स्रोत कहना ज़्यादा यथोचित है. इसलिए परमात्मा को सत-चित्त-आनंद स्वरूप कहते हैं. वह सत अर्थात शाश्वत और परिवर्तनशील हैं. वह परम चैतन्य अर्थात सृष्टि के आदि, मध्य एवं अंत के ज्ञान को जानने वाले सर्वज्ञ हैं. वह सदा आनंद स्वरूप अर्थात अपनी परम चैतन्यता की पराकाष्ठा में अवस्थित रहने वाले हैं. वह सदा एक जैसे हैं. वह अजन्मे और प्रकृति की सतो, रजो एवं तमो अवस्थाओं से सदा परे रहने वाले हैं. परमात्मा अनादि अविनाशी मूल गुणों का सागर हैं. वास्तव में उन्हें व्यक्ति और वस्तु की तरह संज्ञा की सीमा में भी नहीं बांधा जा सकता. फिर भी एक व्यवहारिक विवेकसम्मत भाषा में उन्हें परम ऊर्जावान, परम कल्याणकारी सदा शिव की संज्ञा दी गई है. आध्यात्मिक शक्तियों और गुणों के स्रोत निराकार परमात्मा सर्व प्रकार की ऊर्जाओं के उद्गम एवं आकर्षण का केंद्र हैं. वह अति सूक्ष्म ऊर्जा के सदा दाता हैं. भौतिक जगत के सूर्य के समान इस जगत से परे आध्यात्मिक जगत में अवस्थित परम ज्योति परमात्मा एक चैतन्य सूर्य के समान हैं. उनकी शक्तियों का अनुभव करने के लिए वैसी ही पवित्र मनोस्थिति अर्थात बुद्धि योग की पात्रता का होना अनिवार्य शर्त है.

घटनाओं के घटित होने के बाद संस्मरण बनते हैं. भक्ति की रस्मों-रिवाजों की मान्यताओं में परमात्मा के दिव्य अवतरण के संस्मरण विभिन्न रूपों में मिलते हैं. भक्ति के आदिकाल से ही निराकार परमात्मा के मनुष्य तन में दिव्य अवतरण की प्रतीकात्मक यादगार भी बनी हुई है. उसे ही शिव जयंती कहते हैं. सहस्रों वर्षों से शिव जयंती का त्योहार मनाना यही दर्शाता है कि निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा का दिव्य अवतरण सृष्टि चक्र के क्रम में अतीत में हुआ है, तभी तो उनके दिव्य जन्म (अवतरण) की यादगार शिव जयंती मनाते हैं. सृष्टि अपने एक चक्रीय क्रम में चलती रहती है. परमात्मा इसका नवीनीकरण एवं इसे निरंतरता प्रदान करने के लिए अवतरित होकर अपने मुख्य कर्तव्य कराते हैं. सृष्टि के परिवर्तन की प्रक्रिया में परमात्मा का अवतरण भी अनिवार्य रूप से निश्चित है. आध्यात्मिक दृष्टि से हम सभी आत्माओं का अनादि अविनाशी संबंध परमात्मा से है. हमारा अपना पुरुषार्थ और परमात्म शक्तियों का सूक्ष्म सहयोग ही हमें नया जन्म देता है. वह हमारे आत्मिक पिता परम पिता हैं. वह पिताओं एवं धर्म पिताओं के भी परम पिता हैं. इस दृष्टि से इस शिव जयंती के त्योहार का संबंध केवल क्षेत्र, देश या धर्म-संप्रदाय से नहीं है, अपितु यह संपूर्ण विश्व की आत्माओं से संबंध रखता है, इसलिए यह सार्वभौमिक है. परम पिता परमात्मा शिव के नाम, रूप, कर्तव्य और दिव्य जन्म का यह संक्षिप्त एवं विवेकसम्मत स्पष्टीकरण है. अत: शिव जयंती के उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए. यह समय परमात्मा के कर्तव्यों का चल रहा है. अब अनेक भावनाओं, मान्यताओं या कर्मकांडों में समय नष्ट न करके परम पिता को यथार्थ रूप से पहचानें और उनसे अपना बुद्धि योग लगाकर स्वयं को धन्य अनुभव करें. इसी समय के लिए कहा गया है कि अभी नहीं, तो कभी नहीं.

परमात्मा का अंत पाना कठिन है. विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करने वाले वैज्ञानिकों ने भी यही कह दिया कि जहां विज्ञान समाप्त होता है, वहीं से अध्यात्म शुरू होता है. विज्ञान केवल यही कहता है कि ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के पार ऊर्जा का कोई ऐसा स्त्रोत है, जो इन सभी ऊर्जाओं को नियंत्रित करता है. वह स्त्रोत क्या है? इसके उत्तर में विज्ञान भी मौन है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

दस-बीस पुस्तकों के लेखक अपने शोषण और प्रकाशक की शान-शौकत को गालियां देते हैं. मेरा कहना है कि प्रकाशक हज़ारों पुस्तकें प्रकाशित करता है.

अनंत विजय

कुछ तो है, जिसकी पर्दादारी है

हिंदी में साहित्यिक किताबों की बिक्री के आंकड़ों को लेकर अच्छा-खासा विवाद होता रहा है. लेखकों को लगता है कि प्रकाशक उन्हें उनकी कृतियों की बिक्री के सही आंकड़े नहीं देते हैं. दूसरी तरफ़ प्रकाशकों का कहना है कि हिंदी में साहित्यिक कृतियों के पाठक लगातार कम होते जा रहे हैं. बहुधा हिंदी के लेखक प्रकाशकों पर रॉयल्टी में गड़बड़ी के आरोप भी जड़ते रहे हैं, लेकिन प्रकाशकों पर लगने वाले इस तरह के आरोप कभी सही साबित नहीं हुए. निर्मल वर्मा की पत्नी गगन गिल और राजकमल प्रकाशन के बीच का विवाद हिंदी जगत में खासा चर्चित रहा. गगन गिल को लगा था कि राजकमल प्रकाशन से उन्हें उचित रॉयल्टी नहीं मिल रही है, लिहाज़ा उन्होंने हिंदी के इस शीर्ष प्रकाशन गृह पर रॉयल्टी कम देने का आरोप लगाते हुए निर्मल की सारी किताबें वापस ले ली थीं. उसके बाद यह पता नहीं चल पाया कि गगन गिल को निर्मल वर्मा की किताबों पर दूसरे प्रकाशन संस्थानों से कितनी रॉयल्टी मिली. अभी हंस के जनवरी अंक में राजेंद्र यादव ने एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया है. राजेंद्र जी ने लिखा, वस्तुत: हिंदी प्रकाशन अभी भी पेशेवर नहीं हुआ है और उसी डंडीमार बनिया युग में बना हुआ है. मेरे ऊपर आरोप है कि मैं प्रकाशकों का पक्ष लेता हूं कि लेखक अभी भी हवाई दुनिया में रहते हैं. दस-बीस पुस्तकों के लेखक अपने शोषण और प्रकाशक की शान-शौकत को गालियां देते हैं. मेरा कहना है कि प्रकाशक हज़ारों पुस्तकें प्रकाशित करता है और अपनी लागत पर दस-पांच प्रतिशत बचाता भी है तो यह राशि निश्चय ही किसी भी लेखकीय रॉयल्टी से सैकड़ों गुना अधिक होगी. राजेंद्र यादव आगे लिखते हैं, आज लेखक-प्रकाशक के रिश्ते बेहद अनात्मीय और बाजारू हो गए हैं, कच्चा माल दो और भूल जाओ.

अपने इस संपादकीय लेख में यादव जी ने यह भी बताया है कि उनकी जवानी के दिनों में ओमप्रकाश जी, विश्वनाथ, रामलाल पुरी और शीला संधू किस तरह लेखकों से दोस्ती का संबंध रखते थे. लेखकों की हर महीने पार्टी होती थी और एडवांस रॉयल्टी देकर वे लेखकों पर लिखने के लिए दबाव डालते थे. लेकिन राजेंद्र यादव ने रिश्तों के बाज़ारू और अनात्मीय होने की वजह नहीं बताई. हिंदी के इस शीर्ष लेखक से यह उम्मीद तो की ही जा सकती है कि वह इसकी वजह भी बताते और अपने अनुभवों के आधार पर इस रिश्ते की गरमाहट को बचाए रखने के लिए कुछ उपाय सुझाते, पर बजाय एक वरिष्ठ लेखक की भूमिका अख्तियार करने के यादव जी

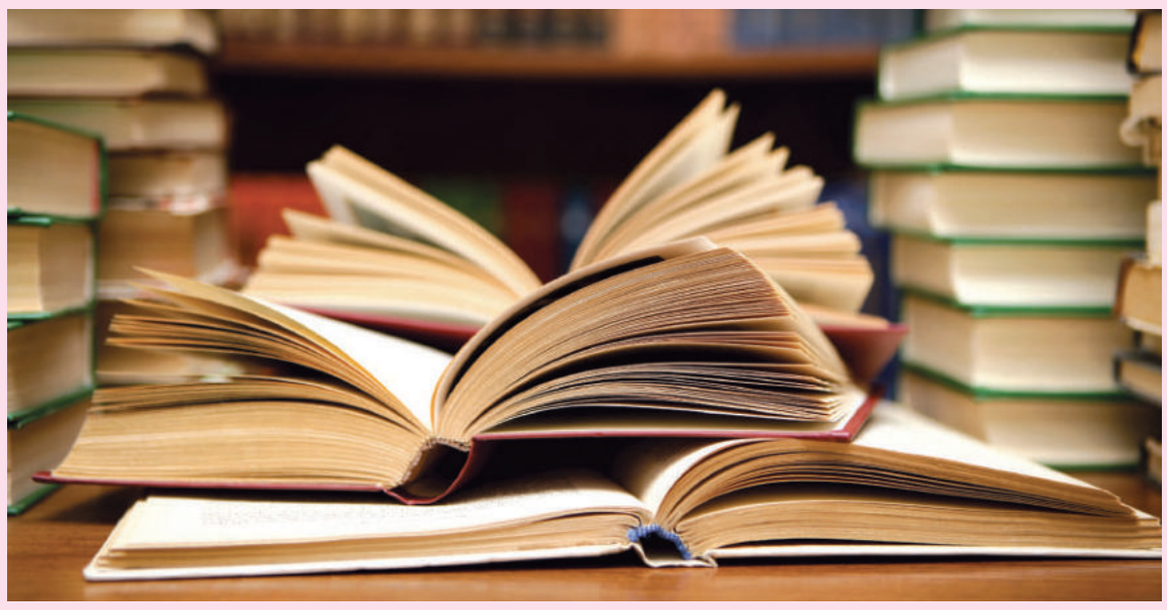

व्यक्तिगत लेन-देन के ब्यौरे में उलझ कर रह गए. कहने लगे कि राजकमल और वाणी से मेरी लगभग 90 पुस्तकें प्रकाशित हुई, अनुवादित, संपादित और लिखित, मगर दोनों जगह मिलाकर आंकड़ा डेढ़ लाख मुश्किल से छू पाता है, जबकि दस-बीस किताबें ऐसी भी हैं, जिनके हर साल संस्करण होते हैं, आठ-दस विभिन्न पाठ्यक्रमों में भी लगी हैं. यादव जी का संपादकीय पढ़ने के बाद मुझे छाया मयूर छपने के बाद का एक प्रसंग याद आ रहा है. छाया मयूर के अंक में भारत भारद्वाज ने हिंदी की चुनिंदा पुस्तकों पर लिखा था. अब ठीक से याद नहीं है, लेकिन भारत जी के उस लेख को लेकर राजेंद्र जी कुछ विचलित और क्षुब्ध थे. उसके बाद मैंने राजेंद्र जी का एक इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें साठ या सत्तर के दशक में ही रॉयल्टी के लाख रुपये मिला करते थे. मुझे याद नहीं है कि अब वह इंटरव्यू कहां है, लेकिन यह प्रसंग इस वजह से याद है कि तब मैंने सोचा था कि लेखकों को ठीकठाक पैसे मिलते हैं. साठ-सत्तर के दशक में भी लाख-डेढ़ लाख और चार दशकों के बाद भी लाख-डेढ़ लाख, यह तो बेहद नाइंसाफी है. यादव जी को साफ तौर पर बताना चाहिए था कि उन्हें कितने पैसे रॉयल्टी के मिलते हैं और क्या प्रकाशक उन्हें एडवांस भी देते रहे हैं. उनके लेख से यह ध्वनि निकलती है कि किताबघर और सामयिक प्रकाशन उन्हें सही रॉयल्टी देते हैं. लेख को पढ़ते वक़्त मेरे दिमाग़ में यह कौंधा कि यादव जी की क्या मजबूरी है कि वह वाणी और राजकमल के साथ बने हुए हैं, क्यों नहीं अपनी किताबें सामयिक और किताबघर को दे देते हैं. रॉयल्टी में कमी का अंदेशा भी है और हंस के पच्चीस साल पूरे होने पर जो किताबें छपीं, वे भी वाणी और राजकमल से ही छपीं. कुछ तो है, जिसकी पर्दादारी है. दरअसल यह पूरा मामला बेहद उलझा हुआ है और उतना आसान है नहीं, जितना दिखता है. हिंदी में साहित्यिक कृतियों का अब बमुश्किल तीन सौ से लेकर पांच सौ प्रतियों का संस्करण होता है और दूसरा संस्करण छपने में सालों बीत जाते हैं. इसके ठीक उलट अंग्रेजी में हालात बिल्कुल जुदा हैं. वहां एक औसत से लेखक की कमज़ोर कृति की भी आठ-दस हज़ार प्रतियां बिक ही जाती हैं. ऐसा नहीं है कि हिंदी का बाज़ार कम बड़ा है, बल्कि हाल के दिनों में तो हिंदी का बाज़ार भी बहुत बढ़ा है. तो फिर क्या वजह है कि हिंदी में एक साहित्यिक कृति के अपेक्षाकृत कम संख्या वाले संस्करण को बिकने में अंग्रेजी की तुलना में काफी ज़्यादा वक़्त लगता है. मुझे लगता है कि इसकी कई वजहें साफ तौर पर नज़र आती हें. हमारे देश में हिंदी का बाज़ार अवश्य बढ़ा है, यह तो अख़बारों की बढ़ती प्रसार संख्या और उनके नए

लेख को पढ़ते वक़्त मेरे दिमाग़ में यह कौंधा कि यादव जी की क्या मजबूरी है कि वह वाणी और राजकमल के साथ बने हुए हैं, क्यों नहीं अपनी किताबें सामयिक और किताबघर को दे देते हैं. रॉयल्टी में कमी का अंदेशा भी है और हंस के पच्चीस साल पूरे होने पर जो किताबें छपीं, वे भी वाणी और राजकमल से ही छपीं. कुछ तो है, जिसकी पर्दादारी है. दरअसल यह पूरा मामला बेहद उलझा हुआ है और उतना आसान है नहीं, जितना दिखता है.

संस्करणों की लोकप्रियता से पता चल जाता है और प्रामाणिक भी लगता है. इसको ही हम हिंदी का विस्तार मानते हुए इस निष्कर्ष पर भी पहुंच जाते हैं कि साहित्यिक कृतियों का बाज़ार बढ़ा है. मेरे ख्याल से आकलन का यह तरीक़ा सही नहीं है. अख़बारों और पत्रिकाओं की संख्या में इज़ाफ़े के आधार पर साहित्यिक कृतियों की बिक्री का अंदाज़ा लगाना ग़लत है, बल्कि इससे एक भ्रम और अविश्वास की स्थिति पैदा होती है. लेखकों को यह लगने लगता है कि उनकी कृतियां काफी बिक रही हैं और प्रकाशक सिर पीट रहा होता है कि जितनी पूंजी लगाकर किताब प्रकाशित की, उसका निकल पाना भी संभव नहीं हो पा रहा है. ये दोनों ही स्थितियां प्रकाशन जगत के लिए हानिकारक हैं. अबसे कुछ दिनों बाद नई दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला लगने वाला है. वहां भी इस बात की चर्चा होगी, बहस होगी, लेकिन होगा कुछ नहीं. प्रकाशकों और लेखकों के बीच इस तरह के अविश्वास की स्थिति हिंदी के लिए अच्छी नहीं है. अब वक़्त आ गया है कि राजेंद्र यादव जैसे बड़े लेखक व्यक्तिगत दर्द से ऊपर उठकर इस मसले के स्थायी हल के लिए पहल करें और एक मुकम्मल रास्ता निकालें.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

सर्वश्रेष्ठ पुस्तक समीक्षा

राग दरबारी : विसंगतियों का यथार्थ चित्रण

विनय बोधिसत्व

राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित राग दरबारी हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल का सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास है. राग दरबारी का प्रथम प्रकाशन 1968 में हुआ और पेपरबैक्स संस्करण 1983 में प्रकाशित हुआ. 1991 तक इस उपन्यास से 10 संस्करण प्रकाशित हुए. यह उपन्यास अंग्रेजी के अलावा 15 अन्य भाषाओं में अनूदित है.

अक्टूबर 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित श्रीलाल शुक्ल की अनेक कृतियों में राग दरबारी सर्वाधिक लोकप्रिय है. इसका शीर्षक भी विशिष्ट है. इसके शीर्षक के बारे में लेखक संजीव कुमार का कहना है कि राग दरबारी संगीत का एक राग है, जो मध्यकालीन सामंतों के दरबार में उन्हें रिझाने के लिए गाया जाता था. श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी शीर्षक के माध्यम से इस संदेश को संप्रेषित करना चाहा है कि सत्ता के साथ जुड़े रहने के लिए एक ख़ास क़िस्म के लोचदार व्यक्तित्व की ज़रूरत होती है, जो अवसर के अनुकूल नया तेवर अपनाता है. उपन्यास की विषय वस्तु की अगर बात करें तो उपन्यास के फ्लैप पर अंकित अंश उपन्यास के विषय के आधार को प्रभावपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करता है. यह राग उस दरबार का आधार है, जिसमें हम देश की आज़ादी के बाद हम जी रहे हैं. कथा भूमि है एक बड़े नगर से कुछ दूर बसे गांव शिवपालगंज की, जहां की ज़िंदगी प्रगति और विकास के समस्त नारों के बावजूद, निहित स्वार्थों और अनेक अवांछनीय तत्वों के आघातों के सामने घिसट रही है. यद्यपि राग दरबारी की कथा वस्तु शिवपालगंज गांव से ही जुड़ी हुई है, पर इसकी अंतर्वस्तु देशव्यापी है. प्रो. लल्लन राय राग दरबारी के संबंध में कहते हैं कि उपन्यास के केंद्रीय चरित्र वैद्यजी हैं. वह बद्री पहलवान और रूप्पन के पिता

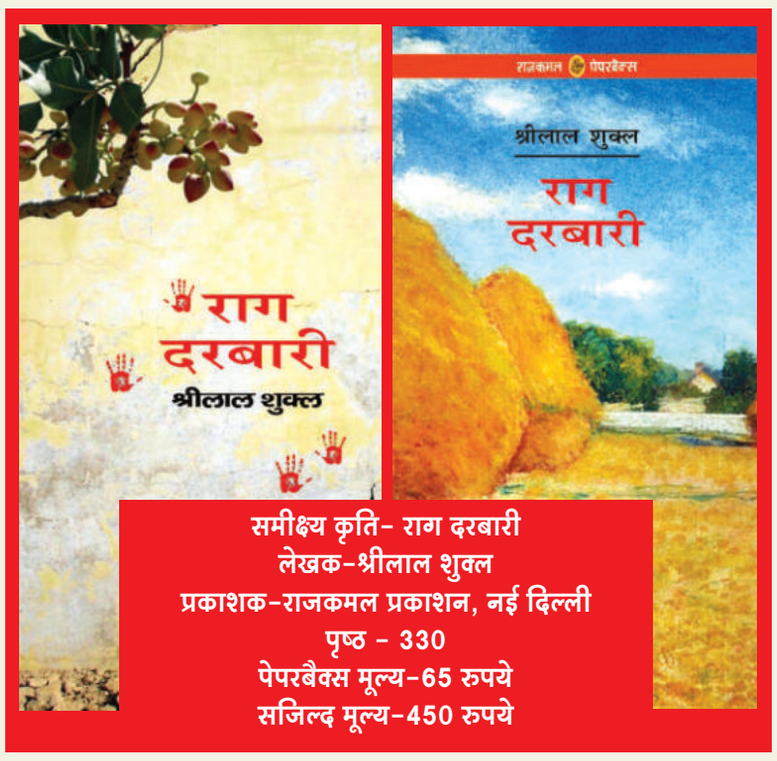

समीक्ष्य कृति- राग दरबारी
लेखक-श्रीलाल शुक्ल
प्रकाशक-राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
पृष्ठ - 330
पेपरबैक्स मूल्य-65 रुपये
सजिल्द मूल्य-450 रुपये

और रंगनाथ के मामा हैं. पेशे से वैद्य होने के साथ ही वह छंगामल इंटर कॉलेज के मैनेजर, कॉ-ऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर और अपने दरबारी सनीचर की आड़ में ग्राम सभा के प्रधान भी हैं. इस प्रकार वह उस राजनीतिक संस्कृति के साक्षात प्रतीक हैं, जो प्रजातंत्र और लोकहित के नाम पर हमारे चारों ओर फलफूल रही है. प्रो. राय के अनुसार, इस उपन्यास में प्रतीकात्मक रूप में स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाज में व्याप्त अराजकता, भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार, अवसरवादिता, लूट-खसोट, चुनावी छदम, प्रशासनिक एवं न्यायिक विद्रूप को अत्यंत कौशल के साथ उजागर किया गया है. राग दरबारी में उपन्यासकार की व्यंग्यात्मक शैली सार्थक और प्रभावपूर्ण है. उपन्यास में आंचलिक शब्दों का रोचक प्रयोग हुआ है, जैसे तिड़ी-बिड़ी, टांय-टांय, फुट्टफैरी, लासेबाजी, ठांसना, टें बोल जाना इत्यादि. 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत राग दरबारी एक ऐसा उपन्यास है, जिसमें स्वातंत्र्योत्तर भारत की राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक इत्यादि क्षेत्रों की विसंगतियों का यथार्थ चित्रण किया गया है. यह व्यंग्यात्मक औपन्यासिक कृति कथ्य, संवेदना और भाषिक संरचना की दृष्टि से विशिष्ट है. रोचकता की दृष्टि से बेजोड़ है. यह उपन्यास पठनीय है.

श्रीलालजी एक ऐसे साहित्यकार थे, जिन्होंने अपने उपन्यासों में समाज के हर वर्ग का, हर परिवर्तन का और हर स्तर का वर्णन किया. यह एक अलग विषय है कि राग दरबारी कालजयी बन गया और लोगों ने अपने को उस तक सीमित कर लिया. श्रीलाल शुक्ल का व्यक्तित्व बड़ा सहज था. वह हमेशा मुस्कुराकर सबका स्वागत करते थे. लेकिन अपनी बात बिना लाग-लपेट कहते थे. व्यक्तित्व की इसी ख़ूबी के चलते उन्होंने सरकारी सेवा में रहते हुए भी व्यवस्था पर करारी चोट करने वाली राग दरबारी जैसी रचना हिंदी साहित्य को दी.

feedback@chauthiduniya.com

किताब मिली

पुस्तक का नाम
और पानी उतर गया

लेखक
के.एस.तिवारी

प्रकाशक
राजकमल प्रकाशन

मूल्य
150 रुपये

इस किताब में जल संकट पर गहरी चिंता जताते हुए जल संरक्षण पर ज़ोर दिया गया है.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.
चौथी दुनिया एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

एप्पल आईपॉड नैनो में कैमरा

एप्पल आईपॉड नैनो में एक शानदार क्वालिटी का कैमरा इनबिल्ड होगा. एप्पल ने नैनो आईपॉड की डिज़ाइन में बिना कोई बदलाव किए नया कैमरे वाला आईपॉड बनाया है.

गैजेट बाज़ार में एप्पल की नई डिवाइस को लेकर अफ़वाहों का बाज़ार गर्म है. दरअसल एप्पल आईपॉड का नया संस्करण लांच करने पर विचार कर रहा है. ख़ास बात यह है कि एप्पल के नए आईपॉड में ऐसे फीचर ज़रूर दिए गए होंगे, जो गैजेट बाज़ार में एक नई तकनीक की शुरुआत करेंगे.

एप्पल का आईपॉड अब तक सबको ख़रीदना रास नहीं आ रहा था, क्योंकि अब तक इसमें कैमरा नहीं था और इस वजह से इसकी लोकप्रियता में कमी आ रही थी. लेकिन अब ख़ुशख़बरी यह है कि एप्पल के नए आईपॉड नैनो में जल्द कैमरे की सुविधा भी मौजूद होगी. एप्पल आईपॉड नैनो में एक शानदार क्वालिटी का कैमरा इनबिल्ड होगा. एप्पल ने नैनो आईपॉड की डिजाइन में बिना कोई बदलाव किए नए कैमरे वाला आईपॉड बनाया है. 7 जेनेरेशन के नए नैनों में इस तरह का पहला अनोखा फीचर दिया जा रहा है. एप्पल जल्द ही नए कैमरे से लैस आईपॉड नैनो का प्रोडक्शन भी शुरू भी कर देगा. नया आईपॉड नैनो आने वाले दिनों में ऑडियो बाज़ार की दिशा बदल सकता है, क्योंकि अभी तक किसी कंपनी ने इस तरह के किसी भी फीचर को अपने ऑडियो उत्पाद में नहीं जोड़ा है. एप्पल के नए कैमरे आईपॉड नैनो का ऑडियो बाज़ार में बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

निकॉन एल810 कूलपिक्स

निकॉन का कूलपिक्स सीरीज के कैमरे काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं, इसकी वजह इसकी कम क़ीमत में बढ़िया क्वालिटी मिलना आंका गया है. अपने इसी ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए निकॉन ने कूलपिक्स सीरीज के अंतर्गत एक नया कैमरा लांच किया है. यह नया कैमरा कूल पिक्सल सेगमेंट के अंतर्गत लांच किया है. कूलपिक्स एल810 में तकनीकी रूप से 16.1 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है. निकॉन कूलपिक्स एल810 में कई ख़ास फीचर दिए गए हैं, जिसमें ख़ास है सीसीडी इमेज सेंसर जिससे फोटो खींचना आसान हो जाता है. निकॉन के नए कैमरे में ब्लैक कलर की ग्रिप की वजह से फाटो कैपचर करने में काफ़ी मदद मिलती है. कैमरे का साइज छोटा होते हुए भी इसमें 16.1 मेगापिक्सल लेंस दिया गया है. इमेज प्रीव्यू करने के लिए कैमरे में 3 इंच की बड़ी एलसीडी स्क्रीन भी दी गई है. इसमें निकॉन लेंस डाला गया है, जिसका वेरिएशन 22.5 एमएम से लेकर 585 एमएम लेंस है. निकॉन एल 180 कूलपिक्स एल सीरीज के अंतर्गत पहला जूम मॉडल है, जो पिक्चर क्वालिटी को बिना नुक़सान पहुंचाए 26 एक्स ऑप्टिकल जूम कर सकता है. कई कलर ऑप्शनों में मौजूद निकॉन एल180 में एए बैटरी लगती है और यह वीआर फंक्शन मोड पर काम करता है.

इमेज प्रीव्यू करने के लिए कैमरे में 3 इंच की बड़ी एलसीडी स्क्रीन भी दी गई है. इसमें निकॉन लेंस डाला गया है, जिसका वेरिएशन 22.5 एमएम से लेकर 585 एमएम लेंस है.

टेनका के म्यूजिक हेडसेट

हेडसेट को ऑडियो डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए 3.5 एमएम ऑडियो जैक की सुविधा भी मौजूद है. कंपनी ने नए हेडसेट को 2000 रुपये की अनुमानित क़ीमत में लांच किया है.

म्यूज़िक गैजेट्स बनाने वाली कंपनी टेनका ने ऑडियो बाज़ार में नया म्यूज़िक हेडसेट उतारा है. इसकी ख़ासियत यह है कि इस हेडसेट में वॉयरलैस तकनीक की सुविधा दी गई है. देखने में हेडसेट का लुक काफ़ी आकर्षक और ट्रेंडी है. हेडसेट में म्यूज़िक सुनने के साथ-साथ फोन कॉल भी अटैंड की जा सकती है.

तकनीकी रूप से हेडसेट में 180 घंटे का स्टैंडबॉय टाइम और 22.2 घंटे का टॉक टाइम दिया गया है. इसके अलावा अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो चिंता की कोई बात नहीं. टेनका के नए हेडसेट को फुल चार्ज होने में मात्र 3.5 घंटे लगते हैं. हेडसेट को ऑडियो डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए 3.5 एमएम ऑडियो जैक की सुविधा भी मौजूद है. कंपनी ने नए हेडसेट को 2000 रुपये की अनुमानित क़ीमत में लांच किया है. ट्रेंडी स्टाइल लुक के नए टेनका हेडसेट में दिया गया हेडबैंड काफ़ी फ्लेक्सीबल है, जिसकी वजह से यह यूजर के अनुसार एडजस्ट किया जा सकता है.

लैपटॉप बैग्स और स्किन

जेब्रोनिक्स ब्रांड के तहत कंप्यूटर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सामान और दूरसंचार से जुड़े उत्पादों एवं एसेसरीज की आपूर्ति करने वाली कंपनी टॉप नॉच इंफोट्रोनिक्स ने स्टाइलिश लैपटॉप एसेसरीज की अपनी रेंज का विस्तार किया है. कंपनी ने प्रीमियम लैपटॉप बैग और स्किन्स पेश की है. लैपटॉप बैग के दो मॉडल पेश किए गए हैं. ये हैं जेबस्टर जेडईबी-बीपी 5000 बैकपैक-स्टाइल बैग और जेबस्टर जेडईबी-ईबी 1000 एक्जीक्यूटिव स्टाइल टॉप-लोडर. दोनों ही बैग टिकाऊ और पानी से बेअसर रहने वाले (वाटर रेजिस्टेंट) मटीरियल से बने हैं. इनकी बाहरी परत काफ़ी कड़े कवच से ढंकी है, ताकि लैपटॉप को झटकों आदि से कोई ख़तरा न हो और खरोंच से भी बचाया जा सके. जेब-बीपी 5000 को कंधे से लटकाने के लिए इसमें गद्देदार पैड वाली पट्टी लगी है, ताकि इसे लेकर चलने में न तो भारीपन लगे और न ही किसी तरह की कठिनाई हो. इसका इंटीरियर भी अत्यंत मुलायम है, जिससे लैपटॉप पर झटके या कंपन का कोई असर नहीं होता और आपका लैपटॉप व एसेसरीज पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं. इसमें मोबाइल फोन, एमपी3 प्लेयर आदि के लिए छोटे से पाउच भी लगे हैं और बोतल रखने के लिए दोनों तरफ़ अलग से पैक बने हैं. ये पैक आप चाहें तो बैग से अलग भी कर सकते हैं. बैग में बड़ी सी चेन लगी है, जिससे आप पूरा बैग खोल सकते हैं और अंदर कई छोटे पॉकेट्स बने हैं, ताकि आप एक ही जगह व्यवस्थित तरीक़े से अपना सारा ऐसेसरीज रख सकें. जेब-ईबी 1000 एक्जीक्यूटिव लैपटॉप बैग हार्ड ब्लैक एंड व्हाइट शेल डिज़ाइन में उपलब्ध हैं, जो इसे प्रोफेशनल लुक देता है. दोनों ही बैग शानदार लगते हैं और 15.6 इंच के लैपटॉप के लिए मुफ़ीद हैं. लैपटॉप बैग के अलावा जेब्रोनिक्स ने लैपटॉप स्किन्स की तीन सीरीज भी पेश की है-3डी, डिज़ाइनर और एलीट. टिकाऊ, कड़े विनाइल मटीरियल के बने ये स्किन्स आपके लैपटॉप को निजी लुक व स्टाइल प्रदान करते हैं. साथ ही दाग़-खरोंच आदि से भी बचाते हैं. 3डी स्किन्स आकर्षक व रंगीन अंदाज़ में 3डी विजुअल इफेक्ट पैदा करते हैं. डिज़ाइनर सीरीज की स्किन्स दो डिज़ाइन में आती है. एक स्पोर्ट बाइक और दूसरी रेसिंग कार के साथ. खेल और गेम के दीवानों को यह अलग ही अपील देगी. एलीट सीरीज में एक अनूठी टेक्सचर्ड सरफेस डिज़ाइन उपलब्ध कराया गया है. यह पांच डिज़ाइन में पेश किया गया है. ये तीनों ही स्किन्स लैपटॉप पर किसी तरह का दाग़ नहीं छोड़ते और इन्हें आसानी से हटाया जा सकता है.

आईफोन डॉक स्पीकर

इसमें कोई शक नहीं कि एप्पल के उत्पाद पूरी दुनिया में मशहूर हैं. पीसी बाज़ार में एप्पल आईफोन और आईपॉड के लिए कई एसेसीरीज उपलब्ध हैं. कुछ कंपनियां आईफोन और आईपॉड एसेसरीज को लेकर चर्चा में रहतीं है, जिसमें से आईफोन डॉक स्पीकरों को काफ़ी पसंद किया जाता है. जेवियो ने भी बाज़ार के रुख़ को देखते हुए नए टोस्टर शेप में आईफोन डॉक स्पीकर पेश किए हैं.

यह स्पीकर 105/160/70 एमएम के आकार में यूनीक टोस्टर डिज़ाइन में बना है. इसमें ड्यूल 50 एमएम स्पीकर है, जो 150 हर्ट से लेकर 18 हर्ट फ्रिक्वेंसी रिस्पांस देता है. इसमें 80 डीबी सिग्नल नॉयस रेशियो होने की वजह से आवाज़ बिना किसी बाहरी नॉयज के काफ़ी साफ सुथरी और क्लीयर आती है. यह 1000 एमएएएच लीथियम ऑयन बैटरी पर काम करता है. जेवियो के नए डॉकिंग स्पीकरों की डिज़ाइन इनकी सबसे बड़ी ख़ासियत है. ब्रेड टोस्टर डिज़ाइन के डॉक स्पीकरों में सिल्वर कलर का प्रयोग किया गया है, जो इसके लुक को और आकर्षक बनाता है. नए टोस्टर डॉक में 50 एमएम के स्पीकर दिए गए हैं, जो 3 वॉट के एम्प्लीफायर से दमदार साउंड प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा स्पीकरों में लियॉन बैटरी भी दी गई है.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

समय का फेर

सोमदेव लगता है कि अपने बुरे दौर से गुजर रहे हैं. चोटिल होने के कारण आस्ट्रेलियाई ओपन में नहीं खेलने वाले भारतीय टेनिस खिलाड़ी सोमदेव देववर्मन एटीपी की सोमवार को जारी ताजा विश्व रैंकिंग में 32 स्थान नीचे लुढ़ककर शीर्ष 100 से बाहर हो गए. सोमदेव इससे पहले 90 वें स्थान पर थे, अब वह 464 रेटिंग अंक के साथ 122 वें स्थान पर खिसक गए हैं. वह कंधे की चोट के कारण साल के शुरुआती ग्रैंडस्लैम में नहीं खेल पाए थे. पिछले एक साल में यह पहला अवसर है जब सोमदेव चोटी के 100 खिलाड़ियों से बाहर हुए हैं. सोमदेव सात फरवरी 2011 को 30 स्थान की छलांग लगाकर शीर्ष 100 में शामिल हुए थे और इसके बाद वह जुलाई में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 62 वीं रैंकिंग पर पहुंचे थे. उनके लगातार ख़राब प्रदर्शन के कारण उनकी रैंकिंग में गिरावट आती रही. एकल के अलावा युगल में भी वह 15 पायदान नीचे 161 वें स्थान पर खिसक गए हैं. इस बीच युगल रैंकिंग में लिएंडर पेस पहले की तरह सातवें, रोहन बोपन्ना 11 वें और महेश भूपति 16 वें स्थान पर बने हुए हैं. पेस और चेक गणराज्य के रादेक स्टेपनेक की आस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियन जोड़ी टीम रेस में शीर्ष पर बने हुए हैं लेकिन भूपति और बोपन्ना की जोड़ी एक पायदान नीचे 12 वें स्थान पर खिसक गई है. उधर, डब्ल्यूटीए रैंकिंग में सानिया मिर्ज़ा एकल में 122 वें और युगल में सातवें स्थान पर बनी हुई हैं

सहारा का धमाका

सहारा पिछले दिनों से कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है. भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ अपना प्रायोजन क़रार ख़त्म करने वाले सहारा ग्रुप ने हॉकी टीम के साथ अपने संबंध को बरक़रार रखने का फ़ैसला किया है. सूत्रों के अनुसार हॉकी इंडिया और सहारा ग्रुप में क़रार आगे बढ़ाने को लेकर सहमति बन गई है. सहारा इंडिया के सूत्रों के अनुसार यह रकम 8 से 9 करोड़ से ज़्यादा नहीं होने वाली. क़रार पांच साल का होने की संभावना है. सहारा के सूत्रों ने बताया कि कंपनी की तरफ़ से हॉकी इंडिया को सात करोड़ रुपये सालाना प्रायोजन का प्रस्ताव रखा गया था लेकिन हॉकी इंडिया चाहता था कि इसे थोड़ा और बढ़ाया जाए. हॉकी टीम की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इस मांग को स्वीकार कर लिया गया है क्योंकि अब यह रकम पहले की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है. उल्लेखनीय है कि सहारा ने 15 जुलाई 2003 को इंडियन हॉकी फेडरेशन के साथ 175 लाख रुपये सालाना का क़रार किया था. इसमें हर दो साल में 10 फ़ीसदी के इज़ाफ़े की शर्त रखी गई थी. यह क़रार 2010-2011 तक का था लेकिन बाद में फेडरेशन को निरस्त कर दिया गया और हॉकी इंडिया का गठन हुआ. हॉकी इंडिया के सूत्रों के अनुसार पिछला क़रार जुलाई 2011 में ख़त्म हो गया था और इसकी मियाद छह महीने के लिए बढ़ाई गई थी. 14 जनवरी को यह भी ख़त्म हो चुकी है. अब जल्द ही नया क़रार होगा. हालांकि सहारा इंडिया के कॉरपोरेट कम्यूनिकेशन हेड अभिजीत सरकार ने एजेंसी से कहा कि इस बारे में कोई भी डील अभी फाइनल नहीं हुई है.

नोवाक जोकोविच को अवॉर्ड

दुनिया के नंबर वन टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच और दुनिया के शीर्ष फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को प्रतिष्ठित लॉरियस अवॉर्ड समारोह में क्रमश: सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और सर्वश्रेष्ठ टीम के पुरस्कारों से नवाज़ा गया है. पिछले दिनों वर्ष का पहला ग्रैंडस्लैम आस्ट्रेलियन ओपन तीसरी बार जीतने वाले जोकोविच ने पिछले सत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन ग्रैंडस्लैम और पांच मास्टर्स खिताब जीते थे. पिछले सत्र में सर्बियाई खिलाड़ी 70 मैच जीते जबकि मात्र छह में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. इसी तरह स्पेन के फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने पिछले सत्र में चमत्कारिक प्रदर्शन करते हुए स्पेनिश लीग और चैंपियंस लीग में खिताबों पर क़ब्ज़ा किया था. पिछले वर्ष वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5000 और 10000 मीटर दौड़ में खिताब जीतने वाली केन्या की लंबी दूरी की धाविका विवियन चेरियोत को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवॉर्ड मिला.

गेट वेल सून युवराज

युवराज सिंह ने अपनी बीमारी को लेकर फीजियो जतिन चौधरी का बचाव किया है. साथ ही युवराज ने बीसीसीआई पर लगाए जा रहे आरोप को भी सिरे से ख़ारिज किया है. पिछले दिनों सोशल नेटवर्किंग साइट पर भेजे अपने संदेश में युवराज ने कहा कि इस हाल के लिए मैं ख़ुद ज़िम्मेदार हूं. मैंने देखा है कि बहुत से लोग जतिन चौधरी पर आरोप लगा रहे हैं. उनकी कोई ग़लती नहीं है बल्कि उन्होंने मेरी मदद ही की है. दवा बदलने का फ़ैसला मेरा ख़ुद का था. साथ ही कुछ लोग इलाज में देरी के लिए मेरे गुरुजी और बीसीसीआई को भी ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं. बोर्ड अध्यक्ष और अन्य सदस्य ने मेरी भरपूर मदद की है और यही कारण है कि आज मुझे अच्छा इलाज मिल पा रहा है. युवराज ने अपने ट्विट पर लिखा था कि वह पहले से काफी बेहतर हैं और उनकी तबीयत में काफी सुधार हुआ है. अमिताभ बच्चन को धन्यवाद देते हुए युवी ने कहा कि विश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बच्चन सर. मेरी तबीयत में हर दिन काफी सुधार हो रहा है. युवराज ने सहयोग के लिए खेल मंत्री अजय माकन सहित नरेंद्र मोदी, उमर अब्दुल्ला और सहारा श्री का भी विशेष रूप से शुक्रिया अदा किया था. युवराज ने लिखा है कि वह अपने प्रेरणास्रोत लांस आर्मस्ट्रांग से मिलने को लेकर बेताब हैं. अंत में युवराज ने उनके निजता का ख्याल रखने के लिए मीडिया का भी शुक्रिया किया था. देश के राष्ट्रपति और क्रिकेट बोर्ड के कार्यकारी समिति के सभी सदस्यों सहित कप्तान महेला जयवर्धने, टीम के सभी सदस्य, टीम स्टाफ और श्रीलंकाई क्रिकेट के सभी खिलाड़ी हम अपने अभिन्न मित्र युवराज सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं.

सर्वश्रेष्ठ लेकिन अंतिम नहीं

भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने हाल ही में कहा है कि लंदन खेल दूसरा ओलंपिक पदक जीतने का उनका संभवत: सर्वश्रेष्ठ लेकिन अंतिम मौक़ा नहीं है. पेस ने कहा कि यह अच्छा मौक़ा हो सकता है लेकिन नहीं पता कि क्या यह मेरा अंतिम मौक़ा होगा. मेरे लिए यह संभवत: लंदन ओलंपिक में युगल स्पर्धा का पदक जीतने के मेरे सर्वश्रेष्ठ मौक़ों में से एक है. इस साल जुलाई में शुरू होने वाले लंदन खेल 38 वर्षीय पेस का छठा ओलंपिक होंगे. इस साल आस्ट्रेलियाई ओपन में चेक गणराज्य के अपने जोड़ीदार राडेक स्टेपनेक के साथ पुरुष युगल का खिताब जीतने वाले पेस करियर स्लैम पूरा करने वाले पहले और एकमात्र भारतीय हैं. वह मिश्रित युगल में भी एलेना वेसनीना के साथ फाइनल में पहुंचे थे. अटलांटा ओलंपिक 1996 में पुरुष एकल का कांस्य पदक जीतने वाले पेस ने हालांकि इस सवाल से बचने की कोशिश की कि लंदन खेलों में उनका जोड़ीदार कौन होगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

गावस्कर की नाराज़गी

लगता है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर भी टीम इंडिया से अच्छे खासे नाराज़ हैं इसीलिए उन्होंने आस्ट्रेलिया में त्रिकोणीय सीरीज़ के दौरान भारतीय टीम के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज़ों की प्रस्तावित रोटेशन नीति की पिछले दिनों आलोचना करते हुए कहा कि इससे संकेत जाता है कि खिलाड़ी अनफिट हैं. ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने भारत और श्रीलंका के बीच पर्थ में खेले गए त्रिकोणीय सीरीज़ के मैच से पूर्व कहा कि इस मैच में गौतम गंभीर या सचिन तेंदुलकर को आराम दिया जाएगा, लेकिन गावस्कर ने इस क़दम की आलोचना करते हुए कहा कि नॉकआउट चरण तक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को उतारना चाहिए.

गावस्कर ने कहा कि प्राथमिकता यह है कि संतुलित टीम उतारी जाए और मैच जीते जाएं. रोटेशन नीति से संकेत जाता है कि खिलाड़ी अनफिट हैं. उन्होंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ टीम उतारी जानी चाहिए फिर चाहे खिलाड़ी ने लगातार आठ मैच ही क्यों नहीं खेल लिए हों. अगर सभी खिलाड़ी फिट हैं तो सभी योजना का हिस्सा होना चाहिए. गावस्कर ने कहा कि अगर आप खिलाड़ियों को रोटेट कर रहे हैं तो आप खिलाड़ियों को आराम दे रहे हैं लेकिन मैच जीतने के बारे में नहीं सोच रहे. इससे संकेत जाता है कि शायद खिलाड़ी अनफिट है या सवाल उठता है कि फिजियोथेरेपिस्ट क्या कर रहा है.

स्पोर्ट्स ऑफ द वीक

वाइफ कैरिंग (भारयस्यमीथम)

इस बार के स्पोर्टस ऑफ द वीक का नाम है वाइफ कैरिंग. यानी अपनी बीबी को अपने कंधों में उठाना. सिर्फ़ उठाना ही नहीं उसे अपने कंधों पर सवार करके एक रेस भी लगानी होती है इस खेल में. यह खेल दुनिया भर के खेलों में काफी दिलचस्प माना जाता है. मूलरूप से फिनलैंड में जन्मे इस खेल की लोकप्रियता दिनोंदिन बढ़ती जा रही है. आज यह स्पोर्ट कई विदेशी मुल्कों से निकलकर भारत में भी पहुंच चुका है. हांगकांग में भी हर साल आयोजित होने वाले वाइफ कैरिंग कांपिटिशन में पतियों का जोश देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि शादी के बाद पति के मन में पत्नी के लिए प्यार कम हो जाता है. यह खेल देखिए, आपको मालूम हो जाएगा कि किस तरह से हसबैंड अपनी कमर की बिना परवाह किए भारी भरकम बीबियों को उठाकर रेस में भाग लेते हैं और विजेताओं को सम्मानित किया जाता है. सीटी बजते ही औरतें अपने अपने पतियों के कंधे पर सवार हो जाती हैं और क़रीब 250 मीटर की दौड़ शुरू हो जाती है. फिनलैंड केसोनकाजावरी शहर में हर साल यह प्रतियोगिता होती है और दुनिया भर के पति पत्नी 50 यूरो की फीस देकर शामिल होते हैं. वहीं नॉर्थ अमेरिका में यह खेल कोलंबस डे के दिन यानी अक्टूबर के वीकेंड में न्यूरी मताइन में खेला जाता है. इसके अलावा यूएसए और हांग कॉन्ग समेत कई देशों में भी यह ज़बरदस्त पॉपुलर है. इसी पॉपुलरिटी ने इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज कर दिया है. अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ़ पत्नी को कंधे में उठाकर भागने से ही आप इस रेस के चैंपियन बन जाएंगे तो एक बार और सोचिए. यह इतना आसान नहीं है. रास्ते में बाधा भी है और पानी भी. तैर कर निकलना है और छलांग भी लगानी है. पत्नी कंधे से गिर गईं तो आउट.. और बाद में पति का क्या हश्र होगा, कोई गारंटी नहीं.. इसलिए पहले ही कह दिया जाता है कि प्रतियोगी अपनी सुरक्षा का ज़िम्मा ख़ुद उठाएं और ज़रूरत समझें तो बीमा करा कर आएं. पता नहीं इसमें पत्नी से पिटाई का क्लेम मिलेगा या नहीं. कभी कभी जानलेवा भी.. अगर इस स्पोर्ट के नियमों की बात करें तो वज़न का ख्याल रखना है, पत्नी 49 किलो से कम की नहीं होनी चाहिए. अगर हो तो फिर बाक़ी का वजन किसी तरह पूरा करना होगा. जीत गए तो पत्नी के वज़न के बराबर की बीयर मिलेगी और हार गए तो. ख़ुद ही सोचिए. 14 साल से चली आ रही प्रतियोगिता हर साल लोकप्रिय होती भारत के केरला के तिरुअनंतपुरम तक आ पहुंची है. तिरुअनंतपुरम में यह प्रतियोगिता पिछले साल यानी 2011 को 1 जनवरी के दिन एकॉर्न इंडिया ने आयोजित करवाई थी. यह संस्था पर्यावरण जागरूकता अभियान से जुड़ी है. यह संस्था भारत के विभिन्न इलाक़ों में इस प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइस कराने का दावा भी करती है. अगर केरल की बात करें तो यह इस खेल को मलयाली भाषा में भारयस्यमीथम के नाम से जाना जाता है. वहीं एशियन कंट्री में इसे मटुकिनीना भी कहते हैं. अगर इसके इतिहास की बात करे तो फिनलैंड में इस खेल की शुरुआत को लेकर कई किस्से हैं. मसलन हेरको रेसवो नाम के एक चोर को इस खेल का आविष्कारक कह सकते हैं. दरअसल यह चोर 1880 के आसपास अपने गैंग के साथ गांवों में चोरी के साथ वहां की औरतों को चुराकर ले जाते थे. इसके लिए उसके गैंग के लोग औरतों को अपने कंधों पर उठाकर भागते थे. इस तरह से यह काम एक मज़बूत दमखम और मस्कुलर पॉवर वाला माना गया है. ग़ौरतलब है किसी भी खेल में मस्कुलर एक्टिविटी ही देखी जाती हैं. सो धीरे धीरे इसने एक विधिवत खेल की शक्ल लेली. और चोरी की जगह लोग अपनी पत्नियों को उठाए इस खेल में काम जाकर लेने लगे. है न मजेदार कहानी. अगले हफ्ते बात होगी किसी और दिलचस्प खेल पर.

राजेश एस कुमार
rajeshy@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 20 फरवरी–26 फरवरी 2012

पहली सफल फिल्म के बाद भाग्यश्री के भाग्य ने उनका साथ छोड़ दिया और उन्होंने कई फ्लॉप फिल्में दीं. भाग्यश्री का अभिनय के क्षेत्र में आना भी भाग्य का ही कमाल था.

राज कंवर के अंतिम संस्कार से शाहरुख़ ग़ायब!

फिल्म इंडस्ट्री को किंग ख़ान के रूप में शाहरुख़ ख़ान जैसा दिग्गज, प्रियंका चोपड़ा जैसी उत्कृष्ट अभिनेत्री और लारा दत्ता सरीखी सेंसुअल स्टार देने वाले जाने-माने निर्माता निर्देशक राज कंवर ने सिंगापुर के एक हॉस्पिटल में बीते शुक्रवार की सुबह फिल्म जगत और दुनिया को अलविदा कह दिया. काफ़ी दिनों से राज अपनी बीमारी का सिंगापुर में इलाज़ करा रहे थे. अपनी इसी बीमारी के चलते उन्होंने अपनी आख़िरी सांसे लीं. राज कंवर के इस तरह से अचानक देहांत होने की ख़बर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है. राज कंवर के पार्थिव शरीर को सिंगापुर से मुंबई लाकर ओशिवारा इलाक़े की शमशान भूमि में सुपर्दे खाक़ कर दिया गया. राज कंवर ने अपने फिल्मी करियर में कई नए चेहरों को रूपहले परदे पर मौक़ा दिया. इन चेहरों में शाहरुख़ ख़ान, प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता प्रमुख हैं. सबसे दुखद बात ये है कि अपने आख़िरी वक़्त में इतने बड़े सितारों की खोज करने वाले राज के अंतिम संस्कार के वक़्त फिल्म इंडस्ट्री के बहुत कम चेहरे इस महान शख्सियत को अलविदा कहने पहुंचे. क्या सिर्फ़ मीडिया में बयानबाज़ी को ही अफसोस ज़ाहिर करना कहते हैं. चाहे वो शाहरुख ख़ान हो या फिर प्रियंका चोपड़ा. किसी ने भी ज़हमत नहीं उठाई कि वो राज के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी और इंसानियत के नाते उनके आख़िरी सफ़र में शामिल हों और राज के परिवार को सांत्वना देने पहुंचे. हालांकि यहां सिर्फ़ शाहरुख़ और प्रियंका को दोषी ठहराना ग़लत होगा. दरअसल, ये फिल्म इंडस्ट्री ही ऐसी है. यहां सब उगते सूरज को ही सलाम करते हैं. इतनी बड़े फिल्म जगत से सिर्फ़ सुनील दर्शन, फरहा खान, लव सिंहा, मनोज वाजपेई, अल्का याग्निक, निर्देशक जोड़ी अब्बास-मस्तान और रजा मुराद ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. काफी समय तक राजकुमार संतोषी के सहायक निर्देशक रहे राज कंवर ने अपनी पहली ही फिल्म दीवाना में शाहरुख़ को लेकर सफलता के झंडे गाड़ दिए थे. फिल्म दीवाना की अपार सफलता के बाद राज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी प्रतिभा के दम पर उन्होंने संजय दत्त अभिनीत दाग़ द फायर, अनिल कपूर अभिनीत लाडला, अजय देवगन अभिनीत जान, सलमान ख़ान और सनी देओल अभिनीत जीत, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा अभिनीत अंदाज़ और अक्षय, कैटरीना को लेकर हमको दीवाना कर गए जैसी हिट फिल्में दी हैं. राज अपने पीछे अपनी पत्नी अनिता और बड़े बेटे (20) करन कंवर और छोटे बेटे(16) अबय कंवर को छोड़ गए है. चौथी दुनिया का परिवार इस महान शख्सियत को तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे.

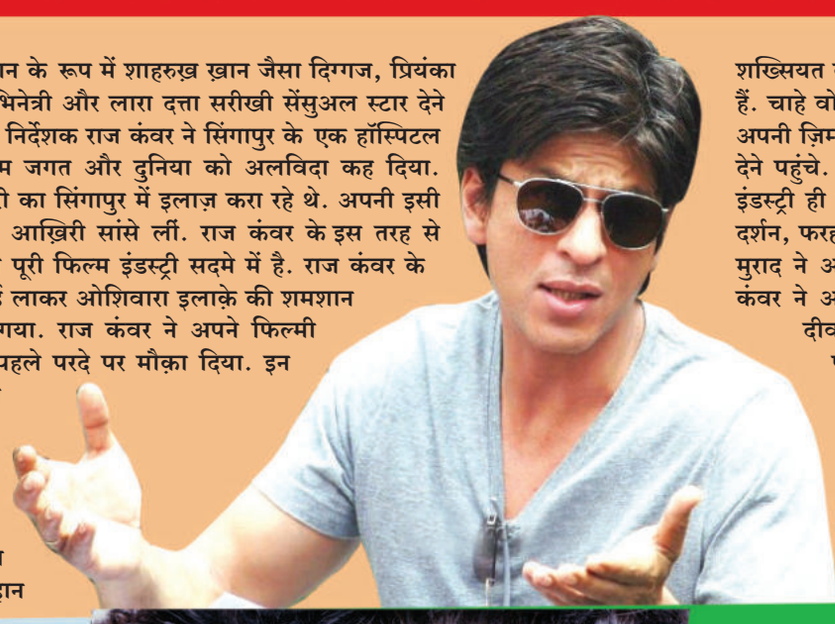

एम्मा वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल फेस बनीं

अभिनेत्री और मॉडल एम्मा वॉटसन के चेहरे को 2011 का वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल फेस घोषित किया गया है. 100 सबसे ख़ूबसूरत चेहरों की 22वीं वार्षिक स्वछंद समालोचक सूची में एम्मा ने सबको हराकर पहला स्थान पाया है. हैरी पॉटर की एक्ट्रेस 21 वर्षीय अभिनेत्री को लावण्य, सुडौलपन, आत्मविश्वास, प्रसन्नता, आशा और सुंदर चेहरे की कसौटी पर खरा उतरने पर पहला स्थान दिया गया है. इस लिस्ट में एक्ट्रेस और रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट रिहाना, सिंगर मारियां कॉटिलॉर्ड और अंबर हर्ड पहले 10 स्थान पर रहीं. मिला कुनिस इस सूची में स्थान बना पाने में सफल रहीं, लेकिन अभिनेत्री एंजेलीना जोली और जेनिफिर एनिस्टन को तो इसमें जगह तक नसीब नहीं हुई. एम्मा वॉटसन उन एक्ट्रेस में से एक हैं, जो बहुत ही व्यावहारिक हैं. प्रसिद्धि से उनके व्यवहार में बदलाव नहीं आया और वह हमेशा सहज ही रही हैं. इसके अलावा उनमें फैशन की भी काफ़ी समझ है. कुल मिलाकर एम्मा बेहद ही ख़ूबसूरत हैं. इसके अलावा एक वेबसाइट द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार एम्मा वॉटसन सेकंड मोस्ट डिजायरेबल वुमेन ऑन अर्थ भी घोषित की गई हैं. इसके लिए पूरे विश्व के 150,000 लोगों ने उन्हें वोट किया है, जबकि एम्मा ख़ुद को ऐसा नहीं मानती हैं. दरअसल वह अपने स्टाइल, फैशन सेंस और लुक्स को बिल्कुल बेकार और बोरिंग बताती हैं.

कंगना को पसंद है लव स्टोरी

अपने अब तक के फिल्मी करियर में कंगना रानावत ने काफ़ी उतार-चढ़ाव का सामना किया है. बॉलीवुड में क़दम रखने के बाद उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन कंगना ने हार नहीं मानी और अंतत: वह अपनी पहचान बनाने में सफल रहीं. ऐसी कामयाबी मिलने के बाद उन्होंने अपने अंदर भी कुछ बदलाव महसूस किया, जिसमें प्रमुख है उनका आत्मविश्वास बढ़ना. इसके अलावा नॉलेज बढ़ी है और हिम्मत भी. वह कहती हैं कि पहले की तरह अब हर कोई मुझे हिट नहीं कर सकता. मेरे अंदर एक एटीट्यूड भी आया है, जो हर कामयाब इंसान के अंदर आता है. यह अकड़ या घमंड नहीं है, बल्कि ख़ुद पर भरोसा है और यह उन्हें पसंद है. कंगना ने करियर की शुरुआत सीरियस रोल्स से की और इधर हल्के-फुलके रोल भी किए, लेकिन उन्हें सीरियस रोल करना ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि वह ख़ुद असलियत में काफ़ी मस्ती पसंद हैं. कैमरे के सामने सीरियस दिखने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है. वैसे एक दर्शक के तौर पर उन्हें लव स्टोरीज ज़्यादा पसंद हैं. प्यार करना, फिर उसमें दिक़्क़तें आना और आख़िर में हीरो-हीरोइन का मिल जाना. यह सब उन्हें बहुत अच्छा लगता है. कई बार कंगना की आवाज़ और लहजे की आलोचना होती है, लेकिन इस पर वह कहती हैं कि आवाज़ उन्हें ऊपर वाले ने दी है, जिसे वह बदल नहीं सकतीं. रानी मुखर्जी का उदाहरण रखते हुए कहती हैं कि आवाज़ के बारे में पहले रानी मुखर्जी को भी बहुत कुछ कहा गया था, लेकिन जैसे-जैसे वह कामयाब होती गईं, लोग चुप होते चले गए. रही लहजे की बात, तो वह नेचुरल है. सक्सेस सब बुराइयों को ढंक देती है.

आज भी उतनी ही सुंदर हैं भाग्यश्री

क्रीम कलर के सलवार सूट में जैसे ही वह काले रंग की मर्सिडीज से उतरीं, लोग अपलक उन्हें देखते ही रह गए. वह थीं ही कुछ ऐसी. जी हां, यह और कोई नहीं मैंने प्यार किया की चुलबुली सुमन यानी अभिनेत्री भाग्यश्री थीं. बनारस की धरती पर जब भाग्यश्री ने क़दम रखा, तब उतनी ही ख़ूबसूरत लग रही थीं, जितनी तक़रीबन 22 साल पहले अपनी फिल्म में लगती थीं. पहली ही फिल्म में अपनी चुलबुली और शोख़ अदाओं से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली भाग्यश्री एक बार फिर से बॉलीवुड में अपने टैलेंट का जादू बिखरने वाली हैं. विचारों से साधारण भाग्यश्री को बनारस से ख़ास लगाव है. काफ़ी समय बाद बनारस आने पर भाग्यश्री यह कहने से नहीं चूकीं कि बनारस में बहुत कुछ बदल गया है. बड़े-बड़े शोरूम और मॉल्स खुल गए हैं. बनारस भी अल्ट्रा मॉडर्न हो रहा है. हालांकि उन्हें ख़ुशी है कि यहां के लोग दिल से बातें करते हैं, जबकि बड़े शहरों में ऐसा नहीं है. उन्हें एक अजीब सा अपनापन देता है यह शहर. उन्होंने बनारस के मूलरूप को बनाए रखने की ज़िम्मेदारी युवाओं पर डालते हुए कहा कि पश्चिमीकरण में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके साथ अपनी परंपरा और संस्कृति का भी ध्यान रखना होगा. हम टेक्नोलॉजी विदेशों से लें, लेकिन अपने सभ्यता को न भूलें. वैसे बनारस की पहचान गंगा से है. वह गंगा आरती की मुरीद हैं. हिंदी फिल्मों में भाग्यश्री का भाग्य एक धमाके की तरह शुरू हुआ, पर जितना आगे चलने की उम्मीद थी वह उतना नहीं चल सकीं. उन्होंने परिवार को ज़्यादा महत्व दिया. महाराष्ट्र के शाही परिवार पटवर्धन में 23 फरवरी, 1969 को उनका जन्म हुआ. भाग्यश्री का पूरा नाम श्रीमंत राजकुमारी भाग्यश्री राजे पटवर्धन है. उनके पिता का नाम मेहरबान श्रीमंत राजा विजय सिंह राव माधोराव पटवर्धन है. भाग्यश्री ने फिल्मों की शुरुआत 1989 में फिल्म मैंने प्यार किया, से की, जिसमें उनके साथ सलमान ख़ान नज़र आए थे. भाग्यश्री की पहली ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम किया. हालांकि पहली सफल फिल्म के बाद भाग्यश्री के भाग्य ने उनका साथ छोड़ दिया और उन्होंने कई फ्लॉप फिल्में दीं. भाग्यश्री का अभिनय के क्षेत्र में आना भी भाग्य का ही कमाल था. उनके पड़ोसी और मशहूर टीवी एंकर अमोल पालेकर ने उनसे अभिनय करने को कहा और कच्ची धूप नामक टीवी शो में भाग्यश्री ने काम करना शुरू किया. यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा और देखते ही देखते भाग्यश्री लोगों की चहेती बन गईं. भोली सी सूरत, मनमोहक मुस्कान और क़ातिलाना अदाओं वाली भाग्यश्री ने अपने बचपन के दोस्त हिमालय दासानी के साथ शादी की थी. शादी के बाद भाग्यश्री ने फिल्मों से किनारा कर लिया. हालांकि उन्होंने पूरी तरह फिल्मों से किनारा नहीं किया, बल्कि उनकी मांग थी कि जिस फिल्म में वह हीरोइन होंगी, उसमें हीरो उनके पति ही होंगे. अब यह बात निर्माताओं और निर्देशकों को रास नहीं आई और नतीजतन उनका फिल्मी करियर बुरी तरह गिर गया. सिर्फ़ एक ही फिल्म से जिस भाग्यश्री को बॉलीवुड में सबने सराहा था, उसे अब कोई पूछता भी नहीं. लेकिन भाग्यश्री ने कभी हार नहीं मानी और थोड़े-थोड़े अंतराल पर वह फिल्मों में नज़र आ ही जाती हैं. उन्होंने अपने छोटे से करियर में बहुत सी चर्चाएं बटोरीं. शुरुआती दिनों में उनका नाम सलमान ख़ान के साथ भी जुड़ा था.

आमिर की राह पर इमरान

अपने अंकल की राह पर चलते हुए बॉलीवुड अभिनेता इमरान ख़ान भी समाज को एक नया नज़रिया देने की कोशिश में लगे हैं. आमिर ख़ान ने अभिभावकों को डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के प्रति नया नज़रिया दिया तो कभी सामाजिक स्थितियों पर एक दुखभरी दास्तान पीपली लाइव के रूप में पेश की. उन्हीं के नक़्शे-क़दम पर चलते हुए उनके भतीजे इमरान ख़ान ने पत्रकारों को पत्रकारिता के कुछ सुझाव दिए हैं. उनकी मानें तो एक अच्छा साक्षात्कार प्रश्न पत्र न होकर एक अच्छी बातचीत जैसा होना चाहिए. एक कार्यक्रम में 29 वर्षीय इमरान ने कहा, अधिकतर पत्रकारों के पास प्रश्न पत्र होते हैं, जिनमें आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? आपकी घूमने की पसंदीदा जगह? आपको ख़ाली समय में क्या करना पसंद है, जैसे प्रश्न होते हैं. यह साक्षात्कार नहीं होता, बल्कि प्रश्नावली होती है. मैं समझता हूं कि एक अच्छा साक्षात्कार चाहे वह अख़बार के लिए हो, टीवी या रेडियो के लिए हो, उसे बातचीत जैसा होना चाहिए. 50 प्रतिशत काम आपका होना चाहिए और 50 प्रतिशत मेरा. इमरान ने बताया कि अगर उन्हें कभी पत्रकारिता करने का मौक़ा मिला, तो वह अभिनेता सलमान ख़ान का साक्षात्कार लेना चाहेंगे, जो उनके मुताबिक़ ख़ुद को शायद ही खोलते हैं. एक ऐसा साक्षात्कार जिसमें सलमान ख़ान ख़ुद को पूरी तरह उजागर करने को तत्पर हों. विशाल भारद्धाज के निर्देशन में बन रही इमरान की अगली फिल्म मटरू की बिजली का मनडोला की शूटिंग की शेड्यूलिंग 14 फरवरी से की गई है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

फिल्म प्रीव्यू

तेरे नाल लव हो गया

बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख और अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा अभिनीत फिल्म तेरे नाल लव हो गया 24 फरवरी को रिलीज होगी. जेनेलिया और रितेश की आगामी फिल्म का निर्माण यूटीवी मोशन पिक्चर्स एंड टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किया है. इस फिल्म की कहानी दो ऐसे लोगों पर आधारित है, जो असामान्य हालात के कारण एक-दूसरे के साथ जुड़ते हैं. इसके बाद दोनों की ज़िंदगी बदल जाती है. ग़ौरतलब है कि दोनों सात साल के बाद किसी फिल्म में एक साथ काम कर रहे हैं. कहते हैं न प्यार के रिश्ते वही निभा सकता है, जो प्यार को समझता हो. इसलिए कुमार तौरानी ने अपनी फिल्म के लिए उन दो सितारों को चुना, जो वाक़ई में एक-दूसरे को प्रेम करते हैं यानी रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा. ये दोनों एक साथ तौरानी की फिल्म तेरे नाल लव हो गया में नज़र आने वाले हैं. प्रोड्यूसर का कहना है कि उनकी कहानी की मांग थी ऐसे किरदारों की जो एक-दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और ये रोल वही निभा सकते हैं, जो रीयल लाइफ में एक-दूजे से प्यार करते हों, समझते हों. इसलिए उन्होंने रितेश-जेनेलिया को चुना है. सेट वाले बताते हैं कि लविंग लव बड्र्स को जब भी शूटिंग से फुर्सत मिलती है तो दोनों एक-दूजे के साथ समय बिताने निकल जाते हैं. दोनों सेट पर भी काफ़ी मस्ती करते थे. तेरे नाल लव हो गया, एक प्रेम कहानी है. इससे पहले दोनों ने साथ में तुझे मेरी क़सम फिल्म में काम किया था. दोनों ने आख़िरी बार वर्ष 2004 में मंदीप कुमार के निर्देशन में बनी प्रेम पर आधारित हास्य फिल्म मस्ती में काम किया था. लेकिन इसके बाद दोनों रील लाइफ में नहीं, बल्कि रीयल लाइफ में नज़र आए और अब उनकी शादी भी हो गई. देखना दिलचस्प होगा कि यह जोड़ी पर्दे पर क्या रंग जमाती है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

दिल्ली, 20 फरवरी–26 फरवरी 2012

www.chauthiduniya.com

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

वक़्फ़ की ज़मीन पर कॉरपोरेट घरानों का क़ब्ज़ा

मयूर रंगारी

आबादी का एक बड़ा हिस्सा तड़प रहा है. यह तड़प रोटी, कपड़ा या मकान के लिए नहीं है, बल्कि अपने वजूद को बचाए रखने के लिए हैं. उसकी आंखों के सामने उसके वजूद को मिटाने की साज़िश रची जा रही है. यह साज़िश हर उस राजनीतिक पार्टी ने रची है, जिसने महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई. सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को वक़्फ़ की संपत्तियों का सर्वे कर वक़्फ़ बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया है, लेकिन सरकार सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन इस मामले में तारीख़ लेने के सिवा कुछ नहीं कर रही है. यही वजह है कि राज्य में वक़्फ़ बोर्ड की अरबों रुपये की संपत्ति पर अतिक्रमण किया जा चुका है. इन अतिक्रमणकारियों में देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी से लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के भाई दिलीप देशमुख के नाम भी शामिल हैं. इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी सरकार उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से कतरा रही है. देशभर में वक़्फ़ बोर्ड की लगभग 5 लाख 72 हज़ार 52 एकड़ ज़मीन है. राज्य में 92 हज़ार 207 एकड़ वक़्फ़ संपत्ति है. इनमें सबसे ज़्यादा मराठवाड़ा के औरंगाबाद, नांदेड़, लातूर, जालना, बीड और परभणी ज़िले में 58 हज़ार 143 एकड़ ज़मीन वक़्फ़ बोर्ड के अधीन आती है. राज्य में 27 हज़ार 539 वक़्फ़ इंस्टीट्यूशन हैं, जिन्हें वक़्फ़ बोर्ड नियंत्रित करता है. इनमें मस्जिद, ईदगाह, इमामबाड़ा, यतीमख़ाना, दरगाह, ख़ानकाह, मक़बरा, अशूर ख़ाना, चिल्ला व क़ब्रिस्तान का समावेश है. इन संस्थाओं की देखरेख के साथ-साथ इनके मुतवल्लियों व पदाधिकारियों को वेतन देने की ज़िम्मेदारी वक़्फ़ बोर्ड की होती है. इसके बावजूद महाराष्ट्र में वक़्फ़ बोर्ड का गठन सही तरीक़े से नहीं किया गया है. नियमानुसार बोर्ड में 11 सदस्य होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में सिर्फ़ 2 सदस्य ही हैं. इनमें तारिक अनवर और मौलाना वस्तानवी भी शामिल हैं. तारिक अनवर बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं. बोर्ड का कोरम पूरा नहीं होने से इसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती. यही कारण है कि वक़्फ़ बोर्ड की अरबों रुपये की ज़मीन या तो बेच दी गई या फिर उस पर अतिक्रमण हो गया है. हालांकि वक़्फ़ क़ानून में स्पष्ट है कि कोई भी वक़्फ़ संपत्ति नहीं बेची जा सकती, लेकिन सही नियंत्रण के अभाव में अरबों रुपये की वक़्फ़ संपत्ति की बंदरबाट की जा रही है.

बग़ैर सर्वे के कैसे होगा गठन

वक़्फ़ बोर्ड के गठन के लिए धारा 99 के तहत सबसे पहले वक़्फ़ संपत्तियों का सर्वे ज़रूरी है. सर्वे के अनुसार जिस समुदाय की जितनी संपत्ति है, उसे उसी आधार पर बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है. यदि सर्वे में शिया समुदाय की संपत्ति अधिक पाई जाती है, तो उसका अलग बोर्ड बनाने के निर्देश क़ानून में हैं. यहां हैरानी की बात यह है कि मुस्लिम समाज के विकास का दावा करने वाली कांग्रेस-राकांपा सरकार ने अब तक इसका सर्वे नहीं कराया है. ग़ौरतलब है कि वर्ष 2002 में सरकार ने महाराष्ट्र राज्य वक़्फ़ बोर्ड बनाया था. कोरम पूरा करने के मामले पर वर्ष 2011 में कुछ लोगों ने वक़्फ़ बोर्ड को निष्क्रिय बताते हुए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था और उसे दोबारा बॉम्बे पब्लिक एक्ट के तहत लाने की बात कही थी. न्यायालय ने अपने आदेश में राज्य सरकार को तत्काल सर्वे कराने के निर्देश दिए थे. इस फ़ैसले को राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है. सर्वोच्च न्यायालय ने भी सर्वे का काम पूरा कर 16 जनवरी, 2012 तक वक़्फ़ बोर्ड गठित करने के निर्देश दिए थे, लेकिन राज्य सरकार निर्देशों का पालन करने की बजाय अदालत से केवल तारीख़ें ले रही है.

सच्चर कमेटी की सिफ़ारिशें नहीं मानीं

राज्य में पूरी वक़्फ़ संपत्ति का 10वां हिस्सा शहरी क्षेत्र में है, यानी लगभग 10 हज़ार एकड़ ज़मीन. अकेले पुणे ज़िले में लगभग 500 हेक्टेयर ज़मीन है. इसमें कुछ ज़मीन की बाज़ार क़ीमत लगभग 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ है. इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अरबों रुपये की वक़्फ़ संपत्ति राज्य के प्रमुख शहरों में महत्वपूर्ण जगहों पर है. यही वजह है कि इस पर अतिक्रमणकारियों की नज़रें हमेशा बनी रहती हैं. इनमें कई संस्थाओं, मुतवल्लियों (अध्यक्ष), मदरसों और अन्य लोगों का समावेश है. सच्चर कमेटी और रंगनाथ आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वक़्फ़ भूमि से अतिक्रमण को हटाया जाए और इससे नियमित आय के साधन ढूंढे जाएं, तो न सिर्फ़ मुस्लिम समाज के हज़ारों युवाओं को रोज़गार मिलेगा, बल्कि इससे इतनी राशि हर वर्ष आ सकती है, जिससे मुस्लिम समाज की अधिकतर समस्याओं का हल निकाला जा सके. लेकिन राज्य सरकार ने इन सिफ़ारिशों को भी कचरे की टोकरी में डाल दिया है. इससे ज़ाहिर होता है कि राज्य सरकार का मुस्लिम समाज के विकास का दावा कितना खोखला है. एक तरफ़ सरकार समिति और आयोग बनाकर करोड़ों रुपये ख़र्च करती है, वहीं जब उनकी सिफ़ारिशें आती हैं, तो उन्हें लागू नहीं करती. इससे राज्य सरकार का दोहरा चरित्र साफ़ नज़र आता है.

feedback@chauthiduniya.com

मुस्लिम समाज के अधिकारों का हनन: शरीफ़

अल्पसंख्यक मामलों के जानकार शाहिद शरीफ़ ने कहा कि वक़्फ़ बोर्ड का गठन नहीं होना मुस्लिम समाज के अधिकारों का हनन है. उन्होंने जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए. शरीफ़ ने कहा कि 50 हज़ार करोड़ रुपये की संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है. जिस वक़्फ़ बोर्ड के माध्यम से मुस्लिम समाज के शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य समस्याओं का हल निकाला जा सकता है, आज उसके गठन को लेकर राजनीति हो रही है. उन्होंने कहा कि नवंबर 2011 में वक़्फ़ संपत्ति की विस्तृत जानकारी सूचना अधिकार कार्यालय से मांगी थी, लेकिन उन्हें अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है. उन्होंने वक़्फ़ संपत्तियों का जल्द से जल्द सर्वे कर वक़्फ़ बोर्ड का गठन करने और बोर्ड में बाहर के लोगों को न लाकर स्थानीय जनता को प्रतिनिधित्व देने की मांग की. शरीफ़ ने कहा कि यदि सर्वोच्च न्यायालय में भी इस मामले का सही हल नहीं निकल पाया, तो उनकी अगली तैयारी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाने की होगी.

मराठवाड़ा पहले अलग था

राज्य में सबसे अधिक वक़्फ़ संपत्ति मराठवाड़ा रीजन में है. अल्पसंख्यक मामलों के जानकार शाहिद शरीफ़ ने बताया कि वर्ष 2002 तक मराठवाड़ा के औरंगाबाद, नांदेड़, लातूर, जालना, बीड़ और परभणी ज़िलों की वक़्फ़ संपत्तियां मराठवाड़ा रीजन वक़्फ़ एक्ट 1954 के अधीन आती थीं. वहीं राज्य के अन्य क्षेत्र की वक़्फ़ संपत्तियां बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट चैरिटी कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र के अधीन थीं. महाराष्ट्र में वर्ष 1995 में वक़्फ़ क़ानून बना और इसे 1 जनवरी, 1996 में लागू किया गया, जबकि इस पर वर्ष 2002 में अमल शुरू हुआ. इसके बाद मराठवाड़ा रीजन सहित पूरे राज्य की वक़्फ़ संपत्तियां इसी क़ानून के तहत आ गईं. इसके पहले अध्यक्ष एमए अज़ीज़ (वर्ष 2002-2006 तक) थे. वक़्फ़ ज़मीनों पर अतिक्रमण और उन्हें हड़पने का सबसे चर्चित मामला देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी से जुड़ा है. मुकेश अंबानी ने मुंबई में 500 करोड़ रुपये की लागत से 27 मंज़िला अपना आलीशान घर एंटीलिया बनाया है, लेकिन यह घर जिस ज़मीन पर बना है वह वक़्फ़ बोर्ड की बताई जा रही है. हालांकि यह मामला न्यायालय में प्रलंबित है. जानकारों के अनुसार इस ज़मीन के मालिक करीम भाई इब्राहिम भाई खोजा थे. इनका एक ट्रस्ट था, जिसके माध्यम से खोजा समाज के बच्चों के लिए यतीमख़ाना चलाया जाता था. यह ट्रस्ट बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट चैरिटी कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र के अधीन था. आरोप है कि अंबानी ने करीम भाई से यह ज़मीन वर्ष 2002 में 21 करोड़ में ख़रीदी, जबकि इसकी वास्तविक क़ीमत 200 करोड़ रुपये है. ज़मीन की ख़रीद-फ़रोख्त होने के बाद इस पर हंगामा शुरू हुआ. पूरा मामला जब वक़्फ़ बोर्ड के पास पहुंचा, तो बोर्ड ने उक्त भूमि को चुनौती देने के लिए दोनों पार्टियों को बुलाया, लेकिन केवल अंबानी के ही लोग आए. खोजा ट्रस्ट से कोई भी नहीं आया. इससे साबित हो गया कि यह ज़मीन वक़्फ़ बोर्ड की है. जब इसे क़ब्ज़े में लेने की बात हुई, तो अंबानी ने वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में याचिका दाख़िल की. वहां भी यही आदेश दिया गया. बाद में बोर्ड ने ट्रस्ट को 16 लाख रुपये जमा करने का आदेश देकर इसमें अंबानी को राहत देने की कोशिश की. आरोप है कि बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष एम.ए. अज़ीज़ ने तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के कहने पर यह किया. बाद में यह मामला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा. सर्वोच्च न्यायालय ने 21 मई 2008 को इसे उच्च न्यायालय में ही हल करने के आदेश दिए. बाद में हुई उच्चस्तरीय जांच में यह सामने आया कि वक़्फ़ बोर्ड ने मुंबई मनपा को नोटिस भेजकर अंबानी के घर के निर्माण का काम रोकने के लिए कहा था, लेकिन मुंबई मनपा ने वक़्फ़ बोर्ड की अन्य विवादित संपत्तियों के निर्माण पर रोक लगा दी. हालांकि अंबानी के एंटीलिया भवन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की. ऐसे में सवाल यह उठता है कि आख़िर मुकेश अंबानी को राहत क्यों दी गई? एक अन्य मामला पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख के भाई दिलीप देशमुख से जुड़ा है. दिलीप देशमुख ने औरंगाबाद में एक हाउसिंग सोसायटी बनाई और वहां बिजनेस कॉम्प्लेक्स का काम शुरू किया. बताया जाता है कि यह ज़मीन भी वक़्फ़ बोर्ड के अधीन है. वहां क़ब्रिस्तान और मस्जिद है. इस निर्माण कार्य का पूरे औरंगाबाद में विरोध हुआ. इसके बाद तत्कालीन सीओ (वर्ष 2006-2008) एआर शेख़ ने उक्त सोसायटी को नोटिस दिया. इसके विरोध में सोसायटी न्यायालय में गई है. ऐसे कई मामले हैं, जिनमें अरबों रुपये की वक़्फ़ संपत्ति पर अवैध रूप से क़ब्ज़ा किया गया है. विधायक नवाब मलिक ने इन सभी मामलों की सीबीआई जांच कराने की मांग की है.

प.पू.सद्गुरु श्री प्रल्हाद महाराज (रामदासी)
साखरखेर्डा, जिला बुलढाना

जयंती के पावन अवसर पर
।। शत् शत् कोटी प्रणाम।।

प्रवीण महाजन और
साप्ताहिक चौथी दुनिया परिवार

महाराष्ट्र हलचल

नागपुर में दलित इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (डिक्की) के छठे केंद्र का उद्घाटन करते डिक्की के अध्यक्ष मिलिंद कांबले, विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रफुल्ल दोशी और अखिल भारतीय व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष बी.सी. भरतिया.

चंद्रपुर में आयोजित 85वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के समापन समारोह में...

अकोला के प्रमिलाताई ओक सभागृह में कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में आयोजित जनजागृति कार्यक्रम...

वाशिम ज़िले के मालेगांव में दिगंबर जैन महासमिति की महिला शाखा द्वारा आयोजित सम्मेलन में शामिल समाज की महिलाएं.

बर्ड फ्लू का साया

प्रशासन ख़तरे से बेख़बर है

क्या महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू लौट आया है? राज्य के गोंदिया ज़िले की सड़क अर्जुनी, अर्जुनी मोरगांव एवं तिरोडा तहसील और भंडारा ज़िले की साकोली तहसील में अचानक 60 से अधिक कौओं की मौत ने प्रशासन के कान खड़े कर दिए हैं. कौओं के ख़ून के नमूने भोपाल स्थित प्रयोगशाला में भेजे गए थे, जिसमें इनकी मौत एच-5 वायरस से होने की पुष्टि हुई है. मामला उस वक्त गंभीर हो गया, जब कौओं के बाद मैना और सुअर के भी मरने की ख़बरें आईं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि इससे निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका है? इस घटना के बाद प्रशासन की तैयारियों का जायज़ा लिया गया...

उड़ीसा में बर्ड फ्लू

उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन (सीपीडीओ) स्थित एक चूजे में एच-5 एन-1 विषाणु पाया गया है, बताया जाता है कि जनवरी माह में राज्य के खुर्दा ज़िले के केरंगा और मयूरभंज ज़िले के बेतनाती में मुर्गियों को मारे जाने के बाद भुवनेश्वर में बर्ड फ्लू के विषाणु की मौजूदगी पाई गई है. कुछ मुर्गियों के ख़ून के नमूने भोपाल स्थित केंद्रीय प्रयोगशाला में भेजे गए थे, जिनमें से एक नमूने में बर्ड फ्लू के विषाणु की पुष्टि की गई है.

वैक्सिन नहीं है

बर्ड फ्लू से मुर्गियों को बचाने के लिए कोई वैक्सिन नहीं है. ऐसे में जहां मुर्गियों में बर्ड फ्लू के विषाणु पाए जाते हैं, वहां और उसके आसपास की मुर्गियों को मारकर, उन्हें गड्ढे में गाड़ा जाता है. वहीं अन्य स्थानों पर स्थित मुर्गियों में यह बीमारी न आए इसलिए उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु उन्हें रानीखेत आरडी का टीका लगाया जाता है.

स्वास्थ्य विभाग के निर्देश नहीं आए

किसी भी आपदा के दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से हमें निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन बर्ड फ्लू के संबंध में अब तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं. बर्ड फ्लू से ग्रसित व्यक्ति में सामान्य बुख़ार के जैसे लक्षण होते हैं. यदि बर्ड फ्लू से संबंधित कोई मामला अस्पताल में आता है, तो हम उसका इलाज करने में पूरी तरह से सक्षम हैं.

डॉ. वाकोडे, अधिष्ठाता (मेयो)

हालात पर नज़र है

बर्ड फ्लू से कौओं की मौत की जानकारी मिली है. हम पूरी स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं. यदि यह बीमारी मुर्गियों में भी आती है, तो यह अधिक चिंता की बात होगी.

डॉ. मनोहर पवार, उपसंचालक, स्वास्थ्य विभाग

सभी पशु अस्पतालों में अलर्ट जारी

कौओं की मौत की घटनाएं सामने आने के बाद हमने सभी पोल्ट्री फार्म और विभाग के सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं. एक लाख से भी अधिक प्रिवेंटिव वैक्सिन मंगवाई गई हैं.

डॉ. के.एस. भिड़े, सहायक संचालक, पशुसंवर्धन विभाग

डॉक्टर महीने में दो बार आते हैं

नागपुर ज़िले के गोरेवाड़ा से लेकर खंडाला मार्ग पर स्थित पोल्ट्री फार्म मालिकों ने बताया कि बर्ड फ्लू होने पर काफ़ी संख्या में मुर्गियों की मौत हो जाती है...

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

महिलाओं के बीच फंसे नेता

ये क्या हो रहा है...

हर चुनाव में असंतोष के नायकों के दर्शन होना सामान्य बात है, लेकिन महत्वाकांक्षा से सराबोर असंतोष की नायिकाओं का चंडी रूप पहले कभी-कभी ही देखने को मिलता था. हालांकि अब वे भी सड़कों पर खुलकर अपना विरोध व्यक्त करने लगी हैं...

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

स्पैनको का कमाल

ग़रीब को लाखों का बिजली बिल भेजा

शुरुआत से ही विवादों में घिरी स्पैनको कंपनी का एक और कारनामा सामने आया है. कंपनी द्वारा बिजली मीटर ख़राब होने की बात कहकर एक ग़रीब महिला को 10 लाख रुपये का बिजली बिल भेजा गया है. मज़े की बात यह है कि इससे पहले महिला को 200 से 300 रुपये तक का ही बिजली बिल आता था. इस मामले ने जब तूल पकड़ा, तो तुरंत स्पैनको के अधिकारियों ने लाखों के बिल को 350 रुपये में बदल दिया.

स्पैनको कंपनी के पास नागपुर शहर में विद्युत वितरण और बिल वसूली की ज़िम्मेदारी महावितरण कंपनी ने दी है. कंपनी शुरुआत से ही विवादों में रही है. कंपनी द्वारा विद्युत वितरण की कमान संभालते ही नागपुर शहर के विद्युत ग्राहकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था. 4-5 दिन कहीं बिजली, तो कहीं अंधकार की स्थिति थी. वहीं कंपनी के इंजीनियरों द्वारा कई ट्रांसफार्मर ख़राब किए जाने की भी घटना हुई थी. इसका महावितरण के कर्मचारी संगठन ने भी विरोध किया था. दूसरी ओर कंपनी के विरोध में शहर के कई सामाजिक संगठनों ने मोर्चे निकाला और धरना दिया. जब बिल वसूली की ज़िम्मेदारी महावितरण कंपनी के पास थी, तो लोगों को अनाप-शनाप बिल भेजने की कई घटनाएं होती थीं. स्पैनको के आने पर इस तरह की घटनाएं नहीं होने की उम्मीद लोगों में थी, लेकिन बिजली उपभोक्ताओं के लिए शराब वही, बोलत नई जैसी स्थिति हो गई है. उत्तर नागपुर के पंचशील नगर निवासी और पेशे से दर्ज़ी सुवर्णा गौतम चालखुरे को कंपनी ने जनवरी माह में 9 लाख 89 हज़ार 700 रुपये का बिल भेजा. 30 जनवरी तक बिल नहीं भरने पर 10 लाख 9 हज़ार 490 रुपये भरने की बात बिल में कही गई है. हैरत की बात यह है कि सुवर्णा चालखुरे को अब तक 200 से 300 रुपये का ही बिल आया है. ऐसे में अचानक लाखों रुपये का बिल देखकर उसकी सास की तबीयत ख़राब हो गई. उसने जब बिल की शिकायत स्पैनको के अधिकारियों से की तो उसे तीन घंटे तक कार्यालय में ही बिठाए रखा गया. जब उसने अधिकारियों से इस संबंध में पूछा तो उसके साथ बदसलूकी भी की गई. इतना ही नहीं उसका बिजली कनेक्शन तक काटने की धमकी दी गई. इस घटना के बारे जब सार्वजनिक तौर पर चर्चा होने लगी तो स्पैनको के अधिकारियों ने फौरन दस लाख रुपये के भारी भरकम बिल को 350 रुपये के बिल में बदल दिया. सवाल यह उठता है कि आख़िर लाखों का बिल सैकड़ों में कैसे तब्दील हो गया? यदि बिल में ग़लती थी तो स्पैनको के अधिकारियों ने पहले ही इसे दुरुस्त क्यों नहीं किया. उधर, सुवर्णा ने कंपनी से मुआवज़े की मांग की है. उसका कहना है कि मामला केवल बिल तक सीमित नहीं है. यदि यह बात किसी बड़े अधिकारी या अमीर व्यक्ति के घर की होती तो उसके साथ वैसा सलूक नहीं किया जाता, जैसा उसके साथ हुआ. सुवर्णा ने कहा कि उसका परिवार ग़रीब ज़रूर है, लेकिन इज्ज़त से जीता है. वह और उसका पति मेहनत कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं. कोई भी उन्हें बेइज्ज़त नहीं कर सकता. उसने अपनी बेइज्ज़ती के लिए कंपनी से मुआवज़े की मांग की है.

सरकार लापरवाह

ऐसे कई मामले हैं, जिनमें कंपनी ने ग्राहकों को मनमाने बिल भेजे हैं. स्पैनको द्वारा विद्युत वितरण की कमान संभालते ही ग्राहकों के पुराने मीटर को बदलकर नए मीटर लगाने की मुहिम छेड़ दी है. कंपनी के इंजीनियर ग्राहकों के घर जाकर पुराने मीटर को पूरी तरह खोलते हैं और उसकी जांच कर उसमें ख़ामियां निकालते हैं. ग्राहकों को तकनीकी जानकारी नहीं होने से उनके पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं रहता. ऐसे में पुराना मीटर बदल जाता है और नया मीटर लग जाता है. कई ग्राहकों ने शिकायत की है कि नया मीटर अधिक रीडिंग दिखाता है, जिससे 200-300 रुपये आने वाला बिल एक हज़ार रुपये के ऊपर चला गया है. बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि पुराने मीटर का नंबर बदलकर नए मीटर का नंबर बिल में जुड़ने तक कंपनी ग्राहकों को एवरेज बिल भेजती है, लेकिन जैसे ही नए मीटर का नंबर बिल में जुड़ जाता है, ग्राहकों को हज़ारों रुपये का बिल आता है. इसके बारे में शिकायत करने पर अधिकारी कई तकनीकी बातें सामने रख ग्राहकों को चुप कर देते हैं, जिसके कारण ग्राहकों को अनाप-शनाप बिल अदा करना पड़ता है. इस तरह से स्पैनको कंपनी ने ग्राहकों से लाखों-करोड़ों रुपये ऐंठ लिए हैं. ग्राहकों ने स्पैनको कंपनी के व्यवहार की जांच कराने की मांग की है.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

आरक्षण में असमानता

प्रदेश में ओबीसी के साथ अन्याय

सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को पिछड़ा वर्ग में रखा गया है. इस वर्ग के लोगों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के तहत भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण दिया गया है. महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या में 40 प्रतिशत लोग पिछड़ा वर्ग से आते हैं. आबादी के लिहाज़ से देखा जाए, तो उन्हें राज्य में प्राप्त आरक्षण की सुविधा बहुत ही कम है. प्रदेश की 40 प्रतिशत पिछड़े तबक़े को महज़ 19 फ़ीसदी ही आरक्षण मिलता है. वहीं दूसरी तरफ़ देश के चार राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में पिछड़ा वर्ग के लोगों को 50 प्रतिशत तक आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है. इस भेदभाव से यह ज़ाहिर होता है कि चुनाव आने पर दलित, पिछड़ों और आदिवासियों का कल्याण करने का दंभ भरने वाली राज्य सरकार चुनाव ख़त्म होने के बाद उन्हें भुला देती है. पिछले दिनों संपन्न हुए मनपा और ज़िला परिषद के चुनावों में भी ऐसा ही देखा गया.

ग़ौरतलब है कि छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, झारखंड और कर्नाटक की सरकारों ने अपने-अपने राज्य में दलितों-पिछड़ों को 50 फ़ीसदी से भी ज़्यादा आरक्षण देने की व्यवस्था की है. इससे उन राज्यों के लाखों पिछड़े लोग विविध योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं. आरक्षण देने के अलावा उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है. राज्य सरकारों के इस प्रयास से कमज़ोर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है. वहीं महाराष्ट्र इस मामले में अन्य राज्यों के मुक़ाबले पिछड़ गया है. राज्य में पिछड़े वर्ग के लोगों की आबादी तक़रीबन 40 फ़ीसदी है, लेकिन उन्हें महज़ 19 फ़ीसदी ही आरक्षण का लाभ मिलता है. राज्य में पिछड़े वर्ग के कई लोग अब भी नौकरी, सरकारी योजना, शिक्षण व आर्थिक लाभ पाने की क़तार में लगे हैं. ख़ासकर नौकरी और प्रमोशन के मामलों में उन्हें अपेक्षाकृत कम लाभ मिल रहा है. जानकारों का कहना है कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से अधिक सक्षम बनाने के लिए छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और कर्नाटक की तर्ज़ पर महाराष्ट्र में भी आरक्षण बढ़ाने की आवश्यकता है. आरक्षण को जनसंख्या की तुलनात्मक दृष्टि से 19 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किए जाने की ज़रूरत है.

फ़िलहाल महाराष्ट्र में सभी वर्गों को 52 फ़ीसदी आरक्षण प्राप्त है. इस 52 प्रतिशत में अनुसूचित जाति के लिए 13 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 प्रतिशत, विमुक्त जाति के लिए 3 प्रतिशत, भटक्या जनजाति को ब, क, ड के अनुसार 8 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है. पिछड़ा वर्ग के लोगों को मात्र 19 प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ है, जो उनकी जनसंख्या की तुलना में काफ़ी कम है. इसे बढ़ाए जाने की ज़रूरत है. ख़ास बात यह है कि नागपुर में हुए गोवारी हत्याकांड के पश्चात गोवारी समाज के लोगों को राज्य सरकार ने 2 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया था, लेकिन उसे अब तक लागू नहीं किया गया है. डॉ. बी.आर. आंबेडकर एम्पलाइज एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय थूल का मानना है कि राज्य सरकार यदि ओबीसी आरक्षण में बढ़ोतरी करती है तो निश्चित ही इससे पिछड़े समाज के लोगों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से विकास होगा. उनके जीवन स्तर में सुधार होगा. संजय थूल के मुताबिक़ उनका एसोसिएशन छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग में आरक्षण बढ़ाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया और अपना प्रस्ताव उनके समक्ष रखा. राज्य सरकार ने उस पर ग़ौर किया और संविधान द्वारा प्रदत्त 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा निर्धारित होने पर भी विधानसभा में विशेष विधेयक पारित कराया. विधेयक के तहत एक कमेटी का गठन किया गया और कमेटी की सिफ़ारिश पर राज्य में कुल आरक्षण 58 प्रतिशत तक बढ़ाया गया. उसके बाद छत्तीसगढ़ में आबादी के आधार पर आदिवासियों को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 12 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है. वहीं तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है. यहां ओबीसी वर्ग के लोगों को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है. इसी तरह झारखंड सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों के मद्देनज़र आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 73 प्रतिशत कर दिया है. वहीं कर्नाटक सरकार ने भी सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए 73 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है. डॉ. बी.आर. अंबेडकर एम्पलाइज एसोसिएशन ने राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से राज्य में आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने की मांग की है. बहरहाल, राज्य में 52 प्रतिशत तक ही आरक्षण की व्यवस्था की गई, लेकिन उसमें गोवारी समाज को घोषित 2 प्रतिशत आरक्षण लागू नहीं किया गया है. इसका मतलब यही है कि महाराष्ट्र में 50 प्रतिशत आरक्षण ही लागू है.

आरक्षण का गणित क्या है?

संविधान के प्रावधानों के अनुसार उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता है. इसके बावजूद राज्य सरकार अगर चाहे तो आरक्षण प्रतिशत को बढ़ाया जा सकता है. जैसा कि तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में किया है.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

संक्षिप्त समाचार

सामाजिक बहिष्कार से हाईकोर्ट हैरान है

महाराष्ट्र को एक प्रगतिशील राज्य के रूप में जाना जाता है. यह भी माना जाता है कि महाराष्ट्र के लोग सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और वैचारिक दृष्टि से उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक खुले विचारों के हैं, लेकिन राज्य में अंतर जातीय विवाह करने वाले युगलों का सामाजिक बहिष्कार करने की बढ़ती घटनाओं के प्रति मुंबई उच्च न्यायालय ने हाल में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चिंता जताई... वकील किरण कुलकर्णी ने खंडपीठ को बताया कि अंतर जातीय विवाह के सामाजिक बहिष्कार झेलने वाले गौड़ ब्राह्मण व कुनबी समाज के लोगों ने भी इस संदर्भ में याचिका दायर की है. इससे अंतर जातीय विवाह करने वाले युगलों को सामाजिक व मानसिक आघात झेलने पड़ते हैं और कई बार परिवार बसने के साथ ही उसमें दरार आने लगती है. इस तथ्य को मद्देनज़र रखते हुए न्यायाधीशों ने उक्त निर्देश दिए हैं.

दानवीर का वृद्धों के लिए दान

वृद्ध माता-पिता को जब सबसे अधिक देखभाल की ज़रूरत होती है, ऐसे वक़्त में युवा पुत्रों द्वारा उनकी उपेक्षा करने की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं. इस वजह से राज्य में वृद्धाश्रमों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है. अपने संतानों की उपेक्षा से द्रवित होकर नंदुरबार निवासी किसान भिका चौधरी ने अपनी दो करोड़ रुपये की क़ीमत वाली दो एकड़ ज़मीन दंडपाणेश्वर मंदिर संस्थान को दान कर दी है. भिका चौधरी का मानना है कि बुज़ुर्ग नागरिकों को होने वाली परेशानियां, उनकी समाज में हो रही उपेक्षा, बेटों-बहुओं का अपमानजनक व्यवहार, संपत्तियों के लिए उनकी ओर दुर्लक्ष्य किया जाता है. इससे वृद्धों की अपनी संतानों से अपेक्षा पूरी नहीं होती है. ग़रीब परिवारों के बुज़ुर्गों की हालत सबसे दयनीय होती है. इन्हीं कारणों से उन्होंने अपनी ज़मीन मंदिर के संस्थान को वृद्धाश्रम के लिए दी है. हालांकि दंडपाणेश्वर संस्थान ने इसके पहले सरकार से वृद्धाश्रम के लिए कई बार ज़मीन देने का अनुरोध किया था, लेकिन अलग-अलग कारण बताकर सरकार ज़मीन देने से इंकार करती रही है. ऐसे में दानवीर भिका चौधरी ने बिना किसी हिचक के अपनी महंगी ज़मीन संस्थान को प्रस्ताव मिलते ही दान करने का फ़ैसला ले लिया. ऐसे ही दानवीरों के कारण समाज को नई दिशा मिलती है.

15 हज़ार रुपये के लिए आत्महत्या की

राज्य में छोटे किसानों की हालत कितनी दयनीय है, यह इस बात से पता चलता है कि मात्र 15 हज़ार रुपये का क़र्ज़ चुका पाने में वे खुद को असमर्थ पा रहे हैं. ठाणे ज़िले के सदन गांव निवासी किसान नासिक साम्ब्रे ने अपना जीवन सिर्फ़ इसी वजह से ख़त्म कर लिया, क्योंकि उस पर 15 हज़ार रुपये का क़र्ज़ था. ख़बरों के मुताबिक़, वह क़र्ज़ देने वालों के तक़ादे से परेशान था. ग़ौरतलब है कि ख़राब मौसम के कारण खेत में खड़ी उसकी फ़सल बर्बाद हो गई थी और वह क़र्ज़ चुका पाने में असमर्थ हो गया था. अंततः 2 फरवरी को उसने अपने ही खेत में आत्महत्या कर ली. जब उस ग़रीब किसान ने आत्महत्या की, उस दौरान प्रदेश के नेता अपने चुनावी दौरे में व्यस्त थे. वे जनता को बड़े वचन बोलकर वोट की जुगाड़ में लगे थे. इसे राज्य का दुर्भाग्य नहीं कहें तो और क्या कहें कि छोटी रक़म के लिए भूमिपुत्रों को परेशान किया जा रहा है. लिहाज़ा वे आत्महत्या कर रहे हैं. नासिक साम्ब्रे द्वारा आत्महत्या करने के बाद उसकी पत्नी और बच्चों के समक्ष आजीविका का संकट पैदा हो गया है.

करोड़पति रिश्वतख़ोर

महाराष्ट्र में आए दिन कोई-न-कोई बड़ा अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ा जा रहा है. इसके बाद भी भ्रष्टाचार कम होने की बजाय और बढ़ता जा रहा है. पिछले दिनों सोलापुर ज़िले में आपूर्ति अधिकारी को 20 हज़ार की रिश्वत लेते जहां गिरफ्तार किया गया था, वहीं अब भंडारा ज़िले में आबकारी विभाग के अधीक्षक विजय कुल्लुर को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने धर दबोचा. कुल्लुर ने बीयर शॉप का लाइसेंस देने के लिए मांढल (तहसील तुमसर) निवासी संदीप वाहिले से एक लाख की रिश्वत की मांग की थी. संदीप ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से कर दी थी. गिरफ्तार करने पर जब जांच अधिकारियों ने उसकी संपत्ति की जांच की तो वह करोड़पति निकला. जांच में पता चला कि कुल्लुर की नामी-बेनामी चल-अचल संपत्तियों में दो लक्जरी बसें भी शामिल हैं, जो पुणे-गोवा मार्ग पर दौड़ रही हैं. इसके अलावा अधिकारियों को 2 लाख 77 हज़ार रुपये की नग़दी भी मिली है. इतना ही नहीं उस रिश्वतख़ोर के पास दो कारें, दो टू व्हीलर, एक फार्म हाउस और पुणे के इंदापुर में वेफर्स की फैक्ट्री भी है. उसकी पत्नी के नाम दो लॉकरों को फ़िलहाल सील कर दिया गया है. ख़बर लिखे जाने तक आभूषणों का मूल्यांकन किया जाना बाक़ी था. जांच अधिकारी अभी भी उसके घर और बैंक खातों की जांच में जुटे हुए हैं. यहां सवाल यह है कि इन सरकारी बाबुओं को हर माह सैलरी के रूप में मोटी रक़म मिलती है, फिर उन्हें अपनी ईमानदारी खोने की ज़रूरत क्या है.

श्री सद्गुरु साईं की पालकी यात्रा 22 मार्च को निकलेगी

श्री सदगुरु साईं चैरिटेबल ट्रस्ट नागपुर द्वारा हर वर्ष आयोजित किए जाने वाले पालकी समारोह का शुभारंभ 21 मार्च से होगा. 21 मार्च को साईं अभिषेक, मंगल स्नान व वस्त्र अर्पण, हवन व महापूजा, आरती प्रसाद का कार्यक्रम होगा. 22 मार्च को साईं मंगलस्नान पादुका पूजा व वस्त्र अर्पण के बाद श्री साईं मंदिर, धंतोली, नागपुर से साईं पालकी शिर्डी के लिए प्रस्थान करेगी. नागपुर शहर भ्रमण के पश्चात वर्धा रोड स्थित साईं मंदिर में शाम 6.30 बजे महाआरती व महावस्त्र अर्पण का कार्यक्रम होगा और रात्रि विश्राम चिंचभवन स्थित हनुमान मंदिर में किया जाएगा. श्री साईं पालकी आसोला सावंगी, सेलू, पुलगांव, अमरावती, यवतमाल, वाशिम, औरंगाबाद आदि शहरों से होकर गुज़रेगी. 12 अप्रैल को राम जन्मोत्सव के समय 12 बजे श्री साईं पालकी शिर्डी स्थित श्रीसाईं समाधि मंदिर प्रांगण पहुंचेगी, जहां शाम 7 बजकर 30 मिनट पर साईं भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा. पालकी यात्रा के दरम्यान सुबह 5.30 बजे काकड़ आरती, 6.30 बजे मंगल स्नान व अभिषेक, दोपहर 12 बजे आरती व नैवेद्य, 4.30 बजे साईं गुरुपाठ अभंग, 6.45 बजे धूप आरती व नैवेद्य और रात्रि 10.30 बजे शेजा आरती होगी. इसके अलावा 4 अप्रैल को गुड़ीपाड़वा के मुहूर्त पर साईं सचरित का साप्ताहिक परायण किया जाएगा. 19 अप्रैल को नागपुर के धंतोली स्थित साईं मंदिर में श्री साईं सत्यनारायण पूजा महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा. यह जानकारी पालकी महोत्सव समिति नागपुर के संयोजक पंकज महाजन ने दी है.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

भुजबल ने एमईटी ब्रांड का नाम मिटाकर ट्रस्ट की संपूर्ण संपत्ति भुजबल परिजनों के नाम पर कर डाली. एमईटी का दूसरा कैंपस नासिक में होना चाहिए, ऐसी इच्छा भुजबल की थी.

Postal Regn. No. RNP/NP/CITY/383/2011-13, RNI No. DELHIN/2009/30467

एमईटी बना भुजबल के गले की फांस

मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सुनील कर्वे ने धर्मदाय आयुक्त और आर्थिक अपराध अंवेषण के यहां लिखित शिकायत में कहा है कि ट्रस्ट से संबंधित अनेक संपत्ति का अपने निजी फ़ायदे के लिए उपयोग करके भुजबल के परिजनों ने एमईटी के नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया है. इतना ही नहीं खुद की जागीर समझते हुए इस शिक्षण संस्थान का उपयोग राजनेता छगन भुजबल और उनके नाते रिश्तेदार कर रहे हैं. सत्ता का फ़ायदा किस क़दर कोई शख्स उठाता है, यह कोई भुजबल और उनके परिजनों से सीखे.

राजेश नामदेव

राज्य के सार्वजनिक निर्माण मंत्री छगन भुजबल एक बार फिर संकट में घिरते नज़र आ रहे हैं. उनके ऊपर पहले से ही इंडिया बुल्स नामक कंपनी का छगन भुजबल पब्लिक वेलफेयर फेडरेशन के नाम से क़िस्तों में करोड़ों का चंदा वसूल करने को लेकर ख़ासा विवाद रहा है. इस बार उनके विश्वासपात्र और अतिनिकटतम व्यक्ति ने ही मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट (एमईटी) में 178 करोड़ रुपये का गोलमाल करने का न केवल आरोप लगाया है, बल्कि धर्मदाय आयुक्त और मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध अंवेषण शाखा के पास लिखित शिकायत भी की है. भुजबल इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और आरोप लगाने वाला व्यक्ति सुनील कर्वे उक्त ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य होने के साथ ही उपाध्यक्ष भी हैं. चूंकि उक्त आरोप किसी विरोधी नेता ने नहीं लगाया है. साथ ही यह मामला शैक्षणिक संस्थान से है. इसलिए इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है. इस ख़ुलासे से भुजबल के समर्थकों में जहां हड़कंप मचा हुआ है, वहीं उनके विरोधियों की बांछे भी खिली हुई हैं. इस आरोप से राज्य के राजनीतिक हलक़ों में भुजबल की बढ़ती मुश्किलों को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि शैक्षणिक संस्थाओं का किसी नेता द्वारा आर्थिक दोहन करने के आरोप लगते रहते हैं और ये नेता ख़ुद शिक्षा महर्षि बनकर समाज में घूमते रहते हैं. मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सुनील कर्वे ने धर्मदाय आयुक्त और आर्थिक अपराध अंवेषण के यहां लिखित शिकायत में कहा है कि ट्रस्ट से संबंधित अनेक संपत्ति का अपने निजी फ़ायदे के लिए उपयोग करके भुजबल के परिजनों ने एमईटी के नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया है. इतना ही नहीं ख़ुद की जागीर समझते हुए इस शिक्षण संस्थान का उपयोग छगन भुजबल और उनके नाते रिश्तेदार कर रहे हैं. सत्ता फ़ायदा किस क़दर कोई शख्स उठाता है, यह कोई भुजबल और उनके परिजनों से सीखे. नासिक में खुलने वाले एमईटी के प्रस्तावित कैंपस का भुजबल नॉलेज सिटी नामकरण करने की बात उन्होंने स्वयं क़बूल की. इस मद में आए 25 करोड़ रुपये और भुजबल की बहू विशाखा के इदीन फर्नीचर कंपनी के शोरूम के लिए आठवीं मंज़िल पर 15000 स्क्वेयर फुट की जगह और उस पर लगने वाला 6 वर्ष का भाड़ा, विजिटिंग प्राध्यापक व फैक्ल्टी सदस्यों के लिए तात्कालिक निवास के लिए गेस्ट हाउस और ख़ुद के आवास वह भी कई वर्षों तक बग़ैर किराए दिए कई सवाल पैदा करते हैं. इस तरह भुजबल एंड फैमिली पर एमईटी को 178 करोड़ रुपये का चूना लगाए जाने का आरोप है. कर्वे का कहना है कि उक्त मामलों के अलावा निजी और राजनीतिक समारोहों पर होने वाला ख़र्च भी ट्रस्ट द्वारा उठाया जाता रहा है. उक्त सभी मुद्दे ट्रस्ट के संचालक मंडल की 29 सितंबर को हुई बैठक में उठाया गया था. बैठक में भुजबल परिवार से उक्त सभी बक़ाया रक़म ट्रस्ट के पास जमा कराए जाने का अनुरोध किया गया था. हालांकि जब भुजबल व उनके परिजनों द्वारा सदस्यों की मांग को ठुकरा दिया गया तो यह क़दम उठाना पड़ा और मामले की शिकायत करनी पड़ी. कर्वे का कहना है कि जब वर्ष 1989 में एमईटी की स्थापना हुई थी, उस वक़्त भुजबल ने संस्था के लिए संपूर्ण निधि की व्यवस्था स्वयं करने का आश्वासन दिया था. उस समय उन पर मात्र शैक्षणिक विकास करने की ज़िम्मेदारी थी, लेकिन आश्वासन के बाद भी संस्था के लिए एक रुपये का योगदान नहीं दिया. विश्व पटल पर संस्था का नाम विख्यात करने के लिए हम सब ने प्रत्यन किया, लेकिन भुजबल ने एमईटी ब्रांड का नाम मिटाकर ट्रस्ट की संपूर्ण संपत्ति भुजबल परिजनों के नाम पर कर डाली. एमईटी का दूसरा कैंपस नासिक में होना चाहिए, ऐसी इच्छा भुजबल की थी. इस कैंपस का महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम देने की सूचना भुजबल ने दी थी. हालांकि वर्ष 2006 में उसे बदल कर भुजबल नॉलेज सिटी कर दिया गया. इसके परिणामस्वरूप संस्था को जो आर्थिक नुक़सान हो रहा था उसके एवज में भुजबल 25 करोड़ रुपये ब्याज़ सहित देने की बात कहते रहे हैं, लेकिन अब तक एक रुपया भी उनके द्वारा न दिए जाने का आरोप भी कर्वे ने लगाया है. उनका यह भी कहना है कि नासिक स्थित भुजबल नॉलेज सिटी पर पूरी तरह से भुजबल परिवार का ही वर्चस्व है. वहां क्या चल रहा है, इसकी एमईटी संचालन मंडल को किसी तरह की जानकारी नहीं दी जाती है. सबसे हैरत की बात यह है कि यहां किसी को भी कोई हिसाब भी देखने को नहीं दिया जाता है. इसके साथ ही बांद्रा स्थित एमईटी का नाम बदल कर भुजबल नॉलेज सिटी करके भुजबल ने सीधे-सीधे ट्रस्ट के नियमों का उल्लंघन किया है. इस पूरे प्रकरण पर छगन भुजबल अपना बचाव करते हुए कहते हैं कि पिछले एक साल से सुनील कर्वे से हमारा विवाद शुरू है. उसी विवाद के चलते कर्वे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं. कर्वे स्वयं चार्टेड एकाउंटेंट हैं. वाउचर में वही हस्ताक्षर करते हैं. फिर घोटाला कैसे हो सकता है? उन्होंने आशंका ज़ाहिर की है कि मनपा-ज़िला परिषद चुनाव के समय कर्वे द्वारा आरोप लगाए जाने के पीछे कोई और हो सकता है. उनका आरोप है कि एक राजनीतिक व्यक्ति की शैक्षणिक संस्था की ओर से कर्वे को ऑफर मिला है. इसलिए एमईटी को छोड़ने के लिए यह रास्ता निकाला है. जिस घोटाले की आज कर्वे चर्चा कर रहे हैं, उसके विषय में कभी कोई बात नहीं कही है. फिर अचानक कैसे घोटाले की बात सामने आ गई, लेकिन भुजबल ने यह नहीं बताया कि कर्वे को अपनी संस्था में ऑफर देने वाला वह राजनेता कौन है? उसकी उनसे क्या दुश्मनी है? वहीं एमईटी की बिल्डिंग में उनकी बहू द्वारा संचालित इदीन फर्नीचर को अचानक 3 फरवरी को हटा लिया गया. जिस समय फर्नीचर शोरूम से सामान निकाला जा रहा था, तब वहां पत्रकारों के प्रवेश पर अघोषित प्रतिबंध लगा दिया गया और गेट को पूरी तरह ढक दिया गया था, ताकि अंदर शोरूम से सामान निकालकर ट्रक में चढ़ाते हुए कोई देख न सके. लेकिन एक कहावत काफ़ी पुरानी है कि, जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि की तर्ज़ पर एक टीवी चैनल की टीम वहां पहुंच गई. उसने शोरूम को ख़ाली किए जाने की चल रही कार्रवाई को लाइव प्रसारित कर दिया. अब सवाल यह उठता है कि जब कर्वे के आरोप झूठे हैं तो इदीन फर्नीचर को वहां से क्यों हटाया गया? इस सवाल का जवाब देने के लिए भुजबल कुटुंब का कोई भी सदस्य तैयार नहीं हुआ.छगन भुजबल के लिए यह मामला सरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि मामला एक शैक्षणिक संस्था से जुड़ा है, जिसकी लिखित शिकायत आर्थिक अपराध अंवेषण शाखा से की गई. यदि जांच होती है तो भुजबल परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. वैसे भी उन पर इंडिया बुल्स जैसी कंपनी से चंदे के रूप में करोड़ों रुपये वसूल करने का आरोप पहले से है. इसलिए एमईटी भुजबल के गले की फांस बन गया है, जो न निग़लते बन रहा है और न उगलते.

feedback@chauthiduniya.com

ट्रस्ट पर भुजबल के परिजनों का क़ब्ज़ा

मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट पर पूरी तरह से भुजबल परिवार का क़ब्ज़ा है. इस ट्रस्ट के छगन भुजबल जहां अध्यक्ष हैं, वहीं पंकज भुजबल सचिव हैं. समीर भुजबल ट्रस्ट के कोषाधिकारी हैं. यह भी कहा जाता है कि भुजबल की बहू विशाखा के आदेश-निर्देश को कोई नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता. वह अपने दैनिक कार्यभार के लिए अब तक वहां के कमरों का जब चाहे, जैसा उपयोग करती रही हैं. अधिकार न होने पर भी वाउचरों पर हस्ताक्षर करने, किसी कार्य के लिए रक़म मंज़ूर किए जाने पर उनकी सहमति महत्वपूर्ण होती थी.

एलटी कौन?

ऐसा लगता है कि विवादों का जिन्न अब छगन भुजबल के पीछे पड़ गया है. इंडिया बुल्स और एमईटी विवाद के बाद एक और मामला सामने आया है. यह ताज़ातरीन मामला है एलटी का. प्रदेश में चर्चा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में मंत्री भुजबल से अधिक एलटी नाम का एक शख्स सक्रिय रहता है. उसके बिना कोई काम नहीं होता है. किसी को ठेका दिलाना हो, किसी का तबादला कराना हो या रद्द कराना हो. एलटी के बिना हो ही नहीं सकता है. बड़े-बड़े ठेकेदार, कंपनियां व सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अभियंता एलटी को हर तरह से ख़ुश रखते हैं. सार्वजनिक निर्माण विभाग के हर कार्य को प्रभावित करने का दम एलटी रखता है. इसलिए यह सवाल उठना लाज़िमी है कि जिस शख्स के सक्रिय हुए बिना सार्वजनिक निर्माण विभाग का पत्ता तक नहीं हिलता है आख़िर वह एलटी है कौन? चर्चा है कि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भुजबल ने एलटी की तरह राज्य के हर विभाग में अपना एक-एक एलटी की नियुक्ति कर रखी है. उक्त एलटी हर व्यक्ति से काम कराने के बदले मोटी रक़म वसूल करते हैं. उनके द्वारा वसूल रक़म भुजबल के ख़ज़ाने में जाती है. एलटी भी कमीशन के रूप में करोड़ों रुपये कमाते हैं.

गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांना नम्र आवाहन

सर्व प्रकल्पग्रस्त बंधू-भगीनींना कळविण्यात येते की, गोसीखुर्द जलाशयात पाणी साठवण पातळीत वाढ करण्यात येणार आहे. सदर पातळी सध्या २३६.६० मी. असून यामध्ये दि. ११.२.२०१२ पासून हळुहळु वाढ करण्यात येणार आहे. प्रथम टप्प्याचा भाग म्हणुन ही वाढ गेल्या वर्षभर पाणी साठविलेल्या २३७.२० मी. या तलांकापर्यंत वाढविण्यांत येणार आहे.

गोसीखुर्द धरणातील २३७.२० मी. तलांकापर्यंत बुडणाऱ्या गावठाणातील शेतीचा व घरांचा मोबदला प्रकल्पग्रस्तांना अदा करण्यात आला आहे. तसेच प्रचलित पुनर्वसन अधिनियम १९९९ नुसार देय संबंधित पुनर्वसित गांवठाणातील नागरी सुविधांची बहुतांशी कामे पूर्ण झाली असुन उर्वरीत (दुरुस्तीसह) कामे मे २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहेत. याशिवाय शासनाने खास गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांसाठी मंजूर केलेल्या विशेष पॅकेज द्वारे अतिरिक्त फायदे व सुविधा देण्यात येत आहेत. तरी प्रकल्पग्रस्तांनी लवक. रात लवकर स्थानांतरीत व्हावे, असे आवाहन व विनंती करण्यात येत आहे. स्थलांतरीत झाल्यावर देखील या प्रकल्पास भविष्यात लागू होणारे सर्व अतिरीक्त लाभ व सुविधा प्रकल्पग्रस्तांना नंतरही देण्यात येतील.

प्रकल्पग्रस्तांच्या बरोबर चार प्रदीर्घ बैठकांमध्ये त्यांनी व्यक्त केलेल्या उणीवा व अडचणी यांचा बहुतांशी निपटारा करण्यात आला आहे व मे-२०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येत आहेत. तसे सर्व संबंधितांना लेखी कळविण्यात आले आहे.

तरी सुद्धा प्रकल्पग्रस्तांची काही प्रमाणात गैरसोय होणार आहे त्याबद्दल दिलगीरी. प्रकल्पग्रस्तांच्या त्यागामुळे या भागातील मोठा विकास होणार आहे. त्यासाठी या प्रकल्पाचे सर्व लाभार्थी त्यांचे सदैव ऋणी राहतील.

जलाशयाची पाणी पातळी वाढविली नाही तर १) मोखेबर्डी उपसा सिंचन योजनेच्या लाभक्षेत्रातील १२६ गावांतील शेतकरी २८,२३५ हे. सिंचनाच्या सुविधापासुन वंचित राहतील. २) गोसीखुर्द डाव्या कालव्यावरील ९० गावांतील शेतकरी ४०,२०६ हे. सिंचनाच्या लाभापासुन वंचित राहतील. ३) नेरला उपसा सिंचन योजनेवरील अवलंबून असलेल्या ११६ गावांतील २८,६८० हे. क्षेत्र सिंचन सुविधेपासून वंचित राहील. ४) एन.टी.पी.सी. मौदा येथील केंद्रातील १००० मेगावॅट विद्युत निर्मिती सुरू होऊ शकत नाही व त्यामुळे महाराष्ट्र व पर्यायाने विदर्भ या विजेच्या लाभापासुन वंचित राहील. ५) गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या केंद्रीय सुकाणू समितीस आश्वासित केलेल्या आराखड्यातील अपेक्षित ऐवढी पाणी पातळी वाढविली नाही तर केंद्र शासनाकडुन या प्रकल्पास मिळणारे अर्थ सहाय्य रोखले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे झाल्यास त्याचा अत्यंत प्रतिकूल परीणाम या प्रकल्पाच्या वेगावर होऊन त्याचा फटका सुमारे १,५०,००० हे. क्षेत्रास बसेल. वरील सर्व कारणामुळे पाणी पातळी वाढविणे क्रमप्राप्त आहे.

सबब आपण आपल्या बाधित शेतातील धान्य (पीके) व घरातील सामान तसेच प्राणीधन सुरक्षीत स्थळी वेळीच हलवावित. तसे न केल्यास होणाऱ्या नुकसानीची जबाबदारी शासनावर राहणार नाही, तरी प्रकल्पग्रस्तांनी लवकरात लवकर स्थानांतरीत व्हावे असे पुनश्च आवाहन व विनंती करण्यात येत आहे.

कार्यकारी संचालक,
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर.

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 20 फरवरी–26 फरवरी 2012

www.chauthiduniya.com

संजीवनी का है ऐलान, झारखण्ड–बिहार में हो सबका मकान

SANJEEVANI BUILDCON

3rd & 4th floor, GEL Church Complex, Main Road, Ranchi, Customer Care No. - 0651-2331429

Sanjeevani Dynasty-I
PLOT-13 LAC, DUPLEX-25 LAC
Near Ranchi College

Sanjeevani Dynasty-II
PLOT-10 LAC, DUPLEX-22 LAC
Booty More

Future City (BIT)
PLOT-4 LAC,
BUNGLOW-10 LAC

Future City (Namkom)
PLOT-4 LAC,
BUNGLOW-10 LAC

Future City (Pithoria)
PLOT-4 LAC,
BUNGLOW-10 LAC

Sanjeevani Mega Township
PLOT-3.5 LAC, BUNGLOW-09 LAC
Hazaribagh

Investments in Bihar

There has been a significant gap in term of the proposal of investments intended towards Bihar and the amount of investments the state received in actual terms. The following two figures depicted the real story in much detail.

Gap between the proposed and implemented investments

(in Rs crores)

Year	Investments proposed	Investments implemented
2008	13577	62
2009	13710	0
2010	65190	0
2011	42941	0
(upto June 2011)		

Source: DIP, Govt. Of India

पूंजी निवेश चुनावी और प्रचार अभियान का

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

शशि शेखर

अभी जयपुर में अप्रवासी भारतीयों का एक सम्मेलन हुआ. वहां भी बिहार में पूंजी निवेश पर चर्चा हुई. अप्रवासी भारतीयों और उसमें भी ख़ासकर अप्रवासी बिहारियों को बिहार में पूंजी निवेश करने के लिए बिहार के कई आला अधिकारी जयपुर पहुंचे. उन्हें लुभाने की हर संभव कोशिश की गई. और ये काम पिछले 6–7 सालों से लगातार हो रहा है. जहां भी अप्रवासी बिहारी आते हैं, वहां बिहार सरकार के अधिकारी पहुंचते हैं. कई बार ख़ुद मुख्यमंत्री भी पहुंचे. उन्हें तमाम संभावनाएं दिखाई जाती हैं. अच्छी सड़क, क़ानून व्यवस्था के सुधरने की बात कही जाती है. यह सब इसलिए होता है, ताकि बिहार में पूंजी निवेश हो सके, बिहार की हालत सुधर सके. यह ज़रूरी भी है. लेकिन इन तमाम कोशिशों का नतीजा क्या निकलता है. कोई अख़बार अगर इन कोशिशों के परिणाम को शून्य बताए या मामूली बताए तो सरकार उसे झूठा साबित कर देगी. लेकिन फिक्की–कैफ की एक सर्वे रिपोर्ट बिहार में पूंजी निवेश की जो कहानी बताती है, क्या उसे भी झूठा मान लिया जाना चाहिए.

2008 से जून 2011 के दौरान बिहार में हुए निवेश की जानकारी देती यह रिपोर्ट बताती है कि 2009, 2010 और 2011 के दौरान क्रमश: 13710, 65190 और 42941 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव आए. लेकिन इसमें से एक पैसा भी वास्तविक रूप से बिहार की ज़मीन पर नहीं पहुंचा यानी प्रस्ताव तो आए लेकिन सिर्फ़ प्रस्ताव बनकर ही रह गए. हां, 2008 में जहां 13577 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव आया, उसमें से महज़ 62 करोड़ रुपये का ही असल निवेश हो सका. रिपोर्ट कहती है कि निवेश के प्रस्ताव और वास्तविक निवेश में भारी अंतर है. इस रिपोर्ट के मुताबिक़ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार के औद्योगिक विकास के रास्ते में अभी भी ज़मीन की अनुपलब्धता, कुशल कामगारों की कमी और कमज़ोर बैंकिंग व्यवस्था (ऋण के संबंध में), बिजली की कमी है. बिहार में अभी बिजली की जितनी मांग है, उसके मुक़ाबले सिर्फ़ आधा ही उत्पादन हो रहा है. इसके अलावा फिक्की यह तो मानता है कि राज्य में निवेश के अनुकूल माहौल बन रहा है, लेकिन फिक्की के एक सर्वे में ही जहां एक तरफ़ 27 फ़ीसदी उद्यमियों ने स्वीकारा है कि राज्य में निवेश का माहौल ठीक नहीं है वहीं 36 फ़ीसदी इस मामले में कोई जवाब नहीं दे पाए या उदासीन रहे. फिक्की ने राज्य में चल रहे मौजूदा उद्योगों के मालिकों के बीच भी एक सर्वे करवाया. सर्वे परिणाम के मुताबिक़ 38 फ़ीसदी उद्यमियों ने माना कि उद्योग का विकास नहीं हो रहा है. 31 फ़ीसदी ने तो यह कहा कि मौजूदा उद्योग अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं. सिर्फ़ 15 फ़ीसदी उद्यमियों ने माना कि राज्य में मौजूदा उद्योगों की हालत ठीक है. उद्यमियों की मांग है कि सरकार उन्हें बेहतर सुविधाएं मुहैया कराएं और ऋण दिलवाने में मदद करे. ज़्यादातर उद्यमियों ने राज्य में बिजली आपूर्ति की स्थिति को बेहद ख़राब बताया है. साथ ही वित्तीय उपलब्धता यानी ऋण वग़ैरह से संबंधित मामले में भी उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है.

यह रिपोर्ट न सिर्फ़ समस्याओं की बात करती है, बल्कि उसने कई सुझाव भी राज्य सरकार को दिए हैं. बिजली, ज़मीन, कामगार, औद्योगिक नीतियों को बेहतर बनाने से संबंधित सुझाव दिए गए हैं. मसलन बियाडा को ऐसे प्रयास करने चाहिए, ताकि रीजनेबल रेट पर उद्यमियों को बड़ा प्लॉट मिल सके. साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बंद या बीमार कल–कारख़ानों की ज़मीन का अधिग्रहण करने का भी सुझाव दिया गया है, ताकि उसे नए खुलने वाले उद्योगों को दिया जा सके. इसी तरह उद्योगों को की जाने वाली बिजली आपूर्ति के संबंध में भी सुझाव दिए गए हैं. जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाए, फ्यूल सब्सिडी दे. कुशल कामगार के लिए आईटीआई पर ध्यान देने, आईटीआई को केंद्र से ज़्यादा पैसा मिलने, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा संख्या में प्रशिक्षण केंद्र खोलने के सुझाव दिए गए हैं, ताकि ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण मिल सके. बहरहाल, अब यह राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है कि अगर वह इस रिपोर्ट को सच मानती है तो इन सुझावों पर ध्यान दे या अगर वह इस रिपोर्ट को ग़लत मानती है, तो फिर इतना ही कहा जा सकता है कि दिल के बहलाने को ग़ालिब यह ख्याल अच्छा है.

shashishekhar@chauthiduniya.com

Questionnaire Survey- Key Findings

Bihar as an investment destination

The response of the industry representatives showed convergence when asked about the attractiveness of Bihar as an investment destination. While 36% of the survey respondents felt the investment outlook of Bihar is positive, an equal share of investors find the outlook to be neutral. On the other hand, 27% of the entrepreneurs felt that the state is not an attractive destination for investors.

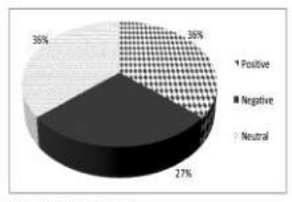

Source: FICCI Industry Research

Performance level of existing Industry

Though the state got a mixed reaction on its outlook as an investment destination, 38% of the existing industry owners said that their firm is not growing and as high as 31% said they are facing survival crisis. They also mentioned that they needed good amount of support from the government and financial institutions like banks to turnaround their flagging growth trajectory. Only 30% said that their firm is doing extremely well or reasonably well.

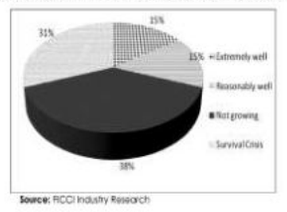

Source: FICCI Industry Research

2008 से जून 2011 के दौरान बिहार में हुए निवेश की जानकारी देती यह रिपोर्ट बताती है कि 2009, 2010 और 2011 के दौरान क्रमश: 13710, 65190 और 42941 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव आए. लेकिन इसमें से एक पैसा भी वास्तविक रूप से बिहार की ज़मीन पर नहीं पहुंचा यानी प्रस्ताव तो आए, लेकिन सिर्फ़ प्रस्ताव बनकर ही रह गए. हां, 2008 में जहां 13577 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव आया, उसमें से महज़ 62 करोड़ रुपये का ही असल निवेश हो सका.

मधुबनी खादी ग्रामोद्योग बदहाली की कगार पर

कभी मधुबनी का पहचान रहा राष्ट्रीय स्तर पर मधुबनी खादी ग्रामोद्योग आज सरकारी उदासीनता एवं बदइंतज़ामी की गर्त में खोता जा रहा है. गांधी और खादी के नाम पर सत्ता का सुख-विलास भोगने वाले सत्ताधारी नेताओं ने खादी ग्रामोद्योग से मुंह मोड़ लिया है. पूंजी के अभाव एवं क़र्ज़ के बढ़ते सूद से मधुबनी खादी ग्रामोद्योग में संचालित मशीन एवं सूती व रेशमी कपड़ों का उत्पादन सहित मसाला, अगरबत्ती, साबुन, मधु आदि उद्योग बंद पड़े हैं, जिससे एक तरफ़ लोगों को खादी उद्योग से बने विशुद्ध घरेलू उपयोग की सामग्री से वंचित होना पड़ रहा है, वहीं खादी ग्रामोद्योग से जुड़े हज़ारों प्रशिक्षित कामगार एवं कतीनों की रोज़ी भी छिन गई है. अब सूती, ऊनी, रेशमी एवं मसलिन कपड़ों का उत्पादन अतीत बनकर रह गया है. स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि प्रखंड एवं ग्रामीण स्तरों पर कार्यरत खादी बिक्री केंद्र कबके बंद हो चुके हैं. अधिकांश कार्यकर्ताओं ने खादी ग्रामोद्योग से नाता तोड़कर रोज़ी-रोटी के लिए दूसरे व्यवसायों को अपना लिया है. खादी ग्रामोद्योग के बचे कार्यकर्ताओं को मिलने वाली अल्प राशि भी अब नहीं मिल पा रही है. नतीजा है कि मधुबनी के प्रसिद्ध खादी ग्रामोद्योग को फिर से जीवित करने की आशाएं क्षीण लगने लगी हैं. मधुबनी खादी ग्रामोद्योग में सूतकारों, बुनकरों, कर्मचारियों व अन्य कामगारों की संख्या कल्पना से अधिक घट गई है. उत्पादन का काम लगभग बंद होने के कगार पर है. भवन की स्थिति जर्जर हो चुकी है. छतों से पानी टपक रहा है. खपरैल ध्वस्त होने के कगार पर है. रंगाई, छपाई, तेल पेराई पूर्णतः बंद है. मधुबनी खादी ग्रामोद्योग पर करोड़ों का क़र्ज़ हो गया है. आम जनता की रुचि खादी कपड़ों के प्रति क्षीण हो गई है. गांधी जी का सपना तार-तार हो रहा है. आर्थिक कठिनाइयों के कारण ज़िला खादी ग्रामोद्योग संघ का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. ज्ञातव्य हो कि मधुबनी खादी ग्रामोद्योग संस्था लगभग 21 एकड़ ज़मीन में अवस्थित है तथा ज़िले में 41 केंद्र हैं, जिनके पास अपनी ज़मीन व भवन हैं.

मधुबनी ज़िला खादी ग्रामोद्योग संघ की अध्यक्ष सरला देवी एवं मंत्री अनिल कुमार झा बताते हैं कि वर्तमान में ज़िले में सालाना लगभग 9 लाख रुपये के कपड़े का उत्पादन होता है. कर्मचारियों की संख्या 35, सूतकारों की संख्या 2000 और बुनकरों की संख्या 35 है. दोनों नेताओं ने बताया कि जब खादी उद्योग पूर्ण रूप संचालित थे, उस समय प्रतिवर्ष 2.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपये तक के कपड़ों का उत्पादन हुआ करता था. मसलीन कपड़ा एवं मसलीन सूत में मधुबनी को विशिष्ट स्थान प्राप्त था. साथ ही मधुबनी के बने खादी के कपड़ों का निर्यात विदेशों में हुआ करता था. मधुबनी खादी उद्योग परिसर में कपड़े की रंगाई, छपाई व धुलाई हुआ करती थी. इसके अलावा तेल पेराई, लकड़ी के सामानों का उत्पादन भी होता था. हज़ारों परिवारों की गुज़र-बसर इसी उद्योग पर निर्भर थी. अध्यक्ष सरला देवी बताती हैं कि खादी ग्रामोद्योग की बदहाली उस वक़्त से शुरू हुई, जब खादी ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा कच्चे मालों की आपूर्ति बंद कर दी गई.

सबसे विषम स्थिति उस समय हुई, जब खादी कपड़ों की आपूर्ति बिहार सरकार के कार्यालयों में एवं रेल विभाग में बंद करवा दी. खादी ग्रामोद्योग के भवनों में अवस्थित दर्जनों सरकारी कार्यालयों द्वारा भाड़ा नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि एसएफसी पर 6 लाख रुपये, कृषि विभाग पर 4 लाख रुपये, जनसंपर्क विभाग पर 2 लाख रुपये, विद्युत विभाग पर लगभग 5 लाख व अन्य किरायेदारों पर लगभग 9 लाख बकाया है. दूसरी ओर खादी ग्रामोद्योग मधुबनी पर बैंक का ऋण 54 लाख 31 हज़ार रुपये, सीबीसी का ऋण 72 लाख एवं खादी कमीशन का 3 करोड़ 50 लाख रुपये बकाया है. ग़ौरतलब है कि प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से ज़िले के कपसिया खादी भंडार में बने 10 गज़ का मसलीन थान एक अंगूठी से आर-पार हो गया, जिसे रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में प्रदर्शनी में रखा गया.

उस समय खादी कपड़ों को खादी कताई, बुनाई कला का अद्भुत चमत्कार माना गया और इस विशिष्टता के लिए मधुबनी खादी ग्रामोद्योग का देश-विदेश में नाम हुआ था. वर्ष 2010 के अप्रैल माह में खादी ग्रामोद्योग की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमुद जोशी के मधुबनी आगमन पर मधुबनी सहित पांच संस्थाओं को विशेष रिवाईवल पैकेज देने की घोषणा से खादी उद्योग के कर्मियों में आशा की किरण जगी थी. लेकिन बाद में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विशेष रिवाईवल पैकेज को ऋण के रूप परिवर्तित कर देने से संस्था इस लाभ को उठाने से वंचित रह गई. यदि उक्त पैकेज को अनुदान के रूप संस्था को मिले तो इससे खादी ग्रामोद्योग कार्य को बढ़ावा दिया जा सकता है. इस सबके बावजूद खादी ग्रामोद्योग पर सरकार विशेष ध्यान देकर बापू के सपने को साकार करे तो यहां की स्थिति सुधर सकती है.

डॉ. इंद्र मोहन झा
feedback@chauthiduniya.com

स्टीवेन जॉन्संस सिंड्रोम से घबराएं नहीं

डॉ. एम एल जैन

चिकेन नेक कहे जाने वाले किशनगंज में डॉ. एम एल जैन प्रसिद्ध फिज़ीशियन चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं. उन्होंने बातचीत में स्टीवेन जॉन्संस सिंड्रोम बीमारी की जानकारी दी. प्रस्तुत है ख़ास अंश.

स्टीवेन जॉन्संस सिंड्रोम क्या है, इसके लक्षण क्या हैं?

सामान्यतः सर्दी, खांसी और बुख़ार रहने पर लोग सर्दी खांसी की आम दवा खाते हैं. कभी-कभी कुछ लोगों में इस दवा के सेवन से पूरे शरीर में सूजन एवं बर्न रोगी जैसी स्थिति हो जाती है या कहें कि पूरे शरीर में दवा कुप्रभाव करके एलर्जी उत्पन्न कर देती है.

ASRFEN-P
riskon Pharma Pvt.Ltd.
Carbo-XT
Ferrous Ascorbate With Folic Acid Tab.
ECTALOPAM
AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium Chloride Cough Syp.
SILIPLEX
MENSOSET
Hair Tonic With Ashoka 1800mg.
ACOBA CAP/SYP/INJ
MUSTAL
Levocetirizine Hydrochloride Montelukast Sodium Tab.

ऐसे रोगी का पता कैसे चला?

विगत महीने पड़ोस डालकोला (बंगाल) की इसी बीमारी से पीड़ित एक महिला मेरे क्लीनिक में पहुंची थी.

इसका इलाज क्या है?

इस रोग का इलाज उसी प्रकार से होता है, जिस तरह जले रोगी का इलाज होता है. इस रोग का इलाज बर्न चिकित्सक की सहायता से समुचित दवा द्वारा होता है और रोगी को ठीक होने में 2 से 3 महीने का समय लगता है.

ललन तिवारी
feedback@chauthiduniya.com

PATALIPUTRA SCHOOL OF FIRE & SAFETY MANAGEMENT
Authorised Study Centre of EIILM University. Code-CIIP/101683
Diploma/PG Diploma/Bachelor Degree/PG Degree in the following Subjects :
• Fire Safety Management • Industrial Safety Management • Occupational Safety & Health Management • Environmental Safety & Health Management
Only one Institute of Bihar where students of Bihar, Magadh & Several other Universities and Employees of industrial organizations of all over India get theoretical & Practical training in fire & Safety Management.
FREE Demo-Classes in the Morning & Evening from Monday to Friday
Website : www.psfsm.com
410, Ashiana Galaxy, Exhibition Road, Patna-800 001
Ph : 0612-3297011, Mob. : 9334107607, 9234929075

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE MOULDED FURNITURE
WINNER OF NATIONAL AWARD
1 YEAR GUARANTY शर्तें लागू
Contact : 9386595926, 9334115955

आदिवासियों को उजाड़ने की कोशिश

नीरज कुमार सिंह

सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को अपने पक्ष में करने के लिए जहां अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वहीं किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा हेतु ज़मीन हस्तांतरण को लेकर अनुसूचित जाति-जनजाति भू रक्षा संघर्ष समिति के बैनर तले सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं और जान दे देंगे पर ज़मीन नहीं देंगे का नारा बुलंद किए हुए हैं. मालूम हो कि सरकार ने चुनाव के समय अल्पसंख्यक मुस्लिम बहुल किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा स्थापित करने का वादा किया था. इसे लेकर स्थानीय लोगों ने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बैनर तले किशनगंज में आंदोलन से लेकर महाधरना का आयोजन किया था. परिणामस्वरूप बिहार सरकार की तरफ़ से किशनगंज के ज़िला पदाधिकारी संदीप कुमार आर पुडकलकट्टी ने भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार पटना के पत्रांक 6/स्था.म. किशनगंज-01/10-1265 (3)/रा पटना दिनांक 01-12-2011 के आलोक में किशनगंज अंचल के मौजा चकला, थाना नं.- 28 खाता सं. 384 खसरा सं. 22, 23, 124, 125 एवं 126 रक़बा 116 गुना 53 एकड़ तथा मौजा गोविंदपुर थाना सं. 61 खाता सं. 40 खसरा सं. 353, 354, 355, 357, 358 एवं 360 रक़बा 107.49 एकड़ इस प्रकार कुल रक़बा 224.02 एकड़ भूमि को दिनांक 30 दिसंबर, 2011 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉ. पीके अब्दुल अज़ीज़ को हस्तांतरण कर दिया. हस्तांतरण के उपरांत चकला एवं गोविंदपुर मौजा में बसे अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग अनुसूचित जाति-जनजाति भू रक्षा संघर्ष समिति के बैनर तले लामबंद होने लगे और 6 फरवरी, 2012 को लगभग 7-8 हज़ार की संख्या में अपने पारंपरिक हथियार तीर-धनुष से लैस होकर समहरणालय के सामने धरने पर बैठ गए. धरने पर बैठे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों ने चौथी दुनिया को जानकारी दी कि चकला एवं गोविंदपुर मौजा की उपरोक्त भूमि हमें सरकार की तरफ़ से बंदोबस्ती में मिली है, जहां विगत 30-40 साल से हमलोग खेती कर रहे हैं.

पहले यह भूमि बंजर एवं बलुआही थी, जिसको हमने मेहनत करके उपजाऊ बनाया है. आज सरकार इस भूमि से हमें बेदख़ल कर रही और प्रशासन फ़र्ज़ी मुक़दमे लादकर हमारा का दमन कर रहा है. जी आर 331/10 प्राथमिकी संख्या 87/10 दिनांक 01-04-10 के बारे में आदिवासियों का कहना है कि यह मुक़दमा फ़र्ज़ी है, जिसमें प्रशासन द्वारा 47 निर्दोष आदिवासियों को फंसाया गया है. वहीं थाना कांड संख्या 24/12 दिनांक 24-01-2012 एएमयू की प्रस्तावित ज़मीन जोतने के मामले में रामेश्वर राम एवं चंद्रशेखर राम के साथ गुलाम अरशद एवं तौहीद पर फ़र्ज़ी मुक़दमा दायर कर जेल भेजा गया है. यह घटना पूर्व मुखिया सह ट्रैक्टर मालिक हाजी साहब एवं वर्तमान मुखिया की आपसी रंजिश का परिणाम है, जबकि जो ज़मीन जोती गई है वह रामेश्वर राम के नाम से बंदोबस्त है, जिसका खाता सं. 384 खसरा 23 रक़बा 2 एकड़ जमाबंदी नं. 786 है. हम इस प्रकार के फ़र्ज़ी मुक़दमों को प्रशासन से वापस लेने की मांग करते हैं. साथ ही इन लोगों का कहना था कि गोविंदपुर एवं चकला मौजे में सरकार के पास मात्र 25 से 30 एकड़ ज़मीन बची हुई है, शेष ज़मीन हमलोगों के नाम से बंदोबस्त है, जिसकी जमाबंदी हमलोगों के नाम से दर्ज है और भूराजस्व लगान भी दे रहे हैं. किशनगंज अंचल अधिकारी की प्रतिवेदन ज्ञापांक सं. 803 दिनांक 22-01-09 में इस बात का उल्लेख है कि मौजा चकला थाना नं. 28 के खाता नं. 384 खसरा 23 रक़बा 2 एकड़ जमाबंदी नं. 786 है. वैसे अनुसूचित जाति-जनजाति भू रक्षा संघर्ष समिति ने जो रिपोर्ट चौथी दुनिया को सौंपी है, उसके अनुसार चकला मौजा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 99 व्यक्तियों के नाम से बिहार सरकार गैरमजरूआ ख़ास खाते की भूमि बंदोबस्त है. वहीं गोविंदपुर मौजा में 38 व्यक्तियों के नाम से भूमि बंदोबस्त है. सरकार की तरफ़ से ज़िला प्रशासन ने वादा किया था कि एएमयू को ज़मीन हस्तांतरण के मामले में बंदोबस्त भूमि को नहीं लिया जाएगा, न ही किसी को विस्थापित किया जाएगा, लेकिन सरकार हमलोगों को बर्बाद और भूखा मारने पर तुली है.

इसके लिए हम जान दे देंगे पर ज़मीन नहीं देंगे. जल, जमीन, जंगल पर हमलोगों का हक़ है. भू-रक्षा संघर्ष समिति की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष कल्पना मुर्मू ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर हो रहे अत्याचार पर सरकार नियंत्रण करे, नहीं तो संपूर्ण बिहार में इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा, जिसमें दूसरे प्रांत से भी अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग आएंगे. धरना को भू-रक्षा संघर्ष समिति के अध्यक्ष टेटा सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष जीतन पासवान और संयोजक अभय मोदी ने भी संबोधित किया और कहा कि इसके लिए लड़ाई न्यायालय में भी लड़ी जाएगी.

feedback@chauthiduniya.com

लावालौंग उपेक्षा का दंश झेल रहा है

अमरेंद्र प्रताप सिंह

अपने गठन के 17 वर्षों के बाद भी चतरा ज़िले का सुदूरवर्ती प्रखंड लावालौंग उपेक्षा का दंश झेल रहा है. इस प्रखंड की जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है. इस प्रखंड का निर्माण 1995 ईस्वी में किया गया था. निर्माण के पांच वर्षों तक यह सिमरिया प्रखंड कार्यालय से ही संचालित होता रहा. यहां की कुल आबादी 38 हज़ार 761 है, जिसमें कुल 4305 व्यक्तियों को ही बीपीएल एवं अंत्योदय का लाभ मिल पा रहा है, जबकि यह प्रखंड अति पिछड़ा एवं हरिजन बाहुल्य क्षेत्र के रूप में चिन्हित है. एक ओर जहां आबादी के 90 प्रतिशत लोग ग़रीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करते हैं, वहीं सरकारी आंकड़ों में 10 प्रतिशत लोगों को ही इस श्रेणी में रखा गया है. आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी इस प्रखंड की 70 प्रतिशत आबादी को ठीक ढंग से सड़क मयस्सर नहीं है, लोगों को पगडंडियों के सहारे ही आवागमन करना पड़ता है.

प्रखंड का मुख्य व्यवसाय पत्तल की तुड़ाई करना एवं उसे बाज़ार में बेचना ही इनकी नियति बन गई है. सरकार के सौतेले रवैये का नज़ारा यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलता है. एक सरकारी आवासीय विद्यालय है, लेकिन उसमें अनियमितता की शिकायतें आम हैं. प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों की हालत भी हद से ज़्यादा बुरी है. विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की पढ़ाई की बात

लावालौंग प्रखंड को हमेशा से चारागाह की तरह उपयोग करने वाले नेताओं ने कभी भी इस क्षेत्र के विकास के प्रति ध्यान नहीं दिया. यही कारण है कि आज भी किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि, चाहे वह विधायक हो अथवा सांसद, किसी ने भी प्रखंड को विकास की धारा से जोड़ने का प्रयास नहीं किया.

निर्माणाधीन प्रखंड कार्यालय

ममता देवी (ज़िला परिषद अध्यक्ष)

तो दूर, मध्याह्न भोजन योजना पर भी आफ़त है. वर्तमान समय में लावालौंग प्रखंड में सिमरिया प्रखंड के बेलगडा गांव निवासी धरमदेव आर्य एवं खपिया गांव के रहनेवाले समाजसेवी मदन कुमार साहा तथा लावालौंग प्रखंड के बुद्धिजीवी गोपाल सिंह भोक्ता की पहल पर एक निजी महाविद्यालय गोपाल सिंह भोक्ता महाविद्यालय प्रारंभ किया गया है, जिसके कारण प्रखंड से बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करने वाले युवक एवं घर से बाहर न निकलने वाली युवतियों को उच्च शिक्षा मिल पा रही है. नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों का कभी गढ़ समझे जानेवाले लावालौंग प्रखंड आज जागरूकता में सबसे आगे है, और शायद यही कारण रहा कि इस सुदूरवर्ती प्रखंड से एक महिला ममता देवी ने घर की चौखट लांघ कर पहले तो आंगनवाड़ी सेविका के रूप में गांव की सेवा में अपना योगदान दिया और बाद में प्रखंड की जनता का अपार स्नेह पाकर ज़िला परिषद सदस्य के तौर पर निर्विरोध निर्वाचित भी हुईं.

वर्तमान में ममता देवी ज़िला परिषद के अध्यक्ष पद पर विराजमान हैं. आपको बता दें कि लावालौंग प्रखंड को हमेशा से चारागाह की तरह उपयोग करने वाले नेताओं ने कभी भी इस क्षेत्र के विकास के प्रति ध्यान नहीं दिया. यही कारण है कि आज भी किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि, चाहे वह विधायक हो अथवा सांसद, किसी ने भी प्रखंड को विकास की धारा से जोड़ने का प्रयास नहीं किया. यहां के ग्रामीणों का कहना है कि आज अगर क्षेत्र में विकास की अगर कोई बात करता है तो वह है ज़िला परिषद अध्यक्ष ममता देवी. इसके अलावा न तो सरकारी स्तर पर और न ही राजनीतिक स्तर पर पहल करने वाला कोई है.

feedback@chauthiduniya.com

खेतों में पानी के लिए जंग छिड़ी

शाहाबाद

शाहाबाद में सोन नहर प्रणाली को लेकर अब राज्य के मुख्य विपक्षी दल राजद ने नीतीश सरकार की घेराबंदी शुरू की है. अरसे बाद एक ऐसा मुद्दा उठकर सामने आया है, जो सचमुच में 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद अस्तित्व में आई सोन नहर प्रणाली को लेकर लड़ी जाने वाली लड़ाई है. हो भी क्यों नहीं, यह सोन नहर प्रणाली पूरे बिहार में अन्न की गारंटी जो है. लाखों हेक्टेयर ज़मीन पर 100 वर्ष से ज़्यादा तक सिंचाई देने वाली सोन नहरें और इसके इंद्रपुरी बैराज पर वर्तमान राज्य सरकार ने क्या किया, इसका लेखा-जोखा अब किसान मांगने लगे हैं. क्योंकि इस छह वर्ष की अवधि में इस परियोजना के साथ कुछ नया तो हुआ नहीं, बल्कि पुराने कार्य भी जस के तस पड़े हुए हैं. अगर यह समय पर पूरे हो जाते तो शायद सिंचाई समस्याओं पर एक हद तक क़ाबू पाया जा सकता था. इन्हें पूरा करने के लिए मात्र दस फ़ीसदी कार्य ही करना है. पूर्ववर्ती सरकार के दावों को अगर माना जाए तो बाणसागर और रिहंद से 80 लाख एकड़ फीट पानी बिहार को मिलना था. इसमें से 5 लाख एकड़ फीट पानी गंगा में प्रवाहित किया जाता है, लेकिन दावेदारी 75 लाख एकड़ फीट पर पूरी दावेदारी बिहार की बनती है. रही बात इंद्रपुरी बैराज से पूर्वी और पश्चिमी संयोजक नहरों में जल स्त्राव की तो पूर्व से क्रमशः 8 हज़ार और 5 हज़ार क्यूसेक प्रवाह की व्यवस्था रही है. इसमें इंद्रपुरी बैराज से अतिरिक्त 8 हज़ार क्यूसेक पानी लेने की व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकार ने शाहाबाद प्रक्षेत्र के लिए की थी, जिसमें एक आउटलेट का निर्माण शुरू हुआ था. इंद्रपुरी बैराज से लेकर डेहरी फाल तक बने इस आउटलेट का 90 फ़ीसदी कार्य इस सरकार में पूरा हो गया था, बाक़ी का काम पूरा होने से पहले राज्य में सरकार बदल गई. इसी सवाल पर इंद्रपुरी पहुंचे पूर्व जल संसाधन मंत्री जगदानंद सिंह ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि केवल यह काम पूरा हो जाए तो शाहाबाद की सिंचाई समस्याओं में समाधान की शुरुआत हो जाएगी.

पूर्ववर्ती सरकार के दावों को अगर माना जाए तो बाणसागर और रिहंद से 80 लाख एकड़ फीट पानी बिहार को मिलना था. इसमें से 5 लाख एकड़ फीट पानी गंगा में प्रवाहित किया जाता है, लेकिन दावेदारी 75 लाख एकड़ फीट पर पूरी दावेदारी बिहार की बनती है. रही बात इंद्रपुरी बैराज से पूर्वी और पश्चिमी संयोजक नहरों में जल स्त्राव की तो पूर्व से क्रमशः 8 हज़ार और 5 हज़ार क्यूसेक प्रवाह की व्यवस्था रही है. इसमें इंद्रपुरी बैराज से अतिरिक्त 8 हज़ार क्यूसेक पानी लेने की व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकार ने शाहाबाद प्रक्षेत्र के लिए की थी, जिसमें एक आउटलेट का निर्माण शुरू हुआ था.

लेकिन राज्य सरकार यह काम पूरा मात्र इसलिए नहीं कर रही है, क्योंकि इसका श्रेय राजद को चला जाएगा. श्रेय के सवाल पर जगदानंद सिंह ने कहा कि हम लिखकर देने को तैयार हैं कि सरकार सोन नहर प्रणाली में भले ही नया काम न करे, सिर्फ़ बचा हुआ काम ही पूरा कर दे तो श्रेय हम उनको दे देंगे. जगदानंद सिंह शाहाबाद के सांसदों, पूर्व सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों सहित पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ इंद्रपुरी पर पहुंचकर सोन नहर प्रणाली से जुड़ी समस्याओं पर मंत्रणा करने के बाद यह कह रहे थे. उन्होंने सरकार पर कई तकनीकी सवाल भी उठाए, जिससे स्पष्ट हो गया कि रिहंद और बाणसागर से हिस्सेदारी लेने के लिए राजद सरकार ने मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश सरकारों पर दबाव बनाकर जिस तरह से केंद्र को बाध्य किया था, उस पर नीतीश सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है, जो सीधे शाहाबाद के चार ज़िलों में सिंचाई व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है. राजद ने राज्य सरकार को इस सवाल पर भी घेरने की शुरुआत की है कि 15 वर्षों में सोन नहर प्रणाली से जुड़े किसानों को हम रोहिणी नक्षत्र में पानी देते थे और धान पकने तक पानी देते जाते थे. अब कौन सी बाध्यता आ गई है कि सरकार न तो रोहिणी नक्षत्र में पानी दे रही है और न ही धान पकने तक नहरों में पानी पहुंचा रही है. सिर्फ़ बीच में रोपने के कार्य किसी तरह से हो जाते हैं और यहां से रिकॉर्ड उत्पादन की बात कहकर एनडीए की सरकार अपनी पीठ थपथपा लेती है. इंद्रपुरी जलाशय परियोजना पर जगदानंद सिंह के साथ पहुंचे राजद के प्रदेश प्रवक्ता राम बिहारी सिंह, पूर्व विधायक ललन पासवान सहित कई नेताओं ने सोन प्रणाली की पहुंच से दूर रह चुके भोजपुर और बक्सर के दियारा क्षेत्र में सिंचाई को लेकर राज्य सरकार को घेरने की बात कही है और बताया कि आंदोलन नहीं, बल्कि किसानों के खेत खलिहान तक जाकर उनके पुश्तैनी रोज़ी-रोटी से जुड़े इस सवाल को समझाने का वक़्त आ गया है, जिसे राज्य की राजग सरकार लगातार उलझाने और बरगलाने के प्रयास में है.

ममता चौहान
feedback@chauthiduniya.com

सारण एक नज़र

बाल फिल्म महोत्सव की तैयारी

विनय कुमार ज़िला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बाल फिल्म महोत्सव संपन्न कराने हेतु बैठक समाहर्ता के कार्यालय प्रकोष्ठ में हुई, जिसमें सारण ज़िला मुख्यालय स्थित छवि गृहों के प्रबंधकों समेत सिनेमा मजिस्ट्रेट विनोदानंद झा, प्रभारी इबरार आलम, ज़िला जनसंपर्क पदाधिकारी विंदुसार मंडल समेत ज़िला शिक्षा प्रोग्राम पदाधिकारी ने भाग लिया. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग एवं ज़िला प्रशासन को बाल चित्र महोत्सव का आयोजन करने का निर्देश भारत सरकारी समना और प्रसारण मंत्रालय ने दिया है. सरकारी एवं ग़ैर सरकारी विद्यालय के छात्र इसे निःशुल्क देखेंगे. इसके तहत इस ज़िले में 24 फरवरी से 26 फरवरी तक इसका आयोजन करने का निर्देश है.

श्रमिक 28 फ़रवरी को हड़ताल करेंगे

देश में कार्यरत सभी केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर 28 फ़रवरी को देश में कार्यरत सरकारी, अर्धसरकारी तथा निजी उद्योग बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेल आदि कार्यालय बंद रहेंगे. भारतीय मज़दूर संघ कार्यालय में हुई सभी संगठनों की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया है. इस हड़ताल में देश में काम कर रहे असंगठित क्षेत्र के 42 करोड़ मज़दूर भी शामिल रहेंगे. इसकी जानकारी ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के महामंत्री अवध किशोर मिश्र ने दी.

रविदास जयंती संपन्न

संत शिरोमणि रविदास की जंयती धूमधाम से बिचला तेलपा में मनाई गई. कार्यक्रम का उद्घाटन विधान परिषद के उपसभापति सलीम परवेज़ ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया. इस अवसर पर मुख्य अतिथि विज्ञान एवं प्रद्यौगिकी मंत्री गौतम सिंह ने संत शिरोमणि रविदास के बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया. कार्यक्रम की अध्यक्षता महादलित प्रकोष्ठ के ज़िला अध्यक्ष सुपेंद्र नाथ चौधरी ने की. स्वागत जदयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ के ज़िला अध्यक्ष श्याम बिहारी अग्रवाल, मंच का संचालन सेवा दल के अध्यक्ष चंद्रभूषण पंडित और धन्यवाद ज्ञापन मनिंद्र कुमार उर्फ़ पप्पू दास ने किया.

गंगा महाआरती संपन्न

हर माह की भांति इस माह भी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर चिरान्द विकास परिषद के तत्वावधान में तीन नदियों के संगम बंगाली बाबा के घाट पर गंगा महाआरती का आयोजन भव्य रूप से किया गया. यह महाआरती बटुक आचार्य राजेश कौशिक द्वारा संपन्न कराई गई. बंगाली बाबा घाट पर महाआरती को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई. मालूम हो कि बंगाली बाबा घाट गंगा, यमुना एवं सरयुग का संगम है. यह घाट चिरान्द में स्थित है, जबकि चिरान्द का पुराना इतिहास रहा है.

अपहरण कांड का आरोपी गिरफ्तार

मढौरा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलनवाज़ अहमद के नेतृत्व में पुलिस बल को एक अच्छी सफलता मिली है. तरैया थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार एवं मशरक थानाध्यक्ष कपूरनाथ शर्मा के साथ गठित पुलिस टीम द्वारा भाजपा नेता विजय प्रताप सिंह के अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस अधीक्षक एके सत्यार्थी ने बताया कि 11 नवंबर, 2011 को मशरक मंडल भाजपा के महामंत्री श्री सिंह को उसके अपने ही बहनोई तरैंया थाना क्षेत्र के गांव निवासी मोहन सिंह ने अपने पांच हाथियार बंद साथियों की सहायता से अपहरण किया. बाद में सवा लाख बतौर फिरौती लेकर उन्हें मुक्त कर दिया .

आमजन से संबंध आवश्यक : डीआईजी

छपरा पुलिस लाइन में प्रशिक्षु आरक्षी के प्रशिक्षण के समापन समारोह में प्रशिक्षु पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए डीआईजी सुनील कुमार ने कहा कि पुलिस का कार्य आधुनिक हो गया है. समाज के मानवाधिकार की रक्षा की ज़िम्मेवारी पुलिस पर ही है. देश की आंतरिक सुरक्षा की सारी जवाबदेही पुलिस के कंधों पर है. आमजन के साथ पुलिस का व्यवहार उत्तम होना चाहिए. पुलिसकर्मियों को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम समाज से ऐसा व्यवहार करेंगे. समारोह में डीएसपी अजय कुमार, एसडीपीओ दिलनवाज़ अहमद सहित ज़िले के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे. समारोह में आरक्षी नीतीश कुमार को प्रथम, अभिषेक कुमार को द्वितीय व सत्येंद्र साह को तृतीय पुरस्कार मिला.

प्रस्तुति- शुभम् रानी चौहान, मनीष कुमार कश्यप, जयनाथ सिंह

एसएसबी कैंप से उजड़ जाएगा मठ!

इंतेजारूल हक़

भारत-नेपाल सीमा पर स्थित पूर्वी चम्पारण ज़िले के छौड़ादानो प्रखंड के कटनौतिया सरेह में स्थित ऐतिहासिक मठ से सटी सड़क पर एसएसबी कैंप स्थापित करने के लिए विभाग व सरकार द्वारा की गई घोषणाएं इन दिनों काफ़ी सुर्ख़ियों में हैं. मठ से सटी सड़क पर एसएसबी का कैंप बनाए जाने पर जहां मठ से आस्था रखने वाले भक्तों में आक्रोश है तो वहीं दूसरी तरफ़ किसानों के माथे पर भी पसीना आ रहा है.

एसएसबी का कैंप बनाए जाने से एक तरफ़ जहां भक्तों के आवागमन व मठ में प्रतिदिन होने वाले अष्टयाम, कीर्तन पर बुरा असर पड़ेगा तो दूसरी तरफ़ 200 किसानों के 25 एकड़ खेत भी प्रभावित होंगे. 1964 में बाबा तपसी द्वारा स्थापित उक्त मठ की पहचान ज़िले में ऐतिहासिक धरोहर के रूप में की जाती है और यहां दूर दराज से भक्त आशीर्वाद लेने, शुभ विवाह कार्यक्रम करने के लिए प्रतिदिन हज़ारों की तादाद में पहुंचते हैं. भक्तों का मानना है कि यहां शिवजी का आगमन होता है और उनकी हर मनोकामना पूरी होती है. पुराने ज़माने के अवशेष यहां आज भी रखे हुए हैं. मठ का पुराना दरवाज़ा भी अनेक मामलों को उजागर करता है.

ग्रामीण बताते हैं कि उक्त दरवाज़े को हटाने के लिए एक बार सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे थे, किंतु कोई सफलता नहीं मिली. इसके बाद से लोगों की आस्था काफ़ी बढ़ गई. मठ के महंत वीरादास के अनुसार, प्रतिदिन इन दिनों हनुमान आराधना, लखराव, आष्टयाम का आयोजन होता है और साल में दो बार भव्य मेला भी लगता है. पूरे चम्पारण में कटनौतिया मेले का नाम चर्चित है. वहां मेले में लोग पहुंचकर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं. मठ के पास अपनी ढाई बिगहा ज़मीन भी है और आस्था का प्रारंभिक दौर से ही केंद्र रहा है. यहां भक्तों के सहयोग से पोखरा में सूर्य मंदिर का भी निर्माण हुआ है, जो अपने आप में अनोखा है. अगर विभाग ने अपना फ़ैसला नहीं बदला तो उक्त मठ बदहाल हो जाएगा. हालांकि कैंप के लिए प्रस्तावित स्थल से क़रीब पांच किलोमीटर की दूरी पर एकडरे पंचायत में सरकार की क़रीब चालीस एकड़ ज़मीन है.

बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री स्व. कृष्ण सिंह का फ़ॉर्म भी यही है. उधर उक्त मठ को बचाने के लिए लोग गोलबंद भी होने लगे हैं और इलाक़े के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है. मठ बचाव संघर्ष समिति की स्थापना कर यहां की जनता अपनी लड़ाई लड़ रही है और उक्त समिति के बैनर तले फ़ैसला बदले नहीं जाने तक लड़ाई जारी रखने का आह्वान किया है. स्थानीय अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है. समिति के अध्यक्ष व प्रसिद्ध चिकित्सक शमीम अहमद, संयुक्त सचिव विरेमार, नवल यादव, संचालक उपाध्याय, केशव प्रसाद, मो. जावेद, ओमप्रकाश, वसीम अख्तर, अमीरुल्लाह आदि ने बताया कि एसएसबी कैंप के लिए प्रस्तावित यह स्थल कहीं से भी मुनासिब नहीं है. खैरवा, मुरली, बेला, श्रीपुर, धपहड़ समेत आधा दर्जन गांव प्रभावित हैं. शौच करने के लिए बाहर निकलने वाली महिलाओं को कई परेशानियां भी झेलनी पड़ेंगी और अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ेगा. दूसरी तरफ़ समाजसेवी व ज़िला जदयू के उपाध्यक्ष तथा तिनकोणी गांव निवासी कामेश्वर सिंह ने बताया कि उक्त मठ की रक्षा करना सब की नैतिक ज़िम्मेदारी है और इसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, वे करेंगे. उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक धरोहर के दर्शन के लिए नेपाल से भी भक्त आते हैं. उधर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री अशोक कुमार श्रीवास्तव ने भी एसएसबी कैंप के लिए प्रस्तावित स्थल का विरोध किया है.

डॉ. शमीम अहमद

ऐतिहासिक मठ
मठ के महंत

feedback@chauthiduniya.com

नई भूमिका में आनंद मोहन

मनोज ठाकुर

पिछले साढ़े चार वर्षों से जेल की काल कोठरी में आजीवन कारावास की सज़ायाफ्ता, जेल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन ने अपने विचारों को काग़ज़ों पर उकेरा है. जेल में विभिन्न विषयों पर इनके गद्य और पद्य के ग्रंथ तैयार हो रहे हैं. उनका पहला काव्य संग्रह क़ैद में आज़ाद क़लम का विमोचन दिल्ली में हुआ.

पिछले कुछ सालों में जेल की काल कोठरी में बंद आनंद मोहन इन दिनों न केवल दार्शनिक हो गए हैं, बल्कि विभिन्न विषयों पर आलेख और कविताएं भी गढ़ रहे हैं. कभी बिहार की राजनीति में युवाओं ख़ासकर राजपूतों के हीरो समझे जाने वाले इस नेता की देश की राजनीति में भी ख़ासी दख़ल थी. लेकिन कुछ ग़लत राजनीतिक फ़ैसलों ने इन्हें काफ़ी नुक़सान पहुंचाया. लंबे समय से जेल के भीतर रहकर आनंद मोहन ने न केवल विभिन्न महान ग्रंथों से लेकर कई दार्शनिकों के विचारों को छक कर पढ़ा है, बल्कि तन्हाई में ख़ुद एक कवि कथाकार और दार्शनिक भी हो गए हैं. आनंद मोहन की पहली कविता संग्रह क़ैद में आज़ाद क़लम का विमोचन हो चुका है. पूर्व सांसद आनंद मोहन फ़िलवक़्त सहरसा जेल में बंद हैं. दो खंडों में लिखे गए उनके कविता संग्रह का अभी पहला खंड ही छपा है.

आनंद मोहन ने अपनी रचना यात्रा को लेकर बताया कि उनकी काल कोठरी नाम से जेल डायरी पूरी है, जो छपने के लिए तैयार है. वह अपनी आत्मकथा भी लिख रहे हैं जिस पर अभी काम चल रहा है. आनंद मोहन ने बताया की पहले उनकी लेखनी आत्मकेंद्रित थी, लेकिन अब उसको आकाश मिल चुका है. अब वह विभिन्न विषयों पर एक साथ लिखते चले जा रहे हैं. जेल में जब बाल गंगाधर तिलक गीता लिख सकते हैं, कार्ल मार्क्स पूंजीवाद पर अनूठी पुस्तक की रचना कर सकते हैं तो फिर आनंद मोहन एक इतिहास क्यों नहीं गढ़ सकते. वैसे लगन हो, हिम्मत और हौसला-जुनून हो तो पहाड़ खोदकर भी दूध की नदियां बहाई जा सकती हैं. ज़ाहिर तौर पर कोई भी व्यक्ति मज़बूत और ईमानदार प्रयास से इतिहास गढ़ सकता है, चाहे वह कितना भी मामूली क्यों न हो.

feedback@chauthiduniya.com

गुणवत्ता का आलम यह है कि क्षेत्र के लोग कई जगहों पर काम बंद करवाकर निगरानी से जांच की मांग करने लगे हैं.

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

अररिया में लूट की छूट

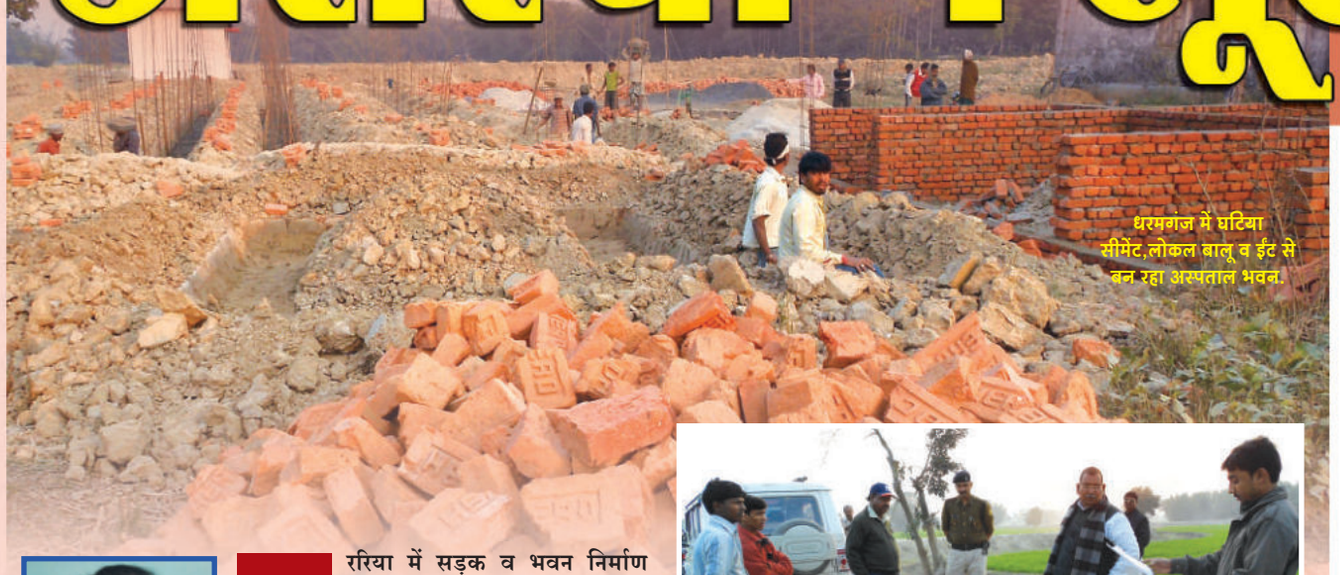

धरमगंज में घटिया सीमेंट,लोकल बालू व ईंट से बन रहा अस्पताल भवन.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की जांच करते एनबीसीसी के अभियंता, साथ में विधायक

उपेंद्र यादव

अररिया में सड़क व भवन निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की अनदेखी कर विकास के पैमाने पर सवाल खड़ा किया जा रहा है. एक तरफ़ सुशासन की सरकार विकास व गुणवत्ता की दुहाई दे रही है तो दूसरी तरफ़ संवेदक, अभियंता एवं अधिकारियों की तिकड़ी मालामाल हो रही है. अररिया ज़िले के विभिन्न प्रखंड क्षेत्रों में कहीं अस्पताल भवन तो कहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित होने वाली सड़कों को प्राक्कलन से कोई मतलब नहीं है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का निर्माण एनबीसीसी के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग कार्य एजेंसी द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है. इनके कार्यों में सड़क की बुनियाद कही जाने वाली बेड मिसाली में ही व्यापक पैमाने पर लोकल बालू मिलोर कर गुणवत्ता को ठेंगा दिखाया जा रहा है. गुणवत्ता का आलम यह है कि क्षेत्र के लोग कई जगहों पर कार्य को बंद करवाकर निगरानी से जांच की मांग करने लगे हैं. हालांकि कई जगह कार्य एजेंसी एनबीसीसी के कार्यपालक अभियंता विजय कुमार के नेतृत्व में कोलकाता की ओमेगा कंसलटेंसी सर्विस के कनीय अभियंता पल्स दास के टीम द्वारा बेड मिसाली की जांच की गई तो 8 से 10 प्रतिशत बालू अधिक पाई गई. जिसे इन अभियंताओं की टीम ने सड़क की मज़बूती की दृष्टि से ग़लत बताया.

इतना ही नहीं सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता को लेकर सिकटी विधायक आनंदी प्रसाद यादव द्वारा भी निगरानी विभाग को पत्र लिखकर जांच की मांग की गई है. क्षेत्र भ्रमण के दौरान विधायक श्री यादव ने कहा कि सिकटी विधानसभा क्षेत्र के पैकेज नंबर 70 में गोपाल नगर से धर्मगंज व बीड़ी हाट से धर्मगंज, कालू चौक से खोरागाछ तक कुल 23 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण कार्य चल रहा है. यहां गुणवत्ता कोई मायने नहीं रह गई है. जनता की गाढ़ी कमाई और सरकारी पैसों को कार्यकारी एजेंसी और पदाधिकारियों की मिलीभगत से लूटा जा रहा है. विधायक श्री यादव ने कहा कि एनबीसीसी के कार्यपालक अभियंता द्वारा गुणवत्ता की जांच तो कराई गई है. लेकिन इस जांच में भी संवेदक से मिलकर जांच एजेंसी ने घालमेल कर लिया है. उन्होंने कहा कि बेड मिसाली की जगह बकरा नदी की बालू सड़कों पर बिछाई जा रही है. इसे देखकर आम लोग भी आक्रोशित हो रहे हैं. इसी तरह पैकेज नंबर 69 के तहत सेनवारी चौक भपटिया से धर्मगंज होकर मेहरू चौक तक जाने वाली सड़क की हालत ऐसी ही है. ठेकेदार अपने मनमर्ज़ी से काम कर रहे हैं. प्राक्कलन से इतर लोकल बालू मिलाकर बेड मिसाली का नाम दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इस भ्रष्टाचार को कोई देखने-सुनने वाला नहीं है. उन्होंने कहा कि एक ओर जनता इस स्थिति को देख आक्रोशित हो रही है. विधायक पर दबाव बढ़ता जा रहा है. जवाबदेह पदाधिकारी कुंडली मार कर ख़ामोश बैठे हैं. कोई सुनने को तैयार नहीं है. ऐसे में निगरानी विभाग से जांच करने का अनुरोध किया गया है.

इसी प्रकार ज़िले के पलासी प्रखंड अंतर्गत धर्मगंज में क़रीब 65 लाख की लागत से निर्माणाधीन अस्पताल में प्राक्कलन के विरुद्ध घटिया ईंट, सीमेंट व लोकल बालू का प्रयोग किया जा रहा है. आरईओ टू के पदाधिकारी भी अपनी जवाबदेही से उदासीन नज़र आते हैं. भाजपा विधायक श्री यादव ने कहा कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मयस्सर कराने के लिए बनाया जा रहा भवन भी संक्रमित होता जा रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

इंडियन इंस्टीच्युट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एण्ड रिसर्च
हेल्थ इंस्टीच्युट रोड, बेउर, पटना-२
(बिहार सरकार, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार तथा आइ.ए.पी.से मान्यता प्राप्त)
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया से संबंधन प्राप्त

We Impart:-

POST GRADUAGE COURSES:
MPT Master of Physiotherapy
MOT Master of Occupational Therapy
MPO Master of Prosthetic & Orthotic
MASLP Master of Audiology & Speech Language Pathology
BPT Bachelor of Physiotherapy
BOT Bachelor of Occupational Therapy
BPO Bachelor of Prosthetic & Orthotic
BASLP Bachelor of Audiology & Speech Language Pathology
BMRT Bachelor of Radio Imaging Technology
BMLT Bachelor of Medical Laboratory Technology
B.Ed. (Special Education)
B.Ophth. Bachelor of Ophthalmology

संस्थान द्वारा संचालित निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं
- स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श
- टीकाकरण
- फिजियोथेरापी
- अकुपेशनल थेरापी
- स्पीच थेरापी
- नेत्र जाँच
- सभी प्रकार की विकलांगता पोलियो,लकवा,गठिया,हड्डी, जोड़ एवं नस से संबंधित सभी प्रकार के रोगों की जांच एवं उपचार
- हकलाना, तुतलाना सहित गूंगे-बहरों की जाँच एवं उपचार हियरिंग-एड
- मानसिक विकलांगता तथा मंद बुद्धिपता जाँच एवं उपचार
- कृत्रिम हाथ,पैर,कैलीपर,पोलियो के जूते,वैशाखी, सर्वाइकल कॉलर, बेल्ट आदि का निर्माण एवं वितरण
- लाचार विकलांगों को तिपहिया-साकिल तथा व्हीलचेयर
- विकलांगों की शल्य चिकित्सा,सर्जिकल करेक्शन
- रियायती दर पर पैथोलोजिकल जाँच,एक्स-रे, इ.सी.जी. तथा शल्य

1 Yr. ABRIDGED DEGREE For DPT & DOT

DIPLOMA COURSES:
DPT Diploma in Physiotherapy
DPO Diploma in Prosthetic & Orthotic
DMLT Diploma in Medical Lab. Tech
D-X-Ray Diploma in x-ray Technology.
DHM Diploma in Hospital Management
DOTA Diploma in Operation Theater Assistant
DECG Diploma in E.C.G.

certificate courses:
CMD Certificate in Medical Dressing
Foundation Course for Teachers in Disability

Form & Prospectus:- Available at the institute counter against payment of Rs. 300/-. Send a DD of Rs. 350/-only for postal delivery, in favour of Indian Institute of Health Education & Research, Patna-2
Eligibility:- For Post Graduate Courses- Degree in the same. 10+2 with science for Under Graduate & Diploma Courses. For B.Ed. Degree in any Subject.

Admission Going On...
डा. अनिल सुलभ निदेशक-प्रमुख

फोन न. : 0612-2253290, 2252999, फैक्स: 0612-2253290,email. iiher_beur@gmail.com, www.iiher.org

महारानी ललिता देव प्रभु कमल यादव महाविद्यालय

(स्थापित-1982)
(भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय,लालु नगर, मधेपुरा एवं राज्य सरकार से स्थायी संबंधन प्राप्त)
तेज नारायण नगर,अररिया:-854311

स्व. तेज नारायण यादव
संस्थापक सचिव

उपेन्द्र यादव
संस्थान के सचिव

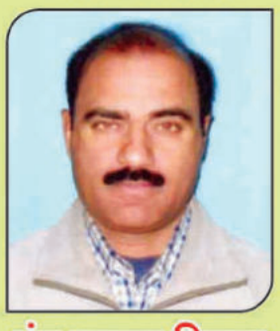

इंदु कुमार सिन्हा
प्रधानाचार्य

तेज नारायण यादव मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट
द्वारा संचालित प्रमुख शैक्षणिक संस्थान

- यमुना प्रसाद स्मारक संस्कृत उच्च विद्यालय, कन्हैली, अररिया
- सुमरित-यमुना-सरयुग संस्कृत महाविद्यालय, कन्हैली,अररिया
- तेज नारायण यादव (कन्हैली)उच्च विद्यालय, अररिया
- महारानी ललिता देव प्रभु कमल यादव इंटर महाविद्यालय, अररिया
- सुमरित-यमुना महिला डिग्री कॉलेज, अररिया (स्थापना-1983)

शिक्षा की अलख जगाने वाले तेज नारायण यादव का जन्म अररिया जिले के पंचायत खाब्दह कन्हैली निवासी किसान यमुना प्रसाद मंडल व महारानी देवी के घर 3 जनवरी 1945 को हुआ था. इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि काफी सबल रही है. तेज नारायण को तीन बहनें व चार भाई थे.इनका लालन-पालन व शिक्षा-दीक्षा अपने फुफेरा भाई चद्रानंद यादव के सानिध्य में खूंट पूर्णिया में हुई. इनका निधन 14 दिसम्बर 1999 को अररिया में हुआ. इनके फुफेरे भाई चद्रानंद यादव ठाकुर उच्च विद्यालय,खूंट पूर्णिया के सचिव थे. श्री यादव प्रथम श्रेणी से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद टीएनबी कॉलेज,भागलपुर से आईएससी व एमएस कॉलेज मोतिहारी से रसायन शास्त्र से स्नातक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए. वे मोतिहारी से ही कानून की डिग्री हासिल की. इसके बाद वे बैंक की नौकरी में चले गये. भारतीय स्टेट बैंक मोतिहारी शाखा में कैशियर पद पर कार्यरत भी रहे. मोतिहारी से स्थानांतरण होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा अररिया में योगदान दिया तथा आजीवन इसी शाखा में कार्यरत रहे. श्री यादव ने माता, पिता, दादा, चाचा, भाई व पत्नी ललिता देवी के नाम पर कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना किए. ये अपने पैतृक गांव कन्हैली में निजी जमीन खरीदकर प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा का दीप जलाया.जिससे आज लोग फलीभूत हो रहे हैं.
इनका व्यक्तित्व शांत व मृदुभाषी स्वभाव का रहा. स्व. तेज नारायण यादव को एक पुत्री आशा कुमारी है और अपने जीवनकाल में ही विवाह दान करवाए थे. स्व. यादव मृत्यु पूर्व ही अपने भांजा उपेद्र प्रसाद यादव को उत्तराधिकारी बनाया. ताकि उनके द्वारा स्थापित विद्यालय, महाविद्यालय व ट्रस्ट आदि का संचालन सुचारू रूप से हो सके. इनके निधन के बाद से ही तेज नारायण यादव मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट के उपेद्र प्रसाद यादव सचिव व रूद्रकिंकर वर्मा अध्यक्ष के रूप में उनके सपनों को साकार करने के लिए इंजिनियरिंग व मेडिकल कॉलेज सहित अन्य शैक्षणिक संस्थान भी खोलने की दिशा में प्रयासरत हैं.

-:: आवश्यक सूचना ::-

एम.एल.डी.पी.के. यादव डिग्री कॉलेज अररिया, बी.एन.एम. यू. मधेपुरा एवं राज्य सरकार से स्थायी मान्यता प्राप्त, विश्वविद्यालय सेवा आयोग के सभी शर्त्तों को पूर्ण करेनवाला अररिया जिला का एक मात्र महाविद्यालय है।

1. महाविद्यालय में छात्रावास की पूर्ण व्यवस्था / प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं वृहत खेल का मैदान
2. दलित/ अति पिछड़ा जाति के छात्र/छात्राओं को कल्याण विभाग / बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम से छात्रवृत्ति की समुचित व्यवस्था.
3. सुयोग्य व कर्मठ शिक्षकों द्वारा पठन-पाठन की व्यवस्था.
4. शत प्रतिशत छात्र/छात्राओं की उत्तीर्णता.
5. नियमित वर्ग संचालन की व्यवस्था.
6. महिला छात्रावास की समुचित व्यवस्था.

उपेन्द्र प्र. यादव
(सचिव)
मो. - 9431060702, 8409127202

प्रो. इन्दु कुमार सिन्हा
प्रधानाचार्य
मो. - 9771238892

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

दिल्ली, 20 फरवरी-26 फरवरी 2012

www.chauthiduniya.com

मुस्लिम आरक्षण के बाद

अब राहुल विकास की बात कर रहे हैं

संजय सक्सेना

राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं. वहीं देश के बड़े राजनेताओं के विपरीत वह प्रधानमंत्री पद के प्रति आसक्त नहीं. उन्हें इस बात की नाराज़गी है कि उत्तर प्रदेश में 22 सालों से ग़ैर कांग्रेसी सरकारें जनता को बेवकूफ़ बनाती चली आ रही है. वह इस मुहिम को ब्रेक देना चाहते हैं, लेकिन चुनाव बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सत्ता के लिए मिल सकते हैं, इस बात को वह टाल जाते हैं. चुनावी दौरे पर निकले राहुल गांधी जब धर्मनगरी वाराणसी पहुंचे तो उन्होंने दिल खोलकर मीडिया से बात की. शब्दों के बाण चलाकर कांग्रेसी युवराज ने भाजपा, बसपा और सपा सभी को दाग़दार साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. वह विपक्ष के उस हमले से भी आहत दिखे, जिसमें प्रियंका को बरसाती मेंढक कहा गया था. शायद उन्होंने यह मुहावरा सुना नहीं होगा, अन्यथा वह यह नहीं कहते कि अगर प्रियंका मेंढक है तो मैं भी उसका भाई होने के नाते मेंढक हुआ. उन्होंने पत्रकारों के सभी सवालों का जवाब दिया, लेकिन मीडिया के सामने वह अपनी बहुमत वाली सरकार बनने की बात नहीं कह सके, बल्कि उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि वह प्रदेश में कांग्रेस को खड़ा करने आए हैं और कांग्रेस को 100 सीटें मिलें या फिर 200 कांग्रेस इससे खड़ी ज़रूर हो जाएगी.

राहुल ने ख़ुद के प्रधानमंत्री बनने की संभावना पर कहा कि हिंदुस्तान के बड़े राजनेता इस बात के लिए आसक्त हैं कि वे प्रधानमंत्री बनें, लेकिन मेरी ऐसी कोई आसक्ति नहीं है. मेरा मक़सद उत्तर प्रदेश का विकास करना है. मैं सिर्फ़ जनता की आवाज़ सुनता हूं और इसे लोकसभा तक ले जाता हूं. मेरा उत्तर प्रदेश में प्रगति लाने का मिशन है. जब तक उत्तर प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा, तब तक राहुल गांधी आपकी झोपड़ियों में किसानों के साथ दिखाई देगा. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कामयाबी के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए राहुल ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए ठोस परिणाम आ रहे हैं. जनता कांग्रेस की तरफ़ देख रही है. मैं जहां भी जा रहा हूं, वहां जनता हमसे कह रही है कि यहां की सरकारों ने उन्हें 22 साल बेवकूफ़ बनाया है. कांग्रेस सांसद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के फिर से खड़े नहीं होने तक वह चैन से नहीं बैठेंगे. उन्होंने कहा सीधा आंकड़ा है. इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी. वह 200 सीटों से भी खड़ी हो जाएगी और 100 सीटों से भी.

राहुल से जब पूछा गया कि वह बहुमत नहीं मिलने पर किसी दल से हाथ मिलाकर सरकार बना सकते हैं तो उन्होंने दोहराया कि वह उत्तर प्रदेश में किसी राजनीतिक पार्टी से समझौता नहीं करने आए हैं. उनका समझौता राज्य की जनता के साथ होगा. हालांकि चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन के सवाल का उन्होंने गोलमोल ही उत्तर दिया. जनता भले ही केंद्र और राज्य सरकार के भ्रष्टाचार से त्रस्त हो, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर उनके मानक शायद अलग हैं, यही वजह है एक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को खरी-खोटी सुनाते हुए कहा कि आडवाणी जी को झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और पंजाब समेत भाजपा शासित राज्यों में भ्रष्टाचार नहीं दिखता. हमें अपने यहां जब भी भ्रष्टाचार का कोई मामला सुनाई दिया, हमने कार्रवाई की.

लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने संबंधी सवाल पर भी राहुल ने कहा कि मैंने संसद में कहा था कि हमें चुनाव आयोग की तरह वैधानिक लोकपाल गठित करने दीजिए. आडवाणी और विपक्षी नेताओं ने मेरे इस विचार की हंसी उड़ाई थी. अब आप जब उनसे पूछते हैं कि आपने संवैधानिक लोकपाल क्यों नहीं बनने दिया तो वे कहते हैं कि वह राहुल गांधी का विचार था, मगर ऐसा नहीं है, वह मेरा नहीं बल्कि देश का विचार था. राहुल ने विदेशी बैंकों में जमा कालेधन को भारत लाने की योग गुरु बाबा रामदेव की मांग संबंधी सवाल का सीधा जवाब नहीं देते हुए कहा कि बाबा रामदेव जी अपने चार-पांच लोगों को काले झंडे लेकर मेरी हर जनसभा में भेज रहे हैं. वे सोचते हैं कि चार झंडे देखकर राहुल भाग जाएगा. आप झंडे लगाओ, गोली मारो, जूता मारो, मैं किसी से नहीं डरता.

ज्ञान आयोग के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की ओर से कांग्रेस के अहम कार्यक्रमों में ख़ुद को बढ़ई का बेटा बताए जाने के औचित्य संबंधी सवाल पर राहुल ने कहा उत्तर प्रदेश में जाति का महत्व है. सैम पित्रोदा कहते हैं कि इस देश में आशा की किरण बाक़ी है. वह लोगों को यह समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति देश को बदल सकता है. अगर आप सोचते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो ग़लत सोचते हैं. प्रदेश के विभाजन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ऐसे फ़ैसले लेना काफ़ी जटिल काम है, क्योंकि यह करोड़ों लोगों के भविष्य का सवाल होता है. राहुल ने कहा कि मायावती ने बिना सोचे-समझे विधानसभा में दो मिनट में राज्य विभाजन का प्रस्ताव पारित करा दिया. भारत में विशेषज्ञ हैं जो इस मामले को देख समझ सकते हैं. मैं समझता हूं कि ऐसे गहरे मामले में विशेषज्ञों की राय लेना ज़रूरी है. कांग्रेस के युवराज ने आरोप लगाया कि मायावती और मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश को नहीं बदलना चाहते. राज्य को एक ही चीज़ बदल सकती है और वह है आपके मुख्यमंत्री का दृढ़ निश्चय. मैं आदर के साथ मायावती और मुलायम सिंह के बारे में कहना चाहता हूं कि वे दोनों उत्तर प्रदेश को नहीं बदलना चाहते.

राहुल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के नेता जनता की आवाज़ की इज्जत नहीं करते, जबकि कांग्रेस ऐसा करती है. राज्य में पिछले 22 सालों से ऐसी सरकारें रहीं जो सिर्फ़ 10 प्रतिशत लोगों के लिए काम करती रही हैं. प्रदेश में कभी गुंडे सत्ता में आते हैं तो कभी चोर. उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रदेश में विकास नहीं हो रहा है तो इसका एक ही कारण है कि जनता की शक्ति का ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रहा है. उन्होंने मायावती को कोसा तो इससे दलित नाराज़ न हो जाएं, इसलिए यह भी कहा कि वह बसपा संस्थापक कांशीराम का सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रदेश की राजनीति में योगदान दिया है. कांग्रेस महासचिव ने मायावती और मुलायम सिंह का नाम लेते हुए कहा कि उन्हें उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, लेकिन वे दोनों जनता से विमुख हो गए हैं.

feedback@chauthiduniya.com

राहुल विकास चाहता है : प्रियंका

बहन प्रियंका, अमेठी का डंका के नारों से सम्मानित की जा चुकी प्रियंका गांधी एक बार फिर अपने भाई राहुल के लिए चुनावी जंग में कांग्रेस की स्टार प्रचारक के रूप में उतर पड़ी हैं. वह पहले भी अपनी मां और भाई के प्रचार के लिए कई बार रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर में चुनावी प्रचार की बागडोर थाम चुकी हैं, जहां उन्हें अप्रत्याशित सफलता मिली है. प्रियंका गांधी ने अमेठी संसदीय क्षेत्र से प्रचार की शुरुआत की. उन्होंने सधे हुए भाषणों से जनता को उनके दर्द को बयान करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी. उन्होंने माया और मुलायम को राहुल का दुश्मन न कहकर भ्रष्टाचार को जनता का असली दुश्मन क़रार दिया. अल्पा फैक्टर से वह लगातार बचती रहीं. उन्होंने कहा जिस स्थान पर जनता को रहना चाहिए, उस स्थान को लेकर विधायक उनका हक़ छीन रहे हैं. उन्होंने कहा कि जो धन विधायक अपने बंगले बनवाने में लगाते हैं, वह जनता का ही है. इसके लिए जनता को जागरूक होकर वोट करना चाहिए, ताकि उनका और प्रदेश का विकास हो सके. उन्होंने माया और मुलायम सिंह को आड़े हाथों लिया और कहा कि ऐसे लोगों की जातिवादी राजनीति से जनता को बचना चाहिए. प्रियंका गांधी ने राहुल के उत्तर प्रदेश के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होने की बात करते हुए कहा कि मेरा भाई बड़ा ढीठ है, मैंने समझाया कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, जनता कांग्रेस को जिताए न जिताए, पता नहीं क्या नतीजा आएगा, लेकिन भाई ने कहा कि यूपी में नतीजे से मतलब नहीं है. यूपी पिछड़ा है. वहां बदलाव लाना हैं इसलिए मेहनत कर रहे हैं. मुझे चुनाव में जीतने न जीतने से कोई विशेष चाहत नहीं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की बेहाल जनता की तस्वीर बदलना चाहता हूं. प्रियंका ने विश्वासभरे लहजे में रोड शो में जनता से कहा कि यूपी में कांग्रेस की सरकार बनाने में मदद कीजिए. विकास में भागीदार बनिए. चुनाव के मौसम में सभी आते हैं मैं भी आती हूं, लेकिन आपके पास विवेक है, इसका इस्तेमाल कर वोट दें. आप ख़ुद अपने विवेक से फ़ैसला लें. आपको जात-पात के दायरे से निकल कर विकास की ओर ले जानी वाली सरकार चुनना चाहिए. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लंबे समय से आप लोगों के बीच आ रहे हैं उनका इस तरह आप लोगों के बीच आना सत्ता पाने की चाहत के लिए नहीं, बल्कि वो सूबे को विकास की पटरियों पर दौड़ाना चाहते हैं. अब वक़्त आ गया है. कि आप ख़ुद सोचे कि आप को क्या करना और क्यों करना है. प्रियंका गांधी की छवि में इंदिरा गांधी की छवि निहारने वाली रायबरेली और अमेठी की जनता उन्हें सर आंखों पर बिठाने के लिए तैयार है. राजनीतिक विद्वान यह भी कहते सुने जाते हैं कि अगर प्रियंका राजनीति में आ जाएं तो निश्चित ही कांग्रेस की छवि चमक जाएगी, लेकिन इस रुकावट के पीछे कौन से कारण हैं कि प्रियंका राजनीति में अपने क़दम क्यों नहीं बढ़ा रही हैं. शायद वह अपने भाई के राजनीतिक करियर के लिए पर्दे के पीछे रहकर काम करना चाहती हैं. प्रियंका गांधी भाई राहुल गांधी के लिए एक सारथी की तरह नज़र आ रही है.

प्रियंका के नपे-तुले सियासी जुमले

कांग्रेस की उम्दा स्टार प्रचारक रूप में प्रियंका अपनी मां सोनियां गांधी और भाई राहुल गांधी के चुनाव प्रचार में आती रही हैं, लेकिन इस बार उनका चुनाव प्रचार में लहजा कुछ अलग ही देखने को मिला है. रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी का रोड-शो और प्रेस कांफ्रेंस में उनके तेवर देखकर कांग्रेसी हैरान रह गए. जब उनके मुंह से यह कहते सुना गया कि आप चाहते हैं मैं राजनीति में आऊं, यह माया और मुलायम से पूछिये कि क्या मैं राजनीति में आऊं. इस वाक्य में दो अर्थ छिपे हैं, पहला यह कि अब तक भाई की ताजपोशी के लिए प्रियंका गांधी लगातार चुनाव के दौरान प्रचार करती रही हैं. लोगों के कुरेदने पर उनके मुख जो निकला वह कांग्रेस में एक लहर पैदा कर देने वाला साबित हो रहा है कि देर सवेर अब प्रियंका गांधी राजनीति में आ सकती हैं. उनके पति रॉबर्ट वढेरा उनके साथ चुनाव प्रचार में अमेठी पहुंचे तो उनसे अख़बारनवीसों ने पूछा कि आप राजनीति में आना चाहते हैं, तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि अगर जनता चाहेगी तो मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा. प्रियंका के सक्रिय राजनीति में आने के सवाल पर वढेरा ने जवाब दिया कि हर चीज़ के लिए एक वक़्त होता है. यह राहुल का वक़्त है, प्रियंका का भी वक़्त होगा, तब देखेंगे. वैसे तो प्रियंका और राहुल को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन परिवार का सदस्य होने के नाते राहुल का संदेश कोने-कोने तक पहुंचाने के लिए यहां आया हूं. आप लोगों को इस बार निश्चित रूप से परिवर्तन देखने को मिलेगा. राहुल के पीएम बनने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि इसका जवाब वह नहीं ख़ुद राहुल देंगे. प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वढेरा के अलग-अलग सियासी वक्तव्यों को समझकर कांग्रेसी सकते में आ गए कि आख़िर प्रियंका और रॉबर्ट इतना मुखर क्यों हो रहे हैं. यह बात पत्रकारों और कांग्रेसियों को पच नहीं पा रही थी. बात दिल्ली तक जा पहुंची, कांग्रेस के केंद्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से पत्रकारों ने इस बाबत पूछा तो उन्होंने कहा कि वह इस बारे में कुछ नहीं जानते. रॉबर्ट के वक्तव्यों को प्रियंका ने सुधारते हुए कहा कि वह अपने पति को अच्छी तरह जानती हैं. वह राजनीति में नहीं आ रहे हैं. वह अपने व्यवसाय में ही ख़ुश हैं. प्रियंका और रॉबर्ट के बयानों से यह बात सियासी गलियारों में बड़ी तेज़ी के साथ फैल चुकी है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की राजनीति में क़दम रख सकती हैं.

दर्शन शर्मा, लखनऊ ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

भारत को वायुसेना के पुराने हो चुके मिग-21 विमानों को बदलने के लिए इन विमानों की आवश्यकता थी. रक्षा मंत्रालय ने इनकी ख़रीद के लिए निविदा निकाली थी.

प्रत्येक चुनाव में भाजपा और संघ के लिए अपने वोटरों को बाहर निकालना टेढ़ी खीर साबित होता है.

चुनावी हलचल

हिंदू और मुसलमानों को साथ लेकर चलने की क़वायद

भारतीय जनता पार्टी चुनावी समर में हिंदुओं को मनाने और मुसलमानों को रूठने से बचाने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती है. उसे इस बात की चिंता नहीं है कि मुस्लिम उसे वोट नहीं देता है. वह तो इतना भर चाहती है कि सांप्रदायिकता का हौवा करके मुसलमानों को बरगलाने वाले नेताओं की दाल चुनावी हांडी में न गल पाए. अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए भाजपा नेतृत्व मुस्लिम समाज के प्रबुद्धजनों के साथ मिल बैठकर हक़ीक़त बताने में लगा है. उसे बताया जा रहा है कि भाजपा की जब केंद्र में सरकार थी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुसलमान भाइयों के अरब देशों में जाकर काम का रास्ता आसान किया था. उन्हें यह भी समझाया जा रहा है कि भाजपा शासित राज्यों में अन्य राज्यों के मुक़ाबले भाईचारा और अमन-चैन ज़्यादा सुरक्षित है. मुसलमानों को ख़ुश रखने के लिए टोटके भी आज़माए जा रहे हैं. हाल में जारी भाजपा के घोषणा-पत्र में भी इसकी छाप दिखाई दी. मीर तक़ी मीर, मिर्ज़ा ग़ालिब, अशफ़ाक़ उल्लाह ख़ां और फ़िराक़ गोरखपुरी जैसे नामों का हवाला [illegible] भाजपा सरकार बनने की दशा में उनके नाम से पुरस्कार की घोषणा करने का वादा भी कर रही है. वहीं गुजरात दंगों के कारण बदनाम हुए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से भी यूपी में किनारा कर लिया गया है. मुसलमान न रूठें इसके लिए नरेंद्र मोदी को प्रचार अभियान से दूर रखा गया है. [illegible] लालकृष्ण आडवाणी और अरुण जेटली के दौरों को देखा जा सकता है. हिंदुओं को साथ रखने के लिए पूर्व उप-प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी एक तरफ़ अयोध्या में जनसभा और रामलला के दर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ़ [illegible] मुस्लिम समाज की बैठक कराई जा रही है.

–अजय कुमार, लखनऊ ब्यूरो

जनप्रतिनिधि मतलब जनता का प्रतिनिधि : मौलाना इम्तियाज़ नदवी

विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं. रायबरेली व अमेठी लोकसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के प्रभारी [illegible] का कहना है कि आज धर्म को राजनीति से अलग कर दिया गया है. सियासत की गंदगी को साफ़ करने के लिए ही वह सियासत में उतरे हैं. उन्होंने कहा कि उलेमा काउंसिल निःस्वार्थ सेवा करने में विश्वास करती है. जनप्रतिनिधि का मतलब जनता का प्रतिनिधि होता है. उसे अपने फ़ायदे को दरकिनार कर समाज की मदद के लिए आगे आना चाहिए. यदि वह ऐसा करने में असमर्थ साबित होता है तो जनप्रतिनिधि बनने लायक़ नहीं है. उन्होंने कांग्रेस की शिक्षा नीति पर प्रहार करते हुए कहा कि भारत की मज़बूत शिक्षा व्यवस्था को कांग्रेस की [illegible] शिक्षा नीति नष्ट करने पर तुली हुई है. नई शिक्षा नीति के तहत इंटर मीडिएट तक किसी भी छात्र अथवा छात्रा को फेल करने का प्रावधान नहीं है. इससे छात्रों में अराजकता बढ़ेगी. नई शिक्षा नीति का दूसरा प्रावधान भी ख़तरनाक है. बच्चा तीन किलोमीटर से अधिक दूर पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहिए. जबकि तीन किलोमीटर में कोई अच्छा तालीमघर नहीं है तो अभिभावक क्या करेंगे. इसी के साथ शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन में 50 प्रतिशत महिला व दलित को शामिल करने का नियम भी शिक्षण संस्थाओं पर ज़बरन क़ब्ज़ा करने के समान है. इस फ़रमान का पालन न करने वाले पर एक लाख रुपये का जुर्माना और अदा न करने पर दस हज़ार रुपये जुर्माना देने का प्रावधान है. राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल इस शिक्षा नीति का विरोध करेगी. वहीं नहीं कांग्रेस ने चैरिटी संस्थाओं की आय पर 30 प्रतिशत आय कर अदा करने का आदेश भी जारी कर दिया है. इससे चैरिटी संस्थाएं बंद हो जाएंगी, जिसका प्रभाव समाज सेवा पर पड़ेगा.

मुझे जिताओ, सपा की ज़मानत ज़ब्त कराओ : बेनी बाबू

कांग्रेस इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने फ़तेहपुर की एक चुनावी सभा में कहा कि सपा ने मुझे बहुत परेशान किया है. मुझे जिताओ और सपा की ज़मानत ज़ब्त कराओ. बेनी ने कहा कि सपा शासनकाल की गुंडागर्दी एवं अराजकता जगज़ाहिर है. प्रदेश की जनता सपा शासन में त्रस्त थी, वहीं बसपा ने जनता के साथ धोखा किया है. भ्रष्टाचार को चार साल में चरम पर पहुंचाकर बसपा ने जनता को ठगा है. अब जनता कांग्रेस को आशाभरी नज़रों से देख रही है. वहीं सांसद अज़हरुद्दीन ने कहा कि कांशीराम का मुख्य उद्देश्य ग़रीबों एवं दलितों के कल्याण पर विशेष ध्यान देने का था. [illegible] गाढ़ी कमाई पत्थरों की मूर्तियों पर ख़र्च कर दी गई है. इसलिए अब पंजे पर मोहर लगाना है, प्रदेश को बचाना है.

बाघ की तलाश में निकली रूपकली

राजधानी लखनऊ में चुनावी सरगर्मी के बीच एक बाघ ने लोगों को घर से निकलना दूभर कर रखा है. [illegible]

– दर्शन शर्मा, लखनऊ ब्यूरो

सभी दल मुस्लिम विरोधी : कमाल अशरफ़

[illegible]

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

नाम के लिए विवादों को हवा

अजय कुमार

पूर्व सपा नेता और अब कांग्रेस की केंद्र सरकार में मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव मोदी बनाम राहुल होने की बात कहकर न केवल एक नई बहस छेड़ दी है. उन्होंने मुसलमानों को अपने जाल में फंसाने के लिए एक तरह से चारा भी डाल दिया है. कांग्रेस ने पहले मुसलामानों का दिल जीतने के लिए मुस्लिम आरक्षण का चारा फेंका था, लेकिन लोगों को समझते देर नहीं लगी कि आरक्षण मुसलमानों के लिए एक झुनझुना है, इससे मुसलमानों की माली हालत सुधरने वाली नहीं है. आरक्षण कार्ड खोखला निकलने के बाद कांग्रेस ने अब मुसलमानों को मोदी का भय दिखाकर उन्हें अपने पाले में लाने का नया खेल शुरू किया है. बेनी इससे पहले अन्ना हजारे पर भी विवादित बयानबाज़ी करके सुर्ख़ियां बटोर चुके हैं.

कांग्रेस के दिग्गज नेता और स्टार प्रचारक बेनी प्रसाद वर्मा ने ज़िला फ़ैज़ाबाद में एक चुनावी सभा में यह शिगूफ़ा छोड़ा. इसके द्वारा वह भाजपा को घेरना चाहते थे. मगर वह यह भूल गए कि भाजपा में ही नरेंद्र मोदी को लेकर अलग-अलग राय है. ऐसे में नरेंद्र मोदी को भाजपा शायद ही भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करे. शायद इन पर इस बात का इसलिए फ़र्क़ भी नहीं पड़ता है, क्योंकि वह तो मोदी बनाम राहुल का हौवा खड़ा करके मात्र मुसलमानों के बीच अपनी पैठ बढ़ाने का सपना सपना संजोए हैं. इसलिए वह उत्तर प्रदेश के चुनाव को सेमीफाइनल की उपमा दे रहे थे. बेनी का कहना था कि वर्ष 2014 में होने वाला आम चुनाव फाइनल मुक़ाबला होगा. बेनी यहीं नहीं रुके, उन्होंने यहां तक भविष्यवाणी कर दी कि आम चुनाव में नरेंद्र मोदी को परास्त करके राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे. बेनी का बाण भाजपा का ही सीना छननी करने तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा प्रमुख मुलायम सिंह को भी खरी-खोटी सुनाई. एक तरफ़ सपाई और कांग्रेसी मिलकर प्रदेश में सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं तो दूसरी तरफ़ बेनी ने घोषणा कर दी कि प्रदेश में कांग्रेस-रालोद की सरकार बनने पर माया और मुलायम को जेल में डाल दिया जाएगा. बेनी के बयान में गंभीरता कम और उत्साह ज़्यादा दिखाई दिया. अगर सचमुच कांग्रेस माया और मुलायम को जेल की सलाख़ों के पीछे डालने का मन बना ले तो इनके ख़िलाफ़ चल रहे आय से अधिक संपत्ति के मामले में वह सीबीआई को खुली छूट दे दे. कौन नहीं जानता है कि केंद्र के कारण ही उक्त दोनों नेताओं के ख़िलाफ़ चल रहे मुक़दमों में तेज़ी नहीं आ पा रही है. नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी की बात की जाए तो बेनी मुग़ालते में हैं. उनकी ही एक मुख्यमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ पिछले दिनों कर चुकी हैं. योजना आयोग आदि भी मोदी की गुड गवर्नेंस की तारीफ़ करते रहता है. गुजरात ने मोदी के कार्यकाल में विकास की जो ऊंचाइयां हासिल की हैं, वह उन्हें या उनके जैसे कुछ लोगों को भले ही न दिखें, लेकिन जो लोग प्रगतिवादी हैं, उन्हें मोदी में कई ख़ूबियां दिखती हैं. गुजरात दंगे के नाम पर मोदी को कठघरे में कब तक खड़ा किया जाता रहेगा. अगर जनता कांग्रेस शासनकाल में हुए दंगों और दिए गए जख़्मों को भूल सकती है तो फिर मोदी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जा सकता. कांग्रेस का अतीत भी कम घिनौना नहीं है. इसके दामन में सिख दंगों सहित तमाम दाग़ हैं. बेनी कहते हैं कि अगर लोहिया ज़िंदा होते तो सपा के समाजवाद का असली चेहरा परिवारवाद देखकर ज़हर खा लेते. उनकी बात ग़लत नहीं है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि वह अपने इस समाजवादी चेले को कांग्रेस की गोद में बैठा हुआ देखकर भी ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते. अगर बेनी सच्चे समाजवादी होते तो मुलायम से नाराज़गी के बाद कांग्रेस में जाकर मलाई खाने का काम नहीं करते, बल्कि समाजवाद का झंडा ऊंचा करने के लिए वह स्वयं सड़क पर आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने की बजाय लालबत्ती को प्राथमिकता दी. बेनी बाबू बिन सिर-पैर के मुद्दों को क्यों हवा दे रहे हैं, इसके पीछे की साज़िश को समझा जाए तो पूरी तस्वीर साफ़ हो जाएगी. असल में बेनी बाबू अपने आप को पिछड़ों का बड़ा नेता मानते हैं. लेकिन पिछले दिनों उनके ही वर्चस्व वाले क्षेत्र में जिस तरह से उनका विरोध किया गया, इससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं. उनका विरोध करने वाली उनकी ही जनता थी, इसलिए वह इसे विपक्षी साज़िश बता नहीं पाए. जनता नाराज़ थी कि बेनी ने अपने इलाक़े के लिए कुछ नहीं किया न विकास की ओर ध्यान दिया, न ही हर साल आने वाली बाढ़ और इससे होने वाले नुक़सान के बारे में उन्होंने कभी सोचा. जनता का गुस्सा जब आपे से बाहर हो गया तो वह सड़क पर उतरने की बजाय बेनी और राहुल-सोनिया की सभाओं में अपनी नाराज़गी का इज़हार करने लगी. कई बार तो बेनी विरोध के चलते मंच तक तो आए, लेकिन बिना बोले ही चले गए. बेनी को लगा कि कांग्रेस में उनकी बनी-बनाई साख चौपट हो सकती है. बस इसी के बाद बेनी बाबू घटिया राजनीति पर उतर आए. वह मोदी बनाम राहुल की बहस छेड़कर मुसलमानों को रिझाने में लग गए तो मुलायम को जेल भेजने की बात भी उन्होंने काफ़ी सोच-समझकर की है. वह ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि अगर प्रदेश में कांग्रेस गठजोड़ वाली सरकार बनने की नौबत आए तो मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें आगे करने में कांग्रेस को कोई दिक़्क़त न आए. वहीं मुलायम भी जेल जाने के डर से अपना मुंह बंद रखें. बेनी बाबू राहुल बनाम मोदी की लड़ाई को आगे बढ़ाकर अपने को कांग्रेस का सबसे बड़ा पैरोकार साबित करना चाहते हैं, तो इसके पीछे कहीं न कहीं उन्हें अपनी ही पार्टी के सांसद पीएल पुनिया को लेकर दिखाई दे रहा ख़तरा भी है. बेनी और पुनिया की राजनीतिक ज़मीन बाराबंकी और आसपास के ज़िलों में ही सीमित है. एक अपने आप को दलितों का रहनुमा समझता है तो दूसरा पिछड़ों का. बेनी को जहां विरोध का सामना करना पड़ रहा है, उनके वर्चस्व वाली विधानसभाओं में कांग्रेसी प्रत्याशियों की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, यहां तक की उन्हें अपने पुत्र राकेश को जिताने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही हैं. वहीं पीएल पुनिया को जनता सिर आंखों पर बैठाए है. उनकी छवि ऐसा नेता की है जो सुख-दुख में जनता के साथ दिखता है. अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कराने के मामले में भी पुनिया की छवि अच्छी है. वह पहली बार सांसद बने हैं, लेकिन उन्होंने बेहतर काम करके अपनी पहचान बना ली है, जबकि बेनी प्रसाद वर्मा वर्षों से राजनीति के शीर्ष पर विराजमान हैं, लेकिन जनता की सुध लेने का समय उन्हें कभी नहीं मिलता. पुनिया की विश्वसनीयता में वृद्धि और बेनी को अपना नाम रोशन करने के लिए ओछे हथकंडे आज़माने को मजबूर कर दिया. वह यह भूल गए कुछ समय के लिए वह भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं, लेकिन जब बैलेट मशीन से नतीजे आएंगे तब उनके लिए अपना दामन बचाना आसान नहीं होगा.

बेनी इससे पहले अन्ना हजारे पर भी हमला बोलकर सुर्ख़ियां बटोर चुके हैं. कुछ दिनों पहले उन्होंने कानपुर में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्हीं से ही पूछा था, कौन अन्ना हजारे है? उनमें हिम्मत है तो वह हमारे संसदीय क्षेत्र में आकर दिखाए. तब बेनी ने कहा था कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में राजनीति ही की है, यह आदमी धोती-कुर्ता पहन कर अपने आप को अनशन मास्टर समझता है. वह अन्ना हजारे पर आरएसएस का एजेंट और सेना का भगोड़ा सिपाही जैसे आरोप लगा चुके हैं, लेकिन आज उन्हें ही अपने इलाक़े में विरोध का सामना करना पड़ रहा है. उनका राहुल और सोनिया के सामने विरोध किया जा रहा है, लेकिन वह इस मसले पर मुंह खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं.

बात नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी की कि जाए तो बेनी मुगालते में हैं. उनकी ही एक मुख्यमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ पिछले दिनों कर चुकी हैं. योजना आयोग आदि भी मोदी की गुड गवर्नेंस की तारीफ करते रहते हैं. गुजरात ने मोदी के कार्यकाल में विकास की जो ऊंचाइयां हासिल की हैं, वह उन्हें या उनके जैसे कुछ लोगों को भले ही न दिखे लेकिन जो लोग प्रगतिवादी हैं, उन्हें मोदी में कई खूबियां दिखती हैं. गुजरात दंगे के नाम पर मोदी को कटघरे में कब तक खड़ा किया जाता रहेगा. अगर जनता कांग्रेस काल में हुए दंगों और दिए गए जख्मों को भूल सकती है तो फिर मोदी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जा सकता. कांग्रेस का तो अतीत भी कम घिनौना नहीं है. इसके दामन में सिख दंगों सहित तमाम दाग हैं.

feedback@chauthiduniya.com

इलाहाबाद बना करोड़पतियों का संगम

इस ज़िले के उम्मीदवार तो मानो कुबेर की नगरी में ही निवास कर रहे हैं. यहां कमज़ोर से कमज़ोर उम्मीदवार अपने को करोड़पति साबित कर रहा है. वहीं उनकी पत्नियां भी संपत्ति के मामले में पीछे नहीं दिख रही हैं. नंदगोपाल नंदी कैबिनेट मंत्री हैं. हाई स्कूल पास हैं. 2007 में उन्होंने भाजपा दिग्गज केशरीनाथ त्रिपाठी और कांग्रेस की डॉ. रीता बहुगुणा को हराया था. इस बार फिर चुनावी अखाड़े ताल ठोंक रहे हैं. अन्य प्रत्याशियों के मुक़ाबले वह संपत्ति के मामले में कई करोड़ के मालिक हैं. उनके पास लगभग 32 करोड़ हैं, जबकि उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता के पास क़रीब 52 करोड़ की संपत्ति है. इसके अलावा उनके नाम लगभग पौने पांच करोड़ और नंदी के पास 84 लाख की अचल संपत्ति है. उनकी पत्नी के नाम बीएमडब्ल्यू, पसाट व फोर्ड इनडेवर जैसी पांच लक्जरी गाड़ियां और 35 लाख के जेवर हैं. वैसे उन पर 30 करोड़ रुपये की देनदारी भी है. जेल में 4 साल से बंद बाहुबली माने जाने वाले पूर्व सांसद अतीक़ अहमद के पास बीस करोड़ से ज़्यादा की चल-अचल परिसंपतियां है. उन्होंने 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान ख़ुद और अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन की चल-अचल संपत्ति 10 करोड़ से कम की घोषित की थी, लेकिन अब वह तीन साल में बढ़कर 20 करोड़ से ज़्यादा की हो गई है. हाई स्कूल अनुत्तीर्ण अतीक़ पर हत्या और अपहरण सहित 44 मुक़दमे हैं. 49 वर्षीय अतीक़ अहमद के नाम से असलहे पिस्टल और राइफल हैं, जबकि परवीन के नाम तीन असलहे दो रिवाल्वर और एक बंदूक़ है. अतीक़ अहमद के ख़िलाफ़ चुनाव मैदान में उतरी बसपा विधायक पूजा पाल ने भी ख़ुद का नाम करोड़पतियों की सूची में दर्ज करा लिया है. विधायक राजूपाल की हत्या के बाद सियासत की ओर रुख़ करने वाली पाल पहला चुनाव हार गई थीं, लेकिन 2007 में अतीक़ अहमद के भाई ख़ालिद अज़ीम उर्फ़ अशरफ़ के मुक़ाबले बाज़ी मार ले गईं. सपा दिग्गज कुंवर रेवती रमण सिंह के पुत्र उज्जवल रमण सिंह और पिछले चुनाव में उन्हें हराने वाले बसपा विधायक आनंद पांडेय उर्फ़ कलेक्टर पांडेय, फूलपुर से सपा प्रत्याशी सईद अहमद और बसपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह, शहर उत्तरी से चुनाव मैदान में क़िस्मत आज़मा रहे भाजपा विधायक उदयभान करवरिया, यहीं से उनके मुक़ाबले मुस्तैद बसपा प्रत्याशी हर्षवर्धन वाजपेई, शहर दक्षिणी से भाजपा प्रत्याशी केशरीनाथ त्रिपाठी, करछना से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे दीपक पटेल और सोरांव से बसपा प्रत्याशी के रूप में दो बार जीत हासिल कर प्रतापपुर से फिर चुनावी जंग में शामिल हुए मुज्तबा सिद्दीक़ी की भी गिनती करोड़पतियों में है. कांग्रेस के टिकट पर अतीक़ अहमद के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ रहे रविप्रकाश बसपा से हाल में नाता तोड़कर सोरांव से अपना दल से उम्मीदवार बने विधायक वाचस्पति, हंडिया विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व गृह राज्यमंत्री राजेंद्र त्रिपाठी, हंडिया से ही पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री राकेशधर त्रिपाठी, शहर उत्तरी से सपा प्रत्याशी शशांक त्रिपाठी, बारा से सपा उम्मीदवार डॉ. अजय कुमार और फूलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी माशूक़ ख़ान की भी चल-अचल संपत्ति करोड़ों में है. कुल करोड़पति प्रत्याशियों की संख्या 26 के आसपास है. इन उम्मीदवारों में कुछ ऐसे भी हैं, जो ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन उनकी गिनती अमीरों में होती है. लनमें सपा की विजमा यादव, सईद अहमद, बसपा की पूजा पाल, नंदगोपाल नंदी, आनंद पांडेय उर्फ़ कलेक्टर, भाजपा के विद्याकांत और अपना दल के अतीक़ अहमद जैसे प्रत्याशियों की शिक्षा हाई स्कूल या इससे भी कम है. उच्च शिक्षा हासिल करने वाले प्रत्याशियों में राकेशधर त्रिपाठी, डॉ. अजय कुमार, दीपक पटेल, श्याम सूरत उपाध्याय, चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, डॉ. भगवत पांडेय, हर्षवर्धन वाजपेई, केशरीनाथ त्रिपाठी और उदयभान करवरिया के नाम का ज़िक्र किया जा सकता है. मुक़दमों के मामले में अतीक़ अहमद सबसे समृद्ध हैं. उनके ख़िलाफ़ कुल 44 मुक़दमे हैं. इसके अलावा रामकृपाल, सईद अहमद, रवि प्रकाश, महेश नारायण सिंह ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर पांच या इससे अधिक मुक़दमे क़ायम हैं. बहरहाल, इलाहाबाद के करोड़पति प्रत्याशियों की संपत्ति जानकार राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि गंगा-यमुना के तट पर बसा यह नगर सचमुच करोड़पतियों का संगम बन गया है. लोगबाग विधानसभा चुनाव धनपतियों के बीच की जंग मान रहे हैं.

अतीक अहमद

नंद कुमार गुप्ता

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

डेसो रफेल सौदा

भारत-फ्रांस ने किया रणनीतिक समझौता

अमिताभ आकाश

भारत ने फ्रांसीसी कंपनी से लड़ाकू विमान ख़रीदने का फ़ैसला कर सभी को चौंका दिया, लेकिन यह सौदा किया जाना पहले से ही तय था. वास्तव में यह भारत की सैन्य महत्वाकांक्षाओं की रणनीति का हिस्सा ही था. आख़िरकार भारत का अभी तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदे की घोषणा हो ही गई. पूरी दुनिया की निगाहें इस पर लगी हुई थीं. रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारतीय वायुसेना के लिए आवश्यक 126 बहुउद्देशीय लड़ाकू रफेल विमान फ्रांस की डेसो एविएशन से ख़रीदे जाएंगे. हालांकि सौदे पर अगले वित्तीय वर्ष में ही हस्ताक्षर किए जाएंगे. क़रार के तहत कंपनी को रफेल फाइटर की पहली स्कैवड्रन तीन साल के भीतर सौंपनी होगी. बाक़ी 108 विमान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स के साथ तकनीकी हंस्तारण द्वारा भारत में ही निर्मित किए जाएंगे. भारत को वायुसेना के पुराने हो चुके मिग-21 विमानों को बदलने के लिए इन विमानों की आवश्यकता थी. रक्षा मंत्रालय ने इनकी ख़रीद के लिए निविदा निकाली थी. इसमें रूसी कंपनी ने मिग-35, अमेरिकी बोंइग कंपनी ने एफ-16, एफ-18, स्वीडन का ग्रिपन, फ्रांस का रफेल और टायफुन यूरोफाइटर (इंग्लैंड, इटली, स्पेन और जर्मनी का संयुक्त उपक्रम) शामिल था. सेना द्वारा सभी मानकों पर इन विमानों को परखने के बाद यूरोफाइटर और रफेल ही अंतिम दौर में पहुंच पाए. मीडिया रिपोर्ट में छनकर आ रही ख़बरों में यूरोफाइटर पर ही अंतिम मोहर लगना तय माना जा रहा था कि अचानक रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि वायुसेना के लिए सरकार द्वारा फ्रांस का डसाल्ट रफेल ही ख़रीदा जाएगा. 11 बिलियन डॉलर (लगभग 52 हज़ार करोड़ रुपये) के इतने बड़े सौदे के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन, स्वीडन, फ्रांस और रूस की सरकारें लॉबिंग कर रही थीं. अमेरिका, भारत पर दबाव डाल रहा था कि वह एफ-16 लड़ाकू विमानों को ही ख़रीदे, लेकिन यह लड़ाकू विमान चीन और पाकिस्तान के पास भी है. चीन इस विमान की तकनीकी क्षमताओं को जानता है, दूसरे आने वाले निकट समय में अमेरिका इन विमानों को अपनी वायुसेना से रिटायर भी करने वाला है. स्वीडन का ग्रिपन वायुसेना की पंसद नहीं था, जबकि रूसी मिग-35 हमारे पास मौजूदा मिग-29 का संशोधित संस्करण ही है. जांचने-परखने के बाद यूरोफाइटर और रफेल ही अंतिम दौड़ में रह गए. तकनीकी क्षमताओं की वजह से यूरोफाइटर को ही अंतिम रूप से तय माना जाने लगा था. मालूम हो कि रफेल को दक्षिण कोरिया, स्वीट्ज़रलैंड, सिंगापुर और मोरक्को ने ख़रीदने से इंकार कर दिया था. भारतीय मीडिया ने भी रक्षा सूत्रों के हवाले से कई बार प्रकाशित किया कि रफेल वायुसेना की पंसद नहीं है. सऊदी अरब अमीरात और ब्राजील ने अवश्य इसे ख़रीदने में रुचि दिखाई है. फ्रांसीसी एअरफोर्स ने 180 विमानों का ऑर्डर कंपनी को दिया था. रफेल को निर्यात के लिए पर्याप्त ऑर्डर न मिलने के कारण फ्रांस

के प्रधानमंत्री ने इस प्रोजेक्ट को और अधिक धनराशि देने से इंकार करते हुए इसके उत्पादन को रोकने की घोषणा की थी. लेकिन दिसंबर 2011 में फ्रांस ने कहा कि रफेल लड़ाकू विमान का उत्पादन जारी रहेगा, लेकिन अचानक भारत ने फ्रांसीसी कंपनी से लड़ाकू विमान ख़रीदने का फ़ैसला कर सभी को चौंका दिया. यह सौदा किया जाना पहले से ही तय था. वास्तव में यह भारत की सैन्य महत्वाकांक्षाओं की रणनीति का हिस्सा ही था, जिसमें भारत की रक्षा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर बनाया जाना है. दुनिया के चार देश अमेरिका, रूस, फ्रांस और इग्लैंड ही फाइटर जेट इंजन बनाने में सफल रहे हैं. यह एक बेहद मुश्किल तकनीक है. भारत भी अपना जेट इंजन कावेरी बना चुका है, लेकिन उच्च स्तरीय परीक्षणों में इसमें ख़ामियां थीं. भारत यदि यह क्षमता हासिल कर लेता तो वह दुनिया का ऐसा केवल पांचवा देश होता. अमेरिका, रूस और इंग्लैंड हमारी मदद करने को तैयार नहीं थे. ऐसे में फ्रांस की जेट इंजन बनाने वाली स्कैमा कंपनी के सहयोग से भारत ने इस क्षमता को हासिल कर लिया. अब इसी कंपनी के साथ उच्च क्षमता वाला जेट इंजन बनाने पर काम चल रहा है, जिसे भारत के ड्रीम प्रोजेक्ट पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान में फिट किया जाएगा. यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि डेसो रफेल में स्कैमा जेट इंजन ही लगा हुआ है. इससे पहले हिंदुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर ध्रुव भी फ्रांस के सहयोग से ही तैयार किया गया.

यूरोफाइटर हमें जेट इंजन तो बेचने के लिए तैयार थी, लेकिन वह हमें जेट इंजन निर्माण के लिए आवश्यक तकनीकी सहयोग के लिए तैयार नहीं थी. हालांकि चीन भी लड़ाकू विमान बना चुका है, पर उसके पास जेट इंजन बनाने की क्षमता नहीं है. भारत द्वारा बनाए गए पहले लड़ाकू जेट तेजस में भी अमेरिकी इंजन लगा है. इसके अलावा सभी तकनीक स्वदेशी है, जबकि चीनी विमान की अधिकांश तकनीक स्वदेशी नहीं है. भारत उच्च क्षमता का कावेरी जेट इंजन बनाते ही पूरी तरह से स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता हासिल कर लेगा. अपने इसी ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए भारत ने फ्रांसीसी सरकार से रणनीतिक सैन्य समझौता किया. हालांकि रक्षा सूत्रों का यह भी कहना है कि रफेल विमान तकनीकी दृष्टि से यूरोफाइटर से बेहतर है. ऐसा नहीं है कि यह समझौता यहीं तक सीमित है. भारत एएमसीए (एडवांस्ड मीडियम कांबैट एयरक्राफ्ट) बना रहा है, जो कि स्टील्थ लड़ाकू विमान होगा, जिसे राडार नहीं पकड़ सकता. फ्रांस के पास इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं है. फ्रांस इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी कर सकता है, जिससे इस महंगे प्रोजेक्ट में भारत का निवेश काफ़ी कम हो जाएगा.

feedback@chauthiduniya.com

भारतीय जनता पार्टी

मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश में

इस बार अगर भाजपा की उम्मीद के अनुसार वोटिंग हो जाती है तो इसकी उम्मीदें परवान चढ़ सकती हैं. वैसे भी भाजपा के लिए यह समय काफी अनुकूल लग रहा है. खासकर चुनावी समर में किसी तरह का ध्रुवीकरण नहीं दिखना भाजपा की सफल रणनीति का ही हिस्सा है.इस समय थोड़ी-बहुत सत्ता विरोधी लहर के अलावा कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिससे भाजपा घाटे में रहे.

पंजाब और उत्तराखंड में मतदान का प्रतिशत बढ़ने से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में चुनाव से पहले ही मौसम खुशनुमा हो गया है. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेताओं को लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश में भी इतनी ही बड़ी संख्या में मतदाता निकलेंगे. अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की तक़दीर बदल जाएगी. इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की वर्षों पुरानी सोच काम कर रही है कि राज्य में मुस्लिम-दलित आदि कुछ क़ौमें तो मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती हैं, लेकिन भाजपा का परंपरागत और मज़बूत वोट बैंक समझे जाने वाले बनिये-ब्राह्मण आदि उच्च जाति के लोग मतदान दिवस को छुट्टी का दिन समझ कर घरों में क़ैद हो जाते हैं. प्रत्येक चुनाव में भाजपा और संघ के लिए अपने वोटरों को बाहर निकालना टेड़ी खीर साबित होता है. मतदाताओं को घर से बाहर निकालने का जो काम अभी तक आरएसएस और भाजपा वाले बख़ूबी नहीं कर पाए, अगर वह काम चुनाव आयोग कर देता है, तो भाजपा के लिए आयोग किसी अवतार से कम नहीं होगा. वैसे चुनावी इतिहास भी इस बात का गवाह है कि जब-जब मतदान का प्रतिशत बढ़ता है, सबसे अधिक फ़ायदे में भाजपा ही रहती है. फिर चाहे चुनाव केंद्र में हो या राज्यों में. अयोध्या कांड के समय हिंदू वोटरों ने भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक समझे जाने वाले नेता भी इस बात से इंकार नहीं करते हैं. उनका तो यहां तक मानना है कि भाजपा को चाहने वाले आधे से अधिक मतदाता घरों से ही नहीं निलकते हैं, जबकि अन्य दलों में यह आंकड़ा काफ़ी ऊंचा रहता है. भाजपा के अगर चालीस प्रतिशत मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, तो अन्य दलों मतदाताओं के मतदान का प्रतिशत 70-75 फ़ीसदी के क़रीब रहता है. इसी अंतर के कारण भाजपा पिछड़ जाती है. राजनीतिक पंडितों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को चाहने वालों का प्रतिशत अच्छा ख़ासा है, लेकिन वोटिंग करके इसको सत्ता तक पहुंचाने वाले हाथ कम पड़ जाते हैं. यदि भाजपा का वोटर आरामतलबी छोड़कर क़सम खा ले कि वह वोट ज़रूर देगा तो भाजपा का ग्राफ बढ़ने में देर नहीं लगेगी.

1980 में भारतीय जनता पार्टी अपने वर्तमान नाम के साथ चुनाव मैदान में उतरी थी. उस समय उसे मात्र 11 सीटों पर विजय हासिल हुई थी. तब 44.92 प्रतिशत मतदान हुआ था. इसके बाद 1985 के विधानसभा चुनाव में जब 45.64 प्रतिशम मतदान हुआ तो इसकी सीटों की संख्या 16 हो गई. 1989 में 51.43 प्रतिशत मतदान हुआ तो भाजपा की सीटें बढ़कर 57 हो गईं. 1991 से लेकर 2002 तक उत्तर प्रदेश में 55 प्रतिशत के आसपास मतदान हुआ. इस दौरान भाजपा की स्थिति भी बेहतर रही. हालांकि इसकी सीटें घटती-बढ़ती रहीं, लेकिन 2005 में जब मात्र 45.94 प्रतिशत मतदान हुआ तो भाजपा सिमट कर 51 पर पहुंच गई. उत्तर प्रदेश में भाजपा का स्वर्णिम काल 1991 का रहा, जब उसे सबसे अधिक 221 सीटें मिलीं. इस बार अगर भाजपा की उम्मीद के अनुसार वोटिंग हो जाती है तो उसकी उम्मीदें परवान चढ़ सकती हैं. वैसे भी भाजपा के लिए यह समय काफ़ी अनुकूल लग रहा है. ख़ासकर चुनावी समर में किसी तरह का ध्रुवीकरण नहीं दिखना भाजपा की सफल रणनीति का ही हिस्सा है. इस समय थोड़ी-बहुत सत्ता विरोधी लहर के अलावा कोई ऐसा मुद्दा नहीं, जिससे भाजपा घाटे में रहे. केंद्र और राज्य सरकार का भ्रष्टाचार, पिछड़ों का भाजपा के प्रति खिंचाव इसके लिए प्लस प्वाइंट साबित हो रहे हैं. उत्तर प्रदेश में भाजपा अगर अच्छा प्रदर्शन करती है, तो भले ही उसकी सरकार न बने लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के समय भाजपा को फ़ायदा हो सकता है. भाजपा की सीटों का आंकड़ा सौ के आसपास भी पहुंच जाए तो इसके लिए कई मुश्किलें अपने आप आसान हो जाएंगी.

मतदान का प्रतिशत बढ़ा, तब तो भाजपा को फ़ायदा होता दिख ही रहा है. इसके अलावा बात भाजपा के अंदरख़ाने की करें तो उसके नेताओं को अपने पक्ष में उत्साहजनक रुझान दिख रहा है. यह रुझान सर्वेक्षणों पर आधारित है. पार्टी द्वारा कराए गए पांच अलग-अलग सर्वेक्षणों को आधार मानें तो आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापसी करेगी. इन्हीं सर्वेक्षणों ने भाजपा में संभावित मुख्यमंत्रियों की लिस्ट लंबी कर दी है. भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव को अपने लिए सुनहरा मौक़ा समझ रही है तो इसके पीछे कांग्रेस, सपा व बसपा की ग़लत रणनीति भी कम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रही है. जिस तरह से बसपा और सपा केंद्र में कांग्रेस गठबंधन सरकार को परोक्ष समर्थन दे रहे हैं, उससे भाजपा को जनता को यह बताने में परेशानी नहीं हो रही है कि उक्त तीनों पार्टियां आपस में मिली हुई हैं और नूराकुश्ती कर रही हैं. तीनों पार्टियां एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही हैं. भाजपा नेताओं द्वारा अपनी जीत तय करने के लिए शब्दों को नाप-तौल कर बोला जा रहा है. भाजपा ख़ासकर भय, भूख, भ्रष्टाचार व आतंक के मुद्दे पर खुलकर बोल रही है. वहीं राम मंदिर जैसे मुद्दे से उसने किनारा कर दिया है, ताकि उसके विरोधी इसकी छवि को धूमिल न कर सकें. यह इसका चुनावी एजेंडा भी है.

अजय कुमार
feedback@chauthiduniya.com

कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने युवाओं के लिए रोज़गार मुहैया कराने की बात कही है और उत्तर प्रदेश को स्वर्ग बना देने की घोषणा की है.

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

युवाओं को लुभाने की कोशिश में राजनीतिक दल

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

अन्ना हजारे और रामदेव का फैक्टर युवाओं को प्रभावित कर रहा है. वहीं निर्वाचन आयोग भी सख्ती से पेश आ रहा है. वहीं ख़राब छवि के प्रत्याशियों को भी विधानसभा की दहलीज़ न लांघने की बात ज़ोर शोर से टीवी चैनल और अख़बारनवीस उठा रहे हैं. यह एक आंदोलन की तरह हो रहा है. विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लुभावने नारे व घोषणा पत्र युवाओं के लिए लार टपकाने वाले भले ही लगते हों, लेकिन इन थोथे वादों को युवा भली-भांति समझ रहा है कि मंत्री बनने के बाद वे माननीय उनके द्वार पर जाने वाली सड़क व पगडंडी को भूल ही जाते हैं. जहां वह हाथ फैलाते हुए वोट मांगने आए थे. कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने युवकों के लिए रोज़गार मुहैया कराने की बात कही है.

दर्शन शर्मा

प्रदेश में युवाओं का जनाधार काफ़ी है. युवा मतदाता चाहता है कि बेहतर रोज़गार मिले, प्रतिभाओं का पलायन रुके, क्योंकि युवाओं के भविष्य पर ही देश का भविष्य निर्भर है. प्रदेश में उद्योग ठप है. औद्योगिक घराने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट, अपराधी, दाग़ी राजनीति से घबराते हैं. यहां का नौजवान ख़ाली हाथ घूम रहा है. पढ़ाई के लिए प्रदेश में कई अच्छे संस्थान है लेकिन प्लेसमेंट के नाम पर ये फिसड्डी हैं. निर्वाचन सूचियों में अंकित 32 प्रतिशत वोटर 30 साल से कम उम्र के हैं. ये जवान ऐसे हैं जो विज्ञान के युग में जन्मे हैं, ये जाति और मज़हब के नाम पर कट्टर नहीं हैं. उनकी आस्था भगवान–ख़ुदा और देश में समान रूप से है, लेकिन रूढ़ीवादी विचारधारा और अंधविश्वास से परे हैं.

आज के युवा राजनीति के नाम पर वोट मांगने वाले धर्मावलंबियों से दूर ही रहना चाहते हैं. ये मज़हब के नाम पर गुमराह नहीं होते, उनके दिल–दिमाग़ में विकास के कार्य जैसे रोटी कपड़ा और मकान, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार जैसी बातें घूम रही है. अख़बारों की सुर्ख़ियों में भ्रष्टतंत्र और लूटतंत्र की बातें सुनते–सुनते वे अब आज़िज़ आ चुके हैं. अन्ना हजारे और रामदेव का फैक्टर भी समाज में अपना प्रभाव डाल रहा है. वहीं निर्वाचन आयोग भी सख्ती से पेश आ रहा है. वहीं ख़राब छवि के प्रत्याशियों को भी विधानसभा की दहलीज़ न लांघने की बात ज़ोर शोर से टीवी चैनल और अख़बारनवीस उठा रहे हैं. यह एक आंदोलन की तरह हो रहा है. विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लुभावने नारे व घोषणा पत्र युवाओं के लिए लार टपकाने वाले भले ही लगते हों, लेकिन इन थोथे वादों को युवा भली–भांति समझ रहा है कि मंत्री बनने के बाद वे माननीय उनके द्वार पर जाने वाली सड़क व पगडंडी को भूल ही जाते हैं. जहां वह हाथ फैलाते हुए वोट मांगने आए थे. कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने युवकों के लिए रोज़गार मुहैया कराने की बात कही है और यूपी को स्वर्ग बना देने की घोषणा की है. वहीं समाजवादी पार्टी के घोषणा–पत्र में लिखा है कि सभी सरकारी सेवाओं में भर्ती की उम्र 35 वर्ष होगी. बेरोज़गार युवाओं को 12 हज़ार रुपये सालाना भत्ता दिया जाएगा. लड़कियों को कन्या धन मिलेगा. अच्छे अंक पाने वाली लड़कियों को साइकिल मिलेगी. लैपटॉप, टेबलेट, ड्रेस का मुफ्त वितरण. सभी ज़िला मुख्यालयों पर युवाओं के लिए स्टेडियम की स्थापना होगी. युवा अधिवक्ता को आर्थिक सहायता दी जाएगी. भूमि अधिग्रहण पर किसान परिवार के युवक को नौकरी सरकार देगी. वहीं भाजपा के घोषणा–पत्र में दावा किया गया है कि पांच साल में एक करोड़ युवाओं को रोज़गार मुहैया कराएगी. युवा अयोग का गठन होगा. बेरोज़गारों को 18 हज़ार रुपये प्रतिवर्ष भत्ता दिया जाएगा और बेरोज़गारों को क्रेडिट कार्ड मिलेगा. बैंकों से तीन फ़ीसदी पर ऋण मिलेगा. एक लाख सिपाही और दो लाख शिक्षकों की भर्ती. सभी वर्गों की बालिकाओं को मुफ्त साइकिल, छात्र छात्राओं को मुफ्त टेबलेट और पांच हज़ार में लैपटॉप भाजपा सत्ता आने पर देगी. कांग्रेस के घोषणा–पत्र में कौशल व रोज़गार मिशन के तहत बीस लाख युवाओं को नई नौकरी दी जाएगी, ताकि नौकरी की तलाश में उन्हें दूसरे राज्यों की ओर न जाना पड़े. पचास हज़ार युवा भारत निर्माण स्वयंसेवकों की नियुक्ति होगी और प्रत्येक वर्ष हर ज़िले में युवा महोत्सव का आयोजन होगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा कोई घोषणा पत्र अभी तक जारी नहीं किया है, जिसमें युवाओं को तसल्ली हो सके. बहुजन समाज पार्टी ने कहा है कि युवाओं को बरोज़गारी भत्ता देने का मतलब उन्हें मानसिक रूप से गुलाम बनाना है. उन्हें सीधे रोज़गार देने पर ज़ोर होना चाहिए. बहुजन समाज पार्टी का दावा है कि वह पांच साल में क़रीब पांच लाख युवाओं को रोज़गार देगी. कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी कहते हैं, अब युवा प्रदेश की तस्वीर बदलेंगे. कांग्रेस का पूरा फोकस युवाओं पर है, क्योंकि

जयंत सिंह चौधरी

पंकज सिंह

हम जानते हैं कि नौजवान तिकड़मी राजनीति, भ्रष्टाचार और मज़हबवाद से प्रभावित नहीं है. व्यवस्था के प्रति गुस्सा उसका नैसर्गिक गुण है. युवाओं के अंदर व्यवस्था के ख़िलाफ़ विद्रोह की ज्वाला कहीं न कहीं छिपी होती हैं. युवाओं को मेरा निमंत्रण है कि वह कांग्रेस से जुड़ें.

हमें पता है कि आज युवा वोट की राजनीति के बजाय प्रदेश की तस्वीर बदलने में विश्वास रखता है. वहीं समाजवादी पार्टी के युवराज और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि देश का भविष्य होने के कारण युवाओं की ज़िम्मेदारी सबसे अहम है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उन्हें ही आगे बढ़कर मोर्चा संभालना होगा. तभी देश–प्रदेश में तरक्क़ी और ख़ुशहाली संभव है. व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई भी अगर कोई मज़बूती से लड़ सकता है वह युवा ही है. उसमें संघर्ष की ज़बरदस्त क्षमता होती है. इस बार विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में युवाओं को अपनी भागीदारी निभानी है. उनके सपनों को मूर्त रूप देने का वक़्त आ गया है. विश्वास है कि वे ऐसी सरकार चुनेंगे जो उनके सुनहरे भविष्य के लिए योजनाएं चलाएगी न कि पत्थरों, स्मारकों में सरकारी ख़जाना लुटाएगी.

भाजपा के युवा नेता पंकज सिंह का कहना है कि युवा शक्ति को प्रोत्साहित किए बिना दुनिया में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं हो सके. प्रतिस्पर्धा में बने रहना है तो युवाओं को आगे बढ़ाना ही होगा. भारतीय जनता पार्टी ही एक मात्र ऐसी पार्टी है, जहां पर संस्कारित युवाओं को राष्ट्रहित के प्रति समर्पण की प्रेरणा दी जाती है. भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र भी युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. युवाओं के लिए अलग नीति बनाने और आयोग गठन के अलावा पांच वर्ष में एक करोड़ रोज़गार के नए अवसर प्रति माह दो हज़ार रुपये बेरोज़गारी भत्ता देने जैसा काम भी भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है. रालोद के सांसद युवराज जयंत चौधरी कहते हैं कि देश निर्माण और समाज के उत्थान में युवाओं की भूमिका सर्वाधिक रही है. राजनीतिक दलों को भी इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए कि युवा वर्ग को न केवल उचित प्रतिनिधित्व मिले, बल्कि नीति निर्धारण में भी भागीदारी हो. ख़ास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े युवाओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाएं, ताकि युवा शक्ति को शत–प्रतिशत सदुपयोग हो. रालोद हमेशा ही युवाओं को प्रोत्साहित करने और मूलभूत समस्याओं के समाधान को प्रयासरत रहा है. शिक्षा व रोज़गार के बेहतर अवसर हमारी प्राथमिकता हैं.

बहरहाल, 2007 के विधानसभा चुनाव में 40 से या उससे कम उम्र के विधायकों की संख्या 74 थी. 29 विधायक 35 वर्ष या कम तथा आठ विधायकों की उम्र 30 वर्ष के आस–पास रही है. सभी दलों ने इस बार भी अधिकतर युवाओं को मौक़ा दिया है. पिछली बार उत्तर प्रदेश के सदन में 74 विधायक पहुंचे थे. राजनेताओं की चौतरफ़ा हो रही निंदा के बावजूद लोगों का भरोसा लोकतंत्र से अभी उठा नहीं है. राजनीतिक पंडितों का मानना है कि सभी नेता ख़राब छवि के नहीं हैं, लेकिन राजनीति के दामन पर अपराधी और भ्रष्टाचारी दाग़ लगने से जनता का विश्वास नेताओं से उठा है. उनका मानना है कि इन अपराधी छवि के नेताओं की जगह बुद्धिमान युवा नेता अपनी जगह बनाएं, लेकिन यह परिपाटी तब लागू होगी जब आमजन में प्रदेश के विकास के लिए सोचने समझने की शक्ति होगी. जनता की मांग युवा छवि के बेदाग़ नेताओं की है, क्योंकि उम्रदराज़ नेता जातिवादी, अपराधी राजनीति और भ्रष्टाचार की बीमारी से ग्रस्त हैं. उन्हें इससे निजात नहीं मिलने वाली. इसलिए नई राजनीतिक पौध ही इसमें कारगर साबित होगी. पार्टी को पैसे देकर बनने वाले प्रत्याशी जीतने के बाद पैसा कमाने की सोच लेकर सदन में पहुंचते हैं. वह अपने ख़र्च से कई गुना कमाने की चाह रखते हैं. इसमें गुनाह किसका है. नेता इससे बाज़ नहीं आते. सोने के मुकुट, सोने की तलवार, सोने की बनी वस्तुएं उन्हें तोहफ़ों में मिलती है. देखते ही देखते एक लखपति प्रत्याशी करोड़पति बन जाता है. जनता उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती. युवा राजनीतिज्ञों का मानना है कि चुनाव आयोग दाग़ी, अपराधी छवि के लोगों को चुनाव लड़ने से किसी तरह पाबंदी लगाए, ताकि देश जल्दी उन्नति कर सके. प्रदेश की पार्टियों द्वारा अपने घोषणा–पत्रों में घोषित बेरोज़गारी भत्ते के कारण इन दिनों बेरोज़गारों की लाइन प्रदेश के रोज़गार कार्यालयों में सुबह से शाम तक लग रही है, लेकिन युवा यह नहीं सोच रहे कि इन चंद रुपयों से उनका कितना भला होगा.

feedback@chauthiduniya.com

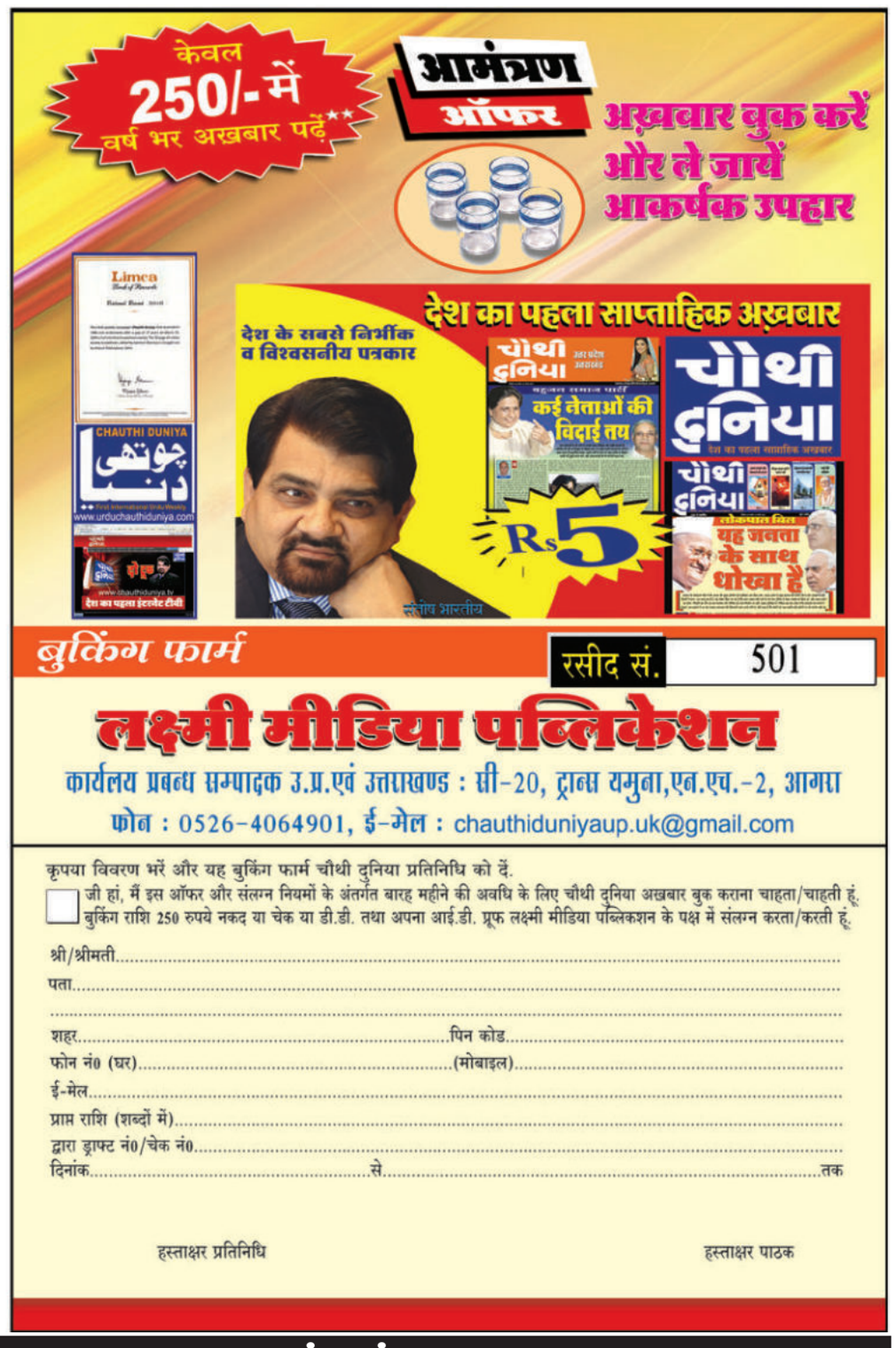

उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सभी ज़िलों में वितरण एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें : श्रीनिवास गुप्ता (ठाकुर), प्रबंध संपादक : 09837082462